संपादकीय

हिन्दुओं की घटती जनसंख्या: खतरे की घंटी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन अनुसार 1950 से 2015 के बीच हिन्दुओं की हिस्सेदारी में 7.82 फीसदी की गिरावट आई। वहीं मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15 फीसदी, ईसाइयों की 5.38 फीसदी व सिखों की 6.58 फीसदी बढ़ी है। इस दौरान, भारत के विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में तेज उछाल देखा गया। अध्ययन के अनुसार भारत की आबादी में बौद्धों की हिस्सेदारी में भी मामूली वृद्धि हुई, लेकिन जैन व पारसियों की संख्या घटी है। जनसंख्या में हिन्दुओं की हिस्सेदारी 1950 के 84.68 फीसदी से घटकर 2015 में 78.06 फीसदी रह गई है। इसी अवधि (65 वर्ष) में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 9.84 फीसदी से बढ़कर 14.09 फीसदी हो गई। बहुसंख्यक आबादी में गिरावट भारत से ज्यादा निकट पड़ोसी देशों में म्यांमार में दर्ज की गई है, जहां बहुसंख्यक थेरवाद बौद्धों की आबादी 10 फीसदी कम हो गई है। पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे निकटतम पड़ोसी देशों में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है। बांग्लादेश की आबादी में जहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 18.5 प्रतिशत का उछाल है, वहीं पाकिस्तान में यह 3.7 प्रतिशत और अफगानिस्तान में 0.29 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बावजूद पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय-हनफी मुस्लिम की हिस्सेदारी में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि और कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्ययन के लेखकों अनुसार आंकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि फल-फूल रहे हैं। अध्ययन में दुनियाभर के 167 देशों के रुझानों का आकलन किया गया, जिसकी रिपोर्ट इसी महीने जारी की गई थी। इसके लेखकों के मुताबिक, भारत का प्रदर्शन बड़े वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अध्ययन के लेखकों में शमिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व मिश्र शामिल हैं।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो कभी भारत का ही अंग हुआ करते थे, आज अलग हैं तो उसका एक बड़ा कारण मुस्लिम जनसंख्या का इन क्षेत्रों में समय के साथ बढ़ना ही था। भारत में आज भी हिन्दुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो यह स्थिति लोकतांत्रिक दृष्टि से तो ठीक है लेकिन अतीत को देखें तो यह भारत के भविष्य के लिए एक खतरा भी है। भारत में जनगणना करने का सिलसिला 1880 में अंग्रेजी हकूमत के समय शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक मुसलमानों की वृद्धि दर हमेशा हिन्दुओं से अधिक रही। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हुई है वहीं अलग होने की आवाज उठी और परिणामस्वरूप भारत के कभी हिस्सा रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान अलग देश बन गये और इन्हीं देशों के हिन्दुओं और सिखों की जिन्दगी नारकीय होती चली गई और परिणामस्वरूप या तो उनको इस्लाम स्वीकार करना पड़ा या देश छोड़ना पड़ा।

आजाद भारत में आज भी जिन क्षेत्रों में हिन्दू, सिख या अन्य धर्मों को मानने वाले अल्पमत में हैं और मुस्लिम बहुमत में है वहां हिन्दुओं और सिखों सहित अन्य धर्मों में आस्था रखने वालों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अलगाववादी नारे और हिंसक झड़पें वहां की रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा बन गए हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को देश भर में जनसंख्या संतुलन बनाये रखने के लिए मुहिम चलानी होगी। क्योंकि अगर इसी तरह हिन्दुओं की आबादी घटती चली गई तो 50-100 वर्षों बाद देश की सभ्यता व संस्कृति पर कुप्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि जहां जनसंख्या में बदलाव आता है वहां देश के रहने वालों का भाग्य भी बदल जाता है। विश्व भर में नज़र दौड़ाकर देखें तो पायेंगे कि जहां कहीं भी ईसाई या इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वालों का प्रतिशत 40 से 50 प्रतिशत हुआ वह देश इस्लामिक या ईसाई देश घोषित हो गए और उन देशों का अतीत से नाता टूट गया तथा भविष्य व भाग्य दोनों बदल गये।

भारत व भारतीय संस्कृति तथा दर्शन तभी बचेंगे अगर भारत में हिन्दू बहुमत में रहेगा। 'सर्वधर्म समभाव' तथा 'सरबत के भले की' भावना को अगर बचाये रखना है तो देश में जनसंख्या के संतुलन को बनाये रखना आवश्यक है। -इरविन

शस्त्र-शास्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं भगवान परशुराम

भगवान परशुराम का आदर्श चरित्र प्रत्येक युग और देश में सदा प्रासंगिक है। वे यथार्थ की कठोर प्रस्तर शिला पर सुप्रतिष्ठित हैं और मानव मन की फूल से भी कोमल तथा वज्र से भी कठोर-'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' अन्तः वृत्तियों के संवाहक हैं। मनुष्य में 'सत' और 'असत' का द्वन्द्व सनातन है। उसके 'सत' का सम्बर्द्धन करने के लिए 'शास्त्र' और 'असत' का नियंत्रण करने के लिए 'शस्त्र' का विधान सभ्यता के अरूणोदय काल में किया गया। आज भी मानव चरित्र सत् और असत् से घिरा है, अतः युग-युगान्तर की तथाकथित विकास यात्रा के बाद आज भी शास्त्र और शस्त्र की सत्ता स्वीकृत है।

यद्यपि भगवान परशुराम के परवर्ती युग में भगवान बुद्ध, महात्मा गाँधी आदि महापुरूषों ने शस्त्र की शक्ति को अस्वीकार कर केवल शास्त्र (आत्मबल) की सत्ता ही प्रचारित की है, किन्तु इन विचारकों के विचार अर्द्धसत्य और काल्पनिक आदर्श ही अधिक सिद्ध हुए हैं। मानव समाज के व्यापक-फलक पर वे अर्थहीन हैं। मनुष्य के अंदर का पशु आज भी शस्त्र के नियंत्रण को ही मानता है। शास्त्र के शिक्षण को तो वह प्रलाप ही समझता है, उसकी उपेक्षा करता है और पर-पीड़न के आत्मघाती पथ पर तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि शस्त्र की धार उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन जाती। सृष्टि का नियम तो यही है कि जब मनुष्य की पशु-वृत्ति प्रबल हो उठती है तो उसका नियन्त्रण करने के लिए मनुष्य को अपने अन्दर का पशु अपने प्रतिपक्षी से भी अधिक उग्र रुप में आग्रह-पूर्वक जगाना पड़ता है, नृसिंह बनना पड़ता है, ताकि वह उन्मत्त पाशविकता को अंकुशित कर भोली मानवता का जीवन निरापद बना सके। राम का संधि प्रस्ताव और युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा शस्त्र बल के विश्वासी रावण और दुर्योधन जैसे लोगों के समक्ष व्यर्थ ही सिद्ध होती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के लिए आत्मरक्षण और समाज-सुख-संरक्षण के निमित्त शस्त्र का आराधन भी आवश्यक है। शर्त यह है कि उसकी शस्त्र-सिद्धि पर शास्त्र-ज्ञान का दृढ़ अनुशासन हो। भगवान परशुराम इसी शस्त्र-शास्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं। सहस्रार्जुन के बाहुबल पर उनकी विजय उनकी शस्त्र-सिद्धि को प्रमाणित करती है तो राज्य भोग के प्रति उनकी निस्पृहता उनके समुन्नत शास्त्र ज्ञान का सबल साक्ष्य देती है। ऐसे समन्वित व्यक्तित्व से ही लोक-रंजन और लोक-रक्षण संभव है।

भगवान परशुराम जन प्रतिनिधि हैं। वे शैव-संस्कृति के समुपासक हैं। शैव-संस्कृति समानता की वर्ण-हीन सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्थापक रही है। उसके सूत्रधार भगवान शिव स्वयं वैराग्य की विभूति से विभूषित हैं। उनके व्यक्तित्व और आचरण में ऐश्वर्य भोग की गन्ध तक नहीं है। प्रायः शक्ति भोगोन्मुखी होती है। शक्ति की उपलब्धि व्यक्ति को विलासी बना देती है और विलास-वृत्ति से वह परपीड़न के पतन-गर्त्त में गिरता है। मानव-विकास के इतिहास में बड़े-बड़े शक्तिमानों के पराभव का यही कारण रहा है। शिव की शक्ति विलासोन्मुखी न होकर त्यागोन्मुखी है, अतः सदा सकारात्मक है और इसीलिए वन्दनीय भी है। यद्यपि शिव के आराधकों में असुर (रावण आदि) शक्ति अर्जन से पूर्व और पश्चात-निरन्तर भोग-विलास में प्रवृत्त रहे हैं और पराभव को प्राप्त हुए हैं तथापि परशुराम द्वारा संरक्षित और परिवर्द्धित शैव-संस्कृति भोग-विलास से दूर लोक-हित के लिए सर्वस्व समर्पण में ही व्यस्त रही है। आज जब सत्ता और शक्ति से जुड़ा वर्ग असुरों की परम्परा के अनुगमन में भोग की पंकिल-भूमि पर सुख तलाश करने में सारी ऊर्जा का क्षरण करता हुआ स्वयं और समाज-दोनों के लिए भस्मासुर सिद्ध हो रहा है, तब लोक-रक्षक परशुराम का चरित्र और आदर्श अनुकरणीय है। उसका स्पष्ट संदेश है कि यदि अर्जित शक्ति का उपयोग शिवत्व की प्रतिष्ठा में करना है तो शक्तिधर को शिव के समान त्यागपूर्ण आचरण करना ही होगा। शिवत्व की साधना के लिए अपेक्षित चिन्तन प्रकृति के एकान्त में ही संभव है, प्रासादों के ऐश्वर्य में नहीं। भगवान परशुराम इसीलिए लोकरक्षा का व्रत लेकर तप-त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, वैभव और ऐश्वर्य से सतत् निर्लिप्त रहते हैं।

डॉ. कृष्णगोपाल मिश्र

शक्तिधर परशुराम का चरित्र जहाँ शक्ति के केन्द्र सत्ताधीशों को त्यागपूर्ण आचरण की शिक्षा देता है, वहाँ वह शोषित पीड़ित क्षुब्ध जनमानस को भी उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अहसास दिलाता है। शासकीय दमन के विरूद्ध वह क्रान्ति का शंखनाद है। वह सर्वहारा वर्ग के लिए अपने न्यायोचित अधिकार प्राप्त करने की मूर्तिमंत प्रेरणा है। वह राजशक्ति पर लोकशक्ति का विजयघोष है। आज स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सैकड़ों-सहस्रों सहस्रबाहु देश के कोने-कोने में विविध स्तरों पर सक्रिय हैं, कहीं न्याय का आडम्बर करते हुए नेतृत्व के छद्म में भोली जनता को छल रहे हैं, उसका श्रम हड़पकर अबाध विलास में ही राजपद की सार्थकता मान रहे हैं तो कहीं अपराधी माफिया गिरोह खुले आम आतंक फैला रहे हैं, तब असुरक्षित जन-सामान्य की रक्षा के लिए आत्म-स्फुरित ऊर्जस्वित व्यक्तियों के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। इसकी आदर्श पूर्ति के निमित्त परशुराम जैसे प्रखर व्यक्तित्व विश्व इतिहास में विरल ही हैं। इस प्रकार परशुराम का चरित्र शासक और शासित-दोनों स्तरों पर प्रासंगिक है।

शस्त्रशक्ति का विरोध करते हुए अहिंसा का ढोल चाहे कितना ही क्यों न पीटा जाये, उसकी आवाज सदा ढोल के पोलेपन के समान खोखली और सारहीन ही सिद्ध हुई है। उसमें ठोस यथार्थ की सारगर्भिता कभी नहीं आ सकी। सत्य हिंसा और अहिंसा के संतुलन बिंदु पर ही केन्द्रित है। कोरी अहिंसा और विवेकहीन पाश्विक हिंसा-दोनों ही मानवता के लिए समान रूप से घातक हैं। आज जब हमारे राष्ट्र की सीमायें असुरक्षित हैं। कभी कारगिल, कभी कश्मीर, कभी बंग्लादेश और कभी देश के अन्दर नक्सलवादी शक्तियों के कारण हमारी अस्मिता का चीरहरण हो रहा है तब परशुराम जैसे वीर और विवेकशील व्यक्तित्व के नेतृत्व की आवश्यकता है।

गत शताब्दी में कोरी अहिंसा की उपासना करने वाले हमारे नेतृत्व के प्रभाव से हम समय पर सही कदम उठाने में हिचकते रहे हैं। यदि सही और सार्थक प्रयत्न किया जाये तो देश के अन्दर से ही प्रश्न खड़े होने लगते हैं। परिणाम यह है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों और व्यवस्थापकों की धमनियों का लहू इतना सर्द हो गया है कि देश की जवानी को व्यर्थ में ही कटवाकर भी वे आत्मतोष और आत्मश्लाघा का ही अनुभव करते हैं। अपने नौनिहालों की कुर्वानी पर वे गर्व अनुभव करते हैं, उनकी वीरता के गीत गाते हैं किन्तु उनके हत्यारों से बदला लेने के लिए उनका खून नहीं खौलता।

प्रतिशोध की ज्वाला अपनी चमक खो बैठी है। शौर्य के अंगार तथाकथित संयम की राख से ढँके हैं। शत्रु-शक्तियाँ सफलता के उन्माद में सहस्रबाहु की तरह उन्मादित हैं लेकिन परशुराम अनुशासन और संयम के बोझ तले मौन हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने सन् 1962 ई. में चीनी आक्रमण के समय देश को 'परशुराम की प्रतीक्षा' शीर्षक से ओजस्वी काव्यकृति देकर सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दी थी। युगचारण ने अपने दायित्व का सही-सही निर्वाह किया, किन्तु राजसत्ता की कुटिल और अंधी स्वार्थपूर्ण लालसा ने हमारे तत्कालीन नेतृत्व के बहरे कानों में उसकी पुकार ही नहीं आने दी। पाँच दशक बीत गये। इस बीच एक ओर साहित्य में परशुराम के प्रतीकार्थ को लेकर समये पर प्रेरणाप्रद रचनायें प्रकाश में आती रहीं और दूसरी ओर सहस्त्रबाहु की तरह विलासिता में डूबा हमारा नेतृत्व राष्ट्र-विरोधी षडयन्त्रों को देश के भीतर और बाहर--दोनों ओर पनपने का अवसर देता रहा। परशुराम पर केन्द्रित साहित्यिक रचनाओं के संदेश को व्यावहारिक स्तर पर स्वीकार करके हम साधारण जनजीवन और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा कर सकते हैं।

महापुरुष किसी एक देश, एक युग, एक जाति या एक धर्म के नहीं होते। वे तो सम्पूर्ण मानवता की, समस्त विश्व की, समूचे राष्ट्र की विभूति होते हैं। उन्हें किसी भी सीमा में बाँधना ठीक नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे स्वातंत्र्योत्तर युग में महापुरूषों को स्थान, धर्म और जाति की बेड़ियों में जकड़ा गया है। विशेष महापुरूष विशेष वर्ग के द्वारा ही सत्कृत हो रहे हैं। एक समाज विशेष ही विशिष्ट व्यक्तित्व की जयंती मनाता है, अन्य जन उसमें रूचि नहीं दर्शाते, ऐसा प्रायः देखा जा रहा है।

यह स्थिति दुभाग्यपूर्ण है। महापुरूष चाहे किसी भी देश, जाति, वर्ग, धर्म आदि से संबंधित हो, वह सबके लिए समान रूप से पूज्य है, अनुकरणीय है। इस संदर्भ में भगवान परशुराम जो उपर्युक्त बिडंबनापूर्ण स्थिति के चलते केवल ब्राह्मण वर्ग तक सीमित हो गए हैं, समस्त शोषित वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत क्रान्तिदूत के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य हैं और सभी शक्तिधरों के लिए संयम के अनुकरणीय आदर्श हैं।

दो सीटों से चुनाव लोकतंत्र का मखौल या अधिकार

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के केरल के वायनाड के साथ यूपी के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा से देश की सियासत अचानक ही गरमा उठी है। वे अपनी परंपरागत अमेठी सीट छोड़कर केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे है। वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह सीट गाँधी परिवार की पुश्तैनी सीट है। सोनिया गाँधी के राज्य सभा में निर्वाचित होने के बाद रायबरेली सीट पर उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा थी मगर उनके इंकार करने पर भाई को मैदान में उतारा गया है। बताया जाता है वायनाड संसदीय सीट अमेठी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होने के कारण उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ना पसंद किया था। हालाँकि साम्यवादी पार्टियों ने राहुल गाँधी के केरल से चुनाव लड़ने की निंदा की है और कहा है राहुल का यह फैसला जनविरोधी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहते हुए गुजरात की वडोदरा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था। दो जगहों से चुनाव लड़ने के पीछे राजनीतिक पार्टियों का यह तर्क होता है कि इससे पार्टी को संबंधित प्रदेश में मजबूती मिलती है। वर्तमान में भारत चुनाव आयोगकिसी भी प्रत्याशी को दो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। आयोग के नियमों का फायदा उठाकर विभिन्न दलों के नेता एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ते है और दोनों सीटों से जीतने के बाद एक सीट से इस्तीफा देते है फिर चुनाव आयोग द्वारा वहां दुबारा चुनाव कराया जाता है। इस भांति चुनाव आयोग को अनावश्यक व्यय का सामना

करना पड़ता है। आजादी के बाद एक से अधिक सीटों पर लड़ने का रिवाज चल रहा है। जन प्रतिननिधित्व कानून, 1951 में संशोधन कर 1996 में यह नियम बनाया गया कि उम्मीदवार अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।

इससे पहले उम्मीदवार कितनी भी सीट से चुनाव लड़ सकते थे। 2004 में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के एक से अधिक सीटों पर चुनाव लडने पर प्रतिबंध या उम्मीदवार द्वारा कोई जीती हुई सीट छोडने पर उसके बाद होने वाले उपचुनाव का खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।

बाल मुकुन्द ओझा

भारतीय राजनीति में एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की परंपरा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 में दूसरे आम चुनाव से की थी। वह उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। उस चुनाव में वे एक साथ उत्तर प्रदेश के तीन निर्वाचन क्षेत्रों- मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ से खड़े हुए थे। बलरामपुर में वे जीत गए थे, जबकि मथुरा और लखनऊ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मथुरा में तो उनकी जमानत भी नहीं बच पाई। एक बार इंदिरा गांधी भी 1980 में अपनी पारंपरिक रायबरेली सीट के अलावा आंध्रप्रदेश की मेडक सीट से भी चुनाव लड़ी थीं। वे दोनों जगह से जीती थीं और बाद में उन्होंने मेडक सीट से इस्तीफा दे दिया था।

1996 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने भी दो जगहों- आंध्रप्रदेश की नांद्याल और ओडिशा की बेरहामपुर सीट से चुनाव लड़ा था। दोनों जगह से जीतने पर उन्होंने नांद्याल सीट खाली कर दी थी, जिस पर उपचुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के आकांक्षी रहे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी 1998 के मध्यावधि चुनाव में दो क्षेत्रों- संभल और कन्नौज से खड़े हुए थे। दोनों ही जगह वे विजयी रहे थे और बाद में उन्होंने कन्नौज सीट खाली कर वहां से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया था। इसके अलावा भी अन्य कई नेता हुए हैं जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है।

इसके अलावा भी अन्य कई नेता हुए हैं जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है।

यह उल्लेखनीय है कई पार्टियों के नेता एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ते हैं और बाद में एक सीट को छोड़ देते हैं। जिस पर फिर से चुनाव होता है। माना जाता है कि ऐसा करन से वक्त तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही संसाधन और पैसा भी खर्च होता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अहंकार त्याग ही गुरु दक्षिणा

मंथन

सात्विकता का भाव रोम-रोम में समाहित करते स्वतः योग्य गुरु से मिलन हो जाता है। सांसारिक लोभ में मन डूबा रहता है तो नकली गुरु से ही संबंध बन पाता है। बहुतेरे लोग गुरु के वेश में छल-छद्म करने वालों का उल्लेख करते देखे जाते हैं। धर्मग्रंथों में एकलव्य, राजा बलि तथा विंध्यपर्वत आदि का जिक्र आता है। गुरु द्रोणाचार्य राजघराने के गुरु थे, इसलिए उन्होंने धनुर्विद्या के लिए एकलव्य का गुरु बनने से इन्कार कर दिया। एकलव्य का संबंध भले राजघराने से नहीं था, लेकिन उनका मन सात्विक प्रवृत्तियों से सराबोर था। उन्हें धनुर्विद्या की वही चाहत थी, जो अर्जुन की थी। ऐसी स्थिति में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। वह अर्जुन से आगे निकलते दिखे। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा कटवा कर ले लिया। जरा इसके निहितार्थ को समझें। अंगूठा एक तरह से अहंकार का प्रतीक है। अर्जुन को उत्तम धनुर्विद्या के ज्ञान के बावजूद यदि अहंकार रहा होता तो महाभारत के महायुद्ध में श्रीकृष्ण को अपना विराट रूप न दिखाना पड़ता। अर्जुन युद्ध में हतोत्साहित थे। हतोत्साहित मन से कोई निशाना नहीं लगाया जा सकता या लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को खुद कहना पड़ा कि मैंने अज्ञानता में यदि कुछ कह दिया हो तो उसे क्षमा करिए, केशव। गुरु के चरणों का महत्व राजा बलि को भी जब समझ में आया तो उन्हें लगा कि सात्विकता के चरण-स्पर्श के बिना मन में विनम्रता नहीं आ सकती। वामन बने नारायण के चरण-स्पर्श से राजा बलि का अहंकार पाताल लोक में चला गया। ऐसी ही कथा विंध्यपर्वत की है। अहंकार के चलते ज्ञान के सूर्य की गति जब बाधित हुई तो गुरु अगस्त्य के चरण-स्पर्श से यह पर्वत वंदनीय बन गया। इन कथाओं का आशय ही है कि सुपात्र बनते ही योग्य गुरु की कृपा खुद ही चलकर आ जाती है। **-साकेत पांडेय**

सर्वसिद्ध मुहूर्त का पर्व है अक्षय तृतीया

हिन्दू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 'अक्षय तृतीया' पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 मई को मनाया जा रहा है। हिन्दू धर्म में प्रत्येक शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए अक्षय तृतीया पर्व को बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर इस वर्ष पांच दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तृतीया तिथि का आरंभ 10 मई की सुबह 10 बजकर 17 मिनट से होगा, जो 11 मई को रात्रि 2 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है और इस दिन सुकर्मा योग भी रहेगा। इस योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है और यह योग 10 मई को दोपहर 12 बजकर 7 मिनट से अगले दिन 10 बजे तक बना रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा, जिसके स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र ग्रह हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करना शुभ फलदायक रह सकता है। इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, ज्योतिष में इस नक्षत्र को शुभ माना गया है। तैतिल और गर करण का निर्माण भी इसी दिन होगा। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को इस वर्ष बेहद खास माना जा रहा है। अक्षय तृतीया तिथि सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली और समस्त सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इस दिन हवन, जप, दान, स्वाध्याय, तर्पण इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग इसी तिथि को समाप्त हुआ था जबकि त्रेता, सतयुग और कलियुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहा जाता है। भारत में कई स्थानों पर अक्षय तृतीया को 'आखा तीज' के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का उल्लेख मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु धर्म सूत्र इत्यादि में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती मानी गई हैं और इस दिन मां लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती तथा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा बरसती है, समृद्धि आती है, जीवन धन-धन्य से भरपूर होता है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। हिन्दू धर्म में मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन बेहद शुभ माना गया है। जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, वैसाख के समान कोई मास नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध योग होते हैं और इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए कोई भी शुभ कार्य सम्पन्न किया जा सकता है।

योगेश कुमार गोयल

इंद्रधनुष

फिटनेस मंत्रा

इमली के पत्तों में हैं बेमिसाल गुण

इमली का पेड़ या दरख्त बेहद सख्त होता है लेकिन इसकी पत्तियां मुलायम। इमली के फायदे तो आप जानते ही होंगे लेकिन इमली के पत्तों में भी बेमिसाल गुण होता है। इमली की पत्तियां सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इससे स्किन संबंधी कई तरह की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं इमली की पत्तियों में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण भी होता है जिसके कारण यह कई तरह के घाव को खत्म कर सकती है। इमली की पत्तियां खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी हैं।

एनसीबीआई के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक इमली के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होता है। इमली के पत्ते में 30 से 70 प्रतिशत तक इथेनॉल होता है, इसलिए इससे शुद्ध एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है। इमली के पत्ते में बेसीलस सब्टिलिस, इंटेरोकॉकस फेकेलिस, स्टेफायलोकॉकस ऑरेस, इश्चेरिया कोलाई जैसे घातक बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है। यानी इमली के पत्तों से दाद-खाज-खुजली की समस्याओं का अंत किया जा सकता है। इमली के पत्ते से डायरिया जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इमली में फ्लेवेनोएड कंपाउड भी होता है जो स्किन के लिए वरदान से कम नहीं है। इमली का तेल लगाने से सौंदर्य में निखार आ सकता है। इमली के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होता है, इसलिए यह बालों को झड़ने या गिरने से रोक सकता है। इसका तेल लगाने से बालों को समय से पहले गिरने से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो इमली के पत्तियों में ऐसा गुण होता है जिसके कारण बालों को पतला होने से रोका जा सकता है। इमली के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या भी रुक जाएगी। इमली के पत्ते में नेचुरल कलरिंग एजेंट होता है जो पिग्मेंट को जल्दी सूखने नहीं देता है। इससे बाल सफेद नहीं होते।

ट्रैंड में

मारुति सुजुकी ने लाँच की नई स्विफ्ट

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को चौथी पीढ़ी की प्रीमियम हैचबैक नई स्विफ्ट लॉन्च की, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.64 लाख रुपये तक है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी टेकुची ने इसे यहां आयोजित एक कार्यक्रम में लाँच करते हुये कहा, 'बिल्कुल नया जेड-सीरीज़ इंजन एक भविष्यवादी पावरट्रेन है

जो प्रदर्शन और स्थिरता का एक नया आयाम लाता है, जो इसे सबसे कुशल हैचबैक बनाता है। इस कार के नये इंजन सहित पूरे विकास पर 1400 करोड़ रुपये की लागत आऋ है। हम अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उन्नत तकनीकों को पेश करके भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव लाना जारी रखेंगे।' कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) पार्थो बनर्जी ने कहा, 'एपिक न्यू स्विफ्ट की शुरुआत के साथ, हम समृद्ध विरासत का निर्माण कर रहे हैं और बेंचमार्क बढ़ा रहे हैं। क्रांतिकारी जेड-सीरीज़ इंजन उच्च ईंधन-दक्षता और कम उत्सर्जन के साथ प्रदर्शन को जोड़कर दोनों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसमें 6 एयरबैग, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ईएसपी, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट जैसी कई सुरक्षा सुविधाओं से लैस, एपिक न्यू स्विफ्ट लगातार बेहतर सुरक्षा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। फीचर से भरपूर केबिन के अलावा, ये एपिक न्यू स्विफ्ट को अपने सेगमेंट में सबसे आकर्षक ड्राइवर-उन्मुख उत्पाद बनाते हैं। कुल मिलाकर 50 नये फीचर दिए गए हैं।'

प्रेरक प्रसंग

न हो प्रतिभा का अहंकार

ऋषि अंगिरा का एक प्रतिभाशाली शिष्य था उदयन। वैसे तो उदयन सर्वगुण संपन्न था लेकिन उसमें एक खामी थी। उसको अपनी श्रेष्ठता का दंभ हो चला था और उसमें अपनी प्रतिभा के स्वतंत्र प्रदर्शन की उमंग रहती थी। वह यदा-कदा अपने साथी-सहयोगियों से अलग-अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया करता था। उसकी इस आदत को देखकर ऋषि अंगिरा ने सोचा कि उनके प्रिय शिष्य की यह वृत्ति उसे ले डूबेगी और समय रहते इसमें सुधार करना जरूरी है। उस समय सर्दी का मौसम था। ऋषि अंगिरा अपने शिष्यों के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे और उनके बीच रखी एक अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। अचानक ऋषि अपने शिष्यों से बोले, 'दहकती हुई अंगीठी से हमें गर्मी मिल रही है। इसका श्रेय इसमें दहक रहे कोयलों को है न?' उनकी बात सुनकर सभी शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद ऋषि पुनः बोले, 'देखो, इस अंगीठी में दहक रहा अमुक कोयला सबसे बड़ा और सबसे अधिक दहक रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि इसे निकालकर मेरे पास रख दो। मैं इसकी ऊष्मा का लाभ निकट से लेना चाहता हूं।' शिष्यों ने चिमटे से पकड़कर वह बड़ा दहकता अंगार उठाया और ऋषि के समीप रख दिया। सत्संग की चर्चा पुनः चल पड़ी। पर यह क्या, जो अंगार अंगीठी में बेहद तीव्रता के साथ दहक रहा था, वह जल्द ही मुरझाने लगा। उस पर राख की परत आ गई और थोड़ी ही देर में वह काला कोयला भर रह गया। ऋषि ने वह कोयला शिष्यों को दिखाते हुए कहा, 'तुम सब चाहे जितने तेजस्वी हो, पर अपने जीवन में इस कोयले जैसी भूल कभी मत कर बैठना। यह कोयला यदि अंगीठी में रहता तो अन्य कोयलों की तपिश के साथ अंत तक दहकता रहता और सबसे बाद तक गर्मी देता। पर अकेले यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अब न तो इसका श्रेय रहा और न ही इसकी प्रतिभा का लाभ हम उठा सके।' यह सुनने के बाद उदयन समेत बाकी शिष्यों को भी समझ में आ गया कि ऋषि-परंपरा वह अंगीठी है, जिसमें प्रतिभाएं संयुक्त रूप से सार्थक होती हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा का अहंकार न तो ज्यादा देर टिकता है और न ही फलित होता है।

हंसगुल्ले

- पत्नी, 'मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या?'

पति, 'नहीं फैंक दे, क्या दान करना...।'

पत्नी, 'नहीं जी, दुनिया में बहुत-सी गरीब और भूखी-प्यासी औरतें हैं, किसी के काम आ जाएंगे...।'

पति, 'तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखी-प्यासी होगी?'

- रिश्तेदार, 'बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे...?'

पप्पू, 'कुछ भी करूंगा, मगर किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा।'

उत्तम हिन्दू में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक लेख और अन्य साहित्य सामग्री प्रकाशित करवाने के इच्छुक लोग कृपया इस मेल आईडी lekhuttamhindu@gmail.com पर अपनी प्रकाशन सामग्री भेजें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

भारत के रिकॉर्ड निर्यात परिदृश्य पर नई चुनौतियां

यह कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले दो वर्षों से रूस-यूक्रेन युद्ध और भू-राजनीतिक चुनौतियों के कारण लाल सागर व्यवधान, पनामा रूट पर आवागमन मुश्किलों, घटते हुए वैश्विक व्यापार और घटते हुए वैश्विक निर्यात के बीच भारत से लगातार रिकॉर्ड निर्यात हुए हैं. लेकिन अब भीषण होते हुए इजराइल-ईरान टकराव से गहराती हुई नई वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच भारत को निर्यात बढ़ाने व आयात घटाने की विशेष रणनीति के साथ आगे आना होगा. खासतौर से हाल ही में 28 अप्रैल को प्रकाशित आर्थिक टैंक ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वस्तु आयात में चीन की जो हिस्सेदारी बढ़कर 30 फीसदी के चिंताजनक स्तर पर पहुंचते हुए 101 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गई है, उसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों से नियंत्रित करना होगा.

गौरतलब है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डॉलर रहा था. ऐसे में गत वित्त वर्ष में सेवा निर्यात 3.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 339.62 अरब डॉलर का रहा, जबकि वस्तु निर्यात 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437.06 अरब डॉलर रहा. जहां पिछले वर्ष में कुल आयात 854.80 अरब डॉलर का रहा, वहीं वर्ष 22-23 में कुल आयात 898 अरब डॉलर मूल्य का रहा था. ऐसे में पिछले वर्ष आयात में कमी से कुल व्यापार घाटे में 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. पिछले वर्ष में आयात में गिरावट की बड़ी वजह तेल का कम आयात था. कच्चे तेल की कीमतें कम रहने से बीते वर्ष में तेल के आयात पर करीब 16 फीसदी कम खर्च हुआ. निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षों में भारत के निर्यात का एक चमकदार पहलू सेवा निर्यात है. भारत डिजिटल माध्यम से मुहैया कराई गई सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है.

डिजिटल माध्यम से सेवा निर्यात के तहत कम्प्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं. भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की तेजी से नई स्थापनाओं के कारण भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है. इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि युद्ध जनित आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने हेतु मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की अहमियत और बढ़ गई है. भारत ने अब तक तीन एफटीए किए हैं. भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मई 2022 में लागू द्विपक्षीय कारोबार में पिछले दो वर्षों में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुए एफटीए से भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है.

निश्चित रूप से जिस तरह से ईरान-इजराइल के बीच टकराव और दुनिया में भू राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उससे कच्चे तेल के दाम के साथ-साथ आपूर्ति संकट बढ़ने की चिंताएं मुंह बाए खड़ी हैं. इससे भारत के वैश्विक व्यापार व निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में भारत को निर्यात बढ़ाने व चीन से आयात घटाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा. देश में उच्च ब्याज दरों और मांग में कमी के कारण निर्यात के मोर्चे पर जूझ रहे छोटे निर्यातकों को कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराने व बैंक को इसके बदले सरकार से मुआवजा दिए जाने के लिए लागू की गई इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम (आईईएस) की जो अवधि 30 जून 2024 को समाप्त हो रही है, उसे एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जाना लाभप्रद होगा. जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लम्बे समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूरदराज के देशों की बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा. यद्यपि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है.

ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करना होंगे. भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. चूंकि भारत को निर्यात बढ़ाने में एफटीए से बढ़ी मदद मिली है, ऐसे में भारत के द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ना होगा. निश्चित रूप से ऐसे रणनीतिक प्रयासों से नई वैश्विक व्यापार और निर्यात चुनौतियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से भारत के बढ़ते हुए निर्यात को बहुत कुछ बचाया जा सकेगा.

और कितने सेल्फ गोल मारोगे

कल जब एक चुनावी रैली में इस विघटनकारी वक्तव्य का मोदी ने झन्नाटेदार देशभक्ति से ओतप्रोत जवाब दिया तो पूरी कांग्रेस के होश उड़ गए और तुरत फुरत सभी रायता समेटने में लग गये। पहले कहा अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन पित्रोदा के इस वक्तव्य से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है यह उनका व्यक्तिगत विचार है, समझ में नहीं आता सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक मंच से कही गई कोई बात कैसे सुविधानुसार व्यक्तिगत हो जाती है।

राकेश शर्मा

एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, इंडी गठबंधन के नेता बारंबार सेल्फ गोल मारेंगे तो मोदी को 2024 के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मैच का विजेता बनने से कौन रोक सकता है। आप रायता फैलाते रहो, और फिर उसे समेटते रहो और आपके सामने जो ऑलराउंडर कप्तान खड़ा है वो हर गूगली, बाउंसर और फुलटॉस को मैदान के बाहर भेजने का एक्सपर्ट है। चुनावी महासमर के मध्य में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कोई अल्प बुद्धि, मंदबुद्धि बालक भी नहीं कर सकता और यह सत्तालोलुप खंडित, विखंडित इंडी गठबंधन के नेता अपने सामने मोदी जैसे एक सशक्त लोकप्रिय नेता को देखकर अर्धविक्षिप्त जैसी बातें कर रहे है जिसमें सत्ता प्राप्त करने के लिए विघटनकारी बू आ रही है।

अब कल का सतनरायण गंगाराम पित्रोदा जो अपने को अंग्रेज जैसा दिखने के लिए सेम पित्रोदा के नाम से ही प्रचलित कर रखा हैं, राजीव गांधी के सलाहकार रह चुके हैं और वर्तमान में शहजादे के राजनैतिक गुरु हैं ने भारत राष्ट्र की अस्मिता पर हमला करते हुए देश को नैन नक्श और चमड़ी के रंग से ही बांटने का कुत्सित प्रयास कर दिया।

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि इंडिया में उत्तर पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण में अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, पश्चिम में अरब जैसे और उत्तर में गोरे होते हैं। इतनी अक्ल तो सबमें है की हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है जहां विभिन्न नैन नक़्श, चमड़ी के रंग, भाषा और भौगोलिक परिस्थिति में भारतीय रहते हैं। उन्हें आप किसी भी रूप में बाँट नहीं सकते क्यूंकि इन सबमें भारत माँ की आत्मा बसती है, भारत के संस्कार और मूल्य बस्ते हैं, इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हम सब एक हैं। कल जब एक चुनावी रैली में इस विघटनकारी वक्तव्य का मोदी ने झन्नाटेदार देशभक्ति से ओतप्रोत जवाब दिया तो पूरी कांग्रेस के होश उड़ गए और तुरत फुरत सभी रायता समेटने में लग गये। पहले कहा अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन पित्रोदा के इस वक्तव्य से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है यह उनका व्यक्तिगत विचार है, समझ में नहीं आता सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक मंच से कही गई कोई बात कैसे सुविधानुसार व्यक्तिगत हो जाती है।

हैरानी तब हुई जब कांग्रेस ने शहजादे के गुरु पर कोई एक्शन नहीं लिया क्यूंकि वो कांग्रेस में सर्वशक्तिमान व्यक्ति के गुरु हैं और गुरु शिष्य परंपरा तो निभानी ही पड़ती है (गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः), इस वक्तव्य पर ना तो शिष्य ने, ना ही उनकी सहोदरी ने और ना ही नाममात्र के अध्यक्ष ने ही निंदा करते हुए कोई वक्तव्य दिया और ना ही पार्टी से निष्कासित किया। हां एक दिखावा जरूर किया जब सतनारायण गंगाराम पित्रोदा ने कांग्रेस को चुनावी समर में पूरी तरह डुबोकर स्वतः अपने पद से इस्तीफा देने की नौटंकी की। ध्यान रहे कांग्रेस ने इस धुर भारत विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया है। यह वही व्यक्ति है जो वही बयान देते हैं जो इनका शिष्य चाहता है या जो कहना चाहते है वह शिष्य से कहलवा देते हैं। ध्यान रहे जब चुनाव घोषणा पत्र में राहुल की कांग्रेस ने जातीय आधार पर जनगणना कर किसी बड़े एक्शन की बात कही तो इसी पित्रोदा ने तब यह कह कर की मृत्यु के बाद अमेरिका में पचपन प्रतिशत संपत्ति पर सरकारी अधिकार होने का जुमला उछाल कर चुनावी भूकंप ला दिया और लोगों में संशय पैदा हो गया की शिष्य गुरु की बात मानकर भारत में यह लागू ना करवा दे। भारत एक राष्ट्र नहीं राज्यों का समूह है वह भी इसी पित्रोदा द्वारा आयोजित एक समारोह में राहुल ने कहा था।

कितना विभाजनकारी वक्तव्य था। अभी इस अनर्गल झंझट से निपट ही रहे थे की लालू ने सात मई की सुबह चुनाव प्रारंभ होने से पहले यह कहकर की मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिम वोट पाने के लिए चुनाव का आख्यान ही बदल दिया और जब शाम को चुनाव संपन्न हो गया तब एक शातिर झूठे की तरह सुबह के बयान से शाम को पलटते हुए कह दिया आरक्षण का आधार सामाजिक होना चाहिए, यह वही लालू हैं जिन्होंने मोदी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो पूरे देश ने एक साथ कहा 'मैं हूँ मोदी का परिवार'।

इनकी बेटी मीसा ने तो यह कहकर हद ही कर दी की मोदी को फांसी देनी चाहिए। उधर अखिलेश के चाचा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने तो सनातन पर एक और चोट करते हुए कह दिया अयोध्या में बना राम मंदिर बेकार है, इसका नक्शा खराब है। क्या इन प्रोफेसर को यह नहीं मालूम कि अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा है। उन सभी भक्तों की भावना कितनी आहत कर दी वो भी एक वर्ग का वोट पाने के लिए। यह इंडी गठबंधन के नेता सनातन को डेंगू, मलेरिया, एचआईवी, करोना कहकर, सनातन समाप्त करने की बात कर, या भारत के राज्यों को चमड़ी के रंग से, नैन नक्श से, जातियों में बांटकर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश में सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिरने वाले नेताओं को राष्ट्र प्रेमी जनता को झेलना पड़ रहा है।

(लेखक आज समाज के कार्यकारी निदेशक हैं।)

"आध्यात्मिक एवं क्षत्रिय शक्ति से परिपूर्ण धुरंधर योद्धा भगवान परशुराम"

भगवान शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु उनके हाथ में सर्वथा रहने के कारण ये परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि ऋचीक के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। परशुराम जी की दक्षता, योग्यता तथा पराक्रम से प्रसन्न होकर महर्षि ऋचीक ने इन्हें सारंग धनुष उपहार में दिया। भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे। शंकर की कठोर तपस्या एवं आराधना के माध्यम से परशुराम जी ने अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की।ये सैन्य विद्या के धुरंधर विद्वान प्रथम पराक्रमी ब्राह्मण थे।

आचार्य दीप चन्द भारद्वाज

भारतवर्ष आध्यात्मिक संपत्ति एवं क्षात्र बल से परिपूर्ण महापुरुषों की पावन धरा है। ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति में पारंगत भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। जिनका संबंध त्रेता युग से है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। संपूर्ण भारत वर्ष में इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका जी थी। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण आदि अनेक ग्रंथों में परशुराम जी का उल्लेख प्राप्त होता है।

पौराणिक साहित्य में सतयुग तथा त्रेतायुग का संधिकाल परशुराम जी का समय माना जाता है। परशुराम भारत की स्वर्णिम ऋषि परंपरा के महान संवाहक हैं। शस्त्र तथा शास्त्र दोनों विद्याओं पर इनका समान अधिकार था। इनके पितामह ऋषि भृगु ने इनका नाम अनंतर राम रखा। भगवान शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु उनके हाथ में सर्वथा रहने के कारण ये परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि ऋचीक के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। परशुराम जी की दक्षता, योग्यता तथा पराक्रम से प्रसन्न होकर महर्षि ऋचीक ने इन्हें सारंग धनुष उपहार में दिया।

भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे। शंकर की कठोर तपस्या एवं आराधना के माध्यम से परशुराम जी ने अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की।ये सैन्य विद्या के धुरंधर विद्वान प्रथम पराक्रमी ब्राह्मण थे। इनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में अवश्य हुआ लेकिन कर्म से परशुराम जी महान क्षत्रिय योद्धा थे। भगवान परशुराम श्री कृष्ण एवं श्री राम दोनों के समय में थे। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने ही प्रदान किया था। सीता स्वयंवर में श्रीराम का अभिनंदन स्वयं इन्ही के द्वारा किया गया था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण भी भगवान परशुराम के शिष्य समान थे। परशुराम जी का समय राजनीतिक उथल-पुथल, अन्याय, अत्याचार से परिपूर्ण था। हैहय वंश के निरंकुश, अहंकारी क्षत्रिय राजा ने पृथ्वी पर नरसंहार का तांडव दृश्य उपस्थित कर दिया था। इस वंश के दमनकारी, निर्दयी राजा सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाया। सैकड़ों प्रकार के सैन्य बल से युक्त इस सहस्त्रार्जुन की अकेले अपने फरसे से परशुराम ने धज्जियां उड़ा दी। परशुराम जी ने अपने परशु से इस आतताई की भुजाएं काट दी थी। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर-के उन की निर्मम हत्या कर दी थी । हैहय राजाओं के द्वारा पिता वध के इस अमानुषी कृत्य ने परशुराम को विह्वल कर दिया था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि परशुराम जी ने इक्कीस बार हैहय वंश के घमंडी क्षत्रिय राजाओं का संहार करके पृथ्वी को आतंकियों से मुक्त कर दिया था। भगवान परशुराम आर्यवर्त की दैवी संपत्ति से परिपूर्ण ऋषि संस्कृति के प्रबल समर्थक एवं रक्षक थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के अन्यायी एवं पथभ्रष्ट राजाओं का समूल नाश करके सनातन वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने का प्रण लिया था। धर्म की स्थापना हेतु परशुराम जी ने चतुर्दिक विजय अभियान चलाया था। सर्वप्रथम दक्षिण प्रांत के अहंकारी राजा श्वेतकेतु को परास्त कर सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया। परशुराम जी का चिंतन राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा के लिए कल्याणकारी था। उनका मानना था कि जिस देश के राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दयी एवं पैशाची रूप धारण करके, ऋषि मुनियों का निर्मम उत्पीड़न करते हों तथा जहां के नागरिक तथा प्रजा अनीति तथा अत्याचारों से तंग आ चुके हों वहां धर्म तत्व तथा आध्यात्मिक वातावरण की स्थापना के लिए तथा पैशाची विचार संपदा से ग्रस्त दैत्यों के संहार के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अपने आध्यात्मिक एवं क्षत्रिय बल के माध्यम से परशुराम जी ने राष्ट्र, प्रजा तथा ऋषि-मुनियों के आध्यात्मिक स्वाभिमान की रक्षा की।

संपूर्ण ऋषि आश्रमों को उन्होंने राष्ट्र दमनकारी राजाओं के आतंक से मुक्त करके उन्हें आध्यात्मिक साधना स्थली का रूप दिया। परशुराम जी ने अपने क्षत्रिय बल का प्रयोग सदैव ऋषि मुनियों के धर्म की रक्षा एवं प्रजा के कल्याण हेतु किया। वरदान में प्राप्त अजेय, अमोघ परशु के माध्यम से इन्होंने दुर्दांत दैत्यों का संहार किया तथा भारतीय वसुंधरा से अनाचारी, विजातीय, ऋषि मुनियों की साधना में बाधक पैशाची वृत्ति का समूल नाश किया। पाप अत्याचार का प्रतिशोध करना परशुराम की आध्यात्मिक साधना तथा क्षत्रिय बल मुख्य उद्देश्य था। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नेय, गोत्र के कारण भार्गव और ब्राह्मण श्रेष्ठ इन नामों से परशुराम जी प्रसिद्ध हैं।

सर्वसिद्ध मुहूर्त का पर्व है अक्षय तृतीया

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है और इस दिन सुकर्मा योग भी रहेगा। इस योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है और यह योग 10 मई को दोपहर 12 बजकर 7 मिनट से अगले दिन 10 बजे तक बना रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा, जिसके स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र ग्रह हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करना शुभ फलदायक रह सकता है। इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, ज्योतिष में इस नक्षत्र को शुभ माना गया है। तैतिल और गर करण का निर्माण भी इसी दिन होगा। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को इस वर्ष बेहद खास माना जा रहा है।

योगेश कुमार गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

हिन्दू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को 'अक्षय तृतीया' पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 मई को मनाया जा रहा है। हिन्दू धर्म में प्रत्येक शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए अक्षय तृतीया पर्व को बहुत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर इस वर्ष पांच दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तृतीया तिथि का आरंभ 10 मई की सुबह 10 बजकर 17 मिनट से होगा, जो 11 मई को रात्रि 2 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है और इस दिन सुकर्मा योग भी रहेगा। इस योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है और यह योग 10 मई को दोपहर 12 बजकर 7 मिनट से अगले दिन 10 बजे तक बना रहेगा।

इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा, जिसके स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र ग्रह हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करना शुभ फलदायक रह सकता है। इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, ज्योतिष में इस नक्षत्र को शुभ माना गया है। तैतिल और गर करण का निर्माण भी इसी दिन होगा। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को इस वर्ष बेहद खास माना जा रहा है।

अक्षय तृतीया तिथि सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली और समस्त सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इस दिन हवन, जप, दान, स्वाध्याय, तर्पण इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग इसी तिथि को समाप्त हुआ था जबकि त्रेता, सतयुग और कलियुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहा जाता है। भारत में कई स्थानों पर अक्षय तृतीया को 'आखा तीज' के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का उल्लेख मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु धर्म सूत्र इत्यादि में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती मानी गई हैं और इस दिन मां लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है।

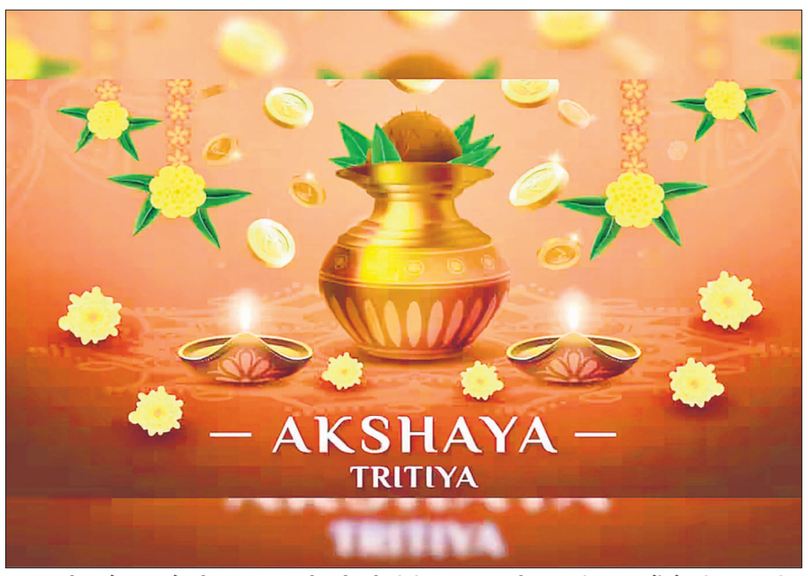

भगवान शिव और मां पार्वती तथा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा बरसती है, समृद्धि आती है, जीवन धन-धन्य से भरपूर होता है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। हिन्दू धर्म में मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन बेहद शुभ माना गया है। जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, वैसाख के समान कोई मास नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध योग होते हैं और इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए कोई भी शुभ कार्य सम्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए लोग बिना पंचांग देखे अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ, घर, भूखंड या नए वाहन आदि की खरीदारी इत्यादि विभिन्न शुभ कार्य करते हैं।

मान्यता है कि इसी तृतीया तिथि को माता पार्वती ने अमोघ फल देने की सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया था, जिसके प्रभाव से अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय इत्यादि करना शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त के साथ इस बार खरीदारी के लिए तीन राजयोग भी बन रहे हैं। मान्यता है कि यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुणा बढ़ जाती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, जिनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था, जिनका जन्म अक्षय तृतीया के ही दिन हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ माना जाता है। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है और भगवान विष्णु के चरणों से गंगा भी इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया को वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी माना जाता है।

इस पर्व को लेकर लोक धारणा है कि इस तिथि को यदि चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फस्ल अच्छी होगी लेकिन यदि रोहिणी पीछे होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। चार धामों में से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट इस पर्व के अवसर पर ही खुलते हैं, जिसके बाद वहां पूजा-अर्चना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन भी वर्ष में एक बार इसी दिन ही किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक चलती हैं और शुभ फल देती हैं। वैसे इस दिन सोना-चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है लेकिन सोना-चांदी खरीदने में असमर्थ हों तो कुछ सस्ती चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जिन्हें खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्राप्त धन-सम्पत्ति एवं पुण्य फल अक्षय रहते हैं और खरीदी गई चीजें मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिलाती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान-पुण्य करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक जाता है और अक्षय तृतीया के दिन उपवास करने वाला व्यक्ति रिद्धि-सिद्धि और श्री से सम्पन्न हो जाता है।

अक्षय तृतीया पर्व के संबंध में मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, उसमें बरकत होती है और वह अक्षय होता है अर्थात इस दिन जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं, उनका फल कभी समाप्त नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति इस दिन बुरे कर्म करता है तो उसके ये कर्म अगले कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। यह भी माना जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता बल्कि जितना दान किया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा अलौकिक कोष में जमा हो जाता है, जो पुनर्जन्म के बाद धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव के रूप में प्राप्त होता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

इंडिया न्यूज
RNI NO: Applied For (RAJHIN28025)
प्रकाशक, मुद्रक एवं कार्यकारी निदेशक **राकेश शर्मा** द्वारा मै. गुड मॉर्निंग इंडिया मीडिया प्रा. लिमिटेड के लिए भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, रेलवे क्रासिंग, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान से मुद्रित कराकर, ए-1, बापूजी मार्ग, ज्योति नगर, लाल कोठी सहकार मार्ग, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित। **संपादक : राणा यशवंत***
*** पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी**

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 10 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

चौथे चरण से पहले भाजपा का नया शिगूफा

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन कर एक रिपोर्ट चुनावों के बीच जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घट गई। वहीं मुसलमानों की आबादी में 43.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश मुस्लिम बहुसंख्यक देश में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदू, ईसाई व अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। इस रिपोर्ट को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि यह भाजपा का चौथे चरण के मतदान से पहले एक नया शिगूफा है। दरअसल पिछले तीन चरणों के मतदान से भाजपा के लिए अच्छी खबरें नहीं आई हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बयानों में अब हिंदू-मुस्लिम पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, प.बंगाल इन तमाम राज्यों में श्री मोदी के भाषणों पर गौर फरमाएं तो उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश साफ नजर आती है। इसलिए इस वक्त आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का आना यह जाहिर करता है कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए मुद्दों का अकाल है, इसलिए अब आभासी मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब उसने अपने पूरे कार्यकाल में जनगणना ही नहीं कराई तो अभी आबादी की बात किस आधार पर कर रही है। और जहां तक मुस्लिम आबादी की बात है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2019-21 में सबसे कम 2.4 रही है, जबकि 2015-16 में 2.6 और 2005-06 में 3.4 थी।

तीन चरणों में भाजपा को नुकसान हो गया है, इसका प्रमाण बुधवार को प्रधानमंत्री के अडानी-अंबानी वाले बयान से मिल गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आखिर में भाजपा को ही मुश्किल में डाल दिया। इस बयान के अगले दिन गुरुवार को शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। जिससे निवेशकों को तीन लाख करोड़ से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, जो शेयर बाजार से अपना पैसा उठा रहे हैं, और क्यों उठा रहे हैं। क्या देश के चुनावी माहौल में भावी सरकार का अनुमान लगाते हुए शेयर बाजार में उठापटक हो रही है, इस पर अब गौर करना होगा।

ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख संपदा थे, अपने हालिया बयानों से उसे गहरे संकट में डाल चुके हैं। '400 पार' के नारे के साथ शुरू हुआ भाजपा का लोकसभा 2024 का चुनावी अभियान मोदी ने ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसे सरकार बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। वैसे तो जिस तरह का विमर्श भाजपा ने पिछले एक दशक से चला रखा था, लोगों का मूड भांपे बगैर श्री मोदी उसे ही आगे बढ़ाते चले गये। हिन्दू-मुस्लिम, विरोधी नेताओं का कथित भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परिवारवाद आदि जैसे घिसे-पिटे नैरेटिव को आगे खींचते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी की बातों में लोगों को अब कोई रस रह गया है। बतौर प्रधानमंत्री दो कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद भी मोदी के पास गिनाने के लिये अपना एक भी काम नहीं है।

इस चुनाव का ऐलान होते तक मोदी अपनी गारंटियों की खूब चर्चा करते रहे। वे दस वर्षों को अपनी सरकार का 'ट्रेलर' बतलाते हुए कहते रहे कि 'असली पिक्चर तो तीसरे कार्यकाल में दिखलाई जायेगी।' उन्होंने अबकी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व 5 ट्रिलियन वाली इकानॉमी बनाने, 2047 तक सबसे विकसित देश बनाने और अगले एक हजार वर्ष तक सबसे आगे रहने जैसे सब्ज़बाग लोगों को दिखलाये। सभी संस्थाएं अपनी मुट्ठी में रखे हुए मोदी की इस 'विकास पुरुष' की छवि को पार्टी का खर्चीला प्रचार तंत्र, उसका आईटी सेल, दरबारी मीडिया और 'ट्रोल आर्मी' आगे बढ़ा रहे थे। राहुल गांधी की दो-दो भारत जोड़ो यात्राओं को मोदी व भाजपा ने हल्के में लिया। उन्होंने इस ओर से आंखें मूंद ली थीं कि कांग्रेस के नेतृत्व में 28 विपक्षी दल एकजुट हो गये हैं। कांग्रेस ने जनसामान्य के बुनियादी सरोकारों पर आधारित विमर्श को पुनर्जीवित किया जिससे जनमत भाजपा की ओर से इंडिया की ओर मुड़ने लगा जो कि प्रतिपक्षी दलों का एक मजबूत गठबन्धन का रूप ले चुका है और इसी शक्ति के साथ चुनाव के तीन चरणों का मतदान पार कर चुका है। तमाम सर्वे, अनुमान एवं विश्लेषण बतला रहे हैं कि तीनों में भाजपा इस कदर पिछड़ रही है कि उसने 400 पार के नारे का उल्लेख करना ही बन्द कर दिया है। हालांकि विपक्ष लोगों को यह नारा भूलने नहीं दे रहा है, पर यह भी बता रहा है कि भाजपा को संविधान समाप्त करने के लिये इतनी सीटें चाहिये। इसके कारण यह लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई में तब्दील हो गई है।

तीन चरणों के मतदान का ही यह असर बतलाया जाता है जिसके कारण शेष चुनाव बचाने के लिये मोदी अपने चिर-परिचित विषय पर लौट आये हैं। वह है ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल के दौरे में वे संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं पर अतिरिक्त द्रवित हुए। हालांकि लोगों ने सवाल उठाया कि मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न व दुष्कर्म पर बोलने से आखिरकार मोदी को किसने रोका था? अपनी सभाओं में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के एक बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए यहां तक कह डाला कि कांग्रेस का मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो हिन्दुओं के गहने छीनकर कई-कई बच्चे वालों को दे दिये जायेंगे (उनका आशय मुस्लिमों से था)। खुद की हिन्दुवादी की छवि को प्रगाढ़ करने के लिये मोदी तीसरे चरण के मतदान के एक दिन पूर्व अयोध्या के राममंदिर पहुंच गये थे। वहां उनकी रामलला के समक्ष साष्टांग होने की तस्वीरें देश भर में प्रकाशित व वायरल कराई गईं ताकि उसका लाभ 7 मई के मतदान में मिल सके।

इतना सब होने के बाद भी कम मतदान और वह भी अपने पक्ष में न होने से आशंकित मोदी ज्यादा बौखलाए नज़र आये। उनके बयान और भी कटु हो चले हैं। इस क्रम में उन्होंने उन अडानी व अंबानी का जिक्र कर डाला (वह भी गलत तरीके से) जिसके अब तक वे सबसे बड़े रक्षक थे। माना जा रहा है कि उनका यह बयान एक तरह से सबसे आत्मघाती साबित होने जा रहा है। इसके जवाब में जैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे श्री मोदी और फंसते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस बयान के जवाब में जो वीडियो जारी किया, उसे करोड़ों लोगों ने देखा और पसंद किया, इसका मतलब यह कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बातों को अब लोग सुन रहे हैं।

यह स्थिति भाजपा के लिए अच्छी नहीं है और अब आबादी का जिक्र छेड़कर भाजपा के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई है, देखना होगा कि चौथे चरण से पहले अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाती है या फिर पूरा चुनाव नकारात्मकता के साथ ही लड़ेगी।

हर चरण के मतदान के साथ बढ़ी है आरएसएस और भाजपा के बीच दरार

■ अरुण श्रीवास्तव

लोकसभा चुनाव में मतदान के हर चरण के बीतने के साथ आरएसएस और पारंपरिक भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पीड़ा और अधिक स्पष्ट होती जा रही है, भले ही आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने उनकी पीड़ा रहने और भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की हो।

जीत का भ्रम पैदा करने के लिए आरएसएस के दिग्गजों द्वारा दिये गये तर्क के विपरीत, उनके कैडर झुकने को तैयार नहीं हैं। वे स्पष्ट हैं कि यदि मोदी जीते तो एक ख़तरनाक निरंकुश शासक बन जायेंगे। हालांकि उन्हें यकीन है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रपति निश्चित रूप से मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। वे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अमित शाह भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में छोटे दलों से समर्थन जुटाने के मिशन पर हैं।

उभरती राजनीतिक स्थिति से आशंकित होकर, राज्य-स्तरीय आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निवारक कदम उठाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इसके महासचिव दत्तात्रे यहोसबोले से संपर्क किया है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को लिखे एक पत्र में यह भी दुख व्यक्त किया है कि यह उनकी निष्क्रियता थी जिसके कारण मोदी भगवा पारिस्थितिकी तंत्र के एकमात्र नेता के रूप में उभरे। राज्य के इन नेताओं ने उन कारणों को भी जानना चाहा है कि जब मोदी संगठनों की संस्कृति और लोकाचार को नष्ट करने के रास्ते पर चल पड़े तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

उन्होंने यह भी बताया है कि अब बदली हुई स्थिति में, बड़ी संख्या में कैडर और स्वयंसेवक चुनाव प्रचार कार्य करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मोदी अपने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग का उपयोग धोखाधड़ी और अवैध रूप से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीईसी द्वारा पहले दो चरणों में डाले गये वोटों के आंकड़ों को सही करना इस परिप्रेक्ष्य में एक अभ्यास है।

तीसरा चरण, जो 7 मई को समाप्त हुआ, पिछले दो चरणों की तुलना में कई मायनों में अलग था। महत्वपूर्ण यह था कि भाजपा शासित राज्यों द्वारा मतदान केंद्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं को भगाने के लिए पुलिस बलों का उपयोग करना। यह राजीव कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग के लोगों से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के आह्वान के ठीक विपरीत हुआ। मतदाताओं को भगाने के लिए पुलिस का क्रूर और आपराधिक उपयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ-शासित उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्पष्ट था।

जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं का अनुपात अधिक है, वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इस तरह की पुलिस-संचालित आपराधिकता का शिकार हो रहे हैं। भगवा पारिस्थितिकी तंत्र और योगी सरकार ने इस भावना को दृढ़ता से पाला कि ये दोनों समुदाय इंडिया ब्लॉक, या किसी अन्य विपक्षी दल को वोट देंगे।

असम में सबसे अधिक 74.86फीसदी मतदान हुआ, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 73.93 फीसदी मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.63फीसदी मतदान हुआ, तथा बिहार में 56.01 प्रतिशत। मोदी जो हाल ही में '400 पार' वाक्यांश का उपयोग करने से परहेज कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर इसे धार (मध्य प्रदेश) की सभा में इस्तेमाल किया।

पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की थी जो विपक्ष, इंडिया ब्लॉक, उम्मीदवारों के पक्ष में थे। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में दोपहर तक मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। कतार में खड़े मतदाताओं को बिना वोट डाले ही वापस जाने को कहा गया। दोपहर तीन बजे के बाद मतदान में तेजी आई। फिर भी चुनाव आयोग के अधिकारियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

पहले के दो चरणों की तरह, वोट डालने के लिए मूल और पारंपरिक भाजपा समर्थकों की अरुचि काफी चिंताजनक थी। दलबदलुओं द्वारा प्रदर्शित उत्साह के विपरीत, भाजपा/आरएसएस के पारंपरिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घर पर रहना पसंद किया।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लंबे समय के बाद, ज्यादातर मामलों में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ समितियों का गठन नहीं किया और यह कार्य भाजपा नेताओं और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर छोड़ दिया। शाम 5 बजे तक 60.19प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 94सीटों पर मतदान हुआ। 2019 में 94सीटों में से कम से कम 86 सीटें भाजपा ने जीती थीं। स्वाभाविक है कि इस चरण में भाजपा को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। विपक्ष और इंडिया गुट के लिए कोई भी लाभ भाजपा, विशेषकर आरएसएस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।

असम में सबसे अधिक 74.86फीसदी मतदान हुआ, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 73.93 फीसदी मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.63फीसदी मतदान हुआ, तथा बिहार में 56.01 प्रतिशत। मोदी जो हाल ही में '400 पार' वाक्यांश का उपयोग करने से परहेज कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर इसे धार (मध्य प्रदेश) की सभा में इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा-'मैं कांग्रेस को अपने वोट बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए ओबीसी कोटा लूटने से रोकने के लिए लोकसभा में 400 सीटें चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों में, हमारे पास एनडीए, क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय सहित लगभग 400 सीटें थीं जिसका हमने इस्तेमाल अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए किया।' इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए किसी योजना पर काम कर रहे हैं।

एक बार फिर भगवा पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय रूप से राहुल गांधी को एक अपरिपक्व राजनेता के रूप में पेश कर रहा है, जो मुद्दे तो उठा सकते हैं लेकिन देश पर शासन नहीं कर सकते। पारिस्थितिकी तंत्र अब राहुल को जमीनी हकीकत से कटे हुए नेता के रूप में चित्रित करने की योजना बना रहा है। केसरिया सूत्रों के अनुसार तो राहुल के खिलाफ नवीनतम दुष्प्रचार अभियान प्रमुख कार्य होने जा रहा है। हालांकि, आरएसएस कार्यकर्ताओं के भूमिगत नेटवर्क के बिना, ऐसा कदम भाजपा के लिए आत्मघाती साबित होगा।

मोदी ने नये निचले स्तर पर उतरते हुए एक नया मुहावरा गढ़ा है- 'वोट जिहाद'। मतदाताओं से 'वोट जिहाद' और 'राम राज्य' के बीच चयन करने का आह्वान करते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की और कहा कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर 'बाबरी ताला' लगायेगी। चुनाव अभियान को लगातार ध्रुवीकृत करने के मोदी के भयावह तरीकों पर चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई नहीं करता।

वोट जिहाद पर उनका स्पष्टीकरण काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'वोट जिहाद का मतलब है कि एक विशेष वर्ग को एकजुट होकर मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा जा रहा है।' सचमुच, यह कांग्रेस या इंडिया नहीं है जो तुष्टिकरण के प्रयास में इतना नीचे गिर गया है; इसके बजाय मोदी स्वयं के अजेय के रूप में पेश करने और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में, कुछ वरिष्ठ भाजपा नेता मोदी के बयानों को चुनाव में धांधली की घिनौनी साजिश मानते हैं। उनका मानना है कि मोदी की टिप्पणियों को हताशा के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आरएसएस और पारंपरिक भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को अपनी आत्मसंतुष्टि छोड़कर पार्टी के समर्थन में आने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है।

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 57 फीसदी के खराब मतदान से मोदी गंभीर रूप से घबड़ा गये हैं। महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा क्षेत्रों में से 11 में 54.09 प्रतिशत मतदान हुआ। पहले दो चरणों में 62प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था।

जाति इस बार 2014 और 2019 से ज्यादा प्रभावी

संविधान बचाने की बात करते हुए भाजपा विरोधी दल जरूर आरक्षण पर जोर दे रहे थे और संविधान पर आंच का मतलब आरक्षण पर आंच बताकर दलित और पिछड़ों को अपनी ओर गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे, पर धीरे-धीरे जाति इस बार के चुनाव का एक बड़ा विमर्श बन जाएगा और इसीसे भाजपा को दिक्कत होने लगेगी इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि राहुल गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जातिवार जनगणना का सवाल बहुत जोर-शोर से उठाया था और कांग्रेस उन राज्यों में भी बुरी तरह हारी जहां उसकी स्थिति अच्छी लग रही थी। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश में जाति के सवाल को न छेड़ने की सलाह देने के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक न होने दी या उसके नेताओं को चुनाव प्रचार में आने नहीं दिया। जाति के पिच पर भी उस्तादी दिखा चुके नरेंद्र मोदी ने जब हिन्दी पट्टी के तीन महत्वपूर्ण राज्यों के साथ हरियाणा के लिए नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा। और वे इस बार के प्रचार में संविधान के मसले पर अपना पक्ष मजबूती से रखते रहे लेकिन चुनाव प्रचार में या उम्मीदवारों के चयन में जाति के सवाल को कभी नहीं भूले।

अरविन्द मोहन

जाति का मसला दिन ब दिन जोर पकड़ता गया। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के सवाल पर पहले से जातिगत खलबली थी। राजस्थान में अचानक जाति आरक्षण उभर आया। केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के एक बयान से देश भर के राजपूत उखड़ गए। उत्तर प्रदेश में वी के सिंह जैसों का टिकट काटना और झारखंड में एक भी राजपूत को टिकट न देना भी भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनने लगा।

जैसे ही पहला दौर बीता और मतदान में गिरावट आई, मोदी जी का स्वर बदल गया। राजस्थान में उन्होंने मंगलसूत्र और कांग्रेस के सत्ता में आने पर हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने जैसे निम्न स्तर की बात शुरू कर दी। मोदी की गारंटी की जगह कांग्रेसी घोषणापत्र पर आक्रमण शुरू किया। बीजद सरकार का एक्सपायरी डेट बताने लगे। ये बदलाव काफी लोगों को हैरान करने वाले थे। विपक्ष ने जैसे तैसे प्रचार अभियान शुरू किया था पर वह तानाशाही/संविधान पर खतरा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मुश्किलें, अग्निवीर योजना की आलोचना और भाजपा के मुसलमान/पाकिस्तान द्वेष को मुद्दा बनाने में लगा रहा। तीन हफ्ते और चुनाव के तीसरे दौर तक आते-आते चुनाव प्रचार को और भी मसाले मिले- झारखंड में कांग्रेसी मंत्री से जुड़े ठिकाने पर नोटों की गड्डियों से लेकर कर्नाटक में भाजपा के सहयोगी दल के उम्मीदवार प्रज्वल और देवगौड़ा परिवार के कुकर्मों का अपूर्व वीडियो खजाना। दल बदल से लेकर उम्मीदवार बदलने और मैदान छोड़ने की घटनाएं भी हुईं। लेकिन चुनाव प्रचार और तैयारियों में भारी लीड के बावजूद भाजपा की बेचैनियां कम नहीं हुईं। टेक्सला के प्रमुख की प्रस्तावित भारत यात्रा का वादा पूरा न होना भी मुद्दा बना और सैम पित्रोदा का बयान भी। पाकिस्तान और मुसलमान तो आगे किया ही गया, मोदी जी अयोध्या हो आए और भगवान राम की मूर्ति का सूर्य अभिषेक करने जैसे बचकाना खेल भी हुए।

लेकिन जाति का मसला दिन ब दिन जोर पकड़ता गया। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के सवाल पर पहले से जातिगत खलबली थी। राजस्थान में अचानक जाति आरक्षण उभर आया। केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के एक बयान से देश भर के राजपूत उखड़ गए। उत्तर प्रदेश में वी के सिंह जैसों का टिकट काटना और झारखंड में एक भी राजपूत को टिकट न देना भी भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनने लगा। बिहार में सिर्फ एक ओर उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो वैश्य उम्मीदवार देने से भाजपा का यह मूल आधार भी नाराज बताया जा रहा है। उधर अखिलेश और लालू यादव ने मुसलमानों का टिकट कम किया (और उत्तर प्रदेश में बसपा ने मुसलमानों का टिकट बढ़ाकर भाजपा की मदद की, यह आरोप लगता रहा) तथा उस कोइरी/कुशवाहा/मौर्य का टिकट बढ़ाया जिससे एक साफ बदलाव दिख रहा है। अखिलेश ने तो अपने परिवार के अलावा अहीरों का टिकट भी कम किया है। उधर तेजस्वी यादव ने सब ओर से ठुकराए मुकेश साहनी को न सिर्फ अपने साथ लिया (और अपने हिस्से से तीन सीट देने के साथ उम्मीदवार भी पकड़ा दिए) बल्कि उनको चुनाव प्रचार में लगातार साथ रखा। यादवों के बाद कोइरी/कुशवाहा और मल्लाहों की संख्या सबसे ज्यादा है और वे गोलबंद भी हुए हैं।

कांग्रेस ने भी एक खेल किया है। उसने हिन्दी पट्टी में सभी जगहों पर जाति का गणित साधने का प्रयास किया है। इसमें उसने भाजपा के निवर्तमान सांसदों से लेकर महत्वाकांक्षी नेताओं को टिकट देने में परहेज नहीं किया और जहां अपना उम्मीदवार या ऐसा बाहरी उम्मीदवार न मिला तो उसने सिर्फ जाति का गणित देखकर उम्मीदवार उतार दिए हैं। भोपाल में कायस्थ और मुसलमान वोट ठीक-ठाक हैं तो एक अनाम से कायस्थ उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके हों या पुराने रीवा रियासत के इलाके। इनके पारंपरिक जातीय टकरावों को ध्यान में रखकर सामने किए गए उम्मीदवार अचानक मुकाबले में आ गए लगते हैं जबकि यहां भाजपा ने पिछला चुनाव भारी अंतर से जीता था। अब वह अंतर पाटना आसान नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में ही विपक्ष इस तरह खड़ा हो जाए तो यह जाति का गणित ही है। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है और हरियाणा में भी। यहां तो शुरूआत तो भाजपा ने ही की थी, गैर-जाति राजनीति को आगे करके। बिहार और उत्तर प्रदेश में उसने भी जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन दो मामलों में चूक हुई है मजबूत केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा मामलों में अपनी जिद चलाने से नुकसान दिखता है। इससे भी ज्यादा पुराने चेहरे दोहराने से भी जाति का जादू ही नहीं मोदी का जादू भी कमजोर होता दिखता है। ले-देकर सारे भाजपा उम्मीदवार ही नहीं एनडीए के उम्मीदवार मोदी-मोदी कर रहे हैं और लाख प्रयास करके भी मोदी जी के लिए उतना बोझ उठाना मुश्किल है जितना नौजवान राहुल, प्रियंका, अखिलेश और तेजस्वी उठा रहे हैं।

फिर चुनाव विज्ञान का वह चर्चित फार्मूला अपने आप प्रभावी होता दिखता है कि जब जाति का विमर्श हावी होगा तो सांप्रदायिक विमर्श पीछे जाएगा और जब साम्प्रदायिक विमर्श हावी होगा तो जाति का विमर्श पीछे रह जाता है। वैसे अब भाजपा भी ब्राह्मण बनिया पार्टी से बहुत आगे निकाल चुकी है और कांग्रेस का आरक्षण या जातीय कार्ड खेलने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और उसके नेताओं को जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल पर बहुत सफाई देनी पड़ रही है और जाति को आधार बनाकर राजनीति करने वाले भाजपा विरोधी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के फंदे में भी फंसे हैं। दो बातें साफ हैं- कम से कम पिछले दो चुनावों की तुलना में इस बार भाजपा के पास कोई केन्द्रीय मुद्दा नहीं है। दूसरे इस बार इन तीन चुनावों में सबसे ज्यादा प्रबल ढंग से जाति दिखाई दे रही है, भले वह मण्डल वाले और जैसी न दिखती हो।

पावन प्रसंग

महान योद्धा और समाज सुधारक परशुराम

भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाने वाले भगवान परशुराम के साथ भी कुछ अद्भुत हुआ माना जाता है। उनके आक्रोश और पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियविहीन करने की घटना को तो खूब प्रचारित कर वैमनस्य फैलाने का उपक्रम किया जाता है पर उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को भुला दिया जाता है। पिता की आज्ञा पर मां रेणुका का सिर धड़ से अलग करने की घटना को भी एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रेरक अ ख्यान बनाकर सुनाया जाता है किंतु सवाल खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति केवल चरम हिंसा के बूते जननायक के रूप में स्थापित होकर लोकप्रिय हो सकता है? क्या हैहयवंश के नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के वंश का समूल नाश करने के बावजूद पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो पाई? रामायण और महाभारत काल में तो पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं के ही राज्य रहे। वे ही उनके अधिपति हुए। इक्ष्वाकु वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आशीर्वाद देने वाले, कौरव नरेश धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने की सलाह देने वाले और सूत पुत्र कर्ण को ब्रह्मशास्त्र की दीक्षा देने वाले परशुराम ही थे।

ये सब क्षत्रिय थे। इस रूप में विवेचन किया जाए तो भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु नहीं, बल्कि शुभचिंतक ही थे। वास्तविकता में भगवान परशुराम आततायी शासकों के प्रबल विरोधी थे। पौराणिक आख्यानों का विवेचन विश्लेषण किया जाए तो समाज सुधारक और जनता को स्वावलंबन से जोड़ने में भगवान परशुराम की अहम भूमिका अंतर्निहित है। केरल, कच्छ और कोंकण क्षेत्रों में जहां परशुराम ने समुद्र में डूबी खेती योग्य भूमि निकालने की तकनीक सुझाई तो वहीं अपने परशु का उपयोग कर जंगलों को साफ कर भूमि को कृषियोग्य बनाने का दायित्व भी निभाया। इन्हीं परशुराम ने हेय माने जाने वाले दरिद्रनारायणों को शिक्षित व दीक्षित कर विप्र बनाया। उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार से जोड़ा और उस समय जो दुराचारी व आचरणहीन थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया।

परशुराम के अंत्योदय के प्रकल्प अनूठे व अनुकरणीय हैं। आज के दौर में उन्हें प्रेरणास्वरूप रेखांकित किए जाने की जरूरत है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जमदग्निपुत्र परशुराम का जन्म हरिश्चंद्रकालीन विश्वामित्र से एक-दो पीढ़ी बाद का माना जाता है। यह समय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में 'अष्टादश परिवर्तन-युग' के नाम से जाना गया है अर्थात यह 7500 विक्रम पूर्व का समय ऐसे संक्रमण काल के रूप में ज्ञात है, जिसे परिवर्तन का युग माना गया।

इसी समय क्षत्रियों की शाखाएं दो कुलों में विभाजित हुईं। एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। चंद्रवंशी पूरे भारतवर्ष में छाए हुए थे और उनका प्रताप चरमोत्कर्ष पर था। हैहयवंशीय अर्जुन वंश चंद्रवंशी था। माहिस्मती नरेश कार्तवीर्य अर्जुन इसी कुल के वंशज थे। भृगु ऋषि इस वंश के राजगुरु थे। जमदग्नि राजगुरु परंपरा का निर्वाह कार्तवीर्य अर्जुन के दरबार में कर रहे थे, किंतु अनीतियों का विरोध करने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि में मतभेद हो गए। परिणामस्वरूप जमदग्नि महिष्मति राज्य छोड़ कर चले गए। इस गतिविधियों से रुष्ट होकर सहस्त्रबाहू कार्तवीर्य अर्जुन आखेट का बहाना करके अनायास जमदग्नि के आश्रम में सेना सहित पहुंच गए। ऋषि जमदग्नि ने अतिथि सत्कार किया, लेकिन स्वेच्छाचारी और युद्धोन्मादी अर्जुन ने प्रतिहिंसास्वरूप जमदग्नि की हत्या कर दी। उसने पूरे आश्रम को उजाड़ दिया और ऋषि की प्रिय कामधेनु गाय को छीन कर ले गए। आश्रम के अनेक ब्राम्हण ने कान्यकुब्ज के राजा गाधि के राज्य में शरण ली। परशुराम जब यात्रा से लौटे तो इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने हैहयवंश के विनाश का संकल्प लिया और इस हेतु पूरी सामरिक राजनीति को अंजाम दिया।

क्षत्रियों के साथ युद्ध करने के बाद परशुराम ने समाज सुधार व कृषि के प्रकल्प अपने हाथ में लिए। उन्होंने केरल, कोंकण, मालाबार और कच्छ क्षेत्र में समुद्र में डूबी कषियोग्य भूमि को बाहर निकाला था। इस समय कश्यप ऋषि और इंद्र समुद्री पानी को बाहर निकालने की तकनीक में निपुण थे। अगस्त्य को समुद्र का पानी पी जाने वाले ऋषि और इंद्र को जल का देवता इसीलिए माना जाता है। परशुराम ने इस क्षेत्र में अपने परशु का उपयोग रचनात्मक कार्य के लिए किया। उपजाऊ कृषि भूमि तैयार की।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से प्रभावित होती बालिका शिक्षा

हाल ही में आईसीएसई समेत विभिन्न राज्यों के दसवीं और बारहवीं के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर प्रदर्शन किया है। यह आंकड़े बताते हैं कि यदि अवसर और सुविधाएं प्रदान किये जाएं तो लड़कियां भी किसी भी परिणाम को अपने पक्ष में करने की भरपूर माद्दा रखती हैं। दरअसल आज़ादी के बाद हमारे देश में चाहे केंद्र की सरकार हो, या राज्य की सरकारें, सभी ने जिन बुनियादी सुविधाओं के विकास पर सबसे अधिक फोकस किया उसमें शिक्षा भी एक अहम विषय था। शहर से लेकर गांव और अमीर से लेकर गरीब तक के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए कई स्तर पर योजनाएं तैयार की गई। बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच को आसान बनाने पर ज़ोर दिया गया। गरीब के बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आये इसके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। किताब-कॉपियां और स्कूल ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराये जाने लगे।

सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक परिणाम भी नज़र आने लगा। आज़ादी के बाद 1951 की पहली जनगणना में जहां देश में साक्षरता की कुल दर महज़ 18.33 प्रतिशत थी वहीं 60 वर्षों बाद 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई। लेकिन इस सुखद आंकड़ों के साथ सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि अभी भी किशोरियों विशेषकर दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों के सामने शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम है। जहां मुश्किल से लड़कियां 12वीं तक भी शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ऐसा ही एक गांव राजस्थान के अलवर जिला स्थित शादीपुर है जहां आज भी महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। इस गांव में बालिका शिक्षा के प्रति जहां समाज में उदासीनता है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भी दम तोड़ती नज़र आती है। अलवर जिला से करीब 67 किमी और तिजारा तहसील से लगभग 20 किमी की दूरी पर आबाद इस गांव की जनसंख्या 300 के आसपास है। इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब 48 प्रतिशत है। स्कूल में कोई महिला शिक्षिका के नहीं होने से लड़कियों को अक्सर माहवारी के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए माहवारी के दिनों में गांव की लड़कियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं। जिससे वह धीरे-धीरे शिक्षा में पिछड़ती चली जाती हैं। 8वीं के बाद की शिक्षा के लिए दूसरे गांव जाने के प्रश्न पर एक अन्य महिला कहती हैं कि हमें अपनी लड़कियों की सुरक्षा की चिंता होती है। ज़माना ठीक नहीं है यदि किसी लड़की के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना हो जाए तो न केवल उस लड़की की बल्कि उसके पूरे खानदान की इज्जत चली जाएगी। इसलिए कोई भी अभिभावक 8वीं के बाद इतनी दूर अपनी लड़की को स्कूल भेजने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं।

आशा नारंग, अलवर राजस्थान

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

सुभाषित *अपने कर्ममें प्रवीणता हासिल करके उसीमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। स्वकर्मको करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।* ❐ *हितोपदेश*

आबादीकी विसंगतियां

जनसंख्याका आर्थिक नीतियोंपर प्रभावको परखनेके उद्देश्यसे प्रधान मंत्रीकी आर्थिक सलाहकार परिषदकी ताजा अध्ययन रिपोर्टमें जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वह सहज करनेवाले हैं। साथ ही यह जनसंख्याकी विसंगतियोंको भी उजागर करती है। रिपोर्टमें बताया गया है कि भारतमें १९५० से २०१५ तक ६५ वर्षोंके कालखण्डमें बहुसंख्यक हिन्दुओंकी आबादीमें ७.८ प्रतिशतकी कमी आयी है, जबकि मुसलमानोंकी आबादीमें ४३.१५ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है। इस समितिने अपनी रिपोर्टमें कुल १६७ देशोंका अध्ययन किया है। आबादीमें हिन्दुओंकी हिस्सेदारी घटनेका सिलसिला पड़ोसी हिन्दूबहुल देश नेपालमें भी दर्ज हुई है। म्यांमारमें भी बहुसंख्यक बौद्धोंकी हिस्सेदारीमें गिरावट आयी है। दूसरी ओर पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तानमें बहुसंख्यक आबादी मुसलमानोंकी हिस्सेदारी तेजीसे बढ़ी है और अल्पसंख्यकोंकी हिस्सेदारी तेजीसे सिमट गयी है। जनसांख्यिकीमें हुए परिवर्तनका वहांकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन प्रणालीपर भी प्रभाव पड़ा है। १६७ देशोंमें बहुसंख्यक उन्हें माना गया है, जिनकी आबादी ७५ प्रतिशतसे अधिक है। इन देशोंमें ६५ वर्षोंके दौरान बहुसंख्यकोंकी हिस्सेदारीमें २२ प्रतिशतकी कमी आयी है लेकिन यह मुस्लिम बहुसंख्यक देशोंपर लागू नहीं होता है। मुस्लिमबहुल ३८ देशोंमें मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ी है। श्रीलंकामें बहुसंख्यक बौद्धोंकी हिस्सेदारी ६४.२८ प्रतिशतसे बढ़कर ६७.६५ प्रतिशत हो गयी है। इसी तरह भूटानमें भी बौद्धोंकी हिस्सेदारीमें तेज वृद्धि हुई है और यह ७१.४४ प्रतिशतसे बढ़कर ८४.०७ प्रतिशतसे स्तरपर पहुंच गया है। भारतमें ईसाई और सिख अल्पसंख्यककी हिस्सेदारीमें क्रमश: ५.३८ प्रतिशत और ६.५८ प्रतिशत बढ़ा है। भारतमें १९५१ की जनगणनाके अनुसार देशकी कुल आबादीमें हिन्दुओंकी हिस्सेदारी ८४.१० प्रतिशत थी। वर्ष २०१५ में यह घटकर ७७.५२ प्रतिशत रह गयी, जबकि इसी दौरान मुसलमानोंकी हिस्सेदारी ९.८० प्रतिशत थी। इसमें ४३.१५ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है। इस दृष्टिसे २०१५ में कुल आबादीमें मुसलमानोंकी हिस्सेदारी बढ़कर १४.०२ हो गयी है। रिपोर्टमें यह भी कहा गया है कि भारतमें अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि वह सम्पन्न भी हो रहे हैं। जो भी हो, देशमें बढ़ी आबादी व्यापक सन्दर्भमें चिन्ताका विषय है, क्योंकि इससे विसंगतियां बढ़ रही है। सीमित संसाधनोंमें बहुत बड़ी आबादीका पोषण और संरक्षण निरन्तर दुष्कर हो रहा है। इसलिए देशके नीति-नियोजकोंको इसपर ध्यान देना होगा कि आबादीको कैसे नियंत्रित किया जाय।

जंगलकी आग

उत्तराखण्डके जंगलोंमें लगी आगने भयावह रूप ले लिया है। इसपर काबू पानेके तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसको लेकर दायर याचिकापर सर्वोच्च न्यायालने चिन्ता जाहिर करते हुए राज्य सरकारको कड़ी फटकार लगायी है। न्यायालयने कहा है कि आगपर काबू पानेके लिए कृत्रिम या मौसमी बारिशके भरोसे हाथपर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। सरकारको बचावके ठोस उपाय करने होंगे। सरकारी वकीलका कहना है कि ०.१ प्रतिशत वन्य जीव क्षेत्रमें आग लगी है, जबकि मीडिया रिपोर्टमें कहा जा रहा है कि ४० प्रतिशत क्षेत्र आगकी चपेटमें हैं। आगके कारण अबतक भारी पैमानेपर वन्य क्षेत्रकी विभिन्न प्रजातियां, वनस्पतियों सहित पर्यावरणको काफी नुकसान पहुंचा है। छह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखण्डमें १५ फरवरीसे ३० जूनतक फायर सीजन माना जाता है और हर साल इसे रोकेनेकी तैयारियां एक नियमित प्रक्रिया है। इसके तहत वनकर्मी फायर लाइंसको साफ करने, घास और झाड़ियोंको कटाने, जलानेपर नियंत्रण और निगरानी आदि करते हैं। इस कारण डीएफओ स्तरके अधिकारियोंने वनकर्मियोंको चुनावी ड्यूटीमें नहीं लगानेके लिए प्रशासनको पत्र लिखा था। मौसम विभागने भी भविष्यवाणी की थी कि इस साल बारिश कम होगी और औसतसे अधिक तापमानके कारण जंगलमें आग लगनेकी घटनाएं अधिक गम्भीर होंगी। इसके बावजूद वन कर्मियोंको चुनावी सम्बन्धी कार्यमें लगा दिया गया। इस कारण फायर सजीनकी तैयारी नहीं हो सकी। उत्तराखण्डके जंगलमें चीड़के पेड़ बहुतायत हैं। अंग्रेजोंने इन्हें तारकोल बनानेके लिए लगाया था जिसका उपयोग आज भी होता है। इनकी पत्तियोंमें तेलकी मात्रा अधिक होनेके कारण गर्मीके दिनोंमें आग पकड़नेकी समस्या विकराल हो जाती है। अग्निशमन कर्मियों और संसाधनोंके सामूहिक प्रयासोंके बावजूद दुर्गम और पहाड़ी रास्तेकी वजहसे आगको बुझाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसपर नियंत्रणके लिए भारी-भरकम कर्मचारियोंकी फौजवाला वन विभाग आजतक कोई ठोस मैकेनिज्म विकसित नहीं कर पाया है। वन सुरक्षाके नामपर हर साल करोड़ों रुपये बहा दिये जाते हैं, लेकिन आज भी आग बुझानेके लिए आसमानी वर्षापर निर्भर है। ऐसेमें सरकारको वन प्रबन्धनके लिए स्थानीय लोगोंके समन्वय बनानेके साथ उन्हें इस प्रक्रियामें शामिल करनेकी आवश्यकता है।

लोक संवाद

इंडी गठबंधन

महोदय,-केजरीवालकी न्यायायिक हिरासत बढ़ गयी है। केजरीवालका दामन कांटो भरा है। केजरीवाल यदि दूधके धुले होते तो कोर्ट हिरासत क्यों बढ़ाती। लोकसभा चुनावमें कांग्रेससे आये सैकड़ों बागियोंको भाजपामें तरजीह मिली है। यह अपने अपने दलकी विचारधारा है। इंडी गठबंधनकी हुंकार मोदीका मेरठसे शंखनाद यह संदेश दे रहा है कि एक देशके विकास और भ्रष्टाचारको खत्म करना चाहता है तो दूसरी तरफ २७ दलोंने एक मंचसे जेलोंमें बन्द भ्रष्टाचारियोंको छुड़ानेकी हुंकार भरी जा रही है। मोदीने बेटियोंका भाग्य बदलने भ्रष्टाचारियोंको जमानत नहीं मिलनेकी बात चौधरी चरण सिंहकी धरतीसे की गयी। जिनके पति भ्रष्टाचारके आरोपमें जेलोंमें बंद है उनकी भावुक अपील क्या कोर्ट मान्य रखेगी। गरीबोंकी मेहनतके रुपये डकारनेवाले देशहितमें बात करेंगे। उनको कुर्सिमोह सता रहा है। राजनीतिमें अवसर मिलते ही ये लोग भ्रष्टाचार किये बिना नही रहते हैं। एक हो रहे हैं वह भी दागी मंत्रियोंकी टोली है। मुख्य मंत्रीको जेल भेजे गये है वहां सहानुभूति बटोर रहे हैं लेकिन उनको सोचना चाहिए कि कोई किसीको एक दिन भी बिना मतलबके जेलमें बन्द नहीं रख सकते हैं। यह तो देशका निरक्षर भी समझ सकता है। अपने गिरेबानमें झांककर देखे। कांग्रेसके दिग्गज नेता अपने कुलके चिरागको सेट करनेके लिए योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी भाजपाके ४०० पारका मखौल उड़ाया है। भाजपासे राजनीति सीखनेवाली ममता बनर्जी भाजपाको चुनौती दे रही है उन्होंने कहा कि भाजपाको दो सौ पार नहीं कर सकती है। सन्देशखालीकी घटनाके बाद ममताकी असलियत सामने आ गयी है कि वह महिलाओंके प्रति कितनी संवेदनशील है। केंद्रीय एजेंसियोंपर निशाना साधा और कहा कि वे तृणमूलको निशाना बना रही है। भ्रष्टाचारमें लिप्त तृणमूल कांग्रेसके नेताओंकी मानसिकता उनके जेल जानेके निमित्त बन रही है। इंडी गठबंधन इस बार सफल नहीं हो सकता है क्योंकि ये देशके लिए विकासकी बात नहीं करते है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनको कुर्सी प्यारी है। **-के. एम., सूरत।**

विकसित देश बनेगा भारत

विश्वमें अर्थ विशेषज्ञ एकमत हैं कि यदि भारत अपने विकास मॉडलमें तेज विकासके साथ समावेशी विकास तथा रोजगार एवं साझी समृद्धिकी रणनीतिपर तेजीसे आगे बढ़ेगा तो भारत २०४७ तक विकसित देश बननेके सपनेको साकार कर सकेगा। इस समय विश्वमें ४० ही देश विकसित हैं, जिनमें प्रमुख रूपसे विकसित यूरोपीय देश हैं।

❐ **डा.जयंतीलाल भंडारी**

भारत इस समय विकासशील देश है। अब भारतके विकसित राष्ट्र बननेकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होनेकी सम्भावनाओंके कई आधार हैं। भारत दुनियामें वैश्विक सुस्तीकी चुनौतियोंके बीच आर्थिक विकासकी डगरपर लगातार तेजीसे आगे बढ़ रहा है। हालमें २६ अप्रैलको प्रकाशित वैश्विक परामर्श एजेंसी डेलॉयट इंडियाकी नयी रिपोर्टके तहत वित्त वर्ष २०२४-२५ के लिए भारतके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धिका अनुमान बढ़ाकर ७.६ से ७.८ प्रतिशत कर दिया है। कहा गया है कि भारतमें मध्यम आय वर्गके लोगोंकी संख्यामें तेज वृद्धिसे क्रय शक्ति बढ़ी है। इस रिपोर्टमें कहा गया है कि पिछले दो सालसे वृद्धिके मजबूत आंकड़ोंने अर्थव्यवस्थाको कोविडके पहलेके स्तरमें आनेमें मदद की है। बुनियादी ढांचेपर सरकारके व्ययमें तेजीसे निवेशको समर्थन मिला है। इससे भारतको वृद्धिकी रफ्तार तेज रखनेमें मदद मिली है। निस्संदेह यह रिपोर्ट ऐसे समयमें आयी है, जब कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मजबूत घरेलू मांग और कामकाज करनेवाली आबादीको देखते हुए वित्त वर्ष २०२४-२५ के लिए भारतका वृद्धि अनुमान ६.५ प्रतिशतसे बढ़ाकर ६.८ प्रतिशत कर दिया है। साथ ही विश्व बैंकने भी वित्त वर्ष २०२४-२५ के लिए भारतकी वृद्धिका अनुमान ६.४ प्रतिशतसे बढ़ाकर ६.६ प्रतिशत कर दिया है। निश्चित रूपसे विकसित भारत बननेके लिए भारतकी मुट्ठियोंमें कई महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। भारतमें पिछले वर्ष २०२३ में आयोजित जी-२० के शानदार सफल आयोजनसे भारतके पास विकासके नये सूत्र आये हैं। भारतके पास पिछले दस वर्षोंकी शानदार विरासत है। यह भारतका ऐसा समय है जब हमारी आर्थिक वृद्धि लगातार बढ़ रही है। भारतमें स्थिति मैन्युफेक्चरिंग, निवेश और निर्यातके मद्देनजर उपयुक्त है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानसे देश तेजीसे आगे बढ़ा है। वैश्विक स्तरपर प्रत्यक्ष विदेशी निवेशमें गिरावटके रुझानके बीच भारत दुनियाके सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करनेवाले प्रमुख देशोंमें शामिल है। भारतका विदेशी मुद्रा भण्डार भी तेजीसे बढ़ा है। वैश्विक सुस्तीके बीच भारतका शेयर बाजार नयी ऊंचाइयोंपर है। पिछले एक दशकमें हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म देशके विकासके लिए गेमचेंजर रहे हैं। भारतमें अहम आर्थिक सुधार हुए और इन सुधारोंमें जन धन, आधार और मोबाइल आधारित सब्सिडी सुधार (जेएएम) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) प्रमुख हैं। निस्संदेह इस समय भारतके पास टिकाऊ विकासके अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचोंपर भारतको विशेष अहमियत दी जा रही है। भारतको संयुक्त राष्ट्र संघका स्थायी सदस्य देश बनानेके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूसका समर्थन रेखांकित हो रहा है और भारत वैश्विक मंचपर बड़ी भूमिकाके लिए तैयार है। भारतके तेजीसे बढ़े कृषि क्षेत्रसे दुनियाकी उम्मीदें बढ़ गयी हैं। तेजीसे बढ़ते भारतीय बाजारके कारण भारतके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीयोंके द्वारा लगातार भारतकी ओर अधिक रेमिटेंस भेजा जा रहा है। इस समय देशके वैज्ञानिकोंके द्वारा अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नये तकनीकी विकासके कारण आर्थिक विकासको गति मिल रही है चीनके प्रति बढ़ती नकारात्मकताके मद्देनजर भारत नये वैश्विक आपूर्तिकर्ता देशके रूपमें उभरकर सामने आया है। अब भारतमें लॉजिस्टिक लागतमें कमी आने लगी है। इतना ही नहीं, भारत दुनियाके ८५ देशोंको हथियार एवं सैन्य सामग्रियोंका निर्यात भी कर रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारके द्वारा विगत दस वर्षोंमें किये गये आर्थिक और वित्तीय सुधारोंके साथ-साथ कठोर प्रशासनिक निर्णयोंसे देशमें आर्थिक विकासकी रफ्तार बढ़ी है। इसके साथ-साथ दुनियामें मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकारके रूपमें भारतकी पहचान, स्टार्टअपका दुनियामें सबसे तेजीसे बढ़ना, भारतमें दुनियाकी सबसे बड़ी युवा आबादीके लिए बढ़ते हुए नये दौरके कौशल निर्माण कार्यक्रम, बड़े पैमानेपर पूंजीगत खर्च, गैर-जरूरी आयातमें कटौती, खेलोंके क्षेत्रमें भारतकी लम्बी छलांगोंसे लाभान्वित होती भारतीय अर्थव्यवस्था और बाहरी झटकोंसे उबरनेकी क्षमता देशके टिकाऊ विकासकी बुनियाद बन गयी है। निश्चित रूपसे भारतको विकसित देश बनानेके लिए वर्तमान विकास मॉडलमें सुधार करना होगा। विकास मॉडलमें समृद्ध भारतके साथ समावेशी भारतकी तस्वीरको हरदम सामने रखना होगा। जहां देशकी अर्थव्यवस्था तेजीसे आगे बढ़ाते रहना होगा, वहीं रोजगार वृद्धि एवं आम आदमीके सशक्तिकरणके अधिक प्रयास करने होंगे। यद्यपि पिछले दस वर्षोंमें बहुआयामी गरीबोंमें बड़ी कमी आयी है। लेकिन अब बकाया १५ करोड़से अधिक गरीबोंको नयी मुस्कराहट देनेका जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। इस बातको भी ध्यानमें रखना होगा कि देशके आम आदमीके कमजोर जीवन स्तरको अच्छे जीवन स्तरमें बदला जाय। देशमें १९ करोड़से अधिक महिलाओंको पेड वर्कफोर्समें शामिल करनेकी रणनीतिको अमलीजामा पहनाना होगा। हमें विकासके लिए चीनकी कम कौशलवाले विनिर्माणकी नीतिको अपनानेकी बजाय हमारे शक्तिशाली सर्विस सेक्टरके जरिये विकासपर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। कई अहम सुधारोंको वैधानिक बनाते हुए उनका तेजीसे क्रियान्वयन करना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि भ्रष्टाचारके उन्मूलन और अन्य सुधारोंकी डगरपर तेजीसे बढ़ना होगा। यद्यपि केन्द्र सरकार २९ श्रम कानूनोंको चार श्रम संहिताओंमें तबदील करनेकी महत्वाकांक्षी योजनाको आकार देनेमें सफल रही है, लेकिन ये अबतक लागू नहीं हुई है। अब एक ऐसे समयमें जब कई देशोंकी कम्पनियां चीनसे बड़ी संख्यामें उद्योग-कारोबार स्थानांतरित करते हुए दिखाई दे रही हैं तब हम अच्छे श्रम कानूनोंसे इसका लाभ उठा सकते हैं। देशके तेज विकासके लिए उभरते क्षेत्रोंमें शोध एवं विकास क्षेत्रमें जरूरी निवेश पर्याप्त नहीं है। शोध एवं विकासके क्षेत्रमें भारतका प्रति व्यक्ति व्यय दुनियामें विभिन्न तेजीसे उभरती अर्थव्यवस्थाओंकी तुलनामें कम है। निश्चित रूपसे देशको विकसित देश बनानेकी सम्भावनाओंको साकार करनेके लिए इस लोकसभा चुनावके माध्यमसे जून २०२४ में गठित होनेवाली सरकार स्थिर और मजबूत होना जरूरी है। देशको एक ऐसी प्रभावी और त्वरित प्रशासनिक निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित करनेवाली क्षमतावान सरकारकी जरूरत है, जो २०४७ तक भारतको दुनियाका विकसित देश बनानेके मद्देनजर ८.९ फीसदी सालाना विकास दर प्राप्त करनेके लिए मौजूदा प्रति व्यक्ति आयको पांच गुनातक करके १२ हजार डालरकी ऊंचाईपर पहुंचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकासके मूल्योंके साथ विकासका जज्बा पैदा करते हुए देशको रणनीतिक रूपसे तेजीसे आगे बढ़ाये।

भारत दुनियाके ८५ देशोंको हथियार एवं सैन्य सामग्रियोंका निर्यात भी कर रहा है। सरकार द्वारा विगत दस वर्षोंमें किये गये आर्थिक और वित्तीय सुधारोंके साथ कठोर प्रशासनिक निर्णयोंसे देशमें आर्थिक विकासकी रफ्तार बढ़ी है। हमें विकासके लिए चीनकी कम कौशलवाले विनिर्माणकी नीतिको अपनानेकी बजाय हमारे शक्तिशाली सर्विस सेक्टरके जरिये विकासपर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। कई अहम सुधारोंको वैधानिक बनाते हुए उनका तेजीसे क्रियान्वयन करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन और अन्य सुधारोंकी डगरपर तेजीसे बढ़ना होगा।

अक्षय तृतीया की पूजा से अक्षय होता है भंडार

❐ **विजय कुमार जैन शास्त्री**

जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से जुड़ा है अक्षय तृतीया पर्व का इतिहास। भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया एवं प्रयाग की (इलाहाबाद) धरती पर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। जो कि इस युग की प्रथम दीक्षा थी। क्योंकि भगवान ऋषभदेव वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर है। दीक्षा को धारण करते ही ध्यान लगाकरके भगवान बैठ गये। भगवान के साथ में 4 हजार राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की। 6 माह पश्चात भगवान ऋषभदेव आहारचर्या बतलाने के लिए कि जैन साधुओं को किस प्रकार आहार करना चाहिए लोगों को इस विधि का ज्ञान हो सके इसलिए आहार के लिए निकले लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि जैन साधुओं को आहार किस प्रकार से करना चाहिए। महायोगी ऋषभदेव जिस ओर कदम रखते थे वहीं के लोग प्रसन्न होकर के बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम करते थे और कहते थे कि भगवान प्रसन्न हो जाईये कहिये क्या काम है, कितने ही लोग भगवान के पीछे-पीछे चलने लगते थे, अन्य कितने ही लोग बहुमूल्य रत्नलाकर भगवान के सामने रखकर कहते थे कि हे देव इन रत्नों ग्रहण कर लीजिए और कितने ही लोग अन्य प्रकार के पदार्थ वस्त्र आभूषण, माला, कन्या, भवन, सवारी आदि दिखाकरके कहते थे कि प्रभु इसे ग्रहण कर लीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। तीर्थंकर भगवन अपनी चर्या में विघ्न मानकरके आगे बढ़ जाते थे। लोग निराश होकर के प्रभु की ओर देखते रह जाते थे और सोचते थे कि किस प्रकार से भगवान को उनकी महचाही वस्तु देकर के हम कृतार्थ हो सकें। इस प्रकार से भगवान को 6 महा व्यतीत हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है और महामुनि कुरूजांगल देश के आभूषण ऐसे हस्तिनापुर नगर के समीप पहुँचते हैं। जैन समाज के वरिष्ठ विद्वान सहितासूरी प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय कुमार जैन शास्त्री ने बताया कि अक्षय तृतीया का प्राचीन इतिहास हस्तिनापुर तीर्थ से ही प्रारंभ हुआ है। वैशाख सुदी तीज को अक्षय तृतीय के नाम से जाना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिस वस्तु का कभी क्षय न हो अर्थात् वस्तु समाप्त न हो और वह महीना वैशाख का था और तिथि तृतीया थी। इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा। लोगों का मानना है कि इस दिवस किया जाने वाला कार्य वृद्धि को प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव को हुए कोड़ा कोड़ी वर्ष (करोड़ों करोड़ो साल) व्यतीत हो गये। लेकिन आज भी अक्षय तृतीया का पर्व मनाने के लिए देश एवं विदेश से जैन श्रद्धालु हस्तिनापुर की धरती पर आते हैं। जैन श्रद्धालु आहार दान की महिमा का वर्णन करते हुए इस पवित्र धरती पर आते हैं। इस पवित्र दिवस का ये महत्व है कि बिना मुर्हूत के ही हजारों विवाह सम्पन्न होते हैं। अगणित ग्रह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। और इसे सर्वश्रेष्ठ मुर्हूत माना जाता है।

हस्तिनापुर नगरी के शासक राजा सोमप्रभ और उनके भाई श्रेयांस कुमार थे। पिछली रात्रि में राजा श्रेयांस को उत्तम-उत्तम 7 स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रात: वह अपने स्वप्नों को अपने भाई सोमप्रभ से उन स्वप्नों को बताकर उनका फल पूछते हैं। प्रथम स्वप्न में मैने सुमेरूपर्वत देखा है, दूसरे में एक कल्पवृक्ष देखा है जिसकी शाखाओं पर आभूषण लटक रहे हैं, तीसरे में सिंह देखा है, चौथे में बैल, पाँचवें में सूर्य और चंदमा, छठे में लहरों से सुशोभित समुद्र तथा सातवें में अष्ट मंगल द्रव्यों को हाथों में धारण किये व्यंतर देवों को देखा है। इन स्वप्नों का उत्तम फल जानकरके अति प्रसन्न चित्त हो करके के चिन्तन ही कर रहे होते हैं कि तभी सुनने में आता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं चारों ओर भारी जन समुदाय एकत्र होकर के भगवान का दर्शन करता है। उनके चरणों की पूजन करता है।

इच्क्षु रस का हुआ पारण, आखा तीज महान।
जय जय ऋषभदेव भगवान, जय जय ऋषभदेव भगवान।।

कोई कहता है कि अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये तीन लोक के स्वामी भगवान ऋषभदेव समस्त राज्य वैभव का त्याग कर पूर्ण दिगम्बर होकर आज अकेले ही इस पृथ्वीतल पर विचरण कर रहे हैं। इतने में ही द्वारपाल द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि प्रभु समीप में ही पधार चुके है और इधर ही आ रहे हैं। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस महल के बाहर आ जाते हैं प्रभु के चरणों में नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं। इतने में ही राजकुमार श्रेयांस को पूर्वभव का जाति स्मरण हो जाता है कि जब में राजा बज्रजंघ की रानी श्रीमती की पर्याय में मुनियों को दिये गये आहार दान की सारी विधि स्मरण में आ जाती है। महाप्रभु ऋषभदेव को देखते ही राजा श्रेयांस एवं सोमप्रभ ने हे भगवन् अत्रो-अत्रो, तिष्ठो-तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आहार-जल शुद्ध है मुद्रा छोडिये आहार ग्रहण करिये नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर लेते हैं एवं अष्ट द्रव्य से पूजन कर नमस्कार करते हैं ऐसे निवेदन कर प्रभु से आहार ग्रहण करने हेतु प्रार्थना करते हैं भगवान ऋषभदे करपात्र में आहार प्रारंभ कर देते हैं बड़ी भक्ति के साथ राजा श्रेयांस इच्छुरस (गन्ने) का आहार देते हैं। उसी समय आकाश से देवों द्वारा रत्न वृष्टि होने लग जाती है नाना प्रकार सुगंधित पुष्पों की वृष्टि होने लग जाती है। देवता भी धन्य है यह दान धन्य यह पात्र धन्य ये दाता ऐसे शब्दों से आकाश गुंजायमान कर देते हैं एवं देवों द्वारा पाँच अतिशय पंचाश्चर्य कहलाते हैं राजा श्रेयांस प्रभु को आहार देने में मग्न हैं देवतागण हर्ष विभोर होकर के पंचाश्चर्य की वृष्टि कर रहे है। प्रभु ऋभषदेव आहार करके वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उस दिन सारे नगर में गन्ने के सार का प्रसाद वितरण किया जाता है। लेकिन फिर भी गन्ने का रस समाप्त नहीं होता है। वह अक्षय हो जाता है।

राजा श्रेयांस ने प्रथम आहार दान दिया क्योंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। तो यह प्रथम आहार था भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या से पूरी सेना के साथ हस्तिनापुर आकर के राजा श्रेयांस व सोमप्रभ का खूब सम्मान किया एवं दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया। इससे पूर्व दान देने की प्रथा इस धरती पर नहीं थी इसका शुभारंभ राजा श्रेयांस के द्वारा ही हुआ। तो यह दानवीर भूमि भी कहलाई। तब से लेकर के आज तक ये हस्तिनापुर की धरती के समीप वर्ती क्षेत्रों में इच्छु (गन्ना) खेती खूब पाई जाती है उस दिन से इस धरती पर गन्ने की खेती भी अक्षय हो गई समीपवर्ती सभी क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है एवं ऐसा मानते है कि जैन साधु जहाँ पर भी विराजमान है उनको आज के दिन गन्ने के रस का आहार करवाया जाता है। जो लोग वर्षीय उपवास करते हैं वे पारणा करने के लिए हस्तिनापुर की धरती पर आकर के अपना उपवास समाप्त करके पारणा इच्क्षु रस से करते है और अपने आप को धन्य मानते हैं यह इस भूमि का असीम पुण्य है। अक्षय तृतीय आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है।

आत्मबोध

परशुरामका जन्मदिवस

❐ **निमेष शास्त्री**

परशुराम राजा प्रसेनजितकी पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्निके पुत्र थे। वे विष्णुके अवतार और शिवके परम भक्त थे। इन्हें शिवसे विशेष परशु प्राप्त था। इनका नाम तो राम था, किन्तु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशुको सदैव धारण किये रहनेके कारण ये परशुराम कहलाते थे। परशुराम भगवान विष्णुके दस अवतारोंमेंसे छठे अवतार थे, जो वामन एवं रामचंद्रके मध्यमें गिना जाता है। जमदग्निके पुत्र होनेके कारण ये जामदग्न्य भी कहे जाते हैं। इनका जन्म अक्षय तृतीया (वैशाख शुक्ल तृतीया) को हुआ था। अत: इस दिन व्रत करने और उत्सव मनानेकी प्रथा है। परम्पराके अनुसार इन्होंने क्षत्रियोंका अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियोंके अहंकारपूर्ण दमनसे विश्वको मुक्ति दिलानेके लिए इनका जन्म हुआ था। भृगुने अपने पुत्रके विवाहके विषयमें जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्रवधूसे वर मांगनेको कहा। उनसे सत्यवतीने अपने तथा अपनी माताके लिए पुत्र जन्मकी कामना की। भृगुने उन दोनोंको चरु भक्षणार्थ दिये तथा कहा कि ऋतुकालके उपरांत स्नान करके सत्यवती गूलरके पेड़ तथा उसकी माता पीपलके पेड़का आलिंगन करे तो दोनोंको पुत्र प्राप्त होंगे। मां-बेटीके चरु खानेमें उलट-फेर हो गयी। दिव्य दृष्टिसे देखकर भृगु पुन: वहां पधारे तथा उन्होंने सत्यवतीसे कहा कि तुम्हारी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मणोचित होकर भी क्षत्रियोचित आचार-विचारवाला होगा। बहुत अनुनय-विनय करनेपर भृगुने मान लिया कि सत्यवतीका बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा, किन्तु पोता क्षत्रियोंकी तरह कार्य करनेवाला होगा। सत्यवतीके पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसेनजितकी पुत्री रेणुकासे विवाह किया। रेणुकाके पांच पुत्र हुए-रुमण्वान, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा पांचवें पुत्रका नाम परशुराम था। वही क्षत्रियोचित आचार-विचारवाला पुत्र था। रामका पराक्रम सुनकर वे अयोध्या गये। दशरथने उनके स्वागतार्थ रामचंद्रको भेजा। उन्हें देखते ही परशुरामने उनके पराक्रमकी परीक्षा लेनी चाही। अत: उन्हें क्षत्रियसंहारक दिव्य धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ानेके लिए कहा। रामके ऐसा कर लेनेपर उन्हें धनुषपर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखानेके लिए कहा। रामने वह बाण चढ़ाकर परशुरामके तेजपर छोड़ दिया। बाण उनके तेजको छीनकर पुन: रामके पास लौट आया। रामने परशुरामको दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने रामके यथार्थ स्वरूपके दर्शन किये। परशुराम एक वर्षतक तेजहीन होकर तपस्यामें लगे रहे। तदनंतर पितरोंसे प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसर नामक नदीके तीर्थपर स्नान करके अपना तेज पुन: प्राप्त किया।

वैश्विक चुनौती बनता पर्यावरण संरक्षण

❐ **जया टण्डन**

प्रकृति द्वारा दिये गये प्राकृतिक संसाधनोंको सुरक्षित रखने एवं अपने ग्रहको बचानेके लिए अन्य बहुत सारी गतिविधियों जैसे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपणका कार्य, कूड़ेका पुर्नचक्रण, फिल्मों एवं नुक्कड़ नाटकोंके माध्यमसे लोगोंको जागरूक करना एवं उत्सवके माध्यमसे आजके दौरका युवा इन गतिविधियोंमें शामिल रहता है। प्रकृति अपने संतुलनको बनाकर रखती है और प्राकृतिक आपदासे बचाव ही हमारी बुद्धिमत्ता है। आज हर शहरमें बढ़ते कूड़ेके पहाड़ हमें जागरूक होनेके लिए कह रहे हैं। यह सही है कि अतीतसे हमें सबक लेना चाहिए और यह भी होता है कि अतीत अपनेको दोहराता भी है। प्राचीन कालमें धरतीके सबसे शक्तिशाली प्राणी डायनासोर थे किन्तु वह कहां लुप्त हो गये। इस अतीतको इतिहास वेत्ता कुछ इस तरह बताते हैं कि छह करोड़ साल पहले धरतीसे एक विशाल धूमकेतु टकराया था उसके टकरानेसे वायुमंडलमें इतनी अधिक धूल-मिट्टी छा गयी और धरतीपर अंधकार छा गया सूर्यकी किरणें भी धरतीपर नहीं पहुंच रही थीं। सूरजकी रौशनीके अभावमें वृक्ष अपना भोजन नहीं बना पाये और नष्ट हो गये। जो जीव पेड़ोंके पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाते थे वह सभी मृत्युको प्राप्त हुए उस समयके जीव आसमानी आफतके शिकार होकर मारे गये किन्तु हम मानव तो विवेकशील प्राणी है हमें इतिहाससे सबक लेना चाहिए और बढ़ते प्रदूषणसे धरतीकी रक्षा करनी चाहिए जिससे मानवीय अस्तित्व सुरक्षित रहे।

धरतीकी आबोहवा आज तेजीसे परिवर्तित हो रही है कहीं अधिक बारिश, बाढ़ तो कहीं बर्फबारीका असंतुलन है। तेजीसे बढ़ती गर्मी जलवायु परिवर्तन, शहरीकरणकी असंतुलित जीवनचर्या और मानवका लगातार प्रकृतिका दोहन प्रकृतिका गिरता स्तर मानवको चेतावनी भी दे रहा है कि संतुलित जीवनशैली एवं प्रकृतिसे दोस्ताना व्यवहार ही सुरक्षाका स्तर मजबूत करेगा। उसके लिए धरतीके सौंदर्यको वृक्षोंसे सजाकर रखना चाहिए। जहां हरियालीका घनत्व रहता है वहां पानीके बादल जल्दी आकर्षित होते हैं। वन संपदा भी खूब प्राप्त होती है। धरतीकी हिफाजत, वृक्षोंका महत्व एवन संरक्षण आज ही नहीं, बीती सदियोंके लोग भी जानते थे। वह वृक्षोंकी हिफाजत अपने जीवनका हिस्सा मानते थे। ईसाकी पंद्रहवीं सदीके उत्तरार्धमें गुजरातके अहमदाबाद सिंहासनपर सुल्तान महमूद बेगडा नामकका शासन था। वह वृक्षारोपणको जीवनमें आवश्यक समझता था। उसका कहना था कि धरतीके जख्मोंको हरे-भरे वृक्षोंसे भर देना चाहिए ताकि मानवको स्वस्थ वायु मिलती रहे। वर्षाके दिनोंमें वह वन महोत्सवका आयोजन करवाता था। गुजरातमें फिरदौस और शअबान जैसे बाग इसी सुल्तानकी कलाके परिचायक हैं। उसने अपने शासन कालमें ६०,००० वृक्षोंको लगवाया और उन्हें सुरक्षित रखा। आधुनिक युगमें बढ़ता वायु प्रदूषण, मिट्टीका प्रदूषण, तापीय प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, शहरी प्रदूषणके कारण बढ़ता जलवायुका बदलाव ग्लोबल वार्मिंग हमें आगाह भी कर रहे हैं कि पृथ्वीपर हरियाली समाप्त हो रही है। पर्यावरणके प्रति जागरूकता और पृथ्वीको प्रदूषित होने बचाना ही विकासकी यात्राकी कुशलता होगी वरन् हमारा अस्तित्व भी खतरेमें रहेगा। आज हमारे जीवनमें प्लास्टिकका उपयोग प्रकृति और मानवके लिए घातक है। प्लास्टिकसे नुकसान पहुंचानेमें हम विश्वमें १५वें नम्बरपर हैं। हमारे रोजके जीवनमें प्लास्टिकका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम अपनी सुविधा देख रहे हैं लेकिन यह प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्यके लिए अत्यंत घातक है। सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिकपर रोक लगा दी है जैसे प्लास्टिकके चम्मच खानेवाले कांटे। कागजके गिलास उसमे भी अंदर प्लास्टिककी कोडिंग होती है। प्लास्टिकको नष्ट नहीं किया जा सकता है और प्लास्टिक जलानेपर दिलकी बीमारी और अस्थमा होनेकी सम्भावनासे इनकार नहीं किया जा सकता है। रिसाइक्लिंग एक समाधान है। प्लास्टिककी पन्नीके बिना सब्जीवाले भी कहते हैं उनकी सब्जी नहीं बिकती है लोगोंको अपनी आदतें बदलनी होगी। प्लास्टिकसे पौलीफ्योल भी बनानेकी प्रक्रिया जारी है। जागरूकतासे हर समस्याका समाधान मिल सकता है। आज पृथ्वीके लिए जहर बन चुका प्लास्टिक वर्ष १९०७ में सिंथेटिक पालिमरसे सस्ती चीजोंको बनाया गया जो केवल एक सौ ग्यारह वर्षमें पृथ्वीको प्रदूषित करनेमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिब्बा बंद खानेकी सामग्री, प्लास्टिककी बोतलों और ग्लासका बढ़ता इस्तेमाल हमारे शरीरको रोगग्रस्त तो कर रहा है और कैंसर जैसे खतरनाक रोगोंसे भी ग्रसित कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषणकी भयावहता यहांतक पहुंच गयी है कि २०५० तक समुद्र और नदियोंमें मछलियोंकी जगह प्लास्टिक होगा। समुद्री नमकसे भी यह हमारे शरीरमें पहुंच रहा है। इस तरह ७५ प्रतिशत प्लास्टिकका कचरा आज प्रदूषणमें बदल गया है और रीसाइक्लिंग केवल दस प्रतिशत प्लास्टिककी होती है। इस तरह आज भारतका हर नागरिक जाने-अनजाने औसतन ३५० ग्राम गैर-जैविक कचरा पैदा कर रहा है, जिसमें ३० प्रतिशत केवल प्लास्टिकका ही कचरा है। यह आंकड़ा देखने-सुननेमें मामूली है लेकिन विशाल जनसंख्याके कारण यह बहुत व्यापक प्रदूषणकी चेतावनी दे रहा है। मानव आज धरतीका सबसे शक्तिशाली प्राणी है वह प्रदूषण भी बढ़ा रहा है तो प्रदूषणको कम करनेके मार्ग भी सुझा रहा है। सड़कोंके निर्माणमें इस प्लास्टिकके कचरेकी उपयोगिता खोजी गयी है और प्लास्टिकके कचरेमें डामर मिलाकर आज सड़कोंको बनानेका कार्य जारी है तो वहीं जागरूक नागरिकोंने मुंबई वर्सोवा बीचपर प्लास्टिकका कूड़ा हटाया तो वहां समुद्रके जीव बीस वर्ष बाद कछुए वापस लौटे हैं। हम आज वनोंको काटकर वहां भी मानवीय आबादीको बसा रहे हैं तभी तो जंगली जानवर हाथी तेंदुए, शेर हमारे घरोंमें घुसकर हमारी समस्याओंको बढ़ा रहे हैं। जीवनके प्रत्येक श्रेत्रमें बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहा है जागो वरन् जीवनका अंधकार जीने नहीं देगा। आज हमारी सरकार एक व्यक्ति एक वृक्ष योजनाको सफल बनानेमें सक्रिय है लेकिन वृक्ष लगानेके साथ उसकी सुरक्षाकी जिम्मेवारी भी हमें लेनी होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिका योगदान आवश्यक है। सफाई, सुरक्षा, स्वच्छतासे जुड़े मुद्दे तो इक्कीसवीं सदीमें हमारा मिशन होने चाहिए। किन्तु पर्यावरणके प्रति बढ़ती उदासीनता बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रमें फैली गंदगी तथा प्रशासनकी बेरुखीसे हम वापस अज्ञानी और गैर-जिम्मेदार घोषित हो गये हैं। आज हर चीज प्लास्टिक बंद उपलब्ध है, हर व्यक्ति अपनी सहूलियत और सुविधाओंको देख रहा है। चीनकी राजधानी बीजिंग २०१२ में बेहद प्रदूषित थी लेकिन योजनाबद्ध और सामूहिकतासे प्रदूषणमें कमी लायी गयी। कचराके रिसाइकिल प्लांट आज हर शहरकी जरूरत बन गये हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

2047 तक भारत के विकास के लक्ष्य पर वोट दें

संजय गोस्वामी

यह नई पीढ़ी का भारत है जहाँ केवल प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए जगह है आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है विजन इंडिया@2047 योजना, जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया है, पर पिछले दो वर्षों से कार्य चल रहा है वर्ष 2047 तक, भारत एक विकसित राष्ट्र की सभी विशेषताओं के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह एक विकसित भारत होगा, जिसके लिए हमारे युवाओं और महिलाओंको महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण सभी दलों के लिए जनादेश का भुनाने मशाला बन गया है आरक्षण के लिए हर पार्टी के अलग-अलग घोषणापत्र होते हैं, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बंधा हुआ है।18वां जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जी-20 में भारत की मेजबानी में थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य; भारत वसुधैव कुटुम्बकम् (विश्व एक परिवार है)के अन्तर्निहित दर्शन को पूर्णतः अभिव्यक्त किया । यह भारत के साथ अन्य सभी विकसित राष्ट्र विभिन्न जी-20 देशों के प्रतिनिधित्व नेतृत्व का मार्गदर्शन किया है जी-20 के नेतृत्व में, देश में,ग्लोबल वार्मिंग, भोजन और ऊर्जा की कमी,आतंकवाद, भूराजनीतिक संघर्ष और डिजिटलअंतर सहित विभिन्न आकस्मिकताएँ दुनिया को स्थिति से निपटने के लिएभारत के प्रयास और वर्तमान स्थितिमें भारत को ?ई दिशा मिली कृपया ड्रीम 2047 में भारत को देखें, 2047 में भारत को महाशक्ति बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिक्की ने भारतीय बिजनेस कंपनी के साथ एक बहु-विषयक पहल शुरू की है-2022 में भारत की विकास क्षमता के लिए कार्य योजना। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत 2047 तक 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, जिससे वार्षिक वृद्धि के साथ एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इस वृद्धि से 60 करोड़ रुपये की नौकरियाँ पैदा होने और प्रति व्यक्ति आय में दस लाख रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को चार प्रमुख क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए-विनिर्माण में नवाचार, एसएमई विस्तार, कौशल विकास और पूंजी बाजार को मजबूत करना। नवाचार प्रौद्योगिकी आधारित होना चाहिए, बल्कि लागत या गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा पर होना चाहिए। 2024-25 के हालिया अंतरिम बजट में उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई, जो भारत में विकास एक सकारात्मक पहल है। विकास के लिए इन क्षमताओं का प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोग आवश्यक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई का विस्तार भी महत्त्वपूर्ण है। उभरती अर्थव्यवस्था प्रणालियों में भारत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का प्रति बिलियन डॉलर मध्यम और बड़े आकार की कंपनियों की संख्या लगभग दोगुना है। अकाउंट एग्रीगेटर और ओपन क्रेडिट जैसे लोग इनेबलमेंट नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं डिजिटल ऋण देने से सम्बंधित उपायों से कम लागत पूंजी तक पहुँच सुनिश्चित

करना और एमएसएमई पर विनियामक और अनुपालन सम्बंधित बोझ को कम करने के लिए काम करें कर दी गई। अगले दशक में और अधिक मध्यम स्तर सहित बहुत कुछ किया जाएगा उद्योग को एमएसएमई दायरे से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें प्रोत्साहन भी शामिल है 3. निर्माण जैसे रोजगारोन्मुख क्षेत्रों में भारत की वृद्धि बढ़ती हुई शक्ति पर फोकस करना है। भारत की जनसांख्यिकी के अनुसार इस मानव पूंजी को आधुनिक और में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है भविष्य के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली से सुसज्जित करके ही उठाया जा सकता है। 4. भारतीय व्यवसायों के लिए पूंजी की कम लागत और किफायती वित्तकोष की आवश्यकता है। हमारे पास एक व्यापक वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र है जिसका तेजी से विकास हो रहा है। तथापि, प्रमुख ऋण दरों को कम करने के लिए एम.एस.एम.ई पूंजी तक पहुँच प्रदान करने के लिए रचनात्मक उपाय अनुबंधों और विवादों को लागू करने के लिए समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आवश्यकता है। 5. फिक्की का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित करना है उद्योग के सदस्यों को एहसास करने के लिए साथ ही सरकारों के प्रमुख नीति निमार्ता भी साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत की आर्थिक क्षमता विश्व भर में विख्यात मान्यता है। हम वैश्विक विनिर्माण का हिस्सा हैं और साथ ही दुनिया का भोजन का कटोरा बन गया सेवाओं के नेता भी हो सकते हैं। फिक्की का मानना है कि 2047 तक अमृत काल के दौरान अपने देश में अभूतपूर्व विकास के गवाह बनेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीद है कि 2024 में मतदाता अपने कीमती वोटों का सोच-समझकर इस्तेमाल करेंगे। यह भी अपेक्षा की जाती है कि शत-प्रतिशत मतदाता चुनाव में भाग लेंगे, वे न केवल चुनाव में भाग लेंगे बल्कि अपने अमूल्य वोट का उपयोग सचेत होकर करेंगे तथा स्वार्थ, मुनाफाखोरी, लालच, धर्म-जाति की भावनाओं से दूर रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कुछ स्वार्थी लोगों के कारण दिन-प्रतिदिन तानाशाही बनता जा रहा है। गणतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें प्रजा पर शासन करने वाला कोई राजा या रानी नहीं बल्कि जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। लेकिन आज कुछ राजनेताओं ने इस परिभाषा को बदल दिया है, अब देश तानाशाही बन गया है। जागरूक होकर राजनीतिक आधार पर चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर व्यवस्था के आधार की खामियों को दूर करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इसे खत्म करने का प्रयास करके भी किया जा सकता है। अगर मतदाता हर चुनाव में जाति-धर्म की भावना से बहकर अपना कीमती वोट डालते हैं तो ऐसा करके वे व्यवस्था को कमजोर करते हैं। हम न केवल अपना भविष्य बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करते हैं, क्योंकि अगर चुनाव के समय किसी गलत उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, तो ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपने निजी हितों को पूरा कर सकता है। वह केवल पाँच विश्व मूल्यों को ही सर्वोपरि रखता है, आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की उसे कोई परवाह नहीं है। इसलिए हर चुनाव में प्रत्येक मतदाता को समझदारी से मतदान करते समय सही उम्मीदवार का चयन कर अपने राज्य और देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा उसे अगले पांच साल तक पछतावे का सामना करना पड़ेगा। कुछ हासिल नहीं होगा। हर चुनाव के दिन लोग अपने लिए कोई महंगी चीज खरीदने में उतनी सावधानी नहीं बरतेंगे, जिसके बारे में वे विज्ञापनों की चकाचौंध में आने से पहले सोचेंगे भी नहीं। जो सामान नहीं चुनता उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। माना कि कुछ राजनेताओं के बुरे कर्मों, राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों की अवसरवादी एवं सिद्धांतहीन नीतियों के कारण कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। राजनीति से उठ गये हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास है अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कोई फर्क. नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, पानी की एक बूंद से भी घड़ा भर जाता है। मतदान अवश्य करना चाहिए, मतदान के माध्यम से भ्रष्ट और दागी नेताओं को भी सबक सिखाया जा सकता है। युवाओं को देश की राजनीति के उज्ज्वल भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और साथ ही अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों को सोच-समझकर मतदान करने के लिए जागरूक करना चाहिए। हमारी स्थिति में आज भी विशेषकर गांवों में महिलाएँ अपने बुजुर्गों की सलाह पर अपने मत का प्रयोग करती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह नई पीढ़ी का भारत है जहाँ केवल प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए जगह है आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं है विजन इंडिया@2047 योजना, जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया है, पर पिछले दो वर्षों से कार्य चल रहा है वर्ष 2047 तक, भारत एक विकसित राष्ट्र की सभी विशेषताओं के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह एक विकसित भारत होगा, जिसके लिए हमारे युवाओं और महिलाओंको महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

संपादकीय

युद्ध नहीं शांति

इस्त्राइल ने दक्षिणी गाजा के शहर राफा में सैनिक अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने सोमवार रात को राफा में हवाई हमले किए जिनमें 23 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस सैन्य कार्रवाई के बाद इस्त्राइल और फिलिस्तीन के बीच संभावित युद्ध-विराम के रास्ते बंद हो गए हैं। हैरानी की बात है कि इस्त्राइल के पैरोकार अमेरिका की अनिच्छा और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के विरोध के बावजूद इस्त्राइल गाजा को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर. इस्त्राइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शांति की राह छोड़कर युद्ध के पथ पर चलने की ताकत और प्रेरणा कहां से मिल रही है। करीब आठ महीने से चल रहे इस युद्ध के बारे में कहा जा सकता है कि इस्त्राइल अब आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति में बढ़त बनाने के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन इस्त्राइल ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया कि इससे उसकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं। गाजा पट्टी के शहर राफा में करीब 14 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं जो इस्त्राइल के ताजा सैन्य अभियान से डरे और सहमे हुए हैं। इनका जीवन संकटग्रस्त है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी है कि राफा में जमीनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी लेकिन इस्त्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने अपने कान बंद कर रखे हैं। इस्त्राइल के सैनिक अभियान से जाहिर होता है कि वह इसके जरिए अपने बंधकों को रिहा कराना और हमास के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है। हालांकि सैन्य कार्रवाई के जरिए बंधकों की रिहाई आसान नहीं है। हकीकत यह है कि इससे बंधकों की जान को खतरा पहुंच सकता है। वास्तव में युद्ध-विराम और शांति समझौते के रास्तों पर आगे बढ़कर ही बंधकों की सुरक्षित रिहाई संभव है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हर समस्या का हल सैनिक अभियान नहीं हो सकता। आक्रामक सैनिक अभियान से गाजा के मासूम नागरिक ही मारे जाएंगे। अब तक करीब 35 हजार नागरिक मारे गए हैं। इस्त्राइल को अपने गॉड फादर अमेरिका से सबक लेना चाहिए कि उसे आखिरकार, अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी क्यों करनी पड़ी। वियतनाम के साथ लड़ाई में उसे क्या हासिल हुआ। बंदूक की गोली से नहीं शांति वार्ता की मेज से ही समस्या का हल निकलेगा। यह सार्वभौमिक सत्य है, जिसे समझा जाना चाहिए।

चिंतन-मनन

काम में तल्लीनता

एक साधक से पूछा गया-आप साधना करते हैं? उसने कहा, जब भूख लगती है, तब खा लेता हूं और जब नींद आती है, तब सो जाता हूं। यही है मेरी साधना। उसने कहा, बड़ी सीधी बात है। यह तो मैं भी कर सकता हूं। साधक से कहा, अच्छा आओ, भोजन करें। दोनों भोजन करने बैठे। भोजन पूरा हुआ। साधक ने पूछा, भोजन कर लिया? हां, कर लिया।
क्या खाया?
रोटी, शाक, चावल और मिठाई।
केवल भोजन ही किया या कुछ स्मृति और कल्पना भी की? भोजन करते-करते अनेक स्मृतियां सामने आ गई। मीठी-मीठी कल्पनाएं भी कीं। भोजन यंत्रवत चलता रहा और मैं उन स्मृतियों और कल्पनाओं में डूबता रहा। परोसी हुई थाली खाली हो गई। हाथ धोकर उठ खड़ा हुआ। साधक ने कहा, भाई! तुमने भोजन कहां किया? भोजन कहां खाया? तुमने तो स्मृतियां खाई हैं, कल्पनाएं खाई हैं, विचार खाया है, रोटी और मिठाई कहां खाई
केवल रोटी और मिठाई खाना बहुत कठिन होता है। आदमी विचार खाता है, कल्पना खाता है। आयुर्वेद का एक सूत्र है, तन्मना भुजीत- भोजन करते समय इसी बात का ध्यान रहे कि मैं भोजन कर रहा हूं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से कही हुई बात है, किन्तु साधना की दृष्टि से यह और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। साधक जो काम करे वह उसी में तन्मय बन जाए अन्यथा व्यक्तित्व खण्डित हो जाता है। डुयल पर्सनेलिटी खतरनाक होती है। जहां खंडित व्यक्तित्व होता है, वहां कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता।

भगवान विष्णु के अवतार है चिरंजीवी परशुराम!

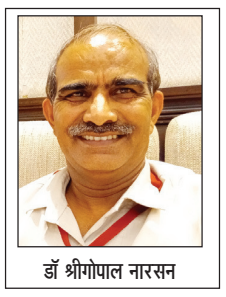

डॉ श्रीगोपाल नारसन

भगवान विष्णु के अवतार है चिरंजीवी परशुराम,जो श्रीराम युग में भी थे और श्रीकृष्ण के समय भी मौजूद रहे, आज भी उन्हें जीवित यानि चिरंजीवी माना जाता है।भगवान परशुराम ने ही भगवान श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। महेंद्रगिरि पर्वत भगवान परशुराम की तपस्या स्थली रहा है।कहते है कि एक बार भगवान गणेश ने परशुराम को शिव दर्शन करने से रोक दिया था, जिससे रुष्ट होकर परशुराम ने गणेश जी पर अपने फरसे से प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया था और वे एकदंत हो गए। त्रेतायुग में सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर भी वे नाराज हो गए थे ,हालांकि बाद में उन्होंने श्रीराम का सम्मान भी किया था।
द्वापर युग में परशुराम ने असत्य वचन के लिए दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत होने का श्राप दे दिया था।उन्होंने ही भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी।भगवान परशुराम को
विष्णु का छठा अवतार माना जाता है।जबकि श्रीराम सातवें अवतार थे। भगवान परशुराम का जन्म 5142 वि.पू. वैशाख शुक्ल तृतीया के प्रथम प्रहर में हुआ था। इनका जन्म सतयुग और त्रेता का संधिकाल भी माना जाता है। भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग के समय में हुआ था।उनकी जन्म तिथि अक्षय तृतीया होने कारण इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है।
साहित्यकार शिवकुमार सिंह कौशिकेय द्वारा किये गए शोध के तहत परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के शासकीय बलिया गजेटियर में परशुराम का चित्र सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध होना बताया गया है।
एक किंवदंती में मध्यप्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जानापाव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म होना बताया गया है। यहां पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम है। कहते हैं कि प्रचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थीं।
एक अन्य मान्यता में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गांव में स्थित एक शतमहला है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थीं और भगवान परशुराम को उन्होंने यही जन्म दिया
वही शाहजहांपुर के जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम से करीब दो किलोमीटर पूर्व दिशा में हजारों साल पुराने मन्दिर के अवशेष मिलते हैं जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। महर्षि ऋचीक ने महर्षि अगत्स्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगत्स्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश मे धर्म प्रचार का कार्य करने लगे। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विद्वता पर इतना मोहित हुआ कि उसने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह इनसे कर दिया। इन्ही रेणुका के पांचवें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद धर्म प्रचार का कार्य बन्द कर दिया और राजा गाधि की स्वीकृति लेकर इन्होंने अपना जमदग्नि आश्रम स्थापित किया और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं रहने लगे। राजा गाधि ने वर्तमान जलालाबाद के निकट की भूमि जमदग्नि के आश्रम के लिए चुनी थी। जमदग्नि ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनवाई थी आज उस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन मन्दिर बना हुआ है जो आज ढकियाइन देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है। भगवान परशुराम के लिए जहां अपने पिता की आज्ञा सर्वोपरि रही वही वे अपने क्रोध व शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते है।कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने पराक्रम से नदियों तक की दिशा मोड़ दी थी।ऐसे बलशाली और पराक्रमी है भगवान परशुराम।
(लेखक आध्यात्मिक चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार)

क्षमता विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलें

भारत उन देशों में है जहां जनसंख्या के आयु वर्गीकरण के आधार पर युवा शक्ति का प्रगति में अधिक योगदान अपेक्षित है। इन संभावनाओं को भरपूर प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि युवाओं को इस प्रगति के अनुकूल अपनी क्षमता विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलें। इसके लिए शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर तो जरूरी हैं ही, पर इसके साथ युवा सोच को ऐसी दिशा देना भी जरूरी है जो सामाजिक आर्थिक प्रगति के अनुकूल हो। यह इस समय और भी जरूरी हो जाता है जब युवाओं के सामने तरह-तरह के अनिश्चय की स्थितियां उपस्थित हैं। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और योग्यता तथा अपेक्षा के अनुकूल रोजगार न मिल पाने की समस्या है। दूसरी ओर, कुछ अन्य स्तर पर भी अनिश्चय और भटकाव है। आखिर, ऐसी क्या बात है कि पंजाब-हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में भी अनेक खाते-पीते परिवारों के युवक भी किसी तरह विदेश जाने से ही अपनी उम्मीदें जोड़ कर बैठ गए हैं। डंकीइ मार्ग के अनेक खतरों को उठाना मंजूर है, इसके लिए परिवार को कर्जग्रस्त होना मंजूर है, पर विदेश जाना एक जिद बन गई है जबकि आसपास के परिवेश से जुड़कर एक बेहतर जीवन तलाशने का विकल्प स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की स्थितियों से लगता है कि एक ओर शिक्षा और रोजगार की स्थिति से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य तरह का भटकाव और अनिश्चय भी है। इस कारण अनेक तनाव भी बढ़ सकते हैं और नशे जैसी तबाही की ओर झुकाव बढ़ सकता है। इन समस्याओं के बीच समाधान की एक बड़ी राह यह है कि कुछ बुनियादी मूल्यों और प्रतिबद्धताओं को युवाओं में प्रतिष्ठित किया जाए और उनकी सोच को इसके अनुकूल बताया जाए। यह सच है कि अधिकांश युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका की सोच प्रमुख है, पर आगे चुनौती यह है कि इसके साथ एक बेहतर समाज बने और युवाओं को इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका में कैसे जोड़ा जा सकता है। युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि छात्र जीवन से ही वे इस बारे में अधिक सोचें कि उनकी प्रतिभाएं अधिक विकसित किस क्षेत्र में हो सकती हैं और किस तरह आसपास के समाज से जुड़ सकती हैं। इस तरह उनकी रचनात्मकता कहीं बेहतर ढंग से उभर सकेगी और समाज की भलाई से भी जुड़ सकेगी। इस पर अनेक युवा कहेंगे कि इस तरह की नौकरी न मिले (जिसमें अपनी रचनात्मक प्रतिभा और समाज की बेहतरी का मिलन हो) तो क्या करें। केवल नौकरी ही सब कुछ नहीं है, स्वरोजगार की भी अनेक संभावनाएं हैं, मित्रों-साथियों के साथ मिल कर भी कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। जरूरत इस बात की है कि इस बारे में खूब सोच-विचार करें, जांच पड़ताल करें, अध्ययन करें और मित्रों, साथियों, अनुभवी व्यक्तियों, अभिभावकों से विमर्श करें कि अपनी प्रतिभा, क्षमता और सामाजिक भलाई के मिलन के आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए। यदि डाक्टर बनना है तो निर्धन लोगों की सेवा में अधिक जुड़ा जाए, यदि अध्यापक बनना है तो शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाएं, यदि पंचायत सदस्य बनना है तो पूरे गांव की भलाई से जुड़ा जाए, यदि किसान बनना है तो पर्यावरण की रक्षा वाली खेती की जाए। यह प्रक्रिया अपने आप इतनी रचनात्मक है कि इसमें गुजरते हुए ही युवाओं की क्षमता और समझ बहुत बढ़ती है और वे बेहतर इंसान भी बनने लगते हैं। इस सोच और विमर्श से गुजरते हुए ही युवाओं की अपने वर्तमान और भावी जीवन के बारे में कुछ ऐसे संकल्प बना लेने चाहिए जो उन्हें बेहतर जीवन और समाज की राह पर चलने में बहुत मदद करेंगे। पहली बात तो यह है कि सभी तरह के नशे से दूर रहने का संकल्प कर लिया जाए। अपने स्तर पर तो यह कर ही लिया जाए और हो सके तो नजदीकी मित्रों और साथियों को साथ लेकर भी यह संकल्प कर लिया जाए। शराब ड्रग्स, सिगरेट-बीड़ी, गुटका आदि सभी तरह के नशों को जीवन भर के लिए त्याग देना चाहिए। खान-पान, आचार, व्यवहार सभी में बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी बड़ा संकल्प प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां आती रहती हैं। सुरक्षा का, किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना से बचाव का अपने और परिवार के स्तर पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। युवाओं को अपने परिवार की भलाई से भरपूर जुड?ा चाहिए। आगे उनका विवाह होता है, तो अपने नये परिवार के प्रति पूरी निष्ठा जीवन भर रखनी चाहिए। युवाओं के लिए यह विशेष तौर पर जरूरी है कि महिलाओं का पूरा सम्मान करें और अपनी पत्नी (या किसी भी अन्य महिला के प्रति) कभी भी हिंसा या अत्याचार न करें। अच्छे पारिवारिक जीवन से एक बुनियाद तैयार होती है तो जीवन-पथ पर सदा सहायक होती है। अपने मित्रों, सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, विास और आपसी सहयोग के संबंध बनाए रखना भी लगभग इतना ही जरूरी है। तरह-तरह की फिजूलखर्ची से बचना चाहिए, केवल भेड़-चाल में आ कर अनाप-शनाप खर्च नहीं करना चाहिए और अपनी तथा परिवार की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ बचत करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी और न्याय के लिए प्रतिबद्धता जीवन में आरंभ से बना लेनी चाहिए और किसी भी अपराध और जुए जैसी बुराइयों के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया में यह समझ बना लेना बहुत जरूरी है कि इनका सही उपयोग क्या है और अनुचित उपयोग क्या है। अनुचित उपयोग से यथासंभव दूर रहना चाहिए। अपने भीतर की हिंसक प्रवृत्तियों को, क्रोध और हिंसा को प्रयास कर दूर करना चाहिए तथा अमन-शांति तथा अहिंसा की राह पर जीवन भर चलना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, रंग आदि के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव से दूर रहना चाहिए और सभी इंसानों की समानता, सभी धर्मों के सम्मान में गहरा विास रखना चाहिए। न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, पर इसके लिए आपसी एकता से अपने को मजबूत भी बना लेना चाहिए। ये कुछ ऐसे जीवन-मूल्य हैं जिन्हें अपना लिया जाए, या जिन्हें अपनाने का निरंतरता से प्रयास किया जाए, तो एक ऐसे जीवन की बुनियाद तैयार हो जाती है, जिससे अपनी प्रतिभाओं और रचनात्मकता को समाज की भलाई से अधिकतम जोड़ा जा सकेगा। कल्पना कीजिए, यदि बढ़ती संख्या में युवक-युवतियां, छात्र-छात्राएं अपने भावी जीवन के बारे में इस तरह सोचने लगें तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। युवा ही हमारे समाज की सबसे बड़ी संपत्ति है, देश और समाज का भविष्य उनके ही हाथों में है। अतः आज के तरह-तरह के भ्रम और भटकाव के बीच उनके लिए जीवन की सही विद्या प्राप्त करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और इस महत्त्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी की हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

– भारत डोगरा

प्रधान संपादक : राघवेंद्र, पटना कार्यालय : रामनगरी आशियाना रोड, पटना/रांची कार्यालय: 201 मानस भवन,कांके रोड, रांची। संपर्क : 7488117482...

झूठ फैलाने का आरोप

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पूर्व तथा वर्तमान कुलपतियों समेत तकरीबन दो सौ शिक्षाविद् ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है जिसमें उनके एक बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस खुलीचिट्ठी में विश्वविद्यालय के प्रमुख पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर कांग्रेस नेता पर झूठ फैलाने का आरोप है। राहुल के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने दावा किया कि कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी है जिसमें योग्यता, विद्वत विशिष्टता और निष्ठा के मूल्य समाहित हैं। यह विवाद राहुल के आरोप के बाद पैदा हुआ। उनके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति में हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता प्रमुख आधार है। यह विवाद ऐसे वक्त पैदा हुआ है, जब लोक सभा के चुनाव चल रहे हैं। कहना गलत नहीं है कि कुलपतियों की नियुक्ति सत्ताधारी दलों के हितों पर ही केंद्रित रही है। कुलपति ही नहीं, शिक्षकों के चयन में भी वैचारिक झुकाव को प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी शैक्षणिक संस्थानों के उच्च पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि निजी राय को सार्वजनिक करने से बचें। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पूर्व आरोप लगते थे कि वामपंथी विचारधारा वालों को तरजीह दी जाती है। चुनाव के दरम्यान राजनीतिक दल और राजनेता एक-दूसरे पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। यह लोकतंत्र है, यहां सारा इख्तियार जनता जनार्दन के हाथ में होता है। बावजूद इसके समझदारी यही है कि सार्वजनिक रूप से कमर के नीचे वार करने से बचा जाए। जब तक हाथ में किसी तरह के साक्ष्य न हों, आरोप-प्रत्यारोप से बचने का प्रयास होना चाहिए। बीते हफ्ते ही एक नामी निजी विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन मखौल बन गया। हमारे शिक्षण संस्थान अपना स्तर उठाने की बजाय बेतुके कारणों से चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। यदि संस्थानों के शीर्ष पदाधिकारी अपने सम्मान की रक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो छात्रों के समक्ष बेहतरीन उदाहरण पेश करने में असफल कहलाएंगे परंतु अपवादस्वरूप इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई है और इन उच्च और सम्मानित पदों के बंटवारे में पक्षपात हुआ है, तो यह नौजवानों को गलत संदेश देने वाला साबित हो सकता है।

भारत में गरीबी उन्मूलन पर पूर्व में गम्भीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया

आरती कुमारी

भारत में हाल ही के वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में आई भारी कमी के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विकसित देशों के कई वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों ने भारत की आर्थिक नीतियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। यह सब दरअसल भारत में तेज गति से हुए वित्तीय समावेशन के चलते सम्भव हुआ है। याद करें वर्ष 1947, जब देश ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय देश की अधिकतम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर थी। जबकि, भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। परंतु, पहिले अरब से आक्रांताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा तथा देश के नागरिकों को गरीबी की ओर धकेल दिया। भारत में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से 'गरीबी हटाओ' के नारे तो बहुत लगे परंतु, गरीबी नहीं हटी। 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ राजनैतिक दलों ने कई बार सता हासिल की किंतु देश से गरीबी हटाने के गम्भीर प्रयास शायद कभी नहीं हुए और गरीब वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ष 2014 में लागू किया गया जिसके माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (Direct Benefit Transfer Scheme) को भी लागू किया गया जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि को सीधे ही हितग्राहियों के बचत खातों में जमा कर दिया जाता है। इससे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 100 प्रतिशत लाभ की राशि सीधे ही उनके हाथों में पहुंच जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013 के बाद से 31 मार्च 2022 तक, 24.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे ही लाभार्थियों के बचत खातों में जमा की जा चुकी है, इसमें अकेले वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 6.3 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के बचत खातों में हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 2014 के पूर्व तक जब इन लाभार्थियों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में नहीं खुले थे तब तक कांग्रेस एवं अन्य सरकारों के शासनकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि सामान्यतः नकद राशि के रूप में इन लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी। आपको शायद ध्यान होगा कि एक बार देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि के एक रुपए में से केवल 16 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंच पाते हैं। शेष 84 पैसे इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र की जेब में पहुंच जाते है। अब आप स्वयं आंकलन करें कि यदि बैंक में 50 करोड़ लाभार्थियों के बचत खाते नहीं खुले होते और यदि उक्त वर्णित केवल 8 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को नकद राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती तो इन लाभार्थियों के पास केवल 4 लाख करोड़ रुपए की राशि ही पहुंच पाती एवं शेष 21 लाख करोड़ रुपए की राशि इन योजनाओं को चलाने वाले तंत्र के पास ही रह जाती। अब आप आगे एक और कल्पना कर लीजिये कि पिछले 70 वर्षों के दौरान कितनी भारी भरकम राशि इन गरीब हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। इस राशि का आकार शायद आपकी कल्पना से भी परे है। सहायता की यह राशि यदि गरीबों तक पहुंच गई होती तो शायद हो सकता है कि देश से अभी तक गरीबी भी दूर हो चुकी होती। अब जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत सहायता की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे ही पहुंच रही है तो देश से गरीबी भी तेजी से कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त कंठ से हो रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों के माध्यम से इस दृष्टि से बहुत ठोस कार्य किया गया है। न केवल 50 करोड़ से अधिक बचत खाते विभिन्न भारतीय बैंकों में खोले गए हैं बल्कि आज इन बचत खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जमा हो गई है और बचत की यह भारी भरकम राशि बैंकों द्वारा देश के आर्थिक विकास में उपयोग की जा रही है। इस प्रकार, भारत का गरीब वर्ग भी इन बैंक खातों के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त 50 करोड़ से अधिक बचत खातों में 50 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, अर्थात अब भारतीय महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं सहित, भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। भारी मात्रा में खोले गए इन बचत खातों के माध्यम से गरीब वर्ग के नागरिकों का बैंकिंग सम्बंधी इतिहास भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जिससे इस वर्ग के नागरिकों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होने लगी है। केंद्र सरकार द्वारा बैकों के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का लाभ भी अब गरीब वर्ग को मिलने लगा है। कोरोना महामारी के तुरंत बाद जब देश में स्थितियां सामान्य बनने की ओर अग्रसर हो रहीं थीं तब केंद्र सरकार ने खोमचा वाले, रेहड़ी वाले एवं ठेलों पर अपना सामान बेचकर छोटे छोटे व्यवसाईयों द्वारा अपना व्यापार पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक विशेष ऋण योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत उक्त वर्णित छोटे छोटे व्यवसाईयों को बैंक द्वारा आसानी से ऋण प्रदान किया गया था क्योंकि इस वर्ग के नागरिकों के पूर्व में ही बैकों में बचत खाते खुले हुए थे। बैकों द्वारा यह ऋण बगैर किसी व्यक्तिगत गारंटी के प्रदान किया गया था। और, हजारों की संख्या में छोटे छोटे व्यवसाईयों ने निर्धारित समय सीमा में इस ऋण को अदा कर, पुनः बढ़ी हुई राशि के ऋण बैकों से लिए थे और अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाया था। बैकों में खोले गए बचत खातों से गरीब वर्ग को इस प्रकार के लाभ भी हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैकों से नहीं जुड़े थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रेल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

कांग्रेस का लगातार भट्टा बैठाने के बाद सैम पित्रोदा को आखिर हटना पड़ा

अशोक भाटिया

अपनी नस्लवादी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सैम पित्रोदा ने बुधवार को अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनके इस फैसले को सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार नहीं था कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की हो इसके पहले भी अपने विवादास्पद बयान से वे कांगेस का भट्टा बैठा चुके है व बाद में कांग्रेस को उन बयानों पर लीपा पोती करके अपने को संभालना पड़ा है । अक्सर राहुल गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले पित्रोदा ने हालिया बयान में कहा कि भारत के पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया , जिसमें वह भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना इस तरह करते नजर आ रहे हैं जिससे कोई भी नाराज हो सकता है।पित्रोदा कहते हैं कि 'भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई-बहनें हैं। वे कहते हैं कि हम अलग-अलग भाषाओं, धर्मों और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है, जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा-बहुत समझौता करता है।' देखा जाए तो यह बहुत सामान्य सी बात है। हम लोग आम जीवन में इस तरह की तुलनात्मक बातें करते रहते हैं। पर जब कोई शख्स आम के बजाय खास बन जाता है तो उसकी बातचीत के कई मतलब निकाले जाते हैं। और जब चुनाव चल रहे हैं और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक के जिम्मेदार सदस्य हैं तो आपकी जवाबदेही और बनती है कि आप क्या बोल रहे हैं? शायद यही कारण है कि सैम पित्रोदा का बयान वायरल होते ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 'आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है, जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं।' आखिर प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर हमला करने का मौका किसने दिया? इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में संपदा के पुनः वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सकते में आ गई। पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल, भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का। भाजपा ने 5 साल में क्या किया, उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किनारा करना पड़ा और पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं। कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती? क्योंकि यह बार-बार देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक गलती करने वाला बार-बार वैसी ही गलतियां करता है। उन गलितयों को पार्टी उनका व्यक्तिगत मामला मानकर पल्ला झाड़ लेती है। यह भी कहती है कि उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है। पर बाद में ऐसे शख्सियत जब पार्टी में पुरस्कृत होते हैं तो संदेह होना लाजिमी हो जाता है। एक उदाहरण दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह लगातार आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जताने के जाने जाते हैं। कभी ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद के नाम के आगे जी लगाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। इसी तरह उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर में भी मारे गए आतंकियों के लिए संवेदना जताई थी। हर बार वो इस तरह की गलतियां करते रहे हैं पर उनपर कोई एक्शन भी नहीं होता। अब लोकसभा टिकट से उन्हें उनकी गलतियों के लिए पुरस्कृत किया गया है।जाहिर है कि ऐसा ही विजय वेडट्टियार और चरनजीत सिंह चन्नी के साथ भी है। चरनजीत सिंह चन्नी ने एयरफोर्स हमले को ही फॉल्स ऑपरेशन की संज्ञा दे दी। विजय वेडट्टियार ने कसाब को निर्दोष करार दे दिया। इस तरह की बातें करने वालों पर कोई एक्शन नहीं होने से कई बार ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस में यह सब एक योजनाबद्ध तरीक से तो नहीं होता।क्योंकि दूसरी पार्टियों में इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत दंडित कर दिया जाता है। पित्रोदा केस में ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया है पर उन्हें दंडित नहीं किया गया है। ये बात खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कही है कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है पर उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है। मतलब सीधा है कि कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया है पित्रोदा खुद अलग हो गए हैं। कांग्रेस में अकसर ऐसा देखा गया है कि किसी खास मुद्दे पर ठीके एक दूसरे से विरोधी विचार सामने आते हैं। और एक साथ आते हैं। द्रमुक नेता उदयनिधि मारन के सनातन को डेंगू मलेरिया कहने के बाद कांग्रेस में एक साथ कई विचार आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे को उदयनिधि मारन की बातों में कोई बुराई नहीं दिखी। पर ठीक उसी समय मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका खंडन किया। देशभर में दर्जनों ऐसे नेताओं के बयान आए जो मारन की बातों से यकीन नहीं रखते थे। तो बहुत से लोगों ने सीधे मारन और खरगे को सपोर्ट किया। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी पार्टी में अलग-अलग विचार सामने आते रहे। कोई समर्थन में था तो कोई इसके विरोध में । कोई भी पार्टी इस तरह के विचारों पर एक मत नहीं है तो निश्चित है कि उसके समर्थकों में कन्फ्यूजन पैदा होगा। पर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इस तरह एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार करके सभी विचार वालों को पार्टी चुनावों में साध लेगी। पर जब जनता के सामने विकल्प को रूप मे ऐसी पार्टियां रहेंगी जो एक विचार पर पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं तो जनता ऐसे ढुलमुल विचार वाले के साथ क्यों जाएगी। यह सही है कि लोकतंत्र में एक आदर्श स्थिति यह है कि पार्टी के अंदर सभी लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हो। इस लिहाज से देखा जाए तो यह सही है। पर विचार स्वतंत्रता के नाम पर पार्टी के मूल विचारों से अलग होने की स्वतंत्रता तो नहीं ही दी जा सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में पार्टी के अंदर विचारों की स्वतंत्रता दे जाती है। पर पार्टी की मूल विचारधारा को जब कोई पार करने लगता है तो उसे पार्टी से अलग ही होना होता है। जैसे कांग्रेस एक राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है।पर जब राष्ट्रवाद से इतर बात करने वाले या धर्मनिरपेक्षता को नकारने वाले लोग अपनी बात रखने लगते हैं उसे कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। पर कांग्रेस के अंदर ऐसा होता। इसलिए ऐसा लगता है कि छवि को लिबरल रखने के लिए नहीं बल्कि पार्टी में अनुशासन की कमी के चलते ऐसा होता है।

अपने ईष्ट को सड़कों पर नचाना कैसी श्रद्धा ?

मनोज कुमार अग्रवाल

इन दिनों भगवान के स्वरूपों को पंडालों शोभायात्रा संकीर्तन यात्रा में सड़कों पर नचाने का नया रिवाज चल निकला है क्या यही है हमारे अपने मान बिंदुओं के प्रति आस्था के प्रदर्शन का तरीका? यह क्या हो रहा है हमारे हिन्दू समाज को खासकर सनातन धर्म में जितनी मनमानी लोग कर रहे हैं शायद ही किसी अन्य धर्म के श्रद्धालु इस तरह की मनमानी भरी क्रियाकलाप करते हैं। आपको बता दें कि करीब छह सौ साल पहले 1486 में जन्मे चैतन्य महाराज ने भक्ति का नृत्य से समन्वय कर हिन्दू सनातन समाज को श्रद्धा भक्ति और आस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया था। भाव विभोर भक्तों का सुध बुध खो कर हरे कृष्णा का संकीर्तन करते हुए गांव गांव भक्ति की रसधारा का प्रवाह किया। आपको बता दें कि हमारे यहां भगवान श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित घटनाओं का रासलीला में चित्रण करने की परम्परा भी कई सौ साल पहले 1776 में शुरू हुई। शुरुआत में बृज क्षैत्र के मंदिरों धर्म शालाओं व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भगवान के रूप और गुण का गुण गाने करने के लिए रासलीला का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि हजारों वर्ष से मथुरा वृंदावन बरसानाबृज क्षेत्र में भगवान के धाम व लीला स्थलो को देखने के लिए श्रद्धालु देश भर से आते थे उन श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और आस्था की रसधार प्रवाहित करने के लिए मथुरा वृंदावन के गुसाईं ब्राह्मण परिवार भगवान के स्वरूप बना कर रासलीला दर्शाते थे कालांतर में यह रासलीला बृज क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकल कर देश भर में आयोजित की जाने लगी। रासलीला के दौरान भगवान कृष्ण राधा के पात्रों को झांकी पावन चरित्रों को आमजन तक पहुंचाने के लिए दर्शायी जाती थी मथुरा वृंदावन बरसाने के छल कपट से दूर सात्विक भोजन व मर्यादित आचरण करने वाले ब्राह्मण परिवार के सदस्य बच्चों समेत देश भर में घूम घूम कर रासलीला का मंचन करते। यही इन सैकड़ों हजारों परिवार की रोजी-रोटी जरिया था। फिर एक और दौर आया करीब ढाई सौ साल पहले 1860 में रामलीलाओं का आयोजन करने का सिलसिला शुरू किया गया।इस की शुरुआत चित्रकूट वाराणसी लखनऊ से हुई। तुलसी लिखित रामचरित मानस पर आधारित ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप रामलीला का चित्रण किया जाता था इस का उद्देश्य भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के पावन चरित्र के उदात्त प्रसंगों का चित्रण कर आम जनमानस को श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए आकर्षित करने का था धीरे-धीरे यह रामलीला आयोजन भारी विस्तार ले गए और श्री राम लीला उत्तर भारत के हर गांव कस्बे शहर में आयोजित की जाने लगी और धीरे-धीरे यह रामलीला आयोजन मेला बन गए। इसी दौरान करीब 50-60 साल पहले रामलीला के दौरान दर्शकों को मनोरंजन के लिए धनुष यज्ञ और राम बारात आदि में नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे इसके बाद तमाम गांव कस्बों की छोटी-बड़ी ज्यादातर रामलीलाओं में इस तरह का सिलसिला चल निकल की रामलीलाओं के मंचों पर नृत्य डांस के प्रोग्राम होने लगे इनमें कुछ स्थानों पर फूहड़ डांस भी किए जाने लगे। शुरू में पुरूष कलाकार ही महिला स्वरूप बना कर नृत्य पेश करते लेकिन धीरे-धीरे महिला कलाकारों को नृत्य के लिए बुलाया जाने लगा।अब स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि इन मेलों में बार बालाएं भी स्टेज पर डांस के लिए बुलाया जाने लगा। वही रासलीला में भगवान कृष्ण और राधा सुदामा सरीखे पात्रों को नृत्य करते दिखाए जाने लगा उधर बीते चार पांच दशक में माता के जागरण का आयोजन किया जाने लगा। शहर कस्बों में अनेक जागरण मंडलियों आरकेस्ट्रा ग्रुपों द्वारा फिल्मी गीतों की तर्ज पर माता के गुणगान का सिलसिला शुरू किया गया जो धीरे-धीरे भगवान के स्वरूप की झांकी और फिर स्वरूपों के नृत्य प्रस्तुतियों में तब्दील हो चला है इसी के साथ बीते दो दशक में माता के जागरण की तर्ज पर ही खाटू श्याम संकीर्तन भी बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने लगे हैं इन आयोजनों के साथ ही माता की चौकी बालाजी संकीर्तन के आयोजन निजी व संस्थाओं के माध्यम से बड़ी तादाद में हर शहर कस्बे में किए जाने लगे हैं। इस में कुछ भी बुरा नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भाव विभोर नृत्य वाली भक्ति अब सिर्फ मनोरंजन और दिखावे वाले मनमाने नृत्य में बदल गई है यह सिलसिला तमाम रथ यात्राओं और दूसरे धार्मिक आयोजनों में चल निकला है सड़कों पर नाचते गाते लोग भगवान के स्वरूप को नचाने लगे हैं भक्त नाचे तो यह चलेगा लेकिन सड़कों पर गरिमा का बिना ध्यान किए भगवान के स्वरूप को नचाने का सिलसिला यकीनन शर्मसार करने वाला है यानि हम नाच रहे हैं तो आप भी नाचिए। तमाम शोभा यात्रा में इस तरह के भगवान के स्वरूप को नृत्य करते हुए प्रदर्शन किया जाने का सिलसिला शुरू हो गया पिछले 30-40 साल में कावड़ यात्रा एक बड़ा आयोजन बन गई इसमें भी गौरा और शिव के स्वरूप को नचाने का सिलसिला चल निकला कावड़ यात्रा के दौरान तमाम तरह की भोजपुरी व हरियाणवी लोक संगीत में गीतों की कैसेट सीडी आने लगी जिन पर भगवान शिव और गौरा के स्वरूप को केंद्र में रखकर बेहद आपत्तिजनक बोल तैयार किए गए और देखते ही देखते इन पर गौरा शिव का स्वरूप धारण कर कलाकार सड़कों पर मटकते लगे यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था काली और महाकाल भी सड़कों पर खिलाए जाने लगे हद तो तब हो गई जब गाना तैयार किया गया छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना हनुमान जो भगवान रूद्र के ग्यारहवें अवतार हैं नवरूद्रो में से एक हैं मान्यता है कि हनुमान अमर अजर अविनाशी हैं जिन्हें अष्ठ सिद्धी और नव निधि का वरदान माता सीता से मिला है और हमारे आस्था के सबसे जीवंत पावन पवित्र स्वरूप है उनके स्वरूप को भी घुंघरू बांध कर भक्त लोग जागरण रथ यात्राओं शोभायात्राओं में सड़क पर नचाने लगे हैं यह श्रद्धा भक्ति और आस्था का कैसा प्रकटीकरण है? हम अपने मनोरंजन के लिए भगवान के पावन स्वरूपों को मल मूत्र से सनी सड़कों पर अमर्यादित गानों के भोंडे बोल पर शोभायात्रा में नचाकर आनंदित हो रहे हैं आप को बता दें कि पूर्व में रासलीला और रामलीला में जो कलाकार अभिनय करते थे वह इन आयोजनों के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन तमाम तरह के व्यसन का त्याग और भूमि पर शय्या लगा कर सोते थे इन स्वरूप में भारतीय आम जन मानस साक्षात भगवान के दर्शन महसूस करता था। लेकिन कहाँ से चल कर अब कहाँ आ पहुंचे हैं हम। हम जिन अपने आदर्श भगवान के चरित्रों को शराब व गुटका खाए कलाकारों को सड़कों व पंडालों में नचाकर इसे सनातन धर्म का हिस्सा मानकर गर्व और गौरव महसूस कर रहे हैं क्या हमारे पतित पावन मान बिंदु चरित्र मनोरंजन के लिए है? भगवान के पावन स्वरूप का इस तरह का अमर्यादित गलत इस्तेमाल करने को कैसे उचित कहा जा सकता है? ऐसे लोगों की बुद्धि पर शरम का अनुभव किया जाए हम सनातन धर्म के अनुयायियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आचार संहिता तैयार करनी होगी ताकि हमारे मान बिंदुओं का इस तरह का मनोरंजन के माध्यम बनाने का खेल तत्काल रुकना चाहिए।

मेष राशि :आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका काफी दिनों से रुका काम पूरा होगा आपको रिलैक्स फील होगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है, जल्द ही आप करियर में नया मुकाम पाने वाले हैं। खासतौर पर साइंस से जुड़े छात्रों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आज माता-पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं।

वृष राशि : आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। जो छात्र कॉलेज में नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो जल्द ही अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज कोई भी काम करते समय आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद जरुर लेना चाहिये। इससे आपको काम में मदद मिलेगी। साथियों के साथ आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आज अपनी गलतियों से कुछ नया सीखेंगे।

मिथुन राशि : आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज कुछ लोग आपसे किसी काम के लिए मदद मांग सकते हैं। परिवार में आपके गुणों की तारीफ हो सकती है। किसी नई तकनीक को अपनाने से आपके व्यापार में इजाफा होगा। जीवनसाथी के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम बनायेंगे। जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी जगह पर परफॉर्मेंस का मौका मिल सकता है।

कर्क राशि : आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको नए लोगों से थोड़ा संभलकर रहना चाहिए। आज आपके ऑफिस में काम को लेकर कोई आपकी शिकायत कर सकता है। आपको अपनी हर चीज परफेक्ट रखनी चाहिए चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। खुद को फिट रखने के लिए आपको योगा करना चाहिए। लवमेट के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी।

सिंह राशि : आज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज किसी विशेष काम की ओर आपका झुकाव हो सकता है, आप अपना पूरा दिन पसंदीदा काम करके गुजारेंगे। आज करियर के मामले में चीज़ें बेहतर होने के आसार हैं। आज सेहत के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। फास्ट फूड खाने से आपको बचना चाहिए। आज आपके बिजनेस में मुनाफा होने का योग बन रहा है।

कन्या राशि: आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी तरह के कानूनी मामले में दोस्तों की मदद मिलेगी। जिससे दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप परिवार वालों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी होंगे। आपको काम में कुछ नए लोगों के साथ साझेदारी करने का मौका मिल सकता है।

तुला राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज आपके घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं, आपको ख़ुशी होगी। आज ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन शाम तक सारा काम अच्छे से निपट जाएगा।

वृश्चिक राशि : आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं यह ख़ुशी आपके घर में बेटे के करियर को लेकर हो सकती है। आज ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिसे पूरा करके आपको भी ख़ुशी होगी। आज की शाम परिवार वालों के साथ बिताएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। आपको माता-पिता के साथ किसी समारोह में जा सकते हैं।

धनु राशि : आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। आज किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। साथ ही समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा, साथ ही आज आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में विचार करेंगे।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा हो सकता है। आज आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया साबित होंगे। आज आपको किसी काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, आज आपका दिन ज्यादा लाभ कमाने का है।

कुंभ राशि : आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। आज जीवनसाथी के साथ आप कोई मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में लोगों से हर तरह का सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज किसी जरूरी काम में आपको भाई-बहनों का सपोर्ट मिलेगा। अपने परिवार वालों के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे। करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। आज आपको किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना चाहिए और आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाये रखने की जरूरत है। आप किसी मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती मजबूत होगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भ्रामक विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भ्रामक विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि इनको प्रसारित करने वाले 'सेलेब्रिटी' और 'इन्फ्लूएंसर' समान रूप से जिम्मेदार होंगे। एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विज्ञापन भ्रामक है तो उसका प्रसार करने वाले सेलेब्रिटी और इन्फ्लूएंसर जिम्मेदार होंगे। इंडियन मेडिकल असोसियेशन द्वारा पतंजलि के खिलाफ विज्ञापनों पर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने ऐसे विज्ञापनों में आने वाले इन्फ्लूएंसरों और सेलेब्रिटीज़ की तगड़ी खिंचाई की। सोशल मीडिया के युग में सेलेब्रिटीज़ व इन्फ्लूएंसरों का काफी प्रभाव होता है और उनके लाखों अनुयाई उनके हर शब्द को पूर्ण सत्य मानते हैं। अनेक मामलों में प्रचार के भ्रामक या गलत होने से उपभोक्ता को नुकसान होता है तथा विज्ञापन में उसका विश्वास घटता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विज्ञापन व्यवहारों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लाखों लोग विज्ञापन देखते हैं, अत: इनका प्रसार करने वाले लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे उत्पादों या सेवाओं पर अपनी मुहर लगाने के पहले समुचित सतर्कता बरतें। ऐसा करने में विफल रहने पर उपभोक्ताओं का विश्वास टूटता है। इसके साथ ही अदालत ने कठोर नियमों तथा क्रियान्वयन मशीनरी पर जोर दिया ताकि भ्रामक विज्ञापन व्यवहारों को हतोत्साहित किया जा सके। हालांकि, वर्तमान कानून और दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को एक स्तर तक संरक्षण देते हैं, पर अक्सर वे उनकी कार्रवाइयों के लिए सेलेब्रिटीज़ व इन्फ्लूएंसरों को जवाबदेह ठहराने में कमजोर साबित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना लोकप्रिय या प्रभावशाली हो, उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता को भ्रमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सेलेब्रिटीज़ और इन्फ्लूएंसरों के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इन लोगों को विज्ञापन समझौते करते समय ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। उन पर अब यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा प्रसारित उत्पाद या सेवायें सच्ची हों तथा विज्ञापन नियमों का पालन करती हों। जवाबदेही का यह उच्च स्तर अनैतिक मार्केटिंग व्यवहारों के खिलाफ शक्तिशाली प्रतिरोधक का काम करेगा तथा इससे इन्फ्लूएंसर साझीदारियों में पारदर्शिता व आधिकारिकता आएगी। हाल ही में अनेक फिल्मी सितारों ने चबाने वाले पान मसाले को 'माउथ फ्रेशनर' के रूप में प्रोत्साहित किया है। अन्य सेलेब्रिटीज़ ने आनलाइन गेम साइटों को प्रोत्साहित किया है जो वास्तव में 'जुआघर' हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक शुरुआत है, पर भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने का रास्ता लंबा है। भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए स्पष्ट और सटीक दिशानिर्देशों की जरूरत है क्योंकि वर्तमान दिशानिर्देश काफी नहीं हैं। लेकिन अक्सर सेलेब्रिटीज़ यह नहीं जानते हैं कि वे किस चीज का प्रोत्साहन कर रहे हैं। हालीवुड स्टार पियरे ब्रान्सन माउथ फ्रेशनर समझ कर एक 'चिविंग टोबैको' विज्ञापन में गलती से आ गए थे। उनको भले ही इस गलती के लिए माफ किया जाए, पर अनेक भारतीय सेलेब्रिटीज़ ऐसे हथकंडों से परिचित हैं। सेलेब्रिटीज़ और इन्फ्लूएंसरों को विकसित होते दिशानिर्देशों का पालन करने के साथ ही अपने दर्शकों की निष्ठा और वफादारी सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता एवं आदर्श व्यवहार को प्राथमिकता देनी होगी। यह उनके सम्मान तथा समाज कल्याण के लिए अच्छा होगा।

नई सरकार की जिम्मेदारियां

देश इस समय नई सरकार की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में सबकी नजरें नए प्रशासन के समक्ष उपस्थित अनेकानेक चुनौतियों पर रहेंगी।

के.एस. तोमर
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

देश इस समय लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद बनने वाली नई सरकार की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में सबकी नजरें नए प्रशासन के समक्ष उपस्थित अनेकानेक चुनौतियों पर रहेंगी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा नेताओं का विश्वास है कि अब की बार वे 'चार सौ पार' का जादुई आंकड़ा प्राप्त करने में सफल होंगे, पर राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 4 जून को आम चुनाव के परिणाम आने के बाद नई दिल्ली में नई सरकार निश्चित रूप से बन जाएगी। इस पृष्ठभूमि में कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि नई सरकार को अनेकानेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

इनमें नई उभरती तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के आधार पर स्वयं को ढालना, कृत्रिम बुद्धि-एआई का तेजी से उभार, चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने की रणनीति बनाना तथा क्षेत्र के सुरक्षा खतरों का मुकाबला करना शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटना भारत के भविष्य में विकसित देशों की बिरादरी में शामिल होने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डिजिटल तकनीकों पर जोर देने के अच्छे नतीजे निकले हैं। इससे कोविड-19 संकट से निपटने, संकट के समय सेवाओं का सुचारु रूप से संचालन करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने में सहायता मिली है। भारत ने मिशन मोड में सेमीकंडक्टर उत्पादन का रोडमैप तैयार किया है, अंतरिक्ष क्षेत्र में नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं तथा एआई में भारत की क्षमतायें बढ़ाने का निर्णय किया है। इनसे भारत को खोज को गति देने में अमेरिका और चीन का मुकाबला करने में सहायता मिली है जो भविष्य की इन तकनीकों पर महारत पाने का प्रयास कर रहे हैं।

विदेश नीति विशेषज्ञों ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत की बढ़ती चिन्ताओं को रेखांकित किया है क्योंकि इसका खास प्रभाव नियंत्रण रेखा-एलओसी पर सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप नए प्रशासन को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संभवत: अमेरिका के सहयोग से एक रणनीतिक योजना विकसित करने पर ध्यान देना होगा। चीन की हालिया रणनीति में भारत के पड़ोसियों को कर्ज नीतियों से प्रभावित करना तथा उनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव-बीआरआई जैसी परियोजनाओं व रक्षा संबंधी उद्यमों के लिए भारी मात्रा में कर्ज का प्रस्ताव करना शामिल है।

उदाहरण के लिए, चीन ने मालदीव के साथ 'सैनिक सहायता' के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें मालदीव को गैर-घातक हथियार सप्लाई करना तथा मालदीव के सुरक्षा बलों को मुफ्त प्रशिक्षण देना शामिल है। यह पुरानी स्थितियों से व्यापक परिवर्तन है जब मालदीव के सुरक्षा बलों को भारत और अमेरिका प्रशिक्षण देते थे। इसके साथ ही भारत को चीन द्वारा 'नई उत्पादक शक्तियों' की प्रगति का जवाब देने की दीर्घकालीन और व्यावहारिक रणनीति बनानी होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अवधारणा का विकास किया है। इसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में खोज के माध्यम से आर्थिक विकास पर ध्यान देने का प्रमुख स्थान है। चीन का उद्देश्य उत्कृष्ट विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ना है। यह भी भारत के लिए एक चुनौती है। इसलिए भारत को अमेरिका से सहायता प्राप्त करने के सारे प्रयास करने चाहिए ताकि वह जापान, आस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ वैश्विक तकनीकी गठजोड़ बना सके जिसमें 'चिप एलायंस' भी शामिल है। भारत को महत्वपूर्ण उभरती तकनीकों के क्षेत्र में इन देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी विकसित करने की दिशा में भी गंभीरता से काम करना होगा। क्षेत्र में चीन के विस्तारित होते संबंध स्पष्ट हैं और भारत को सचेतन ढंग से उसके प्रभाव का मुकाबला करने के कदम उठाने होंगे।

चीन और नेपाल के बीच बढ़ते संबंध इसका उदाहरण हैं। हाल ही में नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार की चीन के साथ वैचारिक निकटता बढ़ी है और यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है। यह खासकर चीन की 'कर्ज जाल' नीति के संबंध में महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चीन ने उसे 23 बिलियन डालर का भारी कर्ज दिया है जिसके बड़े हिस्से का संबंध बेल्ट एंड रोड पहल से है। पाकिस्तान पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है जो 2000 से 2021 के बीच कुल 67.2 बिलियन डालर है। इससे उसकी कर्ज पर निर्भरता स्पष्ट होती है। गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान लगातार चीनी कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और इसके गंभीर खतरे उसके सामने आ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में नई सरकार को हाल में श्रीलंका से संबंध सामान्य होने पर संतोष होगा। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट ने उसे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, पर भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था को 4 बिलियन डालर आर्थिक सहायता के साथ ही मानवीय सहायता भी दी। इसके साथ ही वह श्रीलंका को स्थिरता प्रदान करने के लिए आईएमएफ का 48 महीने का विशेष पैकेज दिलवाने में भी सफल रहा। यह कदम भारत की परंपरागत राजनय तथा पड़ोसी की आवश्यकता पर सहायता के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है। उल्लेखनीय है कि पहले श्रीलंका को भारी कर्ज देने वाले चीन ने आवश्यकता के समय उसकी सहायता नहीं की। ऐसे में भारत के हस्तक्षेप को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया और इससे श्रीलंका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका चुनाव में भारतीय हस्तक्षेप का आरोप लगाया था जिसके चलते उनको 2015 में सत्ता से बाहर कर दिया गया था। यह प्रवृत्ति गोटाबाया राजपक्षे के समय भी जारी रही, जब उन्होंने कोलंबो हवाईअड्डे पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल-ईसीटी का समझौता रद्द कर दिया। यह 2019 के उस समझौते का उल्लंघन था जिस पर जापान, भारत और श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए थे। अब श्रीलंकाई सदन के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्डेरा ने भारत को उनके देश की 'रक्तपात' से रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया है। इस प्रकार चीन की असलियत श्रीलंकाई जनता के सामने उजागर हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध शानदार बने हुए हैं। 23 नवंबर, 2023 को एक संयुक्त आयोजन में मोदी ने जोर दिया कि परस्पर लाभ के आधार पर भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास साझीदार है।

सभी पार्टियों के चुनाव अभियान का एक खास तत्व यह रहा है कि विकासशील देशों के उलट यहां जनता को विदेश नीति की प्रासांगिकता के बारे में जागरूक करने के लिए बहसों, चर्चाओं और विमर्श का अभाव रहा है। घोषणापत्रों में भले ही विदेश संबंधों व भावी रणनीति का उल्लेख रहा हो, पर विकसित देशों की बिरादरी में शामिल होने के लक्ष्य के महत्व पर जोर देने का कोई प्रयास नहीं दिखा। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन युद्ध के कारण थोपे गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान देता है। विदेश नीति के संबंध में खासकर पिछले दस साल से भारत सरकार के निर्णय उसके राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर केन्द्रित रहे हैं।

भारत अपने इस दृष्टिकोण से दुनिया के अधिकांश देशों को सहमत करने में भी सफल रहा है। इसी कारण रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत को रूस से महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों के आयात को भी अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसे में नई सरकार के समक्ष मालदीव और नेपाल के संबंध में विदेश नीति की रूपरेखा निर्धारित करने की चुनौती होगी। विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि मालदीव और नेपाल के संबंध में रणनीतिक दृष्टिकोण में लचीलापन जरूरी होगा ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव का अच्छी तरह मुकाबला किया जा सके।

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण

कई महिलाओं को सशक्त बनाने के बावजूद इस योजना के लाभों तक पूर्ण रूप से सबकी पहुंच संभव नहीं हो पाई है।

मैनिमा अख्तर
(लेखिका, स्तम्भकार हैं)

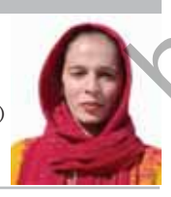

जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के गांवों में, एक मूक क्रांति चल रही है क्योंकि इन क्षेत्रों में महिलाएं उम्मीद योजना - जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेआरएलएम) के माध्यम से स्वरोजगार के रास्ते तलाशने के लिए अपने घरों से बाहर आ रही हैं। इस परिवर्तनकारी पहल का लक्ष्य पूर्ववर्ती 125 ब्लॉकों में 66त्न ग्रामीण आबादी तक पहुंचना, उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना और उनका तब तक पोषण करना है जब तक वे गरीबी से बाहर नहीं आते और जीवन की सभ्य गुणवत्ता का आनंद नहीं लेते।

पिछले साल दिसंबर में, मिशन निदेशक जेकेआरएलएम, इंदु कंवल चिब ने जेकेआरएलएम विजन 2024-30 को साझा करते हुए बताया कि जेकेआरएलएम ने सफलतापूर्वक 725,000 महिलाओं को एकजुट किया है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 87,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया है। ये एसएचजी विभिन्न क्षेत्रों जैसे आजीविका, वित्तीय समावेशन, लिंग और सामाजिक समावेशन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हालांकि, कुछ ग्रामीण क्षेत्र इस महत्वपूर्ण योजना से अनभिज्ञ हैं, और इसके लाभों को भुनाने के लिए व्यापक ज्ञान का अभाव है। ऐसा ही एक क्षेत्र है सीमावर्ती जिले पुंछ की मंडी तहसील का बैला गांव, जो जम्मू शहर से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित है।

हालांकि यह योजना 2016 से पास की मंडी तहसील में चालू है, लेकिन बैला गांव में इसकी पहुंच सीमित है। जब उम्मीद योजना के बारे में पूछा गया, तो इस सुदूर गाँव की महिलाओं की प्रतिक्रिया जागरूकता की कमी थी। जब उन्हें योजना के लाभों के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसके कामकाज को समझने की उत्सुकता व्यक्त की, महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में इसके महत्व को रेखांकित किया। इस संदर्भ में, बैला की रहने वाली 18 वर्षीय मतीना अख्तर ने अपना दृष्टिकोण साझा किया मंडी से सिर्फ दो किलोमीटर दूर रहने के बावजूद, हम इस योजना से अनजान हैं। हमारे देश के एकांत कोनों और विकास योजनाओं के बीच यह बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर हमें, दूरदराज के इलाकों की महिलाओं को, इसके फायदों से वंचित कर देता है। हमें इसके बारे में तभी पता चलता है जब योजना बंद होने की कगार पर होती है। हमारी दूरदर्शिता के कारण ही हमें इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर हम अंधेरे में हैं तो हमें इससे कैसे जुड़ना चाहिए? जब मुझे अपनी किराने की दुकान के लिए धन की आवश्यकता थी, तो मेरे पास नकदी की कमी थी। इसलिए, मैंने सामग्री खरीदने के लिए अपने घर से कुछ लकड़ी बेचने का सहारा लिया। अगर मुझे इस योजना के बारे में पहले पता होता, तो मैं उन लकड़ियों को नहीं बेचता, उसी गांव की 37 वर्षीय फरीदा अख्तर ने अफसोस जताया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें किसी योजना के बारे में जानकारी है? 23 साल की निवासी ज़रीना अख्तर ने जवाब दिया कि उनके समुदाय के भीतर, मान्यता प्राप्त एकमात्र योजना आंगनवाड़ी योजना (आईसीडीएस) है, जो इस एकमात्र कार्यक्रम से परे सरकारी पहलों के ज्ञान और पहुंच में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है। गांव के लोगों के साथ-साथ महिलाओं और पुरुषों में भी काफी डर है. उन्हें असफलता का डर है - अगर वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए तो क्या होगा?

बैला की 19 वर्षीय सलमा अख्तर इस धारणा की पुष्टि करती हैं। उन्होंने योजना के तहत ऋण अधिग्रहण से जुड़े संभावित परिणामों और अनिश्चितताओं के बारे में आशंका व्यक्त की। इन महिलाओं के मन में घर कर रही आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है और उन्हें यह बताने का प्रयास करने की जरूरत है कि यह योजना खतरा नहीं, बल्कि वरदान है। उन्हें यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि यह पहल उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उन्हें इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में काम करने के लिए बनाई गई है। मंडी तहसील में उम्मीद योजना की क्लस्टर प्रमुख नईमा अख्तर के अनुसार, सरकार ने महिलाओं को इससे लाभान्वित करने के लिए इस योजना के तहत अच्छी धनराशि आवंटित की है। मैं अन्य महिलाओं से, जो इस योजना से अनजान हैं, हमसे जुड़ने का आग्रह करती हूं। मंडी लोरेन क्षेत्र में कई व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने इस योजना के माध्यम से पुरस्कृत अवसर प्राप्त किए हैं। वे शारीरिक श्रम किए बिना ही अपने घर का भरण-पोषण कर रहे हैं।

अफसोस की बात है कि बैला की महिलाएं इस असाधारण कार्यक्रम से बेखबर हैं। इस बीच, अन्य क्षेत्रों की महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं और खुद को प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। वे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भरता भी विकसित कर रहे हैं। इससे बैला की महिलाओं के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की उम्मीद जगी है।

आप की बात

मतदाताओं की पसंद

पचहत्तर साल से देश के मतदाता बड़ी संख्या में अपने विकास की चाहत में मुख्यत: एक ही दल के प्रति प्रतिबद्धता पूर्वक मतदान करते रहे। मगर गत 10 वर्षों में उन्हें जो मिला वह पूर्व के 75 वर्षों में भी नहीं मिला था। पिछड़ा वर्ग हो या गरीब वर्ग जो कभी खुद का शौचालय तक बनवाने में सक्षम नहीं थे, उन्हें अब पक्के मकान, खाना पकाने की गैस तथा किसानों व गरीब महिलाओं को नगद राशि निर्बाध रूप से मिल रही है। यही वजह है कि अब अधिकांश मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों से प्रभावित नहीं होते हैं। वह जानते हैं कि जो मिल रहा है। उससे अधिक और ज्यादा देना किसी भी अन्य दल के लिए संभव नहीं है। इस कारण मतदाता येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने के लिए खैराती घोषणाओं की बाढ़ लाने वाले दलों से प्रभावित नहीं होते हैं। उनको पुरानी सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सरकारी योजनाओं में लगे दलालों व बिचौलियों का भी कड़वा अनुभव है। आजकल सोशल मीडिया के चलते लोग अब अधिक समझदार हो गए हैं। वे सरकार की छोटी मोटी खामियों को अनदेखा कर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। मतदाता उसी दल को वोट देंगे जिस पर उन्हें अपनी भावी पीढ़ी के उत्थान और उसे आत्मनिर्भर बनाने का भरोसा होगा।

- **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

आविष्कारों के दुष्प्रभाव

हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वैज्ञानिक अद्भुत चमत्कारों से हमारी पूरी दुनिया को आसान, सहज, सरल, सुखदायक, श्रम रहित बनाकर रख दिया है। मगर हर सुख के अनुपात में ठीक उतना ही दुख उठाना पड़ता है। और यही मोबाइल रुपी स्मार्टफोन के आने से हो गया। संदेशों के आदान-प्रदान और बातचीत तक तो इसकी उपयोगिता बेमिसाल है। इसने प्रत्येक व्यापारी को अंतरराष्ट्रीय लिंक से जोड़ दिया है। मगर इसके साथ आने वाले खतरनाक गेम, करोड़ों रुपए कमाने का लालच देनेवाले गेम और फेक वीडियो जैसी कई समस्याएं भी आकर सामने खड़ी हो रही है। अब तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई के जुड़ जाने के बाद इसके दुरुपयोग की सीमा निर्बाध हो गई है। अब 3 सालके बच्चे के हाथ से आप मोबाइल नहीं छुड़ा सकते। बच्चे ही क्यों किशोर युवा और अब तो वृद्ध भी स्मार्टफोन के चंगुल में फंस चुके हैं। जब महंगा डाटा आता था तो लोग फ्री थे अब फ्री डाटा आने लगा तो लोगों से मिलना महंगा हो गया। हमें विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न आविष्कारों के दुष्प्रभाव पर भी गौर करना होगा क्योंकि वे हजारों साल से चले आ रहे हमारे प्राकृतिक जीवन को मशीनी बनाते जा रहे हैं।

- **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

कैनबिस प्रयोग पर विवाद

एशिया के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थाईलैंड ने दो साल पहले भांग को प्रतिबंधित सूची से हटा दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री थाविसिन ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय नियमों में संशोधन कर भांग को मादक पदार्थ के रूप में पुन: सूचीबद्ध करे। इसके उलट भांग के उपयोग व खपत को लगातार दुनिया भर के कई देश वैधता प्रदान कर रहे हैं। वैसे तो इसके चिकित्सीय उपयोग को वैध घोषित किया गया है, मगर इसका नशे के तौर पर खूब उपयोग हो रहा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, जर्मनी, ग्रीस, इज़राइल, इटली, जमैका, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड और स्विट्जरलैंड ने इसके प्रयोग की अनुमति दी है। थाई सरकार ने 2018 में कैनबिस को चिकित्सा उपयोग के लिए और 2022 में मनोरंजक उपयोग के लिए स्वीकार किया था। लेकिन अब थाईलैंड के युवा इसके नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। थाईलैंड के उदाहरण से कैनबिस के प्रयोग पर सवाल उठने लगे हैं। कैनबिस के चिकित्सकीय प्रयोग के समर्थन और विरोध में तर्क देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन नशे के तौर पर इसका प्रयोग रोकना लगभग असंभव हो गया है।

-**जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

पशु पक्षियों की सुरक्षा

भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। मानव जीवन तो भीषण गर्मी की मार झेलता और सहता है, परंतु पशु पक्षी भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं है। आसमान से बरसती तेज धुप गर्मी पक्षियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। हम सभी का परम कर्त्तव्य होना चाहिए कि पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए द्वार, गैलरी, छत आदि स्थानों पर सकोरे बांध कर रखे और उनमे लगातार पानी भरते रहे। साथ ही साथ गाय, कुत्ते और अन्य जानवरों के लिए भी पानी पीने की सुविधाएं करें। मूक प्राणी बोल नहीं सकते, पर इंसान और इंसानियत का परिचय देकर मानवता के नाते हमे उनकी पीड़ा से रुबरु होना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि पर्यावरण में पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं का अहम योगदान होता है। वर्तमान में गर्मी चरम पर है और सभी को राहत की जरूरत होती है। क्यों न हम संकल्पित होकर अपनी कर्तव्य निष्ठा को मूर्त रुप दें? हालाकि नगरों में कुछ सेवाभावी संस्थाएं इन कार्यों को करती हैं, परंतु समाज के हर नागरिक को भी ऐसे सेवाभाव से जुड़ना होगा। हमें पशु पक्षियों की प्यास बुझाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

- **योगेश जोशी,** बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/Newspaper_Paid

घर मे यदि दीपक न जले तो वह दरिद्रता का चिन्ह है। हृदय मे ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मे ज्ञान दीपक जलाकर उसको देखो : रामकृष्ण परमहंस

जनसंख्या असंतुलन के खतरे को पहचाने समाज

आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने जनसंख्या असंतुलन के गंभीर और बड़े खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट के आंकड़ों ने भारतीय राजनीतिक वातावरण में सरगर्मी बढ़ा दी है। देश के प्रबुद्ध वर्ग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के इन आंकड़ों पर चुनावी या राजनीतिक चर्चा होकर न रह जाए क्योंकि अभी देश में लोकसभा के निर्वाचन चल रहे हैं। ऐसे में आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर चर्चा होना तो स्वाभाविक है लेकिन यह केवल राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। जनसंख्या असंतुलन सामाजिक मुद्दा है, इस पर समाज को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और समाधान की रूपरेखा बनानी चाहिए। अन्यथा भारत को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जिन भी देशों ने जनसंख्या असंतुलन के खतरे को अनदेखा किया, बाद में उसका भारी खामियाजा उसने उठाया है। इसका सबसे सटीक उदाहरण फ्रांस है। फ्रांस के अलावा हालैण्ड, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश जनसंख्या असंतुलन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के कारण किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, वे सबको ध्यान में हैं। याद रहे कि दुनियाभर के विद्वान मानते हैं कि जनसंख्या असंतुलन प्रत्येक देश के लिए खतरनाक है। भारत का तो इतिहास रहा है। भारत के जिन-जिन हिस्सों में हिन्दू धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां-वहां दिक्कतें खड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले भारत के ही हिस्से थे लेकिन जनसंख्या असंतुलन के कारण ये हिस्से समय के साथ भारत से अलग हो गए या अलग कर दिए गए। परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में "1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8 प्रतिशत कम हो गई। जबकि मुस्लिम आबादी 43 प्रतिशत बढ़ गई"। हिन्दुओं की संख्या घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने का जो अंतर है, वह असामान्य है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस आकड़े के बाद भी एक वर्ग यह कहता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय संकट में है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत का मुसलमान पड़ोसी मुस्लिम देशों के मुकाबले अधिक बेहतर जीवन जी रहा है। रिपोर्ट में पड़ोसी देशों के जनसंख्या परिवर्तन का आंकड़ा भी दिया गया है, जिसके अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में गैर-इस्लामिक समुदाय की जनसंख्या तेजी से घटी है। इन देशों में भी मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी गई है। यानी एक बात स्पष्ट है कि चाहे गैर-इस्लामिक देश हो या इस्लामिक देश, दोनों ही जगह मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है लेकिन अन्य समुदायों की जनसंख्या में असामान्य कमी आई है। भारत में आज अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। इन क्षेत्रों अन्य समुदायों का रहना आसान नहीं है। वहाँ की सामाजिक एवं प्रशासिनक व्यवस्थाओं में सीधा हस्तक्षेप मुस्लिम समुदाय करता है। इसलिए भी जनसंख्या असंतुलन सबकी सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन भारत में 'मुस्लिम तुष्टीकरण' की मानसिकता वालों से सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बेमानी होगी। इसलिए जनसंख्या संतुलन बना रहे इसकी अधिक जवाबदेही हिन्दू समुदाय की है। भाजपा ने जनसंख्या असंतुल के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर गंभीर सामाजिक विमर्श खड़े हों और शासन स्तर से जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने के लिए ठोस नीति जल्द बनायी जानी चाहिए। यदि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटती है, तब उसे अविलंब समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना चाहिए।

आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने जनसंख्या असंतुलन के गंभीर और बड़े खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट के आंकड़ों ने भारतीय राजनीतिक वातावरण में सरगर्मी बढ़ा दी है। देश के प्रबुद्ध वर्ग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनसंख्या परिवर्तन के इन आंकड़ों पर चुनावी या राजनीतिक चर्चा होकर न रह जाए क्योंकि अभी देश में लोकसभा के निर्वाचन चल रहे हैं।

अमृत कलश

दुख में अदायगी

दुख तुम्हें वह सब देता है जो सुख नहीं दे सकता। वास्तव में सुख तुम्हें हर चीज से वंचित कर देता है। सुख तुमसे वह सब छीन लेता है जो कभी तुम्हारे पास था, जो तुम कभी थे, सुख तुम्हें मिटा देता है। दुख तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और सुख मूलतः निरहंकार की अवस्था है। वही समस्या है और वही समस्या की जड़, तभी सुखी होना लोगों को बहुत कठिन लगता है। तभी संसार में लाखों लोग दुख में ही जीते हैं... उन्होंने दुख में ही जीने की ठान ली है। यह तुम्हें बहुत सूक्ष्म अहंकार देता है। दुख में तुम सुखी होते हो पर तुम नहीं होते। दुख में सूक्ष्म अहंकार, सुख में तुम्हीं मिट जाते हो। अगर यह समझ में आ जाए तो बात एकदम स्पष्टहो जाती है। दुख तुम्हें विशिष्ट बनाता है। सुख स्मष्टिगतघटना है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। वृक्षसुखी हैं, पशु सुखी हैं और पक्षीसुखी हैं। पूरा अस्तित्व सुखी है,सिवाय मनुष्य के। दुखी होने से व्यक्ति बहुत विशिष्ट हो जाता है। दुख तुम्हें लोगोँ का ध्यान आकर्षित करनेमें कुशल बनाता है। तुम जब भी दुखी होते हो, तुम्हारी ओर ध्यान दिया जाता है, तुम से सहानुभूति की जाती है, तुम्हें प्यार मिलता है। हर कोई तुम्हारा ध्यान रखता है. दुखी व्यक्तिको चोट कौन पहुंचाएगा? दुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कौन करेगा? दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा? यह तो बहुत घटिया बात होगी।

दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्रेम दिया जाता है, उसकी देख-रेख होती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे भूलेगा ही। अगर वह दुखी हैतो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार-पत्नी, बच्चे-सब उसके इर्द-गिर्द होते हैं; इससे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे मित्र हैं।

जब तुम बीमार होते हो, उदास होते हो, दुखी होते हो तो मित्र तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हें ढाढ़स देते हैं, तुम्हें साँत्वना देते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही मित्र तुमसे ईर्ष्या करते हैं। जब तुम वास्तव में प्रसन्न होते हो तो तुम पाओगे कि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है.. दूसरे को लगता है, "तो आप सुखी हैं और हम अभी भी अंधेरे, दुख और नरक में कुलबुला रहे हैं। जब हम दुख में हैं तो आप सुखी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं!" तो संसार तो दुखी व्यक्तियों से बना है और किसी के पास भी संसार के विरोध में जाने का साहस नहीं है, यह बड़े खत्रे, बड़े जोखिम का काम है। तो बेहतर है कि दुख से चिपके रहें, यह तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाए रखता है। यदि तुम सुखी हो तो तुम व्यक्ति हो; दुखी हो तो भीड़ का हिस्सा-हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भारतीय, अरब, जापानी।

बोध कथा

आस्था की दृष्टि

एक मिशनरी ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, 'वे माता काली के रोम-रोम में अनेक ब्रह्मांड होने की बात करते हैं और उस छोटी-सी मूर्ति को काली कहते हैं, यह कैसे?' इस पर परमहंस ने पूछा, 'सूरज दुनिया से कितना बड़ा है?' उन्होंने उत्तर दिया, 'नौ लाख गुना।' परमहंस ने फिर पूछा-'तब वह इतना छोटा कैसे दिखाई देता है?' मिशनरी ने कहा, 'नौ लाख गुना होने पर भी सूरज हमसे बहुत दूर है। इसलिए वह इतना छोटा दिखाई देता है।' परमहंस ने फिर पूछा, 'कितनी दूर?' उन्होंने बताया, 'नौ करोड़, तीस लाख मील।' परमहंस ने विनम्रता से जवाब दिया, 'ठीक इसी प्रकार आप मां काली से इतनी दूर हैं कि आपको वे छोटी दिखाई देती हैं। मैं उनकी गोद में हूं। इसलिए मुझे वे बड़ी लगती हैं। आप स्थूलदृष्टि से पत्थर देखते हैं, मैं आस्था की दृष्टि से शक्तिपुंज देखता हूं।'

कांग्रेस यह भी स्पष्ट नहीं करती कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण के विरुद्ध है

कांग्रेस पर मुस्लिमों को आरक्षण व संपत्ति देने का आरोप और सच

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

मुस्लिम आरक्षण इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह अनुसूचित जाति - जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण हटाकर मुसलमान को देना चाहती है। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष और भाजपा विरोधी कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव में ध्रुवीकरण चाहते हैं जो सरेआम सांप्रदायिकरण है।

मुस्लिम आरक्षण इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वह अनुसूचित जाति - जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण हटाकर मुसलमान को देना चाहती है। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष और भाजपा विरोधी कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव में ध्रुवीकरण चाहते हैं जो सरेआम सांप्रदायिककरण है। अगर चुनाव में किसी संप्रदाय पर हमला किया जाए या उसके विरुद्ध दूसरे संप्रदाय को भड़काया जाए तो यह सांप्रदायिकता की श्रेणी में आएगा और इसके लिए चुनाव कानून ही नहीं सामान्य कानूनों में भी मुकदमा चलाने तथा सजा देने का प्रावधान है। प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया उसे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का षड्यंत्र मान लिया जाए या उसके पीछे तथ्य भी हैं? कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं किंतु यह कहने को तैयार नहीं है कि वह मजहब के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस यह भी स्पष्ट नहीं करती कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण के विरुद्ध है।

कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वचन देते हुए यह सुनिश्चित करने की घोषणा करती है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले तो इसलिए मंशा पर प्रश्न उठता है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है। कांग्रेस सरकारों ने पहले भी मुसलमानों को आरक्षण देने की पहल की है। चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं था, इसलिए अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से ही कर्नाटक में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया। केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान आंध्रप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का कानून बना दिया। यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया और कांग्रेस के सभी नामी वकीलों ने इसमें पैरवी की। आज भी अनुसूचित जनजाति से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बनने वालों को आरक्षण का लाभ मिलता है। वे अल्पसंख्यक होने का भी लाभ पाते हैं और अनुसूचित जनजाति का भी।

कांग्रेस यह तो कह रही है कि इसमें मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है पर

अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है? यूपीए सरकार के दौरान मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस की नीति में शामिल हुआ। मनमोहन सरकार ने सत्ता में आने के बाद सच्चर समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति की भयावह तस्वीर पेश किया और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के नाम पर अनेक अनुशंसाएं की। इनमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी शामिल था। सच्चर समिति की अनुशंसाओं के आलोक में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समितिका गठन हुआ जिसने पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति से धर्म परिवर्तन करने के बावजूद मुसलमानों को आरक्षण देते रहने की सिफारिश की। यही नहीं उसने पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशतों के आरक्षण में से मुसलमान को देने की सिफारिश की। 30 नवंबर 2006 को सच्चर समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री पमनमोहन सिंह ने 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के भाषण में कहा कि 'मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ ही एससी/एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों का उत्थान है। हमें ऐसी नई योजनाएं बनानी होंगी, जिनसे अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिल सके। देश के संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए।' ध्यान रखिए, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को आरक्षण पहले से प्राप्त है, नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इसमें आर्थिक रुप से कमजोर मुसलमान भी शामिल हैं। तो आप आरक्षण की सीमा को बढ़ाना किसके लिए चाहते हैं? अपने भाषणों और वक्तव्यों में राहुल गांधी सहित ज्यादातर नेता अनुसूचित जाति - जनजाति व पिछड़े वर्ग के साथ ही अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं। आखिर अनुसूचित जाति-जनजाति जाति और पिछड़े वर्ग के साथ मुसलमान को क्लब कैसे किया जा सकता है? मुसलमानों ने देश में लंबे समय तक शासन किया और इस कारण वे विशेषाधिकार वर्ग में आते हैं। मुस्लिम नवाबों और जमींदारों की बड़ी संख्या पूरे देश में रही है। उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्होंने जबरन देश का विभाजन भी करवा दिया। मुसलमानों का आर्थिक -सामाजिक - विकास हो इससे किसी को दो राय हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी सरकार में ही सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा हुई है। किंतु हमारे यहां जाति व्यवस्था में हाशिए पर रहे समूहों के कारण आरक्षण का प्रावधान संविधान में लाया गया। इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था न थी और न हो सकती है। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से अन्य पिछड़े वर्ग का हक मार कर ही कांग्रेस या आईएनडीआईए के अन्य दल उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। जब 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की घोषणा की और उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला गया तो कांग्रेस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बाहर आकर बयान दिया कि खुर्शीद साहब ने जो कहा है वह कांग्रेस की मंशा है। पश्चिम बंगाल से इसके संदर्भ में एक डराने वाला आंकड़ा आया है। इस समय वहां 179 जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल हैं जिनमें 118 मुस्लिम है और हिंदू सिर्फ 61। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो उसने राज्यों को भी पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने का अधिकार दिया। ममता बनर्जी ने 71 जातियां शामिल की जिनमें 65 मुस्लिम थे। जब यह पूछा गया कि कहां-कहां ऐसा हुआ इसकी जानकारी दीजिए तो उत्तर आया कि इसकी जानकारी नहीं है। सरकारों ने ऐसे नियम और ढांचे बना दिया जिनसे राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का ज्यादातर लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। इसके बाद क्या किसी संदेह की गुंजाइश रह जाती है?

यह लेखक के निजी विचार है

जयंती आज: भगवान परशुराम को समझने की जरूरत

अत्याचार का नाश करने हुआ परशुराम अवतार!

डॉ. राकेश मिश्र
अध्यक्ष, पं. गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास

जब-जब धरती पर अधर्म, अहंकार, अनाचार और अत्याचार की वृद्धि हुई तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने विविध रूपों में अवतार लिया। उन्होंने हर अवतार में अधर्मी, अहंकारी, अनाचारी और अत्याचारी का नाश किया। भगवान विष्णु दस बार अवतार लेकर अपने विविध रूपों से धरती को अवगत करा गये। इसी कड़ी में भगवान विष्णु अपने छठे अवतार में भगवान परशुराम के रूप में मानव अवतार में अवतरित हुए। अन्य अवतारों में भगवान ने सीमित कार्य और उद्देश्य की पूर्ति कर पुनः अपने धाम को वापस चले गए। लेकिन, परशुराम भगवान विष्णु के एकमात्र ऐसे अवतार हैं, जो अपने बाद वाले के साथ भी सह-अस्तित्व में रहे। प्रभु श्री राम को परशुराम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात अपने दादा को भगवान विष्णुं से प्राप्त धनुष 'शारंग' भगवान श्रीराम को दिया। महाभारत काल में उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया। शास्त्रों के अनुसार तो वे आज तक विद्यमान ही हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के दसवें अवतार, यानी कल्कि की मदद करने के लिए मौजूद हैं, जैसा कि कल्कि पुराण में कहा गया है। परशुराम की सिर्फ एक ही कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कई अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं।

मान्यताओं के अनुसार सात चिरंजीवियों का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। उसमें भगवान परशुराम भी शामिल हैं। भगवान परशुराम जिन सात चिरंजीवी (अमर प्राणियों) में से एक हैं, उसमें हनुमान, कृपाचार्य, बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और व्यास शामिल हैं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अहंकार और अत्याचार को नष्ट करने के लिए परशुराम के रूप में मानव अवतार लिया था। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के यहां

पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी उनमें क्षत्रिय के गुण थे। वैसे कहा जाता है कि उनके पिता के में भी क्षत्रिय के गुण थे। भगवान परशुराम धर्म, धैर्य, बुद्धि, विवेक, शास्त्र और सदाचार के साथ साहस, शौर्य, शक्ति, आक्रामकता और युद्ध कला सहित विभिन्न गुणों से संपन्न थे। परशुराम दो शब्दों का मिलन है परशु और राम। जिसमें परशु शब्द का अर्थ कुल्हाड़ी होता है, इसलिए परशुराम नाम का अर्थ है 'कुल्हाड़ी वाला राम'।

परशुराम के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं और वे रामायण और महाभारत के दौरान भी मौजूद थे। भगवान परशुराम तप और बल में अग्रणी होने के साथ ही न्याय के प्रबल पक्षधर तथा अहंकार और अत्याचार के विरोधी थे। भगवान परशुराम कई नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, जमदग्न्य, रेनुकेय, चिरंजीवी समेत कई नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है।

शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भगवान शिव से शास्त्रों और युद्ध की कलाओं को सीखा। फिर उन्होंने भगवान शिव के निर्देश पर भगवान शिव और अन्य देवताओं से आकाशीय हथियार प्राप्त किए। शिव ने अपने युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए परशुराम को युद्ध के लिए बुलाया। गुरु और पालकी के बीच इक्कीस दिनों तक भयंकर युद्ध चला। परशुराम के युद्ध कौशल को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के बाद उन्हें स्वयं भगवान शिव से कुल्हाड़ी मिली थी।

उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन का वध करना था। सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था और इस घमंड के कारण ऋषि-मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। एक बार सहस्त्रार्जुन के मन में भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में मौजूद कामधेनु गाय को पाने का लोभ हो गया। अपने इस लोभ के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर दी। पति की हत्या हो जाने के बाद परशुराम मां रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गयीं। इस घटना से क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। इसी घटना के आधार पर भगवान परशुराम के संबंध में एक गलत बात फैलाई गई कि वे एक वर्ग विशेष के विरोधी थे, जो सत्य से परे हैं। उन्होंने सिर्फ अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी और अहंकारी लोगों का नाश किया।

भगवान परशुराम एक ओर जहां भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अहंकारी और अत्याचारी का नाश किया, वहीं भगवान शिव के प्रिय के रूप में कल्याण, न्याय और नीति को स्थापित किया। उन्होंने धर्म की स्थापना और जीव कल्याण की प्रेरणा दी। उन्होंने पृथ्वी पर हिन्दू वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते हुए उसे स्थापित किया। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाये गए हैं। संपूर्ण पृथ्वी जीतकर भी भगवान परशुराम स्वयं पहाड़ों को अपना आश्रय स्थल बना लिया और पूरी धरती दान में दे दी। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण तक में मिलता है।

आज भगवान परशुराम की जयंती के दिन हमें भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेकर अधर्म और अनैतिक कार्यों से बचने का संकल्प लेना चाहिए।

परशुं दक्षिणे हस्ते वामे च दधतं धनुः।
रम्यं भृगुकुलोत्तंसं घनश्यामं मनोहरम् ॥

समय-बोध

अक्षय तृतीया: अक्षय वास हो

राजन

अक्सर हम अपने किसी नुकसान होने पर कहते हैं कि पता नहीं किस मुहुर्त या घड़ी में यह कार्य किया था जो सफल नहीं हुआ क्यों कि बच्चों के नामकरण से लेकर विवाह तक और प्रतिष्ठान के शुभारंभ से लेकर घर की नींव रखने या गृहप्रवेश या फिर नया वाहन ही क्यों न खरीदना हो प्रत्येहक शुभ कार्य दिन और मुहुर्त के अनुसार करना हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है।

हमारी संस्ककति में उल्लेसखित है कि वर्ष में साढ़े तीन दिन अबूझ मुहुर्त माने गये है। इन साढ़े तीन दिन मुहुर्त पर्व के बारे में मान्यता है कि इन दिनों का प्रत्येक क्षण अपने आप में विशेष एवं सिद्ध मुहुर्त होता है। इन दिनों कोई भी कार्य बिना मुहुर्त निकलवाये किसी भी समय प्रारंभ किया

जा सकता है यानि इन दिनों में मुहुर्त के लिये कहीं पूछना नहीं पड़ता इन दिनों का प्रत्येक पल अबूझ मुहुर्त होता है। ये साढ़े तीन विशिष्ट मुहुर्त पर्व हैं अक्षय तृतीया, गुडी पढवा, दशहरा और बलि प्रतिपदा का आधा दिन।

हमारी मान्यतानुसार त्रेता युग का प्रारंभ बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ और भगवान परशुराम का जन्म भी इसलिये तिथि को हम अक्षय तृतीया या आखातीज के नाम से जानते है। भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के द्वार श्रृद्धालुओं के दर्शन के लिये इसी दिन खुलने के कारण यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं वर्ष भर में मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में सदैव वस्त्रों से ढकें रहने वाले श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं।

भगवान कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बयान करते हुए कहां गया था कि इस तिथि पर किये हवन एवं दान का कभी क्षय नही होता इसीलिये इसे अक्षय तृतीया कहां जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को भीगी चने की दाल व मिश्री का भोग लगाये जाने की परंपरा हैं। अक्षय तृतीया पर ब्रहमा जी एवं श्री विष्णु भगवान की संयुक्त मिश्रित तरंगें उच्च सगुण देवलोक से पृथ्वी पर आती है फलस्वरूप पृथ्वी की सात्विकता में कई प्रतिशत वृद्धि हो जाती है ऐसे में श्रद्वालु जब पूर्ण श्रद्वा एवं भक्ति से प्रभु आराधना करता है तो समृद्वि दाता इष्ट देवों की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। अक्षय तृतीया को स्नान दान एवं धार्मिक कार्यो के साथ ही पूर्वजों को गति दिलाने हेतु तिल तर्पण की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ईश्वर की अनुकंपा-कृपादृष्टि पाने एवं पितरों के लिये की गई विधियां अविनाशी एवं अक्षय होती है।

बाल विवाह -ऐसा अपराध जो बड़ों की उपस्थिति में होता है

प्रलय श्रीवास्तव

बाल-विवाह यानि छोटी उम्र में बच्चों की शादी। बड़ों की रजामंदी और संरक्षण में होने वाला ऐसा अपराध जो समारोह पूर्वक होता है। जिसमें भागीदार होते हैं माता- पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ौसी, रस्मों को निभाने वाले कर्ता-धर्ता और वे सभी जो खुद ज्ञाता व विद्वान होने का दावा करते हैं। यह ऐसी कुरीति है जो समाज के माथे पर आज भी कलंक बनी हुई है। कच्ची उम्र में बच्चों को बड़ा होने का अहसास कराना आज भी बदस्तूर जारी है।

आखिर बाल-विवाह होते क्यों हैं, इस बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है। चूंकि बच्चे शत-प्रतिशत सच्चे होते हैं, उनका मन भोला होता है। नये कपड़े, मिठाई, उपहार, बैण्ड-बाजा का लालच देकर उन्हें विवाह के मण्डप में बैठा दिया जाता है। अनेक ऐसे क्षेत्र या स्थान भी हैं जहां परम्परा, रीति-रिवाजों के नाम पर बच्चों को कम उम्र में ही ब्याह दिया जाता है। फिर क्या, इस प्रक्रिया का सीधा-साधा असर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तेजी से बढ़ता लिंगानुपात, बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में खून की कमी, मातृ-शिशु मृत्यु दर आदि ऐसे कारण हैं, जिनका सीधा संबंध बाल विवाहों से है। बच्चों को उम्र से पहले ही उन बंधनों और जिम्मेदारियों में लाद दिया जाता है, जिसके लिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होते। बाल-विवाह बच्चों को उनके बचपन से भी वंचित कर देता है। समाज ने 18 साल से कम आयु की बालिका की शादी नहीं करने की कानूनी जानकारी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसने यह भी सीख लिया कि होने वाले बाल-विवाह को सरकार की नजर से कैसे छुपाया जाए।

वैदिक काल तक विवाह से पूर्व वर व वधु के शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस काल में विवाह पूर्ण प्रौढ़ावस्था में होता था। स्त्रियों को वैदिक काल तक ही पुरुषों की तरह के सारे अधिकार थे। वैदिक काल के बाद विवाह प्रथा अल्प वय विवाह में बदलती चली गई।

स्मृति चन्द्रिका, संस्कार कांड कहता है कि यदि योग्यपति प्राप्त नहीं होता है तो कन्या का विवाह तरुण आयु प्राप्त होने से पहले ही अयोग्य वर से कर देना चाहिये। 'प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा' नामक पुस्तक में अल्तेका लिखते हैं कि कन्याओं को हमलावरों से बचाने के लिये भी विवाह एक प्रतिरक्षात्मक उपाय था। वर्ण और जाति के कारण भी बाल-विवाह को प्रोत्साहन मिला। कम उम्र में कन्याओं का विवाह कर लोग उसके भविष्य की चिंता से बचने की कोशिश करते थे। 'भुगतते हैं मां, बच्चे' कम उम्र में शादी होने से न सिर्फ सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है वरन् अच्छे स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने के अधिकार का भी हनन होता है।

बाल-विवाह विरोधी कानून : बाल-विवाह को रोकने के लिए वर्ष 1929 में बाल-विवाह अंकुश अधिनियम बनाया गया। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में कई खामियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिये बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, (पीसीएमए) 2006 को 1 जनवरी 2007 से अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य बाल-विवाह प्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिये पहले कानून की विफलता को दूर करना व बाल-विवाह की रोकथाम के लिये एक समग्र व्यवस्था विकसित करना है। यह कानून 1 नवम्बर 2007 से लागू किया गया है।

'हमारी जिम्मेदारी- एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बाल-विवाह की रोकथाम की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। हर जिले के कलेक्टर को बाल-विवाह की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन स्तर पर इस कोशिश में हर व्यक्ति को मददगार बनना चाहिए। यदि कहीं भी बाल विवाह होते दिखाई दे तो इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाकर बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से रोकना हर नागरिक का कर्तव्य है।

बाल-विवाह रोकने के लिए समुदाय में निचले स्तर पर प्रेरक के रूप में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं स्कूल के शिक्षक उपयोगी माध्यम हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश ने उठाये कड़े कदम : मध्यप्रदेश सरकार हर साल अक्षय तृतीया अथवा आखातीज को बाल विवाह की रोकथाम करती है। बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह रोकथाम अभियान भी चलाया जाता है। समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वे अपने जिले में ऐसे प्रयास करें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बाल विवाह न हो।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

झारखंड : काली कमाई के पहाड़

इस देश में भ्रष्टाचार तो रग-रग में व्याप्त है, लेकिन झारखंड में तो यह मानो अपने पूरे निर्लज्ज स्वरूप में है। वहां हाल में ईडी ने एक छापे में राज्य के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उसके सहायक के यहां छापे मारकर 40 करोड़ रू. नकद बरामद किए हैं। ईडी ने पीएस संजीव लाल और उनके सहायक जगांगीर को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मंत्री ने नोटों की जब्ती से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि भाजपा ने इस भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना दिया है। इस छापे का झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर असर जरूर होगा। वहां कुल चार चरणों में मतदान होना है। मतदान का पहला चरण 13 मई को है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने झारखंड में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सरकारी निज सचिव संजीव लाल और मंत्री के निजी सहायक (बाह्य) जहांगीर समेत अन्य के ठिकानों पर छापा मारा। छापामारी में जहांगीर के घर से भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। ये नकद रुपये कूट के डिब्बों, पॉलिथीन और कपड़े की थैलियों में भर कर रखे हुए थे। जहांगीर के यहां से 31.20 करोड़ रुपये तथा संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से 2.93 करोड़ रुपये नकद जब्त किये हैं। जहांगीर के घर से ईडी की टीम ने फ्लैट से एक लेटर भी जब्त किया है। इसमें ठेकेदारों से ली गई कथित रिश्वत के खुलासे की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सूत्रों के अनुसार विधायकों और अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आलम को लिखे गए कुछ सिफारिशी लेटर भी बरामद किए गए हैं। ये मई 2023 में ईडी की रांची ब्रान्च ने झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा था। जब्त किए नोट इतनी बड़ी तादाद में हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें भी गरम होकर थक गईं। नोट गिनने में बैंक अधिकारियों की मदद लेनी पड़ी। झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर रेड में 25 करोड़ रुपये की नकदी, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज मिले हैं। बताया जाता है कि यह भ्रष्टाचार ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। वीरेंद्र को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पिछले साल अपने बयान में कहा था कि ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य अभियंता रहते हुए वीरेंद्र राम ने ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन लिया, जो कि अपराध की कमाई है। इसके बाद अप्रैल में अधिकारी की 39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त भी की गई थी। उनके खिलाफ झारखंड एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था। सवाल यह है कि झारखंड में नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के पास से इतनी भारी नकदी कहां से आती है? जब दो नंबर के करोड़ों रूपए लोग घर में रखते हैं तो कमीशन का खेल कितना बड़ा होगा? पांच माह पहले दिसबंर में भी झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल थे। जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक, ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। ये पैसा कूड़े की तरह ठूंस कर रखा गया था। हैरानी की बात यह थी इस भ्रष्ट सांसद का परिवार आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ईडी आगे कार्रवाई करेगी तो राज्य में भ्रष्टाचार के और कारनामे उजागर होंगे।

अमन की दरकार, कश्मीर घाटी में मतदान

राजधानी के जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत राजधानी के तमाम विश्वविद्यालयों और कालेजों में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। काफी लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। सिविल सर्विस से लेकर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में काफी कश्मीरी युवक-युवतियां नौकरी भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में घाटी के युवक और युवतियां यहां अपना खुद का व्यवसाय कर रहे है। दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली से सटे दूसरे शहरों में भी कश्मीर से विस्थापित बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। राजधानी में रह रहे कश्मीरी समुदाय का मानना है कि वर्षों बाद उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है। घाटी से विस्थापन के बाद कश्मीरी दंपतियों के दिल्ली में जन्म लेने वाले बच्चे भी अब बड़े हो गये हैं। वे भी अब अपने पूर्वजों की जगह कश्मीर को जाकर देखना चाहते हैं।

आरके सिन्हा

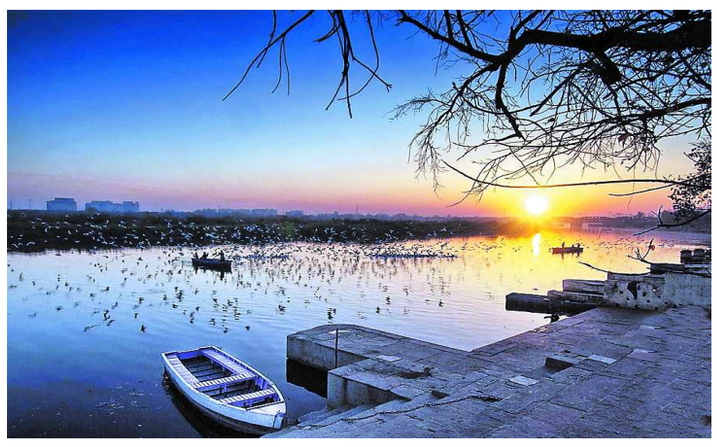

कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कुछ साल पहले तक सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही झुण्ड के झुण्ड दिखाई दिया करते थे, वहां आजकल लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोग खुलकर राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में धारा 370 को हटाये जाने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहे हैं। तब से घाटी की स्थिति में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। घाटी में आतंकवाद जब चरम पर चल रहा था, तब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और अन्य लोग वहां से भागकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में शरण ली थी। तब इनके सामने विस्थापन का संकट झेलने से लेकर अनिश्चित भविष्य की मुश्किलों का सामना करने के अलावा कोई दिशा या रास्ता भी तो नहीं था।

2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने जब धारा 370 को हटाया जिस एतिहासिक संसद के सत्र में भी भागीदार था, तब उनमें एक उम्मीद जगी है। तब से उन्हें यही महसूस हो रहा है कि अब वे किस तरह अपने कश्मीर जाकर फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट सकेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के दौर के बाद लाखों पंडितों ने अपमान और अत्याचार के दौर में घाटी को छोड़ा था। वे आगामी 13 मई को अपना वोट राजधानी के पृथ्वीराज रोड पर स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में जाकर डालेंगे। उस दिन श्रीनगर सीट के लिए वोटिंग होनी है। यहां कश्मीरी पंडितों को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके बाद 20 मई (बारामूला) और 25 मई को (अनंतनाग- राजौरी) में मतदान होगा। तब भी राजधानी और इसके आसपास रहने वाले कश्मीरी पंडित यहां आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे ढ्ढ सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी कराकर वहां की जनता की चुनी हुई सरकार को लाने और विकास कार्य में तेजी लाकर देश की मुख्य धारा से राज्य को जोड़ने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के अपने दौरे में इस बात को साफ तौर पर कहा भी था। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य का यह पहला दौरा था। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब दो लाख लोग वहां पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से बताया था कि कैसे उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालात को बदलने और वहां के युवाओं के लिए भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। राजधानी और एनसीआर में आज भी हजारों कश्मीरी पंडित रहते हैं।

ये अधिकतर दक्षिण दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को सरकार की ओर से हर महीने मासिक राहत पैकेज दिया जाता है। पहले यह 10,000 रुपये था, लेकिन पिछले साल 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसको 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कश्मीरी प्रवासी कार्डों में नाम जोड़ने को भी मंजूरी दे दी थी। इससे प्रवासियों के बड़े और विवाहित बच्चों को अपने स्वयं के कश्मीरी प्रवासी कार्ड प्राप्त करने और एएमआर के लिए पात्र बनने की अनुमति मिल गई।

उग्रवाद के दौरान विस्थापित हुए कश्मीरी परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार 1989-90 में एडहॉक मंथली रीलिफ (एएमआर) शुरू की थी। 16 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रह रहे कश्मीर लोगों के लिए इसको बढ़ाकर कश्मीरियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले 2007 में सरकार ने एएमआर को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। राहत पाने वालों की संख्या भी इस बीच काफी बढ़ी है। शुरू में जितने कश्मीरी परिवार दिल्ली में थे, अब तो उसमें काफी इजाफा हो गया है।

राजधानी के जामिया मिल्लिया इस्लामिया समेत राजधानी के तमाम विश्वविद्यालयों और कालेजों में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। काफी लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। सिविल सर्विस से लेकर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में काफी कश्मीरी युवक-युवतियां नौकरी भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में घाटी के युवक और युवतियां यहां अपना खुद का व्यवसाय कर रहे है।

दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली से सटे दूसरे शहरों में भी कश्मीर से विस्थापित बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। राजधानी में रह रहे कश्मीरी समुदाय का मानना है कि वर्षों बाद उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है। घाटी से विस्थापन के बाद कश्मीरी दंपतियों के दिल्ली में जन्म लेने वाले बच्चे भी अब बड़े हो गये हैं। वे भी अब अपने पूर्वजों की जगह कश्मीर को जाकर देखना चाहते हैं।

इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम कानून (एएफएसपीए) को भी रद्द करने पर विचार कर रही है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कश्मीर की कानून व्यवस्था को अब पूरी तरह जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सरकार भी मान रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्तकियों का मूवमेंट कम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद में 80 फीसदी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं तो पूरी तरह खत्म ही हो गई हैं। बंद, प्रदर्शन और हड़तालें भी नहीं हो रही हैं। गृह मंत्री ने कहा, 2010 में पथराव की 2564 घटनाएं हुई थीं, जो अब शून्य हैं। 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014-23 के दौरान यह घटकर 915 हो गई है। यह 68 प्रतिशत की कमी है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी और घटकर 341 हो गई है, जो 81 प्रतिशत की गिरावट है। सुरक्षा बलों की मौतें 1060 से घटकर 574 हो गईं, जो 46 प्रतिशत की कमी है।

मोदी सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। 36 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए 22 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और 150 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। 90 संपत्तियां भी कुर्क की गईं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

एक बात बहुत साफ है कि सरकार देश विद्रोही ताकतों को कुचलने के लिए तैयार है और जो वार्ता करना चाहता है उसका सदैव स्वागत भी है।

हां, उसे वार्ता संविधान के दायरे में आकर करनी होगी। बातचीत की प्रक्रिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे अलगाववादी संगठनों का कोई स्थान नहीं है। कहना न होगा कि अब देश बदला-बदला सा जम्मू-कश्मीर देख रहा है।

अध्यात्म

सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली?

अगर अध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाये तो सुदामाजी बहुत निर्धन थे। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा माँग कर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि पाँच दिन तक उसे भिक्षा नही मिली। वह प्रति दिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठवें दिन उसे भिक्षा में दो मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते-पहुँचते रात हो गयी। ब्राह्मणी ने सोंचा अब ये चने रात में नही खाऊँगी प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊँगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपडे में बाँधकर रख दिय। और वासुदेव का नाम जपते-जपते सो गयी। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गये। इधर-उधर बहुत ढूँढा। चोरों को वह चनों की बँधी पुटकी मिल गयी चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने में ब्राह्मणी जाग गयी और शोर मचाने लगी। गाँव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौडे, चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गये। (संदीपन मुनि का आश्रम गाँव के निकट था जहाँ भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।) गुरुमाता को लगा की कोई आश्रम के अन्दर आया है, गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ीं, चोर समझ गये कोई आ रहा है, चोर डर गये और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गयी। और सारे चोर भाग गये। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गये। तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया की मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खायेगा वह दरिद्र हो जायेगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम मे झाडू लगाने लगी। झाडू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली गुरु माता ने पुटकी खोल के देखी तो उसमे चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे (रोज की तरह)। गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी। और कहा बेटा ! जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालुम हो गया। सुदामा जी ने सोचा ! गुरु माता ने कहा है यह चने दोनो लोग बराबर बाँट के खाना। लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्रीकृष्ण को खिला दिये तो सारी सृष्टी दरिद्र हो जायेगी। नहीं-नहीं मै ऐसा नही करुँगा, मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जायें मै ऐसा कदापि नही करुँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा लेकिन कृष्ण को नही खाने दूँगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, चने खाकर। लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया

पाकिस्तान: किसका दोस्त किसका दुश्मन ?

ग़ौर तलब है कि भारत पाकिस्तान के मध्य अब तक चार युद्ध हुये हैं। इनमें पहला युद्ध आज़ादी के फ़ौरन बाद 1948 में लड़ा गया जिसका केंद्र कश्मीर था। उसके बाद 1965 में दूसरा युद्ध हुआ जबकि 1971 में वह तीसरा ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया। इसी युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए व बांग्लादेश नामक नये राष्ट्र का जन्म हुआ। यह तीनों ही युद्ध कांग्रेस के शासनकाल में लड़े गये। जबकि 1999 में एन डी ए के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपई के प्रधानमंत्रित्व काल में ऑपरेशन विजय नामक कारगिल युद्ध, मई और जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीरी उग्रवादियों के वेश में उनसे मिलकर नियंत्रण रेखा पार करने और भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का दुस्साहस किया था।

तनवीर जाफ़री

देश में लोकसभा चुनाव हों और पाकिस्तान की इंट्री न हो ऐसा बहुत कम ही देखा गया है। पाकिस्तान के चुनाव में भी प्रायः भारत विशेषकर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। दोनों जगह इसका मक़सद एक ही होता है कि जनता का ध्यान 'कथित राष्ट्रवाद' में उलझाकर उसे रोजगार,मंहगाई,शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचने व चर्चा करने का मौक़ा ही न दिया जाये। इस बार स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में पाकिस्तान को ज़ोर शोर से याद किया है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान ख़ान सरकार के एक पूर्व मंत्री रहे चौधरी फ़वाद हुसैन ने यह कह दिया कि पाकिस्तान को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि फ़वाद उस हद तक भी नहीं गये जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाकर 'अब की बार ट्रंप सरकार' का नारा तक लगवा दिया था। हालांकि चौधरी फ़वाद हुसैन के इस बयान पर राहुल गाँधी या कांग्रेस द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है। परन्तु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इसी बयान को आधार बना कर बात का बतंगड़ खड़ा करने की कोशिश ज़रूर की है। वे चुनावी जनसभाओं में कहते फिर रहे हैं कि 'पाकिस्तान 'कांग्रेस के शहज़ादे' को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है'। मोदी कहते हैं कि 'कांग्रेस मरी, तो पाकिस्तान रोया'। अब पाकिस्तान दुआ कर रहा है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहज़ादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है।' प्रधानमंत्री मोदी का इशारा पाते ही पूरे देश में भाजपाई राहुल और कांग्रेस पर हमलावर हो उठे हैं और कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताने की पुरज़ोर कोशिश होने लगी है। ऐसे में कांग्रेस व भाजपा व उनके नेताओं के पाकिस्तान से रिश्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना बेहद ज़रूरी है।

ग़ौर तलब है कि भारत पाकिस्तान के मध्य अब तक चार युद्ध हुये हैं। इनमें पहला युद्ध आज़ादी के फ़ौरन बाद 1948 में लड़ा गया जिसका केंद्र कश्मीर था। उसके बाद 1965 में दूसरा युद्ध हुआ जबकि 1971 में वह तीसरा ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया। इसी युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए व बांग्लादेश नामक नये राष्ट्र का जन्म हुआ। यह तीनों ही युद्ध कांग्रेस के शासनकाल में लड़े गये। जबकि 1999 में एन डी ए के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपई के प्रधानमंत्रित्व काल में ऑपरेशन विजय नामक कारगिल युद्ध, मई और जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने कश्मीरी उग्रवादियों के वेश में उनसे मिलकर नियंत्रण रेखा पार करने और भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का दुस्साहस किया था। उपरोक्त सभी युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। परन्तु पाकिस्तानी सरकार विशेषकर पाक सेना को 1971 का वह युद्ध भुलाये नहीं भूलता जिसने न केवल पाकिस्तान का नक़्शा बिगाड़ दिया बल्कि इसी युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के समक्ष विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्म समर्पण भी करना पड़ा था। अपनी उसी टीस को मिटने के लिये पाकिस्तान आज तक भारत विरोधी साज़िशें यहाँ तक कि भारत में आतंकवाद तक को प्रायोजित करता रहता है। लिहाज़ा यह प्रचारित करना कि पाकिस्तान कांग्रेस का हितैषी है सरासर दुष्प्रचार के सिवा और कुछ नहीं।

परन्तु इसी सन्दर्भ में भाजपा नेताओं विशेषकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान के प्रति उदारतापूर्ण बर्ताव की बात करना भी ज़रूरी है। याद कीजिये जून, 2005 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के संस्थापक नेता क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कराची स्थित मज़ार पर श्रद्धांजलि देने गये थे। उसी समय वे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाक़त अली ख़ान की मज़ार पर भी श्रद्धांजलि देने गये थे। इस दौरान आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताते हुए कहा था कि वह एक अलग शख़्सियत थे तथा उन्होंने इतिहास बनाया था। उस समय संघ व भाजपा में तो आडवाणी के इस क़दम का विरोध ज़रूर हुआ था मगर कांग्रेस ने चुनाव में इसे मुद्दा कभी नहीं बनाया गया।

उसके बाद मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने दक्षेस देशों के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ भी भारत आए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरीफ़ को उनकी मां के लिये एक शॉल भेंट किया था। शरीफ़ जब वह बेशक़ीमती शॉल लेकर पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी बेटी मरियम शरीफ़ ने इस तोहफ़े के लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया। मरियम ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरी दादी के लिए इतना बढ़िया शॉल गिफ़्ट करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे पिता ने ख़ुद अपने हाथों से यह तोहफ़ा दादी को दिया।' इस के फ़ौरन बाद जून 2014 के प्रथम सप्ताह में ही नवाज़ शरीफ़ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए तोहफे में 'रिटर्न गिफ़्ट' के रूप में एक क़ीमती साड़ी भेजी। उस समय मोदी ने भी ट्वीट किया था -'कि नवाज़ शरीफ़ ने मेरी मां के लिए शानदार सफ़ेद साड़ी भेजी है। मैं उनका आभारी हूं। जल्द ही मैं साड़ी अपनी मां के पास भेज दूंगा।' और उसी दिन देर शाम तक शरीफ़ का ये क़ीमती तोहफ़ा मां हीराबेन तक पहुंच भी गया था। इस तोहफ़े के लिए नरेंद्र मोदी ने उस समय प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का शुक्रिया भी अदा किया था। पड़ोसी देश के साथ आत्मीयता और क़ीमती तोहफ़ों के लेनदेन की ऐसी मिसाल कांग्रेस के शासनकाल में तो कभी नहीं सुनाई दी?

नरेंद्र मोदी व शरीफ़ के बीच आत्मीयता के रिश्ते की यही एक कहानी नहीं। याद कीजिये 25 दिसंबर, 2015 को जब वो पहली बार नवाज़ शरीफ की पोती के निकाह में शामिल होने के लिये बिना किसी पूर्व घोषित कार्यक्रम के पाकिस्तान पहुंच गये थे। उस दिन वो शरीफ की पोती की निकाह में भी शामिल हुए थे। उस समय मोदी ने नवाज़ शरीफ को अफ़ग़ानिस्तानी गुलाबी साफ़ा भी तोहफ़े में दिया था, जिसे शरीफ़ ने उसी समय विवाह समारोह में पहना भी था। तो क्या आडवाणी या मोदी का पाकिस्तान के प्रति दोस्ताना व सद्भावपूर्ण रवैया सौहार्द बनाने की कोशिश माना जाये और पाकिस्तान की नज़रों में हमेशा खटकने वाली कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त 2015 में अमित शाह बिहार चुनाव के दौरान कहते फिरते थे कि यदि लालू -नितीश का महागठबंधन चुनाव जीता और भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाख़े फूटेंगे। आज वही नितीश कुमार भाजपा के साथ हैं तो क्या अब नितीश की जीत पर पाकिस्तान में पटाख़े नहीं फूटेंगे? अवसरवादिता और राजनैतिक शातिरपने की भी आख़िर कोई इन्तेहा होती है ? सच तो यह है कि कांग्रेस व भाजपा के नेताओं के पाकिस्तान से रिश्तों के रिकार्ड ख़ुद इस बात के गवाह है कि पाकिस्तान किसका दोस्त है और किसका दुश्मन?

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

प्रतिष्ठित लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी। व्यापार में धैर्य से काम लेने के कारण बड़ा लाभ मिल सकता है। बीमार लोगों के रोग मुक्ति की सम्भावना है।

वृषभ

आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। सन्तान के करियर की चिन्ता रहेगी। उच्च शिक्षा में अच्छी सम्भावना मिल सकती है। नये सम्बन्धों का भरपूर लाभ उठायेंगे।

मिथुन

व्यवसाय में लाभ की स्थिति कमजोर हो सकती है। हृदय रोगियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये। स्वच्छ और पौष्टिक भोजन का सेवन करें।

कर्क

अनावश्यक मामलों में पड़ने से आपका समय बर्बाद हो सकता है। कुछ लोग आपको लक्ष्यों से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। मन :स्थिति थोड़ी विचलित रहेगी।

सिंह

समाज के लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने के कारण आप के ऊपर लोग काफी विश्वास करेंगे।

कन्या

सरकारी कार्यों में कुछ अवरोध आयेगा लेकिन उसे सम्भाल लेंगे। जीवनशैली में भोग-विलास की अधिकता रहेगी। वाक चातुर्य से लोग प्रभावित होंगे।

तुला

अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप न होने दें। अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें। भावुक होकर किसी पर भरोसा न करें।

वृश्चिक

व्यापार में नये समझौते करने पड़ सकते है। आपके मनोनुकूल कार्य नहीं होंगे। पूजा-पाठ में मन नहीं लगेगा। बुरी संगत के कारण प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है।

धनु

कानूनी मामले को लेकर परेशान हो सकते हैं। मित्रों के साथ पुरानी यादें ताजा करेंगे। ऑफिस के काम से दूर करना पड़ सकता है। आशा से अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होने से उत्साहित रहेंगे।

मकर

आज अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सम्भालकर रखें। लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रखेंगे। मन से कमजोरी न मानें। कुटुम्बजनों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें।

कुंभ

कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। आज गूढ विषयों का अध्ययन करेंगे। मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है।

मीन

बिना पूछे किसी को सलाह न दें वरना अपयश झेलना पड़ सकता है। पार्टनर्स मौके पर आपको धोखा दे सकते हैं। उलझे हुये मामले को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं।

कब बुझेगी पहाड़ों की आग?

उत्तराखंड के जंगलों में आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कुमायूं मंडल के बाद आग ने गढ़वाल मंडल में भी जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय में इस मसले पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। जस्टिस वीआर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आग बुझाने के लिए क्लाउड सीडिंग या इंद्र देवता पर आश्रित रहने की बजाय ठोस उपायों के जरिए इसे नियंत्रित करने को कहा है। टिहरी गढ़वाल की वकील रितुपूर्ण उनियाल की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि आग ने कुमायूं मंडल के जंगल के 44 फीसदी क्षेत्र को गिरफ्त में ले लिया है। पिछले साल नंबवर से अब तक ऐसी 910 घटनाएं हो चुकी हैं। पांच लोग मारे गए हैं। आग से अब तक 1145 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से न्यायालय को अब तक आग पर नियंत्रण पाने के उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। इन घटनाओं के लिए मनुष्य को जिम्मेदार बताते हुए अब तक 62 लोगों को नामजद किया है। नैनीताल सहित घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों तक आग फैलने का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में आग लगने से गर्मी बढ़ती है। बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। जिससे जल प्रणालियों और वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने आपातकालीन उपायों के तहत एक सप्ताह के लिए चारे में आग लगाने के कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। शहरी निकायों को जंगलों में और उसके आसपास ठोस अपशिष्ट जलाने से रोकने के निर्देश दिए गए। इसमें कोई दोराय नहीं कि जंगल की आग एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे प्रतिबंधित करने और दंडात्मक उपायों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जंगलों का जलना, जलवायु संकट के बढ़ने का संकेत दे रहा है। ऐसे में जैव मंडल और जनजीवन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितकीविदों, जलवायु वैज्ञानिकों, भू-विज्ञानी, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रंबधन विशेषज्ञों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रशासन के अलावा जनसमुदाय का सहयोग भी जरूरी होगा। गर्मियों के दौरान वन भूमि में बिखरी और संग्रहित चीड़ की सूखी पत्तियां जल्द आग पकड़ती हैं। फिर जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ दहन कार्य भी जरूरी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की कई रिपोट्र्स बताती हैं, कि कृषि के लिए भूमि साफ करते समय या जलते सिगरेट या बीड़ी के ठूंठों, आकशीय बिजली गिरने, बिजली के तारों के परस्पर टकराने के दौरान उठी चिंगारियों से भी जंगलों में आग लगती है। आम तौर पर फरवरी से जून माह तक ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। पिछले पांच सालों से क्षेत्र में कमजोर मानसून रहा, जिससे सूखा बढ़ा। ऐसे में मौसम की पूवार्नुमान प्रणाली, उपग्रह निगरानी, बचाव प्रणाली के साथ आम जन को भी प्रशिक्षित कर उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है।

नेपाल: नोट पर नक्शा, हकीकत नहीं बदल सकता

सामयिक

दोनों देश अपने साझा मूल्यों एवं हितों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान कर निकाल सकते हैं। इससे चीन का प्रभाव कम होगा और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ मिलेगी। भारत, अपनी समृद्ध विरासत कर प्रदर्शित कर नेपाली जनमत को प्रभावित कर सकता है।

महेश चन्द्र शर्मा

भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच आदिकाल से मधुर संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता रही है। लेकिन कुछ अर्से से इस देश पर चीन का जादू प्रभावी होने लगा है। इसके वषीभूत होकर वह बीच- बीच में कुछ ऐसे उकसाने वाले फैसले लेता जा रहा है जिसकी वजह से भारत के लिए स्थितियां असहज होती जा रही हैं।

इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद होना, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नेपाल सरकार ने यह फैसला लिया कि वह अपने सौ रुपये के नए नोट पर विवादित क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा छापने जा रही है। स्वाभाविक है यह फैसला भारत के लिए किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं है।

इस बाबत हाल ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का कहना है कि हमारी स्थिति स्पष्ट है। नेपाल के साथ हम एक प्लेटफार्म के जरिए अपने सीमा मामलों पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इस बीच यदि नेपाल सरकार की ओर से कोई एक तरफा कार्यवाही वाले कदम उठाए जाते हैं, तो वे हमारे बीच की स्थिति या जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते।

भौगोलिक स्थिति और सामरिक दृष्टि से नेपाल, हमारा सबसे करीब पड़ोसी देश है। इसकी 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा, भारत के पांच राज्यों- उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से मिलती है। सिर्फ सीमाएं ही नहीं मिलती बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी कायम हैं। वर्ष 2015 में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत ने जिस शिद्दत के साथ पड़ोसी-धर्म का निर्वहन किया है। वह काबिल-ए-गौर रहा। उस वक्त भारत ने 1. 54 बिलियन नेपाली रुपये की सहायता उपलब्ध कराई थी।

भारत पारगमन प्रदान कराने वाला नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का स्त्रोत है। वर्ष 2022 के दौरान नेपाल को भारत का निर्यात 8.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जबकि भारत का आयात 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। पनबिजली क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विनिर्माण, सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, रेल-सड़क परियोजनाओं और पर्यटन उद्योग आदि में भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण, गोरखा रेजीमेंट्स के गठन और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण संचालित होता है।

पिछले कुछ अर्से से नेपाल का चीन के प्रति लगाव बढ़ रहा है। उसके पीछे चीन वहां निवेश, सहायता और ऋण उपलब्ध करा रहा है। वह नेपाल को बीआरआई का प्रमुख भागीदार बनाना चाहता है। नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भी चीन का दखल बढ़ा है। ऐसी स्थिति में चीन की शह पर ही वह भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा कर रहा है। ताकि नेपाल का बफर राज्य के रूप में महत्व कम हो जाए। नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि 1861 के मुताबिक विवाद वाले इलाकों- लिपुलेख, लिपियाधुला और कालापानी समेत कालीनदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। चार साल पहले दोनों देशों के बीच यह मुद्दा काफी गरमा गया था। साल 2020 में तत्कालीन केपी ओली सरकार ने जब देश का नक्शा अपडेट किया था तब बदलाव को मजबूती देने के लिए इसके पक्ष में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया था।

मामला तब और भड़का जब भारत ने 8 मई 2020 को लिपुलेख होते हुए मानसरोवर की ओर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताते हुए भारत के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर जाती हुई यह सड़क पूरी तरह भारत के इलाके में पड़ती है।

मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देशों में अस्थायी तौर पर संवाद बंद हो गया था। लेकिन कुछ अर्से बाद दोनों पक्षों को इसका अहसास हुआ। तो इस मसले को एक साझा प्लेटफार्म पर बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमत हुए। यह प्रक्रिया जारी है। इस बीच सौ रुपये के नोट पर नेपाली विवादित क्षेत्रों को शामिल करने के नेपाली सरकार का फैसला नए विवाद के रूप में उभरा है।

नोट पर नक्शा छापने के फैसले पर तो नेपाल के भीतर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्रों पर नेपाल के दावों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं हुई है, उन्हें देश की करंसी पर छापने का फैसला कहीं जल्दबाजी तो साबित नहीं हो जाएगा। ऐसे में इस विवाद को निपटाने की जो प्रक्रिया दोनों देशों ने आपसी सहमति से तय की है, उसे आगे बढ़ाना ही श्रेष्ठ विकल्प है।

दोनों देष अपने साझा मूल्यों एवं हितों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान कर निकाल सकते हैं। इससे न केवल चीन का प्रभाव कम होगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ मिलेगी। साथ ही भारत, अपनी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्म समारोहों तथा वेलनेस रिट्रीट का आयोजन कर नेपाली जनमत को प्रभावित कर सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जल तरंग

शेरवानी की परेशानी

एक दिन सलीम भाई गर्मी के दिन में शेरवानी पहनकर अपने दोस्तों के बीच पहुँचे। उन्हें देखते ही दोस्तों की हँसी छूट गई। कहा-क्या मियाँ! कोई गर्मी के दिनों में शेरवानी पहनता है क्या? अजीब नमूने हैं। एक तरफ इतनी गर्मी है दूसरी तरफ हवा का नामोंनिशान नहीं। ऊपर से तुम्हारा तमाशा अलग से। इन्हीं हरकतों के चलते तुमको कोई लड़की नहीं दे रहा है। बदलों मियाँ बदलो! और कितने दिन ये बचकानी हरकत करेंगे? कुछ तो उम्र का लिहाज करो।

सलीम भाई की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गयी थी। गुस्से को जैसे-तैसे दबाया। फिर कहा-हाँ मियाँ! मेरी हरकतें तुम्हें हँसी दिलाने वाली हैं। फेसबुक, वाट्सप पर वतन स्मार्ट बनता जा रहा है, नई-नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधान और उनके चमचे फ्री में अनाज देने की बात करते हैं। अजब उलटबासी हैं यहाँ! इंसानी बदन मांस और हड्डियों का बना है। लोहे का तो है नहीं! बीमार पड़े तो इंसान अस्पताल जाना चाहता है। हमारे यहाँ अस्पताल से ज्यादा शराबखाने हैं। इंसान की मरम्मत करने से ज्यादा बिगाड़ने के ठिकाने हैं। दो- दो कदम पर मंदिर-मस्जिद मिलेंगे, पढ़ने के लिए स्कूल हरगिज नहीं। अंधविश्वास के ठिकाने जब तर्क- वितर्क पर हावी हो जाते हैं, तब इंसान अच्छे- बुरे की पहचान नहीं कर पाता। कोई एलोपैथी कहता है तो एलोपैथी के पीछे, कोई आयुर्वेद कहता है तो आयुर्वेद के पीछे दौड़ने लगता है। कौआ कान ले गया की तर्ज पर कौए के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। किसी के पास अपने कान छूकर देखने की सोच नहीं है। यहाँ हाथ में स्मार्टफोन, चढ़ने के लिए मेट्रो, पीने के लिए शराब मिल जाए तो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। कोई लड़की साइकिल पर अपने अब्बा को ले जाती है तो उसे आत्मनिर्भर कहते हुए देश का बड़ा तमगा दे दिया जाता है। असली हीरो को लात मारी जाती है और नकली हीरो को छाती से लगा लिया जाता है। जहाँ सांस लेने को एहसान माना जाता हो, वहाँ जीना भी किसी अजूबे से कम नहीं। मानता हूँ कि मैंने ऊपर शेरवानी पहनी है, लेकिन मुझे अंदर से कोई परेशानी नहीं है। कम से कम उन लोगों से तो खुशनसीब हूँ जो न दिखाई देने वाली ढोंगी शेरवानी पहने हैं और अंदर से असलियत में परेशान हैं।

सच है, यहाँ हर कोई ऊपर शेरवानी पहना है और अंदर से परेशानी से दो-चार हो रहा है। अंतर केवल इतना है कि किसी को यह शेरवानी दिखायी देती है तो किसी- किसी को यह नहीं दिखायी देती। सबकी परेशानियों के निशान अलग- अलग हैं। कुछ दिखाने में फेल हो जाते हैं, तो कुछ छिपाने में सफल।

-डा.सुरेश कुमार मिश्रा

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जीवन बोध

क्या है गुरु दीक्षा

गुरुदीक्षा सामान्य कर्मकांड नहीं है। हम सामान्य पूजा- पाठ करते हैं ना। सामान्य कर्मकांड करते हैं वैसा कर्मकांड नहीं है। गुरुदीक्षा के अंदर, आपके अंदर भाव महत्त्वपूर्ण है। अगर ये गुरुदीक्षा आपने शरीर स्तर के ऊपर ली है, तो उसका कोई फायदा, कोई चेंज, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन वो ही गुरुदीक्षा अगर आपने आत्मिक स्तर पे ली है तो आपके अंदर एक ही दिन में चेंज आ जाएगा, एक ही दिन में बदलाव आएगा। गुरुदीक्षा क्या है? वास्तव में, गुरु तो एक समुद्र है। यानी वो सबके लिए खुला हुआ है, सब कोई भी उसमें आ सकता है। यानी गुरु ने तो आपको स्वीकार कर लिया। जिस दिन आपको अनुभूति प्राप्त हुई ना, उसी दिन गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया। गुरु ने अपने गुरुतत्त्व का बीज आपके अंदर बो दिया। लेकिन प्रश्न है, आपने उसको स्वीकार किया क्या? आपने अगर उसको स्वीकार किया, तो वो गुरुदीक्षा ! यानी गुरुदीक्षा लेने के बाद में कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है, एक। दूसरा, गुरुदीक्षा शारीरिक कर्मकांड नहीं है। इसके अंदर आत्मिक कर्मकांड है। यानी आपकी आत्मा तो आप गुरु की आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद में वो इतना सूक्ष्म संबंध है, इतना निकट का संबंध है, इतना पास का संबंध है कि संबंध स्थापित होने के बाद में आपको कुछ करना वो ही नहीं पड़ता। गुरु की जैसे जैसे प्रगति होती जाती है, वैसे-वैसे आपकी प्रगति होती जाती है। **-शिवकृपानंद स्वामी**

विंडो टू द वर्ल्ड

पेट्रा सात अजूबों में से एक

दुनिया के सात अजूबों में से एक यह जॉर्डन में स्थित ऐतिहासिक नगर है, जो पत्थरों से तराशी इमारतों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। लाल रंग के पत्थरों की वजह से इसे रोज सिटी कहा जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन साम्राज्य ने पेट्रा को अपनी राजधानी स्थापित किया था, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है।

व्हॉट एन आइडिया

गर्मियों में क्यों होती है सर्दी-जुकाम की समस्या

गर्मी के इस मौसम में कई लोग सर्दी और खांसी की समस्या से भी परेशान रहते हैं। गर्मी के मौसम में अपने खानपान की आदतों में लापरवाही कर देते हैं, जिसके कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में ऐसी चीजों का सेवन करें जिनसे शरीर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन प्राप्त हो, जो कि व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर करने में सहायक होते हैं।

आज का विचार

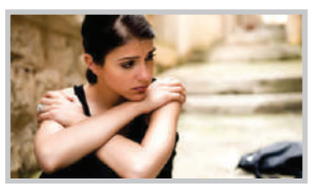

कोई आपका दिल दुखाए, तो बुरा मत मानिए।
कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं, उसी पर सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं।

-श्री ललितप्रभ

अपनों से अपनी सी बात

सच्ची तारीफ जरूर करें

कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, तारीफ की भूख हर किसी को रहती है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सराहे, उसके काम की तारीफ करे। खासकर महिलाओं में यह बात ज्यादा होती है। वो कह रही होती हैं- हमने इतना अच्छा खाना बनाया और पति महाशय चुपचाप खा कर खिसक लिए। हाँ बेचारी से कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाय तो सारे लोग सारा घर सिर पर उठा लेते हैं। जरा खाने की तारीफ कर दो भाई, दो प्यार के मीठे बोल दो, क्या जाता है तुम्हारा। उधर पति कहता है- मैं दिन भर दो रोटी के जुगाड़ के लिए मारा मारा फिरता हूँ। ना जाने किस किस के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, ना जाने किस- किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तब कहीं जाकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। और मुझे कोई इस घर में समझता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल इज्जत करते हैं भाई! पर लोगों का स्वभाव होता उनके श्रीमुख से किसी के लिए तारीफ के, प्यार के दो मीठे बोल ही नहीं निकलते। लोग क्या कहते हैं- अरे साब बड़ा बेकार आदमी है। एक नम्बर का शराबी है, रोज शराब पीता है। चाहे वो बेचारा महीने में एक आध बार ही पीता हो। दूसरा भाई कह देगा- शराब तो ठीक है पर जुआ भी खेलता है और चरित्र का भी हल्का है। अरे किसी के मलहम लगाने वाले बनिए, जख्म कुरेदने वाले नहीं। कोई आपसे आहत, व्यथित, दुःखी न हो, यही सबसे बड़ी साधना है। याद रखें आलोचना करने का अधिकार केवल आपके डॉक्टर, गुरु और सचिव का ही होता है। क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। वो ठकुर सुहाती नहीं बोलते, चाहें लोगों के दिल में रहें या कि उनके दिल से ही उतर जाएं।

-ललित 'अकिंचन'

Feedback@dainiknavajyoti.com

पर्व विशेष

अक्षय तृतीया: अक्षय फल का चमत्कारी महापर्व

भगवान कृष्ण शाश्वत हैं। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन भक्त उनके लिए कुछ भी करते हैं तो उन्हें उसका शाश्वत फल मिलता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। आज के दिन की यही विशेषता है और ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान, तीर्थ और तप अनन्त फलदायी होता है।

-अमितासन दास

अक्षय शब्द का अर्थ है- जो कभी क्षय अर्थात कम ना हो। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के बढ़ते चन्द्रमा का तीसरा दिवस है और आज के दिन से भारत के बहुत से मंदिरों में चन्दन यात्रा शुरू होती है जो पूरे 20 दिन तक जारी रहती है। वृन्दावन के मंदिरों में भगवान को चन्दन का लेप किया जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में उन्हें शीतलता प्रदान करता है। चन्दन यात्रा के दौरान नरसिम्हा जयंती भी आती है और इस विशेष दिवस पर भगवान नरसिम्हा को भी चन्दन का लेप लगाया जाता है, भक्त चन्दन की लकड़ी को पीसकर श्री भगवान को प्रेम और भक्ति से लगाते हैं।

मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन का हर क्षण भाग्याशाली है, क्योंकि इस दिन अति शुभ घटनाएं घटीं। पुराणों के अनुसार इस दिन त्रेता युग की शुरूआत हुई, पवित्र गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ, महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश ने आज ही के दिन महाभारत लिखना शुरू किया जिसमें भगवद्गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम का जन्म हुआ और युधिष्ठिर की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र दिया जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। अक्षय तृतीया का पावन पवित्र त्यौहार निश्चित रूप से धर्म आराधनाएं, त्याग, तपस्या आदि से पोषित ऐसे अक्षय बीजों को बोने का दिन है जिनसे समयान्तर पर प्राप्त होने वाली फसल न सिर्फ सामाजिक उत्साह को शतगुणित करने वाली होगी वरन अध्यात्म की ऐसी अविरल धारा को गतिमान करने वाली भी होगी जिससे सम्पूर्ण मानवता सिर्फ कुछ वर्षों तक नहीं पीढ़ियों तक स्नात होती रहेगी। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर हम सब संकल्पित बनें कि जो कुछ प्राप्त है उसे अक्षुण्ण रखते हुए इस अक्षय भंडार को शतगुणित करते रहें। यह त्यौहार हमारे लिए एक सीख बने, प्रेरणा बने और हम अपने आपको सर्वोतमुखी समृद्धि की दिशा में निरंतर गतिमान कर सकें। अच्छे संस्कारों का ग्रहण और गहरापन हमारी संस्कृति बने, तभी अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता होगी। अक्षय तृतीया किसानों एवं कुंभकारों के लिए विशेष महत्व का दिन है। शिल्पकारों के लिए भी यह बहुत महत्व का दिन है। बैलों के लिए भी बड़े महत्व का दिन है। प्राचीन समय से यह परम्परा रही है कि आज के दिन राजा अपने देश के विशिष्ट किसानों को राज दरबार में आमंत्रित करता था और उन्हें अगले वर्ष बुवाई के लिए विशेष प्रकार के बीज उपहार में देता था। लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि उन बीजों की बुवाई करने वाले किसान के धान्य- कोष्ठक कभी खाली नहीं रहते। यह इसका लौकिक दृष्टिकोण है। यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है तथा गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन खरीदना, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य करना अत्यंत लाभदायक एवं फलदायी होते हैं।

आज के दिन अबूझ सावा होता है और सभी मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के संपन्न किये जाते हैं। हम मन्त्रों का जाप करें जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हमे दिव्य और अक्षय फल मिलता है।

अक्षय तृतीया के दिन सुदामा अपने प्रिय मित्र भगवान कृष्ण से मिले थे, वो दीन थे और उनके पास भगवान को देने के लिए भेंट रुपी चावल के अलावा और कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण तो बस सच्चे प्रेम और भावे के भूखे हैं तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपने सखा सुदामा की झोपड़ी को महल बना दिया।

वृन्दावन में अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को बिहारी जी के चरणों के दर्शन मिलते हैं और खास बात ये है कि ऐसा बस साल में एक बार आज ही के दिन होता है, तो यह महिमा है अक्षय तृतीया के सौभाग्याशाली दिवस की। आज के दिन अबूझ सावा होता है और सभी मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के संपन्न किये जाते हैं। आज के दिन अगर हम पवित्र सरोवरों में स्नान करें, पूजा- अर्चना करें, दान- पुण्य करें, मन्त्रों का जाप करें जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हमे दिव्य और अक्षय फल मिलता है। तो आप भी आज के दिन से महामन्त्र का जाप करके और पूजा अर्चना करके अपने इस अक्षय धन का संचय करें, क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरे कृष्ण !

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक
जलते दीप
जोधपुर, शुक्रवार 10 मई 2024

सवालों के घेरे में टीकाकरण

एक बार फिर भारत में हुआ कोरोना टीकाकरण सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल, ब्रिटेन की कोरोना टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वहां के उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि उसके टीके का दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव हो सकता है। इससे खून के थक्के जमने, खून में प्लेटलेट घटने और इस वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है। अब कंपनी ने दुनिया भर से अपने टीके वापस मंगाने का फैसला किया है। इससे भारत में भी लोगों में एक प्रकार का खौफ पैदा हो गया है। दरअसल, भारत में लगाया गया कोविशील्ड टीका एस्ट्राजेनेका के फार्मूले पर ही तैयार किया गया, जिसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। हमारे यहां इसके टीकाकरण को लेकर शुरू में ही विवाद छिड़ गया था। तब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उचित प्रक्रिया से परीक्षण किए बगैर इसे व्यापक स्तर पर लगाया जा रहा है। मगर तब सरकार, तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ, यहां तक कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी बार-बार लोगों को आश्वस्त किया था कि कोरोना के टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। मगर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि कोविशील्ड को चूंकि ब्रिटेन में मान्यता मिल चुकी थी, इसलिए भारत में उसे तीन के बजाय दो चरण में परीक्षण कराने के बाद ही मंजूरी दे दी गई थी। टीकाकरण के बाद यहां भी कई लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि उनके शरीर पर टीके का दुष्प्रभाव पड़ा है। पिछले साल जब देश में दिल का दौरा पड़ने के मामलों में उछाल दर्ज किया गया, उत्सवों में नाचते, कसरत करते या खेलते हुए अचानक लोगों के गिर कर मर जाने की घटनाएं बढ़ गईं, तो इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में सवाल भी पूछे गए। तब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इस पर अलग-अलग संस्थाएं अध्ययन कर रही हैं और उनके नतीजे आने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मगर अभी तक इससे जुड़े एक भी अध्ययन की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। अब भी चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी टीके का दुष्प्रभाव उसके लगने के चार से छह हफ्तों में प्रकट हो जाते हैं। अब दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं रह गया है। मगर लोगों में इसके दुष्प्रभावों को लेकर जो भय पैदा हो गया है, उसके निराकरण की दरकार बनी हुई है। यह ठीक है कि जिस तरह कोविड ने पांव पसारना शुरू किया था और उसकी चपेट में आकर लोगों की मौत हो रही थी, उस पर काबू पाने के तत्काल उपाय की जरूरत थी। ऐसे में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उत्पादन से काफी राहत मिली थी। मगर सरकार इस तथ्य से आंख नहीं चुरा सकती कि टीकाकरण में जल्दबाजी दिखाई गई और इन्हें लेने के लिए लोगों को बाध्य किया गया। यह भी तथ्य है कि दुनिया का कोई भी टीका सौ फीसद सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता, हर किसी का कोई न कोई दुष्प्रभाव होता ही है। मगर इस आधार पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संदेह के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। अभी तक सरकार कोरोना से हुई मौत के वास्तविक आंकड़े न जारी करने को लेकर सवालों से घिरी हुई है, अगर कोविशील्ड को लेकर भी उसने टालमटोल का रवैया अख्तियार किया, तो विवाद और बढ़ेगा ही।

अदना सा कर्मचारी किरोड़ी

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के छापे में झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के एक मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर से करोड़ों रुपये के ढेर बरामद होना, हर नागरिक को परेशान कर गया। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि यह धन कैसे जुटाया गया होगा और चुनाव के दौरान इसकी क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि एक अदने से आदमी के घर इतना धन कैसे पहुंचा? कौन इस खेल के खिलाड़ी हैं? पैसा किसका था? निस्संदेह, ऐसे तमाम सवाल आम नागरिकों को परेशान करते हैं। हालांकि,यह छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े एक मामले में हुई थी, जिसे पिछले वर्ष ईडी ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। धनशोधन का एक हिस्सा मंत्री के निजी सचिव व उसके घरेलू सहायक से भी जुड़ा था। जाहिर बात है कि सचिव व सहायक तो मात्र मोहरे हैं और बड़े स्तर के संरक्षण के बिना नोटों के अंबार नहीं लगाये जा सकते। प्रकरण यह भी बताता है कि कैसे विकास कार्यों का पैसा उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से राजनेताओं तक पहुंचता है। बहरहाल, हाल के दिनों में आम चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की सख्ती के चलते भारी मात्रा में जो नगदी आदि बरामद की गई है, वह भी चौंकाने वाली है। पहले चरण के मतदान से पूर्व चार हजार छह सौ करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी हो चुकी थी। यह बरामदगी आजाद भारत के आम चुनावों के दौरान हुई सबसे बड़ी बरामदगी है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हर रोज सौ करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी हो रही है। इस बरामदगी में पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा मादक पदार्थों का रहा है। जाहिर है ये नगदी, सामान व नशीले पदार्थ मतदाताओं को बहकाने,भ्रमित करने व लुभाने के लिये ही ले जाए जा रहे थे। ये कोशिशें धनबल के जरिये चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की हो रही थीं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव के दौरान काले धन को सफेद करने की कवायदें खासी तेज हो जाती हैं। इस कालेधन का महज एक छोटा हिस्सा ही चुनाव आयोग और दूसरी नियामक एजेंसियों की नजर में आता है। राजनीतिक दल भी पांच साल तक ज्ञात-अज्ञात स्रोतों से अर्जित धन को चुनावी चंदा बताकर मतदाताओं को बहकाने-लुभाने में खर्च करते रहे हैं। बहुत सारे अनैतिक धंधों से जुड़े लोग भी चुनाव के दौरान जीतने वाले राजनीतिक दल या प्रत्याशी को आर्थिक सहायता देकर बाद में मोटा मुनाफा हासिल करते हैं। यह विडंबना ही है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी हम अपनी चुनाव प्रणाली को पारदर्शी व स्वतंत्र नहीं बना सके। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले संदिग्ध धन का उपयोग कई तरीके से किया जाता रहा है। हाल के दिनों में शीर्ष अदालत की सक्रियता से चुनावी बॉन्डों के लेनदेन में जो विसंगतियां उजागर हुई उसे सारे देश ने देखा। कैसे दागदार कंपनियां भी चुनावी बॉन्ड खरीदकर पाक-साफ बनी और बड़ी योजनाएं हासिल करने में सफल हुई। जाहिर है कि बड़ी कंपनियां राजनीतिक दलों के चंदे में निवेश इसी मकसद से करती हैं कि जब उनकी सरकार बने तो मुनाफे के शार्टकट हासिल किये जा सकें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की कारगुजारी पर नजर रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने कई ऐसे रुझान उजागर भी किये। इस मामले में अदालतों के अलावा चुनाव आयोग को भी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले धनबल पर अंकुश लगाने के लिये सख्त कदम उठाने होंगे। इस दौरान उन सरकारी अधिकारियों पर भी निगाह रखी जानी चाहिए जो अनुचित ढंग से राजनीतिक दलों को मदद करने का प्रयास करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि भविष्य में उस दल की सरकार बनने पर मलाईदार पद व मनचाही पोस्टिंग हासिल की जा सके। आयोग को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुचित धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिये कठोर कदम उठाने चाहिए। इस दौरान मादक पदार्थों व शराब की बड़ी मात्रा में बरामदगी भी गंभीर चिंता का विषय है। चुनाव आयोग की शक्तियों के विस्तार की भी जरूरत महसूस की जा रही है।

प्रसंगतः ईमानदारी का पाठ

देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सादगी और ईमानदारी के लिए शुरू से विख्यात थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी ने उन्हें मीडिया प्रभारी बनाया। कांग्रेस की गतिविधियों की कौन सी खबर प्रकाशित होनी है, कौन नहीं, इसका निर्णय राजेंद्र बाबू को करना होता था। वह अखबारों में खबरें भी खुद ही पहुंचाते थे। एक बार वह इलाहाबाद के लीडर प्रेस गए। उस समय लीडर प्रेस के संपादक सी वाई चिंतामणि थे। उनकी राजेंद्र बाबू से गहरी दोस्ती थी। जब राजेंद्र बाबू प्रेस पहुंचे तो गेट पर बैठे चपरासी ने कहा, 'इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। उनके पास कई नेता बैठे हुए है। आप को इंतजार करना पड़ेगा।' राजेंद्र बाबू ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, 'ठीक है, यह उन्हें दे दो। जब वह खाली हो जाएंगे तो मुझे बुला लेंगे।' चपरासी ने कार्ड चिंतामणि की मेज पर रख दिया और चला आया। उस समय ठंड ज्यादा थी और हल्की बूंदाबादी भी हो रही थी। राजेंद्र बाबू भीग गए थे। कार्यालय के बाहर कुछ मजदूर अंगीठी जला कर आग ताप रहे थे। राजेंद बाबू भी वहीं बैठ गए। काफी देर के बाद चिंतामणि की नजर उस कार्ड पर पड़ी। वह नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने चपरासी से पूछा, 'यह कार्ड देने वाले सज्जन कहां हैं?' चपरासी ने कहा, 'वहां बैठ कर आग ताप रहे हैं। मैंने उन्हें रोक लिया था।' चिंतामणि को देख कर राजेंद्र बाबू भी आ गए। दोनों गले मिले। चिंतामणि ने कहा, 'आज इसकी गलती से आपको बहुत तकलीफ हुई।' फिर वह चपरासी को डांटते हुए बोले, 'तुमने राजेंद बाबू को रोका क्यों?' राजेंद्र बाबू का नाम सुनते ही चपरासी कांपने लगा और माफी मांगते हुए बोला, 'मैंने आप को पहचाना नहीं साहब। मुझे माफ कर दें।' राजेंद्र बाबू बोले, 'तुमने कोई गलती की ही नहीं तो माफी क्यों मांगते हो। तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है और आगे भी इसी तरह निभाते रहना।'

'नोटा' को कांग्रेसी प्रत्याशी बनाने की कोशिश

– हेमंत पाल

देश में इंदौर की अपनी अलग पहचान है। ये शहर लगातार सात बार देश में स्वच्छता में अव्वल रहा। शुद्ध हवा में इसने कीर्तिमान बनाया। स्मार्ट सिटी के कामकाज के मामले में भी इंदौर को देश में पहला नंबर मिला। पिछले लोकसभा चुनाव में इंदौर ने अपने एक उम्मीदवार को साढ़े पांच लाख से ज्यादा के अंतर से जिताकर संसद में भेजा था, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मध्यप्रदेश के मालवा अंचल का यह शहर खासी चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि संसदीय सीट के कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा वापस लेने वाले दिन चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर सबको चौंका दिया। ऐसी स्थिति में चुनाव पूरी तरह एक तरफ़ा हो गया। यानी भाजपा के उम्मीदवार के सामने अब कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा।

चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह स्थिति काफी पेचीदगी वाली होती है कि ऐन वक्त पर उसका उम्मीदवार मैदान छोड़ दे। न सिर्फ चुनाव से हट जाए, बल्कि नामांकन पर्चा वापस लेने के बाद प्रतिद्वंद्वी दल में शामिल हो जाए। इंदौर में कांग्रेस के साथ यही हुआ! नामांकन पत्रों की जांच के बाद जब सही पाए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, तो संपत्ति ब्योरे के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम को प्रदेश में सबसे ज्यादा अमीर कांग्रेसी उम्मीदवार माना गया। लेकिन कई हफ्तों तक चुनाव प्रचार के बाद वे अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाकर मैदान से हट गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उनमें से किसी को समर्थन देने के बजाय मतदाताओं से यह अपील की, कि वे अपना वोट 'नोटा' में डालें।

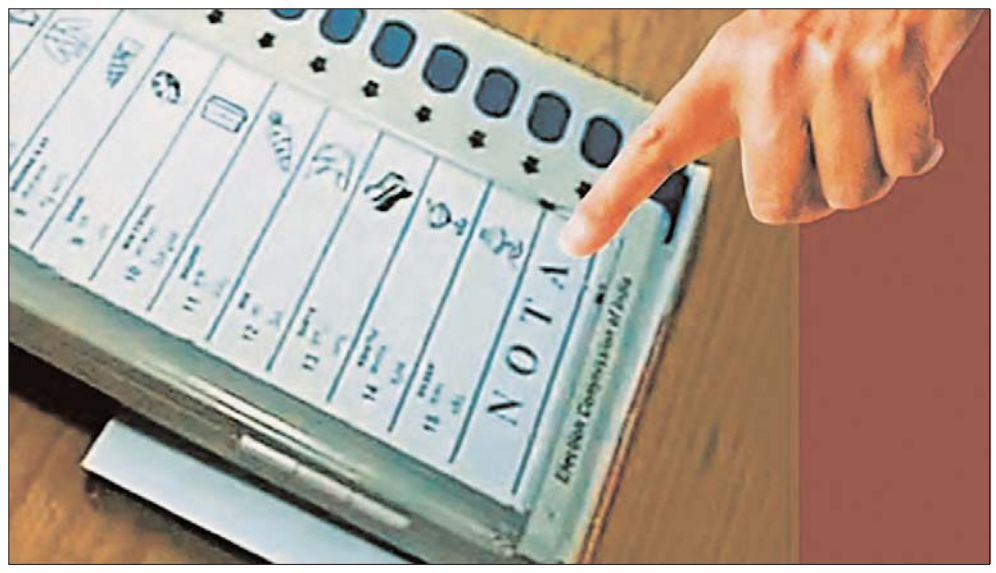

ये संभवतः देश में अनोखा उदाहरण है, जब किसी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल ने प्रतिद्वंद्वी पार्टी से मुकाबले के लिए 'नोटा' का सहारा लिया। कांग्रेस ने बाकायदा इस बात की घोषणा की है कि जो मतदाता इंदौर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से खुश नहीं हैं, वे 'नोटा' का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज कराएं। दरअसल, कांग्रेस उम्मीदवार का चुनाव से पीछे हटना भाजपा का राजनीतिक हथकंडा समझा जा रहा है। बदले हालात में कांग्रेस के पास ऐसा कोई विकल्प भी नहीं था कि वो मुकाबले में उतर सके। तो उसने 'नोटा' को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। लेकिन, सवाल है कि क्या 'नोटा' का दबाने से कोई ऐसा नतीजा सामने आएगा जो नतीजे पलट दे? तो इसका जवाब 'नहीं' ही होगा। क्योंकि, 2013 में जब मतदाताओं को 'नोटा' का विकल्प देने का फैसला हुआ, तब यह भी स्पष्ट किया गया था कि 'नोटा' को कितने भी वोट मिल जाएं, पर इससे नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। यानी 'नोटा' में जाने वाले वोट रद्द समझे जाएंगे। लेकिन, इससे चुनाव में 'नोटा' का विकल्प उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का 14वां देश जरूर बन गया।

यह बात सही है कि 'नोटा' के आंकड़ों से चुनाव नतीजे अप्रभावित रहते हैं, पर इससे उम्मीदवार की जीत पर सवालिया निशान जरूर लगता है। माना कि ईवीएम का यह बटन 'बिना दांत का शेर' है, पर इसकी गुर्राहट के चर्चे तो होते ही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव (2019) में देशभर में 'नोटा' का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 65,22,772 थी। अनूठी बात तो यह कि देश के करीब 20 राजनीतिक दलों के करीब तीन दर्जन उम्मीदवार ऐसे भी थे, जिन्हें 'नोटा' से कम वोट मिले, पर वे जीत का झंडा लेकर संसद में पहुंचे। 2013 में जब 'नोटा' का बटन अस्तित्व में आया, उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसे प्रयोग किया गया। उस चुनाव में 60 लाख से अधिक मतदाताओं ने इसे चुना। सबसे ज्यादा 6 लाख बार 'नोटा' का बटन उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने दबाया। यहां 23 सीटें ऐसी थी, जहां हार-जीत के अंतर से ज्यादा वोट 'नोटा' को मिले। इसी लोकसभा चुनाव में बिहार में 5.80 लाख, गुजरात में 4.54 लाख, मध्य प्रदेश में 3.91 लाख, ओडिशा में 3.32 लाख, छत्तीसगढ़ में 2.24 लाख और झारखंड में 1.90 लाख वोट 'नोटा' खाते में गए।

अभी भले ही 'नोटा' को 'नख और दंतविहीन शेर' समझा जाता हो, पर तय है कि भविष्य में 'नोटा' की ताकत को बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की याचिका भी दायर की गई है। अपील की गई है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 'नोटा' को बहुमत मिलने पर उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शून्य घोषित कर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। कहा गया है कि 'नोटा' को 'काल्पनिक उम्मीदवार' के रूप में माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को इस बारे में नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस याचिका पर विचार करने को सहमत हो गया है, जिसमें 'नोटा' में अधिक वोट पड़ने पर चुनाव आयोग को फिर चुनाव का नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।

अब सारी नजरें इस बात पर लगी हैं कि जब इंदौर का चुनाव नतीजा घोषित होगा तो 'नोटा' में कितने वोट पड़ेंगे? क्योंकि, इस संसदीय क्षेत्र में 'नोटा' का आशय सिर्फ 'नन ऑफ द एबव' (इनमें से कोई नहीं) ही नहीं है। बल्कि, इसे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना लिया।

लेकिन वहीं चुनावी मुकाबले में भाजपा के सामने कोई प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार न होने से मतदाताओं में मतदान के प्रति भी रूखापन दिखाई दे रहा है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि 'नोटा' में पड़े वोटों का आंकड़ा बढ़े या नहीं, पर मतदान का प्रतिशत जरूर गिर जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन चुनाव, सिर्फ मोदी चेहरा

पिछले तीन चुनावों में हर बार बढ़ी वोटिंग, भाजपा को मिला फायदा, इस बार बीजेपी-कांग्रेस दोनों में गुटबाजी

छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर लोकसभा के लिए वोटिंग हो गई। पिछले चार चुनावों में छत्तीसगढ़ में एक बात सुकून देने वाली है कि वोटिंग का परसेंट हर बार एक-दो प्रतिशत बढ़ता रहा। 7 मई को शाम 6 बजे तक छत्तीसगढ़ में 67.07 प्रतिशत वोटिंग हुई। आंकड़े अभी बढ़ेंगे। इससे पहले तीन चुनावों में लगातार वोटिंग बढ़ी थी। 2009 में 55.3 फीसदी, 2014 में 69.5 प्रतिशत और 2019 में 73. 8 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यानी पिछले 15 सालों में करीब 18 प्रतिशत वोटिंग बढ़ी है। सशक्त लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है।

मुद्दाविहीन चुनाव- पिछले चुनावों के विपरीत इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन हो गया लगता है। 2009 और 2014 में यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा जबरदस्त उछला था। इस दौरान 2-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श घोटाला, कॉमन वेल्थ गेम्स घोटाला समेत कई घोटालों की चर्चा होती थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 2019 में पांच साल पूरे करने के बाद राफेल का मुद्दा पूरे देश में छाया। लेकिन पुलवामा की आतंकी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर कांग्रेस की बयानबाजियों ने चुनाव का रुख मोड़ दिया। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव बना, जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ मोदी का चेहरा है और अगर मुद्दे हैं, तो कांग्रेस उसे अब तक लोगों के बीच पहुंचा नहीं पाई। कांग्रेस हर मंच से महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी, दलित, सांप्रदायिकता पर बात करती रही, लेकिन ये बातें घरों तक नहीं पहुंच पाई। इन सबके जवाब में भाजपा मोदी का चेहरा सामने ले आई।

छत्तीसगढ़ में कितना कारगर रहा मोदी का चेहरा- छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जो हाल देश के बाकी हिस्सों का है, कमोबेश वही हाल छत्तीसगढ़ का है। जब प्रत्याशियों की घोषणा की गई, तो कई चेहरे अप्रत्याशित थे। दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडेय को छोड़कर सभी नए चेहरे सामने लाए गए। ये ऐसे नाम थे, जो बहुत ज्यादा चर्चा में कभी नहीं रहे, जबकि इनके सामने कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा। यानी भाजपा को मोदी के चेहरे पर इतना भरोसा था कि टिकट मिलेगा, तो संगठन जिताकर ले आएगा। दिग्गजों को उतारने के बाद भी आखिरी तक कांग्रेस में इस आत्मविश्वास की कमी दिखती रही।

टिकट ही नहीं चाहते थे कई कांग्रेसी नेता- चुनाव से पहले ये चर्चा काफी तेज थी कि, कांग्रेस के नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इस फेहरिस्त में भूपेश बघेल का भी नाम था। हालांकि इन चर्चाओं को उस समय विराम लग गया, जब नामों की घोषणा हुई। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री समेत दिग्गज पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों को चुनावी समर में उतारा। कारण शायद ये हो सकता है कि चर्चित नामों को उतारने से पब्लिक के बीच में ज्यादा मेहनत की जरूरत न हो।

..तो क्या मोदी का जादू चल गया- पहले और दूसरे चरण तक तो हर तरफ मोदी-मोदी की गूंज थी, लेकिन तीसरे चरण में यह चमक थोड़ी फीकी हुई। राम मंदिर, धारा 370, हिन्दू-मुस्लिम जैसे फैक्टर ज्यादा नहीं दिखे। ये कहा जा सकता है कि तीसरे चरण के आते-आते मोदी के नाम ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के पास इस वैक्यूम का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वोटर्स के पास विकल्प मोदी का नाम हो सकता है। हालांकि यह फ्लक्चुएशन बहुत कम ही रहा होगा, लेकिन ये हुआ है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन मजबूती के साथ विकल्प दे पाता तो उनके लिए स्थिति थोड़ी ठीक हो पाती। फिर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस नतीजों की उम्मीद कर रही थी, वो आसानी से उन्हें हासिल नहीं होगी। 2019 में 9 भाजपा और 2 कांग्रेस के आंकड़े रिपीट भी हो जाएं, तो संशय नहीं। क्या रहा सीटों का हाल-

बस्तर सीट- कांग्रेस ने कवासी लखमा को उतारा। वे लोकप्रिय चेहरा हैं। भाजपा ने एकदम नया प्रत्याशी दिया। बड़े नेता नहीं चाहते थे कि एक और लीडरशिप बस्तर से खड़ी हो, लेकिन मोदी मैजिक ने बस्तर में काम किया। लोग मोदी और फूल को जानते हैं।

कांकेर- कांकेर में सांप्रदायिक ध्रूवीकरण दिखा है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस से चुनाव हारे बिरेश ठाकुर ने काफी मेहनत की, लेकिन ध्रूवीकरण का फायदा भाजपा के भोजराज नाग को मिल सकता है। मोदी मैजिक यहां चला है।

राजनांदगांव- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से ये वीआईपी सीट बन गई। यहां उन्होंने बहुत मेहनत की है। सांसद संतोष पांडेय के खिलाफ एंटी इकम्बेंसी भी थी। लेकिन मोदी मैजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा संतोष पांडेय को मिल रहा है।

दाऊ सुरेंद्र के दिए बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ- चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता सुरेंद्र दाऊ ने मंच से उनको जमकर खरी-खरी सुनाई। दाऊ ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर राजनांदगांव से प्रत्याशी बदलने तक की मांग कर दी थी। भूपेश के खिलाफ सुरेंद्र दाऊ ने मोर्चा खोल दिया था, जो पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रहा।

अकबर, एजाज और नवाज खान का नाम भी इलेक्शन से जुड़ा- प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने राजनांदगांव में चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही ये बयान देकर सियासी हलचल मचा दी। जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश को वोट देना यानी नवाज खान, अकबर और ढेबर को वोट देना है। इसका असर रहा है।

महासमुंद- जाति फैक्टर और मोदी के चेहरे पर यहां चुनाव हुआ। साहू समाज एकजुट दिखा है। दूसरा कोई मुद्दा काम नहीं किया। भाजपा ने सिटिंग एमपी चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी को उतारा। समाज एकजुट हो गया। इस कारण टक्कर की स्थिति बन गई।

रायपुर- यहां 40 साल से विधायक और मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल के जीत के फासले की चर्चा है। कांग्रेस के विकास उपाध्याय ने बृजमोहन जैसे बड़े नेता के खिलाफ अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में बृजमोहन को पछाड़ना आसान नहीं। बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र भेजने को लेकर भी चर्चाएं रहीं। राज्य में उनके कद के सामने दूसरे कोई मंत्री टिक नहीं रहे थे। कुछ टकराहट भी हो सकती थी। लिहाजा चर्चा रही कि शक्ति संतुलन के लिए बृजमोहन के केंद्र भेजना ठीक रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री के रूप में वे अभी हैं। अगर बड़ी जीत हुई, तो केंद्र में मंत्री के दावेदार रहेंगे।

कोरबा- 2019 में देश में मोदी लहर थी। तब कांग्रेस ने बस्तर और कोरबा की सीट जीती थी। ज्योत्सना महंत सांसद थी। कांग्रेस ने दोबारा उन्हें उतारा, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी थी। गुटबाजी भी हुई, लेकिन जितनी गुटबाजी कांग्रेस में थी, उतनी ही भाजपा में भी। बड़े नेता ही नहीं चाहते थे कि सरोज पांडेय कोरबा से चुनाव जीतें। वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पार्टी में बड़ा कद है। चुनाव जीतने पर वे भी मंत्री की दावेदार हैं। मोदी मैजिक यहां भी दिखा है। पाली तानाखार यहां की विधानसभा सीट है, जहां इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। अगर गोंगपा ने ज्यादा वोट काटे, तो इसका फायदा भाजपा को होना स्वाभाविक है। पिछली बार ज्योत्सना महंत ज्यादातर जगहों से पीछे थीं, उन्हें जीत यहीं से मिली थी।

जांजगीर-चांपा- इस लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। शिव डहरिया ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जवाबदारी देकर जमकर मेहनत की। यह बसपा का भी गढ़ रहा है। बसपा तो इस चुनाव में बेहद कमजोर हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में संविधान बदलने की चर्चा रही। दलित क्षेत्रों में संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की स्वीकार्यता बहुत अधिक है। भाजपा से कमलेश जांगड़े को काफी टक्कर मिली है। उन्हें सिर्फ मोदी के नाम का सहारा रहा।

बिलासपुर- साहू वर्सेस यादव के कारण यह सीट चर्चा में आ गई। स्थानीय विष्णु यादव, महापौर रामशरण यादव भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस से भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर शिफ्ट किया गया। देवेंद्र ने बहुत कम समय में शानदार छाप छोड़ी। तोखन साहू मुंगेली क्षेत्र से आते हैं। दिलीप सिंह जूदेव को छोड़ दें, तो ज्यादातर सांसद मुंगेली क्षेत्र से ही रहे हैं। साहू वोटर्स की बहुलता है, लेकिन दूसरे नंबर पर यादव समाज के वोटर्स हैं। कांग्रेस ने इन्हीं वोटरों को साधने के लिए देवेंद्र को शिफ्ट किया। रामशरण यादव टिकट खरीद-बिक्री वाले ऑडियो टेप में ट्रैप हो गए। विष्णु यादव की जमीनी तैयारी बहुत कमजोर थी। देवेंद्र यादव चर्चित नाम थे, चुनाव के लिए आर्थिक मैनेजमेंट में सक्षम थे, लिहाजा उन्हें मौका मिला। यह डिप्टी सीएम अरुण साव के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वरिष्ठ भाजपा नेता व विधायक अमर अग्रवाल के लिए भी। अरुण साव मुंगेली से ही विधायक हैं और अमर अग्रवाल को बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा क्लस्टर की जिम्मेदारी भी दी गई है। भविष्य में कैबिनेट का फेरबदल यहां की जीत-हार पर भी निर्भर होगा।

सरगुजा- कांग्रेस से बीजेपी में आए चिंतामणि महाराज को टिकट मिलने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन मोदी के चेहरे की वजह से यहां भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दिया। कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह महंगाई के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई। राज्य बनने के बाद अब तक कांग्रेस यहां जीत नहीं पाई है।

रायगढ़- ये सीट हमेशा से भाजपा की रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम ओपी चौधरी की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। 25 सालों बाद राजपरिवार की सदस्य मेनका सिंह को कांग्रेस ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट में राठिया समाज के लोग सबसे ज्यादा है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को सीधे इसका फायदा मिलते दिखा वहीं मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है।

दुर्ग- दुर्ग क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की लम्बी फेहरिस्त है, लेकिन इस चुनाव के दौरान राजेन्द्र साहू प्रचार में अकेले पड़ गए। यहां के तीन नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव खुद अलग-अलग क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे। जबकि बाकी नेता फील्ड पर दिखाई ही नहीं दिए। दुर्ग में बड़ा चेहरा नहीं होने से मामला एक तरफा भाजपा की ओर दिख रहा है।

राधिका खेड़ा विवाद के कारण याद रहेगा यह चुनाव- ऐसे तो इस चुनाव में छोटे-मोटे विवाद सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर का इस्तीफा रहा। राधिका ने कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पर अभद्रता का आरोप लगाया। इसके बाद नेशनल मीडिया के सामने राम भक्ति के कारण अपमानित होने का आरोप लगाया और भाजपा ज्वाइन कर ली। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित विषय यदि कोई आया, तो वह यही था। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के सामने मंच पर दाऊ सुरेंद्र का बयान भी चर्चा में रहा। चरणदास महंत का मोदी को मारने का मुद्दा भी छाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में इस बात की चर्चा करते रहे कि कांग्रेसी मोदी को डंडा मारना चाहते हैं। उधर, बस्तर में कवासी लखमा का सरसो तेल लेकर प्रचार करना भी याद रहेगा। चुनाव के बीच ही बिरनपुर में सीबीआई की एंट्री हुई। महादेव घोटाले और आबकारी घोटाले में जांच तेज हुई।

चार बड़े नक्सल एनकाउंटर- लोकसभा चुनाव के बीच चार बड़े नक्सल एनकाउंटर हुए। 30 अप्रैल को नारायणपुर में अबूझमाड़ के टेकामेटा गांव में मुठभेड़ हुई थी। जिसमें 63 लाख के 10 नक्सली मारे गए थे। इनमें एक 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली जोगन्ना भी था। 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेठिया के हापाटोला इलाके में मुठभेड़ हुई। यहां फोर्स ने 1 करोड़ 78 लाख रुपए के कुल 29 नक्सलियों को ढेर किया था। यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे सफल ऑपरेशन था। 6 अप्रैल को तेलंगाना राज्य की सीमा पर मुठभेड़ हुई थी। इसमें 3 नक्सली मारे गए थे। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में मुठभेड़ हुई। यहां पुलिस ने 13 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक पुलिस ने कुल 91 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नारायणपुर और कांकेर की मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों पर कुल 2 करोड़ 41 लाख रुपए का इनाम था।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

अडानी अम्बानी पर मोदी के बयान के बाद जांच जरूरी

लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाता रहा है कि वे अपने मित्रों अम्बानी और अडानी के फायदे के लिए सरकारी स्तर पर काम कर रहे हैं। अब मोदी ने अडानी अम्बानी को लेकर तेलंगाना के करीम नगर में चुनाव सभा में आरोप लगाया कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से राहुल गांधी ने अंबानी-अडानी को गालियां देना बंद कर दिया है। चुनाव में अडानी-अंबानी से कितना माल उठाया है? काले धन के कितने बोरे भरकर के रुपए मारे हैं? क्या टेंपो भरकर के नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है, आपने रातों-रात अंबानी-अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है? पांच साल तक अंबानी-अडानी को गाली दी और रातों-रात गालियां बंद हो गई। 14 मार्च को लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद से राहुल गांधी ने कितनी बार अंबानी-अडानी का नाम लेकर उन पर और मोदी पर अपने पुराने आरोप दोहराए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सामने आकर बताया कि 3 अप्रैल से 7 मई तक राहुल अपने भाषणों में 103 बार अडाणी और 30 बार अंबानी का नाम लेकर आरोप लगाते रहे हैं। उसके बाद एबीपी न्यूज सहित एक-दो चैनल ने मोदी के आरोप को झूठ की जगह गलतबयानी बताते हुए राहुल के चुनाव प्रचार के भाषण के दो-तीन वीडियो भी दिखाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर आरोप की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई और तारीख के साथ राहुल के अंबानी-अडाणी पर दिए भाषण के वीडियो अपलोड किए गए। मोदी के आरोप का राहुल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको यह मालूम होगा कि ये लोग टैंपों से पैसा देते हैं। क्या यह पर्सनल एक्सपीरियंस है? एक काम कीजिए, सीबीआई-ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी इंक्वायरी कराइए। भाजपा के भ्रष्टाचार के टैंपो का ड्राइवर और खलासी कौन है, यह देश जानता है। सवाल ये है कि मोदी ने ये बयान क्यों दिया? पूरा देश जानता है कि पिछले 10 साल से मोदी ने कभी भी अंबानी-अडानी का सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिया। तब चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा क्यों किया? भाजपा जिस तरह रणनीति बनाकर चुनाव लड़ती है, उसमें ये संभव नहीं है कि यह कोई अनायास दिया गया बयान हो। इसके पीछे कारण क्या रहे, इनका आने वाले दिनों में पता लग सकेगा। महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि क्या ईडी,सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री के इस बयान को गंभीरता से लेकर अडानी-अंबानी के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी? क्या टेंपो में भरकर गए बोरों को जब्त करने के लिए उनके यहां छापेमारी की जाएगी? देश का प्रधानमंत्री अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो जाहिर है कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त सबूत व तथ्य होंगे, तो क्यों नहीं मोदी खुद ही इन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा देते हैं। ताकि पता लग सके कि अंबानी-अडानी तथा राहुल के बीच क्या डील हुई है और कितना माल उन तक पहुंचा है। मोदी का बयान ये भी जाहिर कर रहा है कि दोनों उद्योगपति काला धन कमा रहे हैं। फिर तो उन पर का कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मोदी तो खुद काले धन और अवैध कमाई के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और ईडी कई विपक्षी नेताओं को मनी लांड्रिग और काली कमाई के आरोप में जेल पहुंचा चुकी है। यहां तो प्रधानमंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेताओं के मामलों में तो पूछताछ के दौरान आरोपी के नाम लेने पर ही ईडी उन्हें दबोच लेती है।

तप, शक्ति एवं मंगल का पर्व है अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई, 2024 को है। यह दिन किसानों एवं कुंभकारों के लिए विशेष महत्व का दिन हैं। शिल्पकारों के लिए भी यह बहुत महत्व का दिन है। बैलों के लिए भी बड़े महत्व का दिन है। प्राचीन समय से यह परम्परा रही है कि आज के दिन राजा अपने देश के विशिष्ट किसानों को राज दरबार में आमंत्रित करता था और उन्हें अगले वर्ष बुवाई के लिए विशेष प्रकार के बीज उपहार में देता था। लोगों में यह धारणा प्रचलित थी कि उन बीजों की बुवाई करने वाले किसान के धान्य-कोष्ठक कभी खाली नहीं रहते। यह इसका लौकिक दृष्टिकोण है। लोकोत्तर दृष्टि से अक्षय तृतीया पर्व का संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ के साथ जुड़ा हुआ है। तपस्या हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, आधार तत्व है। हिन्दु धर्म में उपवास व्रत के रूप में प्रतिष्ठित है। विशिष्ट तिथियों, पर्वों, त्यौहारों पर विविध उद्देश्यों एवं कामनाओं की पूर्ति के लिये उपवास किये जाते हैं।

ललित गर्ग

अक्षय तृतीया महापर्व का न केवल सनातन परम्परा में बल्कि जैन परम्परा में विशेष महत्व है। इसका लौकिक और लोकोत्तर-दोनों ही दृष्टियों में महत्व है। यह त्यौहार अध्यात्म, आरोग्य, मंगल एवं उपवास का विलक्षण संगम है। इस त्यौहार के साथ-साथ एक अबूझा मांगलिक एवं शुभ दिन भी है, जब बिना किसी मुहूर्त के विवाह एवं मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक एवं मांगलिक ढांचों में ढले अक्षय तृतीया पर्व में हिन्दू-जैन धर्म, संस्कृति एवं परम्पराओं का अनूठा संगम है। रास्ते चाहे कितने ही भिन्न हों पर इस पर्व के प्रति सभी जाति, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय और धर्मों का आदर-भाव अभिन्नता में एकता का प्रिय संदेश दे रहा है। युद्ध, हिंसा एवं महामारी के समय में संयम एवं तप की अक्षय परम्परा को जन-जन की जीवनशैली बनाने की जरूरत है। अक्षय तृतीया का पावन पवित्र त्यौहार निश्चित रूप से धर्माराधना, त्याग, तपस्या आदि से पोषित ऐसे अक्षय बीजों को बोने का दिन है जिनसे समयान्तर पर प्राप्त होने वाली फसल न सिर्फ सामाजिक उत्साह को शतगुणित करने वाली होगी वरन अध्यात्म की ऐसी अविरल धारा को गतिमान करने वाली भी होगी जिससे सम्पूर्ण मानवता सिर्फ कुछ वर्षों तक नहीं पीढ़ियों तक स्नात होती रहेगी। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर हम सब संकल्पित बनें कि जो कुछ प्राप्त है उसे अक्षुण्ण रखते हुए इस अक्षय भंडार को शतगुणित करते रहें। यह त्यौहार हमारे लिए एक सीख बने, प्रेरणा बने और हम अपने आपको सर्वोतमुखी समृद्धि की दिशा में निरंतर गतिमान कर सकें। अच्छे संस्कारों का ग्रहण और गहरापन हमारी संस्कृति बने, तभी अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता होगी।

इस्लाम में नमाज, जकात, हज आदि बुनियादी धार्मिक कृत्यों में एक है रोजा। रोजा का अर्थ बताया गया-रुक जाना। कुरआने करीम-रोजा सब मुसलमानों का फर्ज है। रोजा उपवास का एक रूप है, जो चांद एवं तारों की साक्षी से खोला जाता है। इसी प्रकार साइबेरिया, अमरीकन- इंडियन कबीलों एवं युनाइटेड स्टेट्स के उत्तरी-पश्चिमी इलाकों में भी किसी-न-किसी रूप में उपवास किये जाते हैं- ऐसा शोधार्थी मानते हैं। उनका विश्वास है, उपवास के समय ईश्वर सपनों के माध्यम से दैवीय शिक्षा देते हैं। पेरु में पादरी के समक्ष पापों को स्वीकारने के लिये उपवास जरूरी माना जाता है। जूडेइज्म में प्रायश्चित के दिन एवं अन्य अवसरों पर उपवास का विधान है। इन सब तथ्यों का निष्कर्ष है कि उपवास सभी धर्मों और सभी देशों में धार्मिक आस्था के साथ हुआ व्यापक उपक्रम है। कहा जाता है कि संसार की जितनी समस्याएं हैं तपस्या एवं उपवास से उनका समाधान संभव है। संभवत: इसीलिए लोग विशेष प्रकार की तपस्याएं करते हैं और तपस्या के द्वारा संसार की आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों संपदाओं को हासिल करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में वर्षीतप यानी एक वर्ष तक तपस्या करने वाले साधक इसदिन से तपस्या प्रारंभ करके इसी दिन सम्पन्न करते हैं। यह संसार से मोक्ष की मुस्कान, शरीर को तपाने और आत्मस्थ करने का अवसर है। अक्षय तृतीया तप, त्याग और संयम का प्रतीक पर्व है। इसका सम्बन्ध भगवान ऋषभदेव के युग और उनके कठोर तप से जुड़ा होने से वर्षीतप की परम्परा चली। यह ऋषभ की दीर्घ तपस्या के समापन का दिन है। अपने आदिदेव की स्मृति में जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में असंख्य श्रावक-श्राविकाएं वर्षीतप करते हैं। जिनकी तपस्या का पूर्णाहुति एवं नये वर्षीतप के संकल्प के लिये इस दिन देशभर में आचार्यों और मुनियों के सान्निध्य में अनेक आयोजन होते हैं। इसका मुख्य आयोजन हस्तिनापुर (जिला मेरठ- उत्तर प्रदेश) में श्री शांतिनाथ जैन मन्दिर में एवं प्राचीन नसियांजी, जो भगवान ऋषभ के पारणे का मूल स्थल पर आयोजित होता है, वहां पर देशभर से हजारों तपस्वी एकत्र होते हैं और अपनी तपस्या का पारणा करते हैं। सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा का नाम है ऋषभ। वे सम्राट से संन्यासी बने, उनके प्रति जनता में गहरा आदर भाव था। यही कारण रहा कि उनके प्रजाजनों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान ऋषभदेव को भिक्षा में भोजन की भी आवश्यकता होगी। भगवान ऋषभ प्रतिदिन शुद्ध आहार की गवेषणा एवं तलाश करते हुए घर-घर में घूमते, लेकिन अज्ञानता के सघन आवरण के कारण कोई भी उन्हें भोजन उपहृत नहीं करता। लोग उन्हें आदर के साथ हाथी, घोड़े, रथ, रत्नाभूषण, रत्न जड़ित पादुकाएं ग्रहण करने की प्रार्थना करते। उनका मत था कि वे अपने सृजनहार को अपने पास की सबसे बड़ी एवं कीमती वस्तु उपहृत करें। इस तरह बिना आहार के भगवान ऋषभ की तपस्या के बारह महीने पूरे हो गए। इस क्रम में आप पादविहार करते हुए हस्तिनापुर पधारते हैं। आपका प्रपौत्र श्रेयांस कुमार राजमहल के गवाक्ष में बैठा सड़क के दृश्य को देख रहा है। अचानक उसकी नजरें सड़क पर भिक्षा की गवेषणा में नंगे पैर घूमते अपने संसारपक्षीय परदादा भगवान ऋषभदेव पर पड़ती है। भगवान ने प्रपौत्र श्रेयांस के हाथों इक्षुरस का सुपात्र दान लेकर एक नई परम्परा की शुरूआत की। इन अप्रत्याशित क्षणों के साक्षी बनकर देवलोक से समागत देवतागण भी अहोदानं-अहोदानं की ध्वनि प्रकट करते हुए पांच प्रकार के द्रव्यों की वर्षा की। एक दृष्टि से धर्म क्षेत्र में नयी सोच के दर्शन कराने वाला दिन बन गया। यही सन्दर्भ तपस्या और साधना का शुभ मुहूर्त बन गया। प्रतीकात्मक रूप में इसे वर्ष भर तक एकांतर तप (एक दिन छोड़कर पुन: उपवास) की साधना के साथ मनाये जाने की परम्परा ने विगत कुछ वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। तपस्या को जैन धर्म साधना में अत्यन्त महत्पूर्ण स्थान दिया जाता है। मोक्ष के चार मार्गों में तपस्या का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। तपस्या आत्मशोधन की महान प्रक्रिया है और इससे जन्म जन्मांतरों के कर्म आवरण समाप्त हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसकी साधना से जीवन विकास की सीख हमारे चरित्र की साख बने। हममें अहं नहीं, निर्दोष शिशुभाव जागे। यह आत्मा के अभ्युदय की प्रेरणा बने।

सनातन धर्म में इसी दिन शादियों के भी अबूझ एवं स्वयंसिद्ध मुहूर्त रहता है और थोक में शादियां होती है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वे पुरी तरह सफल होते हैं एवं शुभ कार्यों को अक्षय फल मिलता है। भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया था। जो दक्षिण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है तथा गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन खरीदना, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य करना अत्यंत लाभदायक एवं फलदायी होते हैं। इतना ही नहीं अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन एवं प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ के पट (द्वार) भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
अधिकारियों का रवैया नकारात्मक रहेगा। विरोधियों के साथ वाद-विवाद न करें। संतान से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा की संभावना है। धनखर्च होगा। कार्य सफलता में विलंब होने के कारण निराशा का अनुभव होगा।

वृष
आज आपको काफी संवेदनशीलता का अनुभव होगा। इस कारण किसी के द्वारा आपकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। आज आपको मां की बीमारी की चिंता होगी। मकान या जमीन के दस्तावेजी काम आज न करें।

मिथुन
अनुकूल वातावरण रहेगा और साथियों का सहयोग मिलेगा। आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे। दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे।

कर्क
आज आप के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आप पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। परिवार में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहेगा। मन में भावनात्मकता बढ़ेगी। मां की ओर से फायदा होगा। उत्तम विवाह सुख प्राप्त होगा। काम समय से पूरा नहीं होगा।

सिंह
काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नए काम की शुरुआत न करें। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा। वाणी पर संयम रखें। खर्च ज्यादा होगा। आज आपका दिन शुभ है। व्यापार बढ़ाने को लेकर आपके प्रयास रंग लाएंगे।

कन्या
जमीन-जायदाद के दस्तावेजी काम कर सकेंगे। आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं एवं अनुकूलताओं से भरा होगा। लेखन-साहित्य से जुड़े काम कर सकेंगे। हालांकि, व्यवसायिक स्थल पर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी। आपका मन द्रवित हो उठेगा।

तुला
मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे। अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिलेगी। कमिशन, ब्याज से आपकी आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
आज रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ मुलाकात से आप आनंद का अनुभव करेंगे। आर्थिक योजना में आपको पहले थोड़ी मुसीबत हो सकती है, आपके जरूरी काम भी शुरुआती विलंब के बाद आसानी से पूरे होने पर शांति का अहसास करेंगे।

धनु
महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान रखें। वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें। विदेश से कोई समाचार मिल सकता है। कानूनी बातों का निर्णय सोच-समझकर करें। आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आको लाभ होगा।

मकर
प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे। पत्नी के संग से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा।

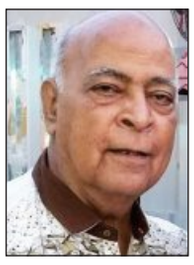

कुंभ
दूसरों की ओर से चिंता कम होगी। इस कारण आप का मन खुश रहेगा। परिजनों या दोस्तों के साथ अच्छे भोजन का अवसर मिलेगा। कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों से संबंधित व्यवस्था कर सकेंगे।

मीन
मानसिक व्यग्रता को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता, योग का सहारा लें। महिला और पानी से बचकर रहें। अभ्यास के लिए समय मध्यम है। आज आप को ज्यादा संवेदनशील एवं भावुकता भरे विचार आएंगे। महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा।

आज का इतिहास

10 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की 1503 में खोज की।
- पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद (आगरा) में प्रवेश किया।
- ब्रिटिश सेना ने जमैका पर 1655 में कब्जा किया।
- लुई 15वें की मौत के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा 1774 में बना।
- नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को 1796 में हराया।
- लंदन की नेशनल गैलरी को 1824 में आम लोगों के लिए खोला गया।
- भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था।
- दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को 1857 में मार डाला था।
- नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम में 1916 में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय खोला गया।
- जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग पर 1940 में आक्रमण किया।
- रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर 1945 में कब्जा किया।
- सोवियत सेना 1959 को अफगानिस्तान पहुंची।
- अमेरिका ने 1972 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- लंदन में ईरानी दूतावास पर 1980 में कब्जा खत्म हुआ।
- पहली बार बॉम्बे (वर्तमान में मुंबई) 1981 में रात में क्रिकेट मैच खेला गया।
- संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी।
- दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गयी।
- दक्षिण अफ्रीका की सोने की एक खान में लिफ्ट पर 1995 में ट्रेन गिरने से 104 मजदूरों की मौत।
- मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जोकि अल्बर्टो फिसानों 2003 में 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे।
- लाहौर-अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर 2005 में भारत और पाकिस्तान सहमत।
- नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आस्कर एरियास ने 1987 में दुबारा कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य स्थली पर होने वाले भेदभाव पर 2007 में रिपोर्ट जारी की।
- सीरिया की राजधानी दमिश्क 2012 में दो बम धमाकों में 55 लोगों की मौत और 370 अन्य घायल।
- दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2014 के आम चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जीत हुई ।

10 मई को जन्मे व्यक्ति

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब का जन्म 1834 में हुआ।
- बांग्ला और हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म 1905 में हुआ।
- भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं 'पद्म भूषण' से भी सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ।

विशेष आलेख

कांग्रेस का लगातार भट्टा बैठाने के बाद सैम पित्रोदा को आखिर हटना पड़ा

अशोक भाटिया

अपनी नस्लवादी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सैम पित्रोदा ने बुधवार को अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनके इस फैसले को सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार नहीं था कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की हो इसके पहले भी अपने विवादास्पद बयान से वे कांगेस का भट्टा बैठा चुके है व बाद में कांग्रेस को उन बयानों पर लीपा पोती करके अपने को संभालना पड़ा है । अक्सर राहुल गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले पित्रोदा ने हालिया बयान में कहा कि भारत के पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया , जिसमें वह भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना इस तरह करते नजर आ रहे हैं जिससे कोई भी नाराज हो सकता है ।पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई-बहनें हैं। वे कहते हैं कि हम अलग-अलग भाषाओं, धर्मों और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है, जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा-बहुत समझौता करता है। देखा जाए तो यह बहुत सामान्य सी बात है। हम लोग आम जीवन में इस तरह की तुलनात्मक बातें करते रहते हैं। पर जब कोई शख्स आम के बजाय खास बन जाता है तो उसकी बातचीत के कई मतलब निकाले जाते हैं। और जब चुनाव चल रहे हैं और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक के जिम्मेदार सदस्य हैं तो आपकी जवाबदेही और बनती है कि आप क्या बोल रहे हैं? शायद यही कारण है कि सैम पित्रोदा का बयान वायरल होते ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है, जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर हमला करने का मौका किसने दिया?

इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में संपदा के पुन: वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सकते में आ गई। पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल, भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का। भाजपा ने 5 साल में क्या किया, उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किनारा करना पड़ा और पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं। कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती? क्योंकि यह बार-बार देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक गलती करने वाला बार-बार वैसी ही गलतियां करता है। उन गलतियों को पार्टी उनका व्यक्तिगत मामला मानकर पल्ला झाड़ लेती है। यह भी कहती है कि उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है। पर बाद में ऐसे शख्सियत जब पार्टी में पुरस्कृत होते हैं तो संदेह होना लाजिमी हो जाता है। एक उदाहरण दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह लगातार आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जताने के जाने जाते हैं। कभी ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद के नाम के आगे जी लगाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। इसी तरह उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर में भी मारे गए आतंकियों के लिए संवेदना जताई थी। हर बार वो इस तरह की गलतियां करते रहे हैं पर उनपर कोई एक्शन भी नहीं होता। अब लोकसभा टिकट से उन्हें उनकी गलतियों के लिए पुरस्कृत किया गया है।

जाहिर है कि ऐसा ही विजय वेडट्टियार और चरनजीत सिंह चन्नी के साथ भी है। चरनजीत सिंह चन्नी ने एयरफोर्स हमले को ही फॉल्स ऑपरेशन की संज्ञा दे दी। विजय वेडट्टियार ने कसाब को निर्दोष करार दे दिया। इस तरह की बातें करने वालों पर कोई एक्शन नहीं होने से कई बार ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस में यह सब एक योजनाबद्ध तरीक से तो नहीं होता ।क्योंकि दूसरी पार्टियों में इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत दंडित कर दिया जाता है। पित्रोदा केस में ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया है पर उन्हें दंडित नहीं किया गया है। ये बात खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कही है कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है पर उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है। मतलब सीधा है कि कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया है पित्रोदा खुद अलग हो गए हैं। कांग्रेस में अकसर ऐसा देखा गया है कि किसी खास मुद्दे पर ठीके एक दूसरे से विरोधी विचार सामने आते हैं। और एक साथ आते हैं। द्रमुक नेता उदयनिधि मारन के सनातन को डेंगू मलेरिया कहने के बाद कांग्रेस में एक साथ कई विचार आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे को उदयनिधि मारन की बातों में कोई बुराई नहीं दिखी। पर ठीक उसी समय मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका खंडन किया। देशभर में दर्जनों ऐसे नेताओं के बयान आए जो मारन की बातों से यकीन नहीं रखते थे। तो बहुत से लोगों ने सीधे मारन और खरगे को सपोर्ट किया। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी पार्टी में अलग-अलग विचार सामने आते रहे। कोई समर्थन में था तो कोई इसके विरोध में । कोई भी पार्टी इस तरह के विचारों पर एक मत नहीं है तो निश्चित है कि उसके समर्थकों में कन्फ्यूजन पैदा होगा। पर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इस तरह एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार करके सभी विचार वालों को पार्टी चुनावों में साध लेगी।

चुनाव आयोग को कम वोटिंग के कारणों से सबक लेना चाहिए

तीसरे चरण के मतदान के अंत में आधे लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने के साथ ही सबसे चिंताजनक बात जो सामने आई है, वह है मतदाताओं द्वारा कम मतदान। गत 2019 के चुनावों की तुलना में यह औसतन लगभग 3.5 प्रतिशत कम मतदान है, जिसका मतलब है कि लाखों मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए व्यापक जागरूकता अभियान और प्रधानमंत्री द्वारा सभी मतदाताओं और विशेष रूप से पहली बार मतदाताओं से की गई जोरदार अपील के बावजूद संख्या में गिरावट आई है। गुजरात जैसे राज्यों में भी मतदान प्रतिशतता कम हो गई है, जहां मतदान लगभग 58 प्रतिशत है, जो 2014 और 2019 के चुनावों की तुलना में कम है। पिछले चुनाव में यह 64.11 फीसदी था। उत्तर प्रदेश में भी यही कहानी है। आम धारणा थी कि मतदान प्रतिशत कम होने पर कैडर आधारित राजनीतिक दलों को फायदा होता है, क्योंकि ऐसी पार्टियों के प्रतिबद्ध कैडर मतदाता चाहे कुछ भी हो, मतदान के लिए जाते हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि गैर-कैडर आधारित राजनीतिक दल, जो फ्लोटिंग मतदाताओं पर निर्भर हैं, हारने वाले हैं। हालांकि यह सिद्धांत कई बार गलत साबित हुआ है। जाहिर तौर पर इसमें अन्य कारक भी शामिल हैं। इनमें से एक है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के प्रति मतदाताओं की उदासीनता। एक वर्ग शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि यह 'एक पार्टी की दौड़' है और मतदान करने का कोई मतलब नहीं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की मनमानी के डर से मतदान नहीं करने का फैसला किया। हालांकि इसका एक बड़ा कारण चुनावों का डेढ़ महीने से अधिक समय तक चलने वाला लंबा कार्यक्रम हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव कराने के लिए यह सबसे बड़ी अवधि है। और यह पहली बार है कि आम चुनाव के नतीजे जून महीने में घोषित किए जाएंगे। इससे राजनीतिक थकावट और देश भर में बढ़ते तापमान के कारण मतदान प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

भीषण गर्मी के दौरान चुनावी प्रक्रिया को इतनी लंबी अवधि तक फैलाने के सवाल पर चुनाव आयोग के पास कोई विश्वसनीय जवाब नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान पहले ही 40 डिग्री सैल्सियस को पार कर चुका है और मई के महीने में इसके और खराब होने की संभावना है। केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के अन्य स्टार प्रचारकों के अभियान की उपयुक्तता से प्रभावित हुआ होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पीर पराई चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता?

-ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पुरा हो गया है, जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं राजनेताओं एवं उम्मीदवारों के दागदार चरित्र की परते खुलती जा रही है। एक समय था कि जब लोग देश के नेताओं के सार्वजनिक जीवन में आचरण का अनुसरण करते थे। नेताओं को भी समाज में अपनी छवि व प्रतिष्ठा की फिक्र रहती थी। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में कई क्षत्रप परिवारों के ऐसे नेता भी सामने आए हैं जिन्होंने सत्तामद में चूर होकर तमाम नैतिकताओं व मयार्दाओं को ताक पर रखा। पिछले दिनों कर्नाटक में हासन सीट से जनता दल (सेक्यूलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार के जो गंभीर आरोप लगे, उसने राजनीति में पतन की पराकाष्ठा को दशार्या है। वही रांची में एक पुराने मामले की जांच कर रही ईडी को रेड में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर पर काम करने नौकर के यहां से 39 करोड कैश बरामद हुआ है। यौन उत्पीड़न, दुराचार, भ्रष्टाचार एवं देशद्रोह पर सवार नेताओं एवं दागदार उम्मीदवारों से जुड़ा यह चुनाव लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न है। हमारी राजनीति एक त्रासदी बनती जा रही है। राजनेता सत्ता के लिये सब कुछ करने लगा और इसी होड़ में राजनीति के आदर्श ही भूल गया, यही कारण है देश की फिजाओं में विषमताओं और विसंगतियों का जहर घुला हुआ है और कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। डर लगता है राजनीतिक भ्रष्टाचारियों से, अपराध को मंडित करने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से, देश की एकता एवं अखण्डता को दांव पर लगाने वालों से एवं यौन उत्पीड़न व दुराचार से नारी अस्मिता को नौंचने वालों से।

देश दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। समाज में बहुत कुछ बदला है, मूल्य, विचार, जीवन-शैली, वास्तुशिल्प सब में परिवर्तन है। चुनाव प्रक्रिया बहुत खचीर्ली होती जा रही है। ईमानदार होना आज अवगुण है। अपराध के खिलाफ कदम उठाना पाप हो गया है। धर्म और अध्यात्म में रुचि लेना साम्प्रदायिक माना जाने लगा है। किसी अनियमितता का पदार्फाश करना पूर्वाग्रह माना जाता है। सत्य बोलना अहम्-पालने की श्रेणी में आता है। साफगोही अव्यावहारिक है। भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं देना समय को नहीं पहचानना है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इन और ऐसे बुनियादी सवालों पर चर्चा होना जरूरी है। आखिर कब तक राजनीतिक स्वार्थों के नाम पर नयी गढ़ी जा रही ये परिभाषाएं समाज और राष्ट्र को वीभत्स दिशाओं में धकेलती रहेगी? विकासवाद की तेज आंधी के नाम पर हमारा देश, हमारा समाज कब तक भुलावे में रहेगा? चुनाव के इस महायज्ञ में सुधार की, नैतिकता की, मूल्यों की, सिद्धान्तों की बात कहीं सुनाई नहीं दे रही है? दूर-दूर तक कहीं रोशनी नहीं दिख रही है। बड़ी अंधेरी और घनेरी रात है। न आत्मबल है, न नैतिक बल।

महान एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए आयोज्य यह चुनावरूपी महायज्ञ आज महाभारत बनता जा रहा है, मूल्यों और मानकों की स्थापना का यह उपक्रम किस तरह लोकतंत्र को खोखला करने का माध्यम बनता जा रहा है, यह गहन चिन्ता और चिन्तन का विषय है। विशेषतः चारित्रिक अवमूल्यन, आर्थिक विसंगतियों एवं विषमताओं को प्रश्रय देने का चुनावों में नंगा नाच होने लगा है और हर दल इसमें अपनी शक्ति का बढ़-चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात केवल चुनावी चंदे ही नहीं बल्कि विदेशों से मिलने वाले चंदों की भी है। आज सवाल बहुत बड़ा है और वह है भारत की राजनीति को प्रत्यक्ष विदेशी प्रभाव से बचाना। आम आदमी पार्टी पर जिन कथित भारत-विरोधी विदेशी ताकतों से भारी राशि लेने के आरोप लगे हैं, वह हमारी समूची चुनाव प्रणाली के लिए चुनौती है।

क्या कभी सत्तापक्ष या विपक्ष से जुडे.लोगों ने या नये उभरने वाले राजनीतिक दावेदारों ने, और आदर्श की बातें करने वाले लोगों ने, अपनी करनी से ऐसा कोई अहसास दिया है कि उन्हें सीमित निहित स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ राजनेता समझा जाए? यहां नेताओं के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं न ही राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है यह तथ्य कि इस तरह का कूपमण्डूकी नेतृत्व कुल मिलाकर देश की राजनीति को छिछला ही बना सकता है। सकारात्मक राजनीति के लिए जिस तरह की नैतिक निष्ठा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए राजनेताओं में जिस तरह की परिपक्वता की अपेक्षा होती है, उसका समूचे विपक्षी दलों में अभाव एक पीड़ादायक स्थिति का ही निर्माण कर रहा है। और हम हैं कि ऐसे नेताओं के निर्माण में लगे हैं!

चुनावों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत मानी जाती है, पर आज चुनाव लोकतंत्र का मखौल बन चुके हैं। चुनावों में वे तरीके अपनाएं जाते हैं जो लोकतंत्र के मूलभूत आदर्शों के प्रतिकूल पड़ते हैं। इन स्थितियों से गुरजते हुए, विश्व का अव्वल दर्जे का कहलाने वाला भारतीय लोकतंत्र आज अराजकता के चौराहे पर है। जहां से जाने वाला कोई भी रास्ता निष्कंटक नहीं दिखाई देता। इसे चौराहे पर खडे.करने का दोष जितना जनता का है उससे कई गुना अधिक राजनैतिक दलों व नेताओं का है जिन्होंने निजी व दलों के स्वार्थों की पूर्ति को माध्यम बनाकर इसे बहुत कमजोर कर दिया है। आज ये दल, ये लोग इसे दलदल से निकालने की क्षमता खो बैठे हैं। महाभारत की लड़ाई में सिर्फ कौरव-पांडव ही प्रभावित नहीं हुए थे। उस युद्ध की चिंगारियां दूर-दूर तक पहुंची थीं। साफ दिख रहा है कि इस महाभारत में भी कथित अराजक राजनीतिक एवं आर्थिक ताकतें अपना असर दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इन स्थितियों में अब ऐसी कोशिश जरूरी है जिसमें महान भारत के नाम पर महाभारत की नई कथा लिखने वालों के मंतव्यों और मनसूबों को पहचाना जाए। अर्जुन की एकाग्रता वाले नेता चाहिए भारत को, जरूरी होने पर गलत आचरण के लिए सर्वोच्च नेतृत्व पर वार करना भी गलत नहीं है।

यह सही है कि आज देश में ऐसे दलों की भी कमी नहीं है, जो नीति नहीं, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के आधार पर बने हैं, लेकिन नीतियों की बात ऐसे दल भी करते हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए कथनी और करनी की असमानता चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने में हमारे राजनीतिक दलों ने नीतियों-आदर्शों के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो जनतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत और स्वस्थ होने का संकेत देते हों, फिर भी यह अपेक्षा तो हमेशा रही है कि नीतियां और नैतिकता कहीं-न-कहीं हमारी राजनीति की दिशा तय करने में कोई भूमिका निभाएंगी। भले ही यह खुशफहमी थी, पर थी। अब तो ऐसी खुशफहमी पालने का मौका भी नहीं दिख रहा। लेकिन यह सवाल पूछने का मौका आज है कि नीतियां हमारी राजनीति का आधार कब बनेंगी? सवाल यह भी पूछा जाना जरूरी है कि अवसरवादिता को राजनीति में अपराध कब माना जाएगा? यह अपने आप में एक विडम्बना ही है कि सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित राजनीति की बात करना आज एक अजूबा लगता है। यह सही है कि व्यक्ति के विचार कभी बदल भी सकते हैं, पर रोज कपड़ों की तरह विचार बदलने को किस आधार पर सही कहा जा सकता है? सच तो यह है कि आज हमारी राजनीति में सही और गलत की परिभाषा ही बदल गई है- वह सब सही हो जाता है जिससे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति होती हो और वह सब गलत हो जाता है जो आम आदमी के हितों से जुड़ा होता है, यह कैसा लोकतंत्र बन रहा है, जिसमें लोक ही लुप्त होता जा रहा है?

नरसी मेहता रचित भजन ह्यवैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे गांधीजी के जीवन का सूत्र बन गया था, लेकिन यह आज के नेताओं का जीवनसूत्र क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं आज के राजनेता पराये दर्द को, पराये दुःख को अपना मानते? क्यों नहीं जन-जन की वेदना और संवेदनाओं से अपने तार जोड़ते? कोई भी व्यक्ति, प्रसंग, अवसर अगर राष्ट्र को एक दिन के लिए ही आशावान बना देते हैं तो वह महत्वपूर्ण होते हैं। पर यहां एक दिन की अजागरूकता पांच साल यानी अठारह सौ पचीस दिनों को अंधेरों के हवाले करने की तैयारी होती है। यह कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम वोटर होकर और कैसा राजनीतिक नेतृत्व निर्मित हो रहा है?

कांग्रेस का लगातार भट्टा बैठाने के बाद सैम पित्रोदा को आखिर हटना पड़ा

अशोक भाटिया

अपनी नस्लवादी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सैम पित्रोदा ने बुधवार को अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनके इस फैसले को सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार नहीं था कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की हो इसके पहले भी अपने विवादास्पद बयान से वे कांगेस का भट्टा बैठा चुके है व बाद में कांग्रेस को उन बयानों पर लीपा पोती करके अपने को संभालना पड़ा है।

अक्सर राहुल गांधी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले पित्रोदा ने हालिया बयान में कहा कि भारत के पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया , जिसमें वह भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की तुलना इस तरह करते नजर आ रहे हैं जिससे कोई भी नाराज हो सकता है।पित्रोदा कहते हैं कि 'भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई-बहनें हैं। वे कहते हैं कि हम अलग-अलग भाषाओं, धर्मों और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है, जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा-बहुत समझौता करता है।' देखा जाए तो यह बहुत सामान्य सी बात है। हम लोग आम जीवन में इस तरह की तुलनात्मक बातें करते रहते हैं। पर जब कोई शख्स आम के बजाय खास बन जाता है तो उसकी बातचीत के कई मतलब निकाले जाते हैं। और जब चुनाव चल रहे हैं और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक के जिम्मेदार सदस्य हैं तो आपकी जवाबदेही और बनती है कि आप क्या बोल रहे हैं?

शायद यही कारण है कि सैम पित्रोदा का बयान वायरल होते ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 'आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है, जिसने मुझे गुस्से में भर दिया है। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं।' आखिर प्रधानमंत्री को कांग्रेस पर हमला करने का मौका किसने दिया?

इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में संपदा के पुनः वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सकते में आ गई। पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल, भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का। भाजपा ने 5 साल में क्या किया, उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किनारा करना पड़ा और पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं। कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।

सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती? क्योंकि यह बार-बार देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक गलती करने वाला बार-बार वैसी ही गलतियां करता है। उन गलितयों को पार्टी उनका व्यक्तिगत मामला मानकर पल्ला झाड़ लेती है। यह भी कहती है कि उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है। पर बाद में ऐसे शख्सियत जब पार्टी में पुरस्कृत होते हैं तो संदेह होना लाजिमी हो जाता है। एक उदाहरण दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह लगातार आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जताने के जाने जाते हैं। कभी ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद के नाम के आगे जी लगाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। इसी तरह उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर में भी मारे गए आतंकियों के लिए संवेदना जताई थी। हर बार वो इस तरह की गलतियां करते रहे हैं पर उनपर कोई एक्शन भी नहीं होता। अब लोकसभा टिकट से उन्हें उनकी गलतियों के लिए पुरस्कृत किया गया है।जाहिर है कि ऐसा ही विजय वेडट्टियार और चरनजीत सिंह चन्नी के साथ भी है। चरनजीत सिंह चन्नी ने एयरफोर्स हमले को ही फॉल्स ऑपरेशन की संज्ञा दे दी। विजय वेडट्टियार ने कसाब को निर्दोष करार दे दिया। इस तरह की बातें करने वालों पर कोई एक्शन नहीं होने से कई बार ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस में यह सब एक योजनाबद्ध तरीक से तो नहीं होता।क्योंकि दूसरी पार्टियों में इस तरह की हरकत करने वालों को तुरंत दंडित कर दिया जाता है।

पित्रोदा केस में ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया है पर उन्हें दंडित नहीं किया गया है। ये बात खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कही है कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है पर उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है। मतलब सीधा है कि कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया है पित्रोदा खुद अलग हो गए हैं।

कांग्रेस में अकसर ऐसा देखा गया है कि किसी खास मुद्दे पर ठीके एक दूसरे से विरोधी विचार सामने आते हैं। और एक साथ आते हैं। द्रमुक नेता उदयनिधि मारन के सनातन को डेंगू मलेरिया कहने के बाद कांग्रेस में एक साथ कई विचार आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे को उदयनिधि मारन की बातों में कोई बुराई नहीं दिखी। पर ठीक उसी समय मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका खंडन किया। देशभर में दर्जनों ऐसे नेताओं के बयान आए जो मारन की बातों से यकीन नहीं रखते थे। तो बहुत से लोगों ने सीधे मारन और खरगे को सपोर्ट किया। इसी तरह राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी पार्टी में अलग-अलग विचार सामने आते रहे। कोई समर्थन में था तो कोई इसके विरोध में । कोई भी पार्टी इस तरह के विचारों पर एक मत नहीं है तो निश्चित है कि उसके समर्थकों में कन्फ्यूजन पैदा होगा। पर कांग्रेस नेताओं को लगता है कि इस तरह एक ही मुद्दे पर अलग-अलग विचार करके सभी विचार वालों को पार्टी चुनावों में साध लेगी। पर जब जनता के सामने विकल्प को रूप मे ऐसी पार्टियां रहेंगी जो एक विचार पर पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं तो जनता ऐसे ढुलमुल विचार वाले के साथ क्यों जाएगी।

यह सही है कि लोकतंत्र में एक आदर्श स्थिति यह है कि पार्टी के अंदर सभी लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हो। इस लिहाज से देखा जाए तो यह सही है। पर विचार स्वतंत्रता के नाम पर पार्टी के मूल विचारों से अलग होने की स्वतंत्रता तो नहीं ही दी जा सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में पार्टी के अंदर विचारों की स्वतंत्रता दे जाती है। पर पार्टी की मूल विचारधारा को जब कोई पार करने लगता है तो उसे पार्टी से अलग ही होना होता है। जैसे कांग्रेस एक राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है।पर जब राष्ट्रवाद से इतर बात करने वाले या धर्मनिरपेक्षता को नकारने वाले लोग अपनी बात रखने लगते हैं उसे कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। पर कांग्रेस के अंदर ऐसा होता। इसलिए ऐसा लगता है कि छवि को लिबरल रखने के लिए नहीं बल्कि पार्टी में अनुशासन की कमी के चलते ऐसा होता है।

नासूर बनते बाल विवाह

-रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही है। जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिनमें बाल विवाह भी एक हैं। किसी भी बच्चे की शादी उसके निश्चित आयु से पहले यानी बाल्यकाल में होना बाल विवाह कहलाता है। यह एक रूढ़िवादी प्रथा है। यह प्रथा बच्चों की सारे मनवा अधिकारों को खत्म कर देता है। जैसे- खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा आदि के अधिकारों को समाप्त कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। प्राचीन सभी प्रथाओं में बाल विवाह सबसे बड़ा कुप्रथा है। क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही वह अपने शिक्षा और खेलकूद के अधिकारों आदि से वंचित रह जाते हैं। इस कुप्रथा का शिकार ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। बाल्यकाल में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है।

विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बाबजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे इस प्रथा की भेंट चढ़े जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बेटी बचावो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही है। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। आजकल कई लड़कियां खुद भी आगे आकर अपना बाल विवाह रुकवाने का प्रयास करने लगी है। भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र अभी पढने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है।

देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता का बढ़ना, शिक्षा के प्रसार के कारण लड़कियों के प्रति अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आना, शहरीकरण में वृद्धि तथा कठोर कानूनों की उपस्थिति को माना जा सकता है।

भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है। लेकिन देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है। अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में गिरावट आई है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत हो गया। जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2 प्रतिशत हो गया। बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी कमी 2006 और 2016 के बीच हुई। सबसे कम कमी 2016 से 2021 के बीच हुई। इन बाद के वर्षों के दौरान छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई।

आंकड़ों से साफ है कि आजादी के 77 साल बाद भी इस देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। हम अपनी बेटियों को बाल विवाह और कम उम्र की गर्भावस्था से नहीं बचा पाए हैं। यही कारण है कि इस देश में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) के शिकार हैं। यूनिसेफ द्धारा जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। लेकिन कई प्रदेशों में यह प्रथा अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है। यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू कि ओर इशारा करती हैं। जिसे अक्सर हम रीति-रिवाज व परम्परा के नाम पर अनदेखा करते हैं। देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय-समय पर उसमें संशोधन कर उसे ओर प्रभावशाली बनाया गया हैं। फिर भी लगातार बाल विवाह हो रहे हैं। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल व एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया है।

अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके प्रति सामाजिक जागरुकता की कमी। जब तक समाज में बल विवाह रोकने के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह कुरीति खत्म नही होने वाली है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। सिर्फ कानून के भरोसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को नहीं रोका जा सकता है। देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना होगा। सरकार को भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये बने कानून का कड़ाई से पालन करवाना होगा। बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में जोरदार अभियान चलाना होगा। साथ ही सरकार को विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम भी चलाने होंगे ताकि गरीब परिवार गरीब परिवारों की बच्चियां बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

चौथा चरण: सपा के लिये नाक की बात, कन्नौज-इटावा हैं खास

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में चौथा चरण समाजवादी पार्टी के लिये विशेष महत्व रखता है। चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान में 13 सीटों पर ही चुनाव भी होना है। चौथे चरण में सपा के दबदबे वाली इटावा और कन्नौज की लोकसभा की दो ऐसी सीटें है. जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थीं,लेकिन अब यहां खासकर इटावा में हालात काफी बदल गये हैं। फिर भी सपा की यहां जीत की संभावनाएं कम नहीं हैं।पहले बात कन्नौज की। कन्नौज लोकसभा सीट इन दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यहां से चुनाव मैदान में कूदने के कारण सुर्खियों में है। सपा ने यहां पहले तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, नामांकन से ठीक पहले तेज प्रताप का नाम कट गया। इस सीट अखिलेश के समाने भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को टिकट दिया है। बसपा के इमरान बिन जाफर भी यहां मैदान में हैं। कन्नौज हमेशा से लोकसभा सीट नहीं थी।यह 1967 में अस्तित्व में आई थी। साल 1967 में हुए आम चुनाव में कन्नौज सीट पर डा0 राम मनोहर लोहिया को जीत मिली थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतरे लोहिया ने कांग्रेस के एसएन मिश्रा को मात्र 472 वोटों से हराया था।

इसके बाद कन्नौज लोकसभा सीट 1999 के चुनाव से खास हो गई। क्योंकि कन्नौज सीट पर सपा उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि तब के सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव मैदान में स्वयं उतर गये थे। इस चुनाव में उनकी टक्कर किसी बड़े राजनीतिक दल के उम्मीदवार की बजाय एक गैर-मान्यता प्राप्त दल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रत्याशी से हुई। मुलायम सिंह ने लोकतांत्रिक कांग्रेस की तरफ से उतरे अरविंद प्रताप सिंह को 79,139 वोटों से हराया। 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज के साथ ही संभल लोकसभा सीट से भी जीत दर्ज की थी। नतीजों के बाद मुलायम सिंह यादव संभल सीट से सांसद बने रहे और कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया।

साल 2000 में हुए उप-चुनाव में कन्नौज सीट मुलायम सिंह के बेटे और मौजूदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उतारा गया। इसके साथ ही अखिलेश ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली। अखिलेश का राजनीति में यह प्रवेश जीत के साथ हुआ। उन्होंने इस उपचुनाव में जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे। साल 2004, इस बार कन्नौज सीट से एक बार फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं। इस चुनाव में अखिलेश के सामने बसपा से ठाकुर राजेश सिंह थे। अखिलेश ने बसपा प्रत्याशी को 3,07,373 वोटों के विशाल अंतर से हरा दिया। पांच वर्षो के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सपा की ओर से उतरे अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर जीत हासिल की लेकिन उनकी जीत का अंतर घट गया। उन्होंने बसपा उम्मीदवार डॉ. महेश चंद्र वर्मा को 1,15,864 वोट से हराया। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुब्रत पाठक 2009 में तीसरे स्थान पर रहे।

2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए।बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधान परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गये। फिर कन्नौज सीट पर उप-चुनाव की जरूरत पड़ गई। इसके बाद कन्नौज सीट पर उप-चुनाव हुआ जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे दो उम्मीदवारों ने उप-चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा था जबकि भाजपा उम्मीदवार अंतिम समय में अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए थे। इस तरह से शीला दीक्षित के बाद डिंपल यादव कन्नौज सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला बन गईं।

2014 के लोकसभा चुनाव में देश के ज्यादातर हिस्सों में भाजपा को जीत मिलती है। हालांकि, कन्नौज में पार्टी सपा के सामने हार जाती है। इस चुनाव में डिंपल यादव ने भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक को रोचक मुकाबले में 19,907 वोटों से हरा दिया। डिंपल को 4,89,164 वोट मिले। वहीं, भाजपा के प्रत्याशी को 4,69,257 वोट मिले,लेकिन पांच साल के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने देशभर की 303 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें कन्नौज की अहम जीत भी शामिल रही। आखिरकार सुब्रत पाठक कन्नौज का किला भेदने में कामयाब हो गए। पाठक ने इस चुनाव में डिंपल यादव को 12,353 वोटों से हराया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 5,63,087 वोट मिले। वहीं, सपा के उम्मीदवार को 5,50,734 वोट मिले। अब बात 2024 के चुनाव की कर लेते हैं। इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ही चुनाव मैदान में हैं। वहीं, सपा की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। जबकि डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं,जहां मतदान हो चुका है बसपा ने इमरान बिन जाफर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कन्नौज की जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। स्माजवादी पार्टी के दबदबे वाली एक और इटावा सीट की बात की जो तो इस सीट पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को 3-3 बार जीत मिली है हालांकि पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार पार्टी के पास हैट्रिक लगाने का मौका है. इटावा सीट पर दलित वोटर्स की बहुलता है. हालांकि ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. इटावा लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का अभी भी गढ़ मानी जाती थी. हालांकि पिछले दो बार से पार्टी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को मैदान में उतारा है. जबकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद राम शंकर कठेरिया को उम्मीदवार बनाया है. जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद सारिका सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

साल 2019 आम चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार राम शंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम शंकर कठेरिया ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश कठेरिया को 64 हजार से ज्याद वोटों से हराया था. बीजेपी उम्मीदवार को 5 लाख 22 हजार 119 वोट मिले थे. जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 4 लाख 57 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार दोहरे को 16 हजार 570 वोट मिले थे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इटावा में सपा के कमजोर पड़ने की कई वजह रहीं हैं जिसमें प्रमुख तौर पर सपा द्वारा इटावा लोकसभा सीट की बजाय मैनपुरी लोकसभा सीट को ज्यादा प्राथमिकता देना विशेष है।चाचा-भतीजे के बीच की रार, पुराने वरिष्ठ कार्यकताओं की नए पदाधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं उपेक्षा सपा की कमजोरी का कारण बने हैं। इस लोकसभा चुनाव में चाचा शिवपाल सिंह अब सपा के साथ हैं। ऐसे में कहीं न कहीं कार्यकर्ता चुनाव में मजबूती देख रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के अपने ही गढ़ में 2014 और 2019 में लगातार दो बार चुनाव हारने के कारणों का अगर विश्लेषण किया जाए तो 2014 में जहां मोदी लहर ने भाजपा को संजीवनी दी वहीं 2017 के बाद मुलायम परिवार में चाचा भतीजे के बीच हुए मतभेदों ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। दो खेमों में संगठन व कार्यकताओं के बंट जाने के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को नुकसान भी हुआ। हालांकि इस चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन भी था। तब भी भाजपा अपना परचम लहराने में कामयाब रही। इस चुनाव में चाचा की पार्टी प्रसपा ने भी शंभूदयाल दोहरे को चुनाव मैदान में उतारकर वोटों का नुकसान किया था। उस समय चाचा शिवपाल सिंह यादव के समर्थकों में मायूसी छाई और उनके खास रहे पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, पूर्व जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, ब्लाक प्रमुख बसरेहर दिलीप यादव भाजपा में शामिल हो गए। इस चुनाव में भी पार्टी हाईकमान की उपेक्षा से नाराज पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया भी भाजपा के खेमे में आ गए। इस चुनाव में सपा, बसपा के रास्ते अलग-अलग हैं। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य कहते हैं कि संगठन कतई कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि बड़े नेताओं के दौरे न होने को लेकर कहा कि कार्यक्रम फाइनल हो रहे हैं। आजादी के बाद से समाजवादियों का गढ़ रहा इटावा लगातार उनके लिए मुफीद रहा है। व्यक्तिगत तौर पर कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया व राम सिंह शाक्य तीन बार विजयी हुए वहीं सपा से चुनाव लड़े रघुराज शाक्य भी दो बार चुनाव जीते थे। चौथे चरण में जिन सीटों पर मुकाबला होगा उसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच शामिल हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

लगातार बढ़ रहा घरेलू कर्ज

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है, जीडीपी में बचत का हिस्सा 50 सालों में सबसे कम रहा है। 2011 से 2022 के बीच बचत घटती जा रही है। वहीं प्रति व्यक्ति जीडीपी आय मैं 140 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में लोगों की बचत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बचत में शेयर मार्केट, बैंक के बचत खाते, एफडी, शेयर मार्केट, सोना, म्युचुअल फंड इत्यादि को भी शामिल किया गया है। 2022 के वित्तीय वर्ष में 17.1 लाख करोड रुपए की बचत थी। जो 2022-23 में घटकर 14.02 लाख करोड रुपए रह गई है। सकल जीडीपी में बचत का हिस्सा केवल 5.3 फ़ीसदी बचा है। जो पिछले 50 वर्षों में सबसे कम है। लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन बचत कम होती जा रही है। रिपोर्ट में कर्ज आसानी से मिलने के कारण सामाजिक मानसिकता में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साल भर में लोगों का घरेलू कर्ज 54 फ़ीसदी बढ़ गया है। 2021-22 में घरेलू खर्च 7.69 लाख करोड रुपए था। जो 2022-23 में बढ़कर 11.88 लाख करोड रुपए हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 54 फ़ीसदी घरेलू कर्ज बढ़ा है। बैंकों से क्रेडिट कार्ड से और गैर बैंकिंग कंपनियों से यह कर्ज लिया गया है। 2012 के बाद से लोगों पर घरेलू कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण बाजारों में ब्रांडेड सामान की बिक्री लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण अंचल अब शहरी क्षेत्र को मात देते हुए देख रहे हैं। जनवरी 24 से मार्च 24 की तिमाही में ग्रामीण क्षेत्र की मांग 7.6 फ़ीसदी बढ़ गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में 5.7 फ़ीसदी मांग घट गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ब्रांडेड वस्तुओं को लेकर यह परिवर्तन सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है। वह बड़ी चिंता जनक है। बचत 50 वर्षों में सबसे कम हो गई है इसका मतलब है कि अब भारतीय नागरिक अपनी हर जरूरत के लिए कर्ज और सरकार के ऊपर निर्भर होते चले जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों की सामाजिक व्यवस्था और भौतिक संसाधनों के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है। उसके कारण ग्रामीण अंचल जो अभी तक कर्ज के बहुत ज्यादा दबाव में नहीं थे ग्रामीण अंचलों के परिवार भी अब कर्ज के बोझ से दबते चले जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार है। कर्ज लेकर खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया गया है। इसका असर जीडीपी और कर वसूली के लिए सरकार के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी कर्ज के बोझ से दबता चला जा रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक स्तर तक कर्ज लेने को जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन जब इसे चुका नहीं पाते हैं, तो इसका ठीक उलटा असर होता है। इसका असर अभी दिखना शुरू हो गया है। आने वाले सालों में यह निम्न एवं मध्यम वर्ग के साथ-साथ सरकार के लिए भी कर्ज एक मुसीबत बनने जा रहा है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया बचत के आधार पर किया जा सकता है कर्ज के आधार पर नहीं। कर्ज लेने पर ब्याज का बोझ भी बढ़ता है। किस्त और ब्याज की तुलना में यदि आय नहीं बढ़ती है, तो वह आम नागरिकों के जन-जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

बालिका वधुओं को पढ़ाने वाले धन्नाराम की प्रेरणास्पद कहानी

– अमरपाल सिंह वर्मा

राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। हर साल अक्षय तृतीय के अबूझे सावे पर राज्य में हजारों बच्चे वैवाहिक बंधन में बांध दिए जाते हैं। न्याय पालिका के कड़े आदेशों, सरकार के अभियानों और सख्त कानूनों के बावजूद राज्य में बाल विवाह पर लगाम नहीं लग पाई है। भले ही गांव-देहात के लोगों को बच्चों का विवाह न करने के लिए मनाना मुश्किल है मगर फिर भी अनेक संगठन एवं लोग इस बुराई के खात्मे के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों में शामिल हैं नागौर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता धन्नाराम नायक, जो बाल विवाह के खिलाफ कई दशकों से मुहिम चलाए हुए हैं। धन्नाराम नागौर जिले में जायल तहसील के झाड़ेली गांव में उरमूल खेजड़ी संस्थान नामक गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। उन्होंने इस संस्था के जरिए न केवल बाल विवाह के खिलाफ अलख जगाई है बल्कि बचपन में ब्याह दी गईं गांवों की लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे धन्नाराम के काम को नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने पत्रकारिता के लंबे कॅरियर में चार साल तक नागौर में काम किया है। इस दौरान मुझे धन्नाराम और उनकी संस्था की गतिविधियों को देखने का अवसर मिला। एक बार जब मैं झाड़ेली गांव में उरमूल खेजड़ी संस्थान में गया तो वहां दर्जनों छोटी उम्र की लड़कियां पढ़ाई करती हुई मिलीं। इनमें से कइयों के हाथों में मेहंदी और मांग में सिंदूर सजा देख मुझे हैरानी हुई। साफ पता चल रहा था कि उनकी बच्चियों का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया गया है। दरअसल, नागौर जिले में अशिक्षा और रूढियों के कारण ज्यादातर बच्चों की शादी होश संभालने से पहले ही कर दी जाती है। लोग बड़ी बेटियों के साथ छोटी कम उम्र बच्चियों के हाथ भी पीले कर देते हैं लेकिन गौना उसके स्यानी होने के बाद किया जाता है। धन्नाराम ने अपने साथियों के साथ वर्ष 2004 में आसपास के गांवों में सर्वे किया तो ऐसी बच्चियों की बड़ी तादाद सामने आई, जो कभी स्कूल नहीं गई थीं या फिर जिन्होंने थोड़े समय के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इनमें ऐसी नाबालिग बच्चियां भी थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। पूछने पर शादीशुदा बच्चियों ने पढ़ने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ऐसी लड़कियों को चिन्हित किया और गौना होने तक उन्हें पढ़ाने के लिए उनके परिजनों को राजी कर लिया। उस समय क्षेत्र में बाल विवाह की समस्या को देख धन्नाराम ने दो काम शुरू किए। एक तो वह ग्रामीणों को बाल विवाह नहीं करने के लिए के लिए प्रेरित करने लगे। दूसरा यह कि जो लोग बाल विवाह करने पर अड़े रहे तो उन्हें विवाहित बच्चियों को पढ़ाने के लिए राजी करना शुरू किया। उन्हें दूसरे काम में ज्यादा सफलता मिली। ग्रामीण उरमूल खेजड़ी संस्था के शिक्षा शिविरों में बच्चियों को पढने भेजने लगे। साथ ही शिविर में पढकर जाने वाले किसी भी किशोर अथवा किशोरी का विवाह उनके परिजनों ने निर्धारित से कम आयु में नहीं किया है, यह धन्नाराम की विशिष्ट उपलब्धि है। दरअसल, धन्नाराम ने झाड़ेली में बीस साल पहले वर्ष 2004-05 में शिक्षा से वंचित 11 से 20 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को पढ़ाने के लिए आवासीय शिविरों का सिलसिला शुरू किया था। पहले शिविर में 98 बालिकाएं आईं, जिनमें 25 विवाहित थीं। इसके बाद इन शिविरों में सैकड़ों बालिका वधुओं को पढ़ाया गया। शिविरों में पढ़ाई के बाद अनेक विवाहित लड़कियों ने आठवीं व दसवीं पास कर ली। यह सिलसिला आगे भी इसी प्रकार चला। बाल विवाह के बाद पढ़ने वाली लड़कियों में एक कैलाशी भी थी, जिसने वहां आवासीय व्यवस्था में रहकर दसवीं की परीक्षा पास की। बाद में वह अपने ससुराल तंवरा में सरपंच चुनी गई। ऐसी कई लड़कियां हैं, जिनके जीवन में धन्नाराम की कोशिशों से बदलाव आया। धन्नाराम अब भी बाल विवाह नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में जुटे हैं। राजस्थान में बाल विवाह की समस्या व्यापक है। राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से वर्ष 2019-21 तक किए गए एक सर्वे के अनुसार अधिक बाल विवाह वाले राज्यों में राजस्थान सातवें स्थान पर है। सर्वे में राज्य में 25.4 फीसदी बालिकाओं का बाल विवाह होना पाया गया। राज्य में शहरी क्षेत्रों में अब भी 15.1 फीसदी तो ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 फीसदी बालिकाओं के विवाह किए जा रहे हैं। राज्य में बाल विवाह के मामलों में चित्तौडगढ़ जिला सबसे आगे है। यहां 42.6 फीसदी बाल विवाह होने पाए गए। भीलवाड़ा 41.8 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि झालावाड़ में 37.8 फीसदी बाल विवाह के साथ तीसरे स्थान पर है। नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही, फलौदी, बालोतरा आदि जिलों में भी बड़ी तादाद में बाल विवाह होते हैं। धन्नाराम जी के प्रयास भले ही चंद गांवों तक सीमित हों लेकिन उन्हें छोटा नहीं कहा जा सकता। उनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अगर उनकी तरह हर कोई अपने आसपास के क्षेत्र में करना शुरू कर दे तो यह बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने में बड़ा योगदान साबित हो सकता है। धन्नाराम जी 38 सालों से नागौर जिले में जल संरक्षण, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनार्वास, वंचित एवं मजदूर वर्गों के जीवन में सुधार लाने, युवाओं में कौशल विकास, दिव्यांग कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच जैसे काम भी कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए।

नासूर बनते बाल विवाह

देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है।

– रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही है। जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिनमें बाल विवाह भी एक हैं। किसी भी बच्चे की शादी उसके निश्चित आयु से पहले यानी बाल्यकाल में होना बाल विवाह कहलाता है। यह एक रूढ़िवादी प्रथा है। यह प्रथा बच्चों की सारे मनवा अधिकारों को खत्म कर देता है। जैसे- खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा आदि के अधिकारों को समाप्त कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। प्राचीन सभी प्रथाओं में बाल विवाह सबसे बड़ा कुप्रथा है। क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही वह अपने शिक्षा और खेलकूद के अधिकारों आदि से वंचित रह जाते हैं। इस कुप्रथा का शिकार ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। बाल्यकाल में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बाबजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे इस प्रथा की भेंट चढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बेटी बचावो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही है। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। आजकल कई लड़कियां खुद भी आगे आकर अपना बाल विवाह रुकवाने का प्रयास करने लगी है। भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र अभी पढने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता का बढ़ना, शिक्षा के प्रसार के कारण लड़कियों के प्रति अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आना, शहरीकरण में वृद्धि तथा कठोर कानूनों की उपस्थिति को माना जा सकता है।

भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है। लेकिन देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है। अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में गिरावट आई है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत हो गया। जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2 प्रतिशत हो गया। बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी कमी 2006 और 2016 के बीच हुई। सबसे कम कमी 2016 से 2021 के बीच हुई। इन बाद के वर्षों के दौरान छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई। आंकड़ों से साफ है कि आजादी के 77 साल बाद भी इस देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। हम अपनी बेटियों को बाल विवाह और कम उम्र की गर्भावस्था से नहीं बचा पाए हैं। यही कारण है कि इस देश में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) के शिकार हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। लेकिन कई प्रदेशों में यह प्रथा अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है। यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू कि ओर इशारा करती हैं। जिसे अक्सर हम रीति-रिवाज व परम्परा के नाम पर अनदेखा करते हैं। देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय-समय पर उसमें संशोधन कर उसे ओर प्रभावशाली बनाया गया हैं। फिर भी लगातार बाल विवाह हो रहे हैं। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल व एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया है। अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके प्रति सामाजिक जागरुकता की कमी। जब तक समाज में बल विवाह रोकने के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह कुरीति खत्म नही होने वाली है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। सिर्फ कानून के भरोसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को नहीं रोका जा सकता है। देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना होगा। सरकार को भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये बने कानून का कड़ाई से पालन करवाना होगा। बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में जोरदार अभियान चलाना होगा। साथ ही सरकार को विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम भी चलाने होंगे ताकि गरीब परिवार गरीब परिवारों की बच्चियां बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं)

युवा भारत के भविष्य की उजली तस्वीर

– डॉ मोनिका ओझा खत्री

युवा भारत देश की रीढ़ है, देश के युवाओं में परिवर्तनकारी शक्ति है। किसी भी देश की तरक्की में युवाओं का योगदान होता है। देश के भविष्य के रूप को बदलने के लिए युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर सकारात्मक प्रयास करने होंगे। युवा वर्ग ही देश में सामाजिक समरसता व सद्भावना का माहौल कायम रख सकता है। युवाओं में ऊर्जा सबसे अधिक होती है, केवल उस ऊर्जा को सही जगह लगाने की आवश्यकता है। युवा वर्ग अपने अधिकारों व लक्ष्य से परिचित होता है तो वह देश की दशा बदल सकता है। युवा देश का वर्तमान हैं, तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का अमूल्य योगदान है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान हैं, तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। युवा देश और समाज के जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। स्वामी विवेकानंद सही अर्थों में युवाओं के प्रेरणास्त्रोत और आदर्श व्यक्तित्व थे। विवेकानंद कहा करते थे कि उनकी आशाएं देश के युवा वर्ग पर ही टिकी हुई हैं। वे आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे और खासकर भारतीय युवाओं के लिए उनसे बढ़कर भारतीय नवजागरण का अग्रदूत अन्य कोई नेता नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से राजनीति में निस्वार्थ और रचनात्मक रूप से योगदान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति सार्थक परिवर्तन लाने का एक बड़ा माध्यम है और हर दूसरे क्षेत्र की तरह, राजनीति में भी युवाओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया कि आज, ईमानदार लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, बेईमान गतिविधियों से सम्बंधित राजनीति की पुरानी धारणा बदल रही है। आज ईमानदारी और प्रदर्शन समय की जरूरत बन गए हैं। देश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। इस साल उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाना और लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार देने व आत्मनिर्भर बनाने की है। आज का युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा, रोज़गार और बेहतर भविष्य के लिए आज का युवा जागरूक है और लड़ रहा है। युवा वर्ग महंगी फीस, कोचिंग और फॉर्म पर फॉर्म भरता है। भर्तियों के दौरान पेपर लीक होना आम बात हो गई है। माँ-बाप अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन अंत में उन्हें मिलती है बेरोज़गारी। ऐसे में युवा अवसाद की तरफ जाता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। युवा वर्ग करप्शन फ्री इंडिया चाहता है। आज सम्पूर्ण देश भ्रष्टाचार से आहत है। युवा ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति की राह दिखा सकता है। ऐसे में देश में युवा नेतृत्व की मांग बढ़ी है। युवा नेतृत्व को लेकर आज देशभर में व्यापक बहस छिड़ी है। युवा आबादी ही देश की तरक्की को रफ्तार प्रदान कर सकती है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छ, स्वस्थ और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की है। युवा नेतृत्व से राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता युवा वर्ग की पहचान कराती है। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। युवा वर्ग करप्शन फ्री इंडिया चाहता है। आज सम्पूर्ण देश भ्रष्टाचार से आहत है। युवा ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति की राह दिखा सकता है। ऐसे में देश में युवा नेतृत्व की मांग बढ़ी है।

(134, गुरुनानक पूरा राजापार्क, जयपुर)

कविता

परिंडो में पानी कौन देगा ?

निकला पेड़ के नीचे से
तब चिड़िया बोली मन से
मनवा.............
परिंडे तो लगा दिए
तूने परिंदे के लिए....
पर पानी कौन देगा ?
इन परिंदों के लिए...
सूखे परिंडो को देखकर
दर्द भी देता है।
साथ में धोखा भी....
डूबती चोंच जब परिंडे में
तब न जल मिलता है।
न सकून.......
परिंडे तो लगाए
फ़ोटो भी खिंचवाए
पर परिंडे में पानी
कौन देगा.....
यह भूल गए....
फ़ोटो से नाम भी हुआ
आपका काम भी हुआ
रह तो हम गए प्यासे.....
परिंडे लगाओ तो.......
पानी भी दो परिंदों के लिए....

गुलाब कुमावत खीमेल

(प्रधानाध्यापक, माँ शारदा माध्यमिक विद्यालय, सांचौर)

यह तो सोचना ही होगा कि क्या देश में फरवरी और मार्च के ठंडे महीनों के बीच लोकसभा चुनाव कराने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है? इसके चलते अधिक लोगों को वोट देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। गर्मी में लंबे समय तक रहने से थकान,चक्कर आना और बेहोशी हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों,पार्टी कार्यकर्ताओं मतदाताओं को बहुत संभल कर चलना होगा। उन लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान देना होगा जो विभिन्न राजनीतिक दलों की सभाओं में नेताओं को सुनने के लिए जाते हैं।

भीषण गर्मी में मतदान ही तो ताकत है भारतीय लोकतंत्र की

– आर.के. सिन्हा

आज जब देश के बहुत बड़े भाग में सूरज देवता आग उगल रहे हैं, तब लोकसभा चुनाव के लिए जनता मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल रही है। भारत के कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो गया है। इसके साथ ही लू भी चल रही है। इतने कठोर मौसम में चुनाव प्रचार करना और फिर मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़ा होना सामान्य बात तो नहीं मानी जा सकती है। इसलिए प्रचार भी सुबह या शाम को ही संभव हो पाता है। दोपहर के समय तो मात्र रणनीति ही बनाई जा सकती है। पर इतने खराब मौसम में भी देश के लाखों-करोड़ों मतदाता घरों से निकलकर वोट तो दे ही रहे हैं। यह सुखद भी है और यह हमारे मज़बूत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी है। आखिर देश के जनमानस को पता है कि उनके वोट से ही देश की तकदीर लिखी जाएगी। इसलिए ही लोग वोट देकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर होगा कि मतदाता सुबह जल्दी ही अपने मताधिकार का प्रयोग करके घर वापस आ जायें। उन्हें मतदान केन्द्रों में जाते वक्त अपने साथ पानी की बोतलें करोड़ रख लेनी चाहिएं। मुँह-सिर ढकने के लिये एक गमछा भी सही रहेगा। आप जानते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव आमतौर पर हर पाँच साल में अप्रैल और मई में होता है, और मतदाता और मतदान अधिकारी कठोर गर्मी से निपटने के आदी हैं। लेकिन, इस साल, भारत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का मुकाबला कर रहा है। पिछले महीने, देश में भीषण गर्मी के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बेहोश हो गए थे, बाद में उन्होंने बताया कि भीड़ भरे स्थान और उच्च तापमान के कारण उन्हें असहज महसूस हुआ था। इससे कुछ दिन पहले, पूर्वी शहर कोलकाता में, जहाँ तापमान 43 सेल्सियस से ऊपर चला गया था, एक खबरिया चैनल की एंकर मौसम अपडेट प्रस्तुत करते समय बेहोश हो गई थी। बाद में उसने बताया कि स्टूडियो का कूलिंग सिस्टम खराब हो जाने के कारण बहुत गर्मी हो जाने के कारण ऐसा हुआ ! चुनाव अधिकारी मतदान केंद्रों पर पेयजल की आपूर्ति करके और मतदान का समय बढ़ाकर इससे निपटने के लिए कदम तो उठा रहे हैं। 2019 के चुनाव की तुलना में, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हुए मतदान के पहले दो चरणों में मतदाता मतदान में कम से कम 3त्न की गिरावट देखी गई। चुनाव आयोग को अगले चुनावों के पूर्व एकबार यह विचार करना होगा कि आम चुनावों की तिथियों को अप्रैल - मई की जगह फ़रवरी - मार्च में किया जा सकता है क्या ? इससे पूरे देश में सुविधा होगी। कुछ पर्वतीय राज्यों में बर्फ जमा रहने के कारण दिक्क़त तो हो सकती है, पर उन क्षेत्रों में एक महीने बाद चुनाव और उसके बाद चुनाव परिणामों की घोषणा तो की ही जा सकती है।

यह तो सोचना ही होगा कि क्या देश में फरवरी और मार्च के ठंडे महीनों के बीच लोकसभा चुनाव कराने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है? इसके चलते अधिक लोगों को वोट देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। गर्मी में लंबे समय तक रहने से थकान, चक्कर आना और बेहोशी हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों, पार्टी कार्यकर्ताओं मतदाताओं को बहुत संभल कर चलना होगा। उन लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान देना होगा जो विभिन्न राजनीतिक दलों की सभाओं में नेताओं को सुनने के लिए जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हृदय रोग या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों वाले मरीजों को भी गर्मी में अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। मतदाताओं का कहना है कि वे गर्मी को लेकर आशंकित हैं लेकिन सावधानी बरतेंगे। दिल्ली और हरियाणा की क्रमश: 7 और दस सीटों के लिए मतदान आगामी 25 मई को होना है। आशंका है कि 25 मई को दिल्ली-हरियाणा में पारा 42 सेल्सियस के आसपास होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम समेत एनसीआर के इलाकों में बीते कुछ दिनों से आसमान से आग बरस रही है। दिन में तापमान 40 पार कर जा रहा है और ऐसे में लोगों का गर्मी से जीना मुहाल हो गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का कहर अभी और देखने को मिलेगा। तो बहुत साफ कि जब दिल्ली और हरियाणा के मतदाता अपने मतदान केन्द्र में जाएंगे तो उन्हें बेहद गर्म मौसम में घर से निकलना होगा। इसलिए अगर वे सुबह 11 बजे तक मतदान कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद गर्मी का असर भयावह होने लगेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले में दिल्ली के कुछ इलाकों में 43 डिग्री तक तापमान पहुंचने की उम्मीद है। इतनी भीषण गर्मी में वोट देने के लिए घर से निकलने से पहले बुजुर्गों को अपना ख्याल रखना ही होगा। इस बीच, पुणे महाराष्ट्र के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है, जहाँ 13 और 20 मई को दो और चरणों में मतदान होगा। पिछले एक हफ्ते से पुणे में 39 सेल्सियस और 42 सेल्सियस के बीच तापमान चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके जारी रहने की संभावना है। तो गर्मी के प्रकोप का असर हर तरफ है। इस मौसम में अगर सावधानी न बरती जाए तो हीटस्ट्रोक हो सकता है या डिहाइड्रेशन हो सकता है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 1 जून को होना है। पंजाब आजकल ही गर्मी से झुलस रहा। माना जा रहा है कि राज्य में मतदान वाले दिन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचेगा। आजकल लुधियाना व फाजिल्का सबसे गर्म चल रहे हैं। यहां का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। कहना ना होगा कि इतनी तेज गर्मी में मतदान करने के लिए घर से निकलना कठिन तो है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में 13 मई को चौथे चरण में मतदान करने वाला है। वहां भी चिलचिलाती गर्मी को जनता झेल रही है। इस तापमान में वोट डालने के लिए बाहर आना मुश्किल है। बुजुर्गों को मतदान केंद्रों तक ले जाना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस साल पहली बार, देश में चुनावों की देखरेख करने वाले चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विकलांग लोगों को अपने घरों से वोट डालने की अनुमति दी है। आयोग ने मार्च में चुनावों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही,मतदान केंद्रों पर पेयजल और ओरल हाइड्रेशन सॉल्ट उपलब्ध कराने, मेडिकल किट तैयार रखने और देरी को रोकने के लिए पर्याप्त मतदान कर्मचारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। बहरहाल, आम भारतीय का यही कहना है कि गर्मी हमें वोट देने से नहीं रोक सकती। यही जज्बा भारत और भारत लोकतंत्र की ताकत है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 72

जोखिम से निपटना

क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशि की प्रोविजनिंग से जुड़े मसौदा मानकों के कारण बैंकिंग क्षेत्र में तूफान आ गया है। जैसा कि इस समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ था वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर रियायत की मांग करने वाले हैं। सरकार भी प्रस्तावित मानकों का अध्ययन कर रही है जबकि बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई है। रिजर्व बैंक ने गत सप्ताह यह प्रस्ताव रखा कि परियोजनाओं की फाइनैंसिंग के लिए प्रोविजनिंग को मौजूदा 0.4 फीसदी की जगह 5 फीसदी किया जाए। वाणिज्यिक बैंक 1 से 2 फीसदी पर मानने को तैयार हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक का मसौदा यह सुझाता है कि प्रोविजनिंग में चरणबद्ध ढंग से सुधार किया जाए और इसे 31 मार्च, 2025 तक 2 फीसदी, मार्च 2026 तक 3.5 फीसदी और मार्च 2027 तक 5 फीसदी किया जाए।

कर्जदाताओं की चिंताओं को समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। परियोजनाओं की फाइनैंसिंग के लिए उच्च प्रोविजनिंग उनके मुनाफे पर असर डालेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इससे कर्ज की दर बढ़ेंगी और कुछ परियोजनाओं को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। व्यापक स्तर पर देखें तो यह पूंजीगत व्यय और समग्र वृद्धि पर असर डाल सकता है। फिलहाल रिजर्व बैंक के इस कदम के पीछे के कारणों पर बहस की जा सकती है लेकिन इरादे एकदम स्पष्ट हैं। नियामक का इरादा यह है कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निवेश चक्र के आरंभ में ही घेर दिया जाए। हालांकि निजी क्षेत्र निवेश में बड़ा इजाफा करने का अनिच्छुक रहा है लेकिन सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं। यह बात याद करना उचित होगा कि बीते दशक में जो बैलेंस शीट संकट उत्पन्न हुआ था उसके लिए अधोसंरचना और परियोजनाओं की फाइनैंसिंग ही जिम्मेदार थी। इसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज का स्तर दो अंकों में पहुंच गया था। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक नहीं चाहता है कि बैंकिंग क्षेत्र दोबारा वैसी स्थिति में फंसे। बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट को दोबारा बेहतर बनाने में बहुत अधिक समय, पूंजी और कोशिशें लगी हैं और अब यह दशक भर की सबसे बेहतर स्थिति में है। ऐसे में इसका बचाव होना ही चाहिए।

निश्चित तौर पर अभी यह प्रस्ताव मसौदा स्तर पर ही है और सभी अंशधारकों के सुझावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल, रिजर्व बैंक के अंतिम निर्णय में दो बुनियादी सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो सभी अंशधारकों को भी स्वीकार्य होने चाहिए। पहला बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और मजबूती सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पिछले दशक में भारत यह देख चुका है कि ऋण देने में ढिलाई से क्या हो सकता है। अनुचित ऋण मानकों पर आधारित पूंजीगत ऋण चक्र और उसके बल पर हासिल आर्थिक वृद्धि को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता। रिजर्व बैंक को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 5 फीसदी प्रोविजनिंग क्यों उचित रहेगी। दूसरी बात, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में भेद नहीं किया जाना चाहिए। यह कहा जाता रहा है कि सरकारी परियोजनाओं की प्रोविजनिंग कम होनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र को नुकसान होगा जिससे बचा जाना चाहिए। निजी और सरकारी बैंकों के लिए मानक भी अलग-अलग नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर उच्च प्रोविजनिंग कई बैंकों को लंबी अवधि के ऋण देने से हतोत्साहित भी कर सकती है क्योंकि उनमें जोखिम अधिक होता है। यह बात ध्यान देने लायक है कि बेहतर कॉरपोरेट ऋण बाजार की अनुपस्थिति में भारतीय कंपनियां बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। बैंकों को लंबी अवधि के ऋण से बचाने की सोच अच्छी है लेकिन नीति निर्माताओं को लंबी अवधि की योजनाओं को ऋण के लिए भी सक्षम उपाय करने चाहिए।

विदेशी निवेशकों द्वारा धन वापसी चिंताजनक

हाल के दिनों में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई गिरावट जितनी चिंताजनक है, उतनी ही विनिवेश की बढ़ती गति भी है। विस्तार से बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

करीब एक पखवाड़ा पहले इस समाचार पत्र में खबर छपी थी कि केंद्र सरकार के 17 विभागों के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के 46 प्रस्ताव करीब 12 सप्ताह से लंबित हैं। ऐसे आवेदनों के निपटान की समय सीमा भी 12 सप्ताह है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी इसे लेकर चिंतित था और उसने सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा कि वे इन आवेदनों की मंजूरी की गति तेज करें। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के बाद भी ऐसी देरी हुई।

क्या यह भी बीते कुछ महीनों में देश में सकल एफडीआई आवक में कमी की वजह हो सकती है? यह सही है कि वैश्विक एफडीआई में धीमापन आया है लेकिन देश की सकल एफडीआई आवक में 2022-23 में तेज गिरावट आई और यह 16 फीसदी गिरकर 71 अरब डॉलर रहा। याद रहे कि नौ वर्षों में यह पहला मौका था जब देश की सकल एफडीआई आवक में कमी आई। चिंता की बात यह है कि 2023-24 के पहले 11 महीनों में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा, हालांकि गिरावट की दर में उल्लेखनीय कमी आई। अप्रैल से फरवरी 2023-24 में सकल एफडीआई आवक 2.7 फीसदी गिरकर 65 अरब डॉलर रही। पूरे वर्ष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। यह गिरावट कितनी गंभीर है? नरेंद्र मोदी सरकार कहेगी कि उसके 10 वर्ष के कार्यकाल के शुरुआती आठ साल में हर साल सकल एफडीआई आवक बढ़ी और शेष दो वर्षों की गिरावट के लिए विकासशील देशों में बढ़ी ब्याज दर तथा वैश्विक आर्थिक दिक्कतें जिम्मेदार हैं जिन्होंने अधिकांश देशों में एफडीआई आवक को प्रभावित किया। परंतु यह स्पष्टीकरण देश में एफडीआई प्रवाह की एक बड़ी समस्या की अनदेखी कर देता है। देश में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों द्वारा धन की स्वदेश वापसी या विनिवेश के लिए जो किया जा रहा है, वह कहीं अधिक गंभीर स्थिति की ओर संकेत करता है।

सन 2001-02 से 2008-09 तक मौजूदा विदेशी निवेशकों द्वारा धन की स्वदेश वापसी या विनिवेश सकल एफडीआई आवक का बहुत छोटा हिस्सा था। यह 0.08 से 1.15 फीसदी के बीच सीमित था। बहरहाल, 2009-10 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 12 फीसदी हो गई यानी 38 अरब डॉलर के सकल एफडीआई की तुलना में 4.6 अरब डॉलर की वापसी। 2011-12 में यह बढ़कर 29 फीसदी हो गई यानी 46.55 फीसदी के सकल एफडीआई की तुलना में 13.6 अरब डॉलर की वापसी। यह बात भी उल्लेखनीय थी कि 2009 से 2012 के बीच जब सकल एफडीआई 2.1 से 2.8 फीसदी की अच्छी दर पर था तब भी उस वक्त मौजूदा विदेशी निवेशकों में से कई या तो अपनी पूंजी वापस अपने देश भेज रहे थे या उसे अन्य जगहों पर भेजकर भारत में अपने कारोबार से बाहर निकल रहे थे अथवा विनिवेश के जरिये अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे थे। इन तीन वर्षों के दौरान ऐसी वापसी जीडीपी के 0.3 फीसदी से बढ़कर 0.7 फीसदी हो गई। यह वह अवधि थी जब वैश्विक आर्थिक उथलपुथल थी और ब्याज दरें बढ़ रही थीं। परंतु ऐसी निकासी ने पहले से जुटाए गए विदेशी निवेश को बरकरार रखने की देश की क्षमता पर भी बुरा असर डाला।

बाद के चार वर्षों में हालात में अपेक्षाकृत सुधार हुआ। सकल एफडीआई में 2012-13 से सुधार आने लगा और उल्लेखनीय बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद सकल एफडीआई में मौजूदा विदेशी निवेशकों का विनिवेश और स्वदेश वापसी तेजी से कम हुआ। यह 2011-12 के 29 फीसदी से कम होकर 2015-16 में 19 फीसदी रह गया।

बहरहाल 2016-17 से यह रुझान करीब तीन वर्ष के लिए बदला। देश का सकल एफडीआई प्रवाह बढ़ता रहा, हालांकि इसकी वार्षिक दर कम हुई और एक से आठ फीसदी के बीच रही। परंतु सकल एफडीआई आवक में स्वदेश वापसी और विनिवेश की हिस्सेदारी बढ़कर 30-35 प्रतिशत हो गई। क्या नवंबर 2016 की नोटबंदी और जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लागू होने की मौजूदा एफडीआई के बाहर जाने में कोई भूमिका थी?

कोविड-19 के ठीक पहले यानी 2019-20 में न केवल देश के सकल एफडीआई आवक में 20 फीसदी का इजाफा हुआ बल्कि विनिवेश और स्वदेश वापसी के लिए निकासी की दर भी धीमी हुई। इसके परिणामस्वरूप 2019 में 74 अरब डॉलर की सकल एफडीआई आवक में केवल 18 अरब डॉलर की राशि का विनिवेश हुआ और वह देश से वापस गई। इस प्रकार यह हिस्सेदारी घटकर 25 फीसदी से नीचे आ गई। अगले दो वर्ष देश कोविड से प्रभावित रहा और सकल एफडीआई आवक बढ़ी लेकिन 2022-23 में इनमें 16 फीसदी गिरावट देखने को मिली और यह 71 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान स्वदेश वापसी और विनिवेश भी बढ़कर सकल एफडीआई आवक के 33-34 फीसदी हो गया था और 2022-23 में तो यह 41 फीसदी तक जा पहुंचा। 2023-24 के पहले 11 महीनों में इस चिंताजनक रुझान में और गिरावट आई। अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान यह बढ़कर 41 फीसदी हो गया और इस अवधि की सकल एफडीआई आवक के 59 फीसदी के बराबर रहा।

ऐसे में यह स्वाभाविक है कि एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार विभाग यानी डीपीआईआईटी इस बात का परीक्षण करे कि आखिर क्यों विदेशी निवेशकों के आवेदनों को मंजूर करने में समय लग रहा है। इसका काम इसलिए भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया क्योंकि मोदी सरकार ने 2017 में एक संस्थागत पुनर्गठन किया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दायरे में था, उसे जून 2017 के एक आदेश के जरिये समाप्त कर दिया गया। सरकार के अलग-अलग विभागों को यह अधिकार दिया गया कि वे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ मशविरा करके एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दें। बाद में इसे ही डीपीआईआईटी का नाम दिया गया। देश में एफडीआई की आवक में गिरावट की प्रकृति को देखते हुए डीपीआईआईटी के लिए बेहतर होगा कि वह संस्थागत सुधार के बारे में विचार करे।

विदेशी निवेश के आवेदनों को मंजूरी के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार एफआईपीबी जैसे संस्थान को पुनर्जीवित करने पर विचार कर सकती है जो पर्याप्त अधिकार संपन्न हो और जिसे विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी का काम सौंपा जा सके। इसमें न केवल सुसंगत मंजूरी प्रक्रिया होनी चाहिए बल्कि उसे इतना अधिकार संपन्न भी होना चाहिए कि देश को विदेशी निवेशकों का पसंदीदा केंद्र बनाने की राह में आने वाली किसी भी प्रक्रियागत या नीतिगत दिक्कत को दूर कर सके। फिलहाल विभिन्न विभाग और मंत्रालय शायद इसे लेकर पूरी तरह अधिकार संपन्न न हों।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक नया अंतर मंत्रालयीन संस्थान इस चिंताजनक रुझान की पड़ताल कर सकता है कि आखिर कैसे मौजूदा निवेशक अपनी पूंजी को विनिवेश के जरिये या अन्य तरीकों से वापस ले जा रहे हैं। यह सही है कि भले ही एफडीआई की कुल आवक में इजाफा हो लेकिन कुछ निवेश तो विनिवेश या वापसी के जरिये यहां से जाएगा ही। परंतु भारत में ऐसी निकासी की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। इससे देश के भुगतान संतुलन पर एफडीआई की आवक का सकारात्मक प्रभाव निष्क्रिय हो जा रहा है।

ऐसे में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके तथा उनके आवेदनों की तेज मंजूरी की मदद से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मौजूदा निवेशक देश में बने रहें और अपने कारोबार का विस्तार करके देश की अर्थव्यवस्था को उच्च निवेश का लाभ लेने दें। इन हालात में पहला कदम यही होगा कि यह समझने की प्रक्रिया आरंभ की जाए कि देश के सकल एफडीआई प्रवाह में विनिवेश और धन वापसी की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में बढ़ी क्यों है?

चिप से बढ़ेगी डिजिटल ढांचे की ताकत

बुनियादी ढांचा

विनायक चटर्जी

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बिज़नेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम में 27 मार्च, 2024 को सूचना-प्रौद्योगिकी, संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। वैष्णव ने कहा कि दुनिया में सेमीकंडक्टर का बाजार इस समय 75 अरब डॉलर का है, जो अगले 6-7 वर्षों में दोगुना हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत खास मकसद से अपनी क्षमताएं विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

उन्होंने दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि तकनीक में रुचि रखने वाले लोग आसानी से मिलने, हरित ऊर्जा की उपलब्धता और विशेष रसायन विनिर्माण तंत्र ऐसे कारक हैं जो भारत के पक्ष में जाते हैं। तीसरी अहम बात उन्होंने यह कही कि भारत पूर्ण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इनमें नई चिप से लेकर इनका ढांचा तैयार करने एवं इनकी जांच कर इन्हें फैब्रिकेशन (विनिर्माण) संयंत्र तक ले जाना शामिल हैं। चौथी बात उन्होंने यह कही कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

वैष्णव की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब वैश्विक मंचपर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका का वाणिज्य विभाग चिप निर्माण के लिए 39 अरब डॉलर के अनुदान की पुनर्संरचना कर रहा है। ऐसा समझा जाता है कि अमेरिका ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) को 11.6 अरब डॉलर का अनुदान देगा। इस रकम के साथ चिप बनाने वाली दुनिया की इस शीर्ष कंपनी को अमेरिका में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अनुदान के लिए अन्य कंपनियां भी कतार में खड़ी हैं जिनमें इंटेल, सिक्योर इंक्लेव, ग्लोबल फाउंड्रीज, माइक्रोचिप टेक, बीएई सिस्टम्स सहित कुछ अन्य शामिल हैं। जापान और यूरोपीय संघ भी ऐसे ही कदम उठा रहे हैं।

भारत में सरकार ने 'डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऐंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्ट्मस इन इंडिया' नीति के तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह नीति 21 दिसंबर 2021 को अधिसूचित हुई थी और 76,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। इस नीति का मकसद भारत को आत्मनिर्भर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ढांचा एवं विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार परियोजना लागत का 50 फीसदी हिस्सा वित्तीय मदद के रूप में देगी। यह नीति विशेष तौर पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्स और कम्पाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकन फोटोनिक्स, सेंसर्स और असेंबली एवं टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगी।

राज्य सरकारें भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार से 50 फीसदी समर्थन के अलावा गुजरात सरकार ने टाटा की परियोजना के लिए 20 फीसदी पूंजी समर्थन देने का वादा किया है। टाटा जैसी कई परियोजनाएं इस नीति के अंतर्गत काम कर रही हैं। गुजरात के साणंद में माइक्रॉन की असेंबली एवं टेस्टिंग संयंत्र ने सितंबर 2023 में निर्माण शुरू किया था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपये निवेश से एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी) के साथ साझेदारी कर रही है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली ऐंड टेस्ट (टीएसएटी) प्राइवेट लिमिटेड की अगुवाई में दूसरी परियोजना के तहत असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपये के साथ पैकेजिंग एवं टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना की जाएगी। एक अन्य कंपनी सीजी पावर, रेनेसां इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपये निवेश के साथ असेंबली एवं टेस्टिंग संयंत्र की स्थापना करेगी। टाटा-पीएसएमसी प्रस्ताव एकमात्र ऐसा फैब्रिकेशन संयंत्र है जिसे अब तक सरकार की मंजूरी मिली है। यह भी समझा जा रहा है कि दुनिया के कुछ अन्य देश भारत में प्रवेश करने की रणनीति (स्थान और स्थानीय साझेदार की तलाश) को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

तकनीक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से बात करें तो चिप और सेमीकंडक्टर का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है मगर ये एक जैसे नहीं हैं। सेमीकंडक्टर एक प्रकार की ऐसी सामग्री होती है जो बिजली के चालक और कुचालक के बीच की श्रेणी है। दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) या माइक्रोचिप को चिप कहते हैं। यह एक छोटा सेमीकंडक्टर होता है जिस पर हजारों या लाखों छोटे इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तैयार किए जाते हैं। ये कलपुर्जे एक विशेष कार्य- जैसे कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना- पूरे करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चिप काफी पेचीदा उत्पाद होते हैं जिन्हें बनाना आसान नहीं होता है। फैब्रिकेशन विशिष्ट संयंत्रों में होता है जिन्हें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र या 'फैब' के नाम से जाना जाता है। इन संयंत्रों में फोटोलिथोग्राफी, एचिंग (निक्षारण), डोपिंग और मेटलाइजेशन की मदद से सिलिकॉन वेफर पर चिप का भौतिक ढांचा तैयार किया जाता है।

इस कार्य में तकनीक की गहरी समझ की जरूरत होती है। इसके अलावा लागत के स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने से एक ऐसी अलग किस्म की आपूर्ति व्यवस्था तैयार हो गई है, जिसमें कुछ ही कंपनियां हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डेटा प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट करने के लिए आवश्यक क्षमताओं से लैस करता है। ये एकीकृत सर्किट होते हैं जो सिलिकॉन से बने होते हैं। कुछ वर्ग मिलीमीटर में अरबों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की पैकिंग से ये सर्किट तैयार होते हैं। हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उन सभी के लिए चिप महत्त्वपूर्ण होते हैं। स्मार्टफोन, सर्वर, आधुनिक कारें, मशीनरी एवं ऑटोमेशन, महत्त्वपूर्ण ढांचे और यहां तक कि रक्षा प्रणाली, सभी में चिप की मौजूदगी होती है। भारत में चिप की मांग अधिक है मगर यह सुस्त उपभोक्ता देश है और भू-राजनीतिक तनाव से आपूर्ति व्यवस्था को होने वाले नुकसान की जद में आ सकता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान चिप की कमी और हुआवे पर अमेरिकी प्रतिबंध बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को रेखांकित करती हैं। फिलहाल भारत सेमीकंडक्टर का आयात (100 फीसदी) करता है। मिल रहे संकेतों के अनुसार आयात का आंकड़ा साल 2030 तक बढ़कर 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए अति महत्त्वपूर्ण एवं उच्च-तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप सेमीकंडक्टर आपूर्ति व्यवस्था का स्थानीयकरण करना जरूरी हो गया है। स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने इसके लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं।

साल 2019 के शुरू में सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्रों को 'आधारभूत दर्जा' दे दिया था। ऐसा पहली बार था जब एक विनिर्माण संयंत्र आधारभूत ढांचे की आधिकारिक परिभाषा में शामिल किया गया था। पूंजीगत सब्सिडी आवंटन की प्रक्रिया अगला तर्कसंगत कदम थी। इस उद्योग की संवेदनशीलता, वैश्विक, तकनीकी एवं निवेश संबंधी चुनौतियों को देखते हुए सरकार को दिलचस्पी दिखाने वाली संभावित इकाइयों की जरूरतें पूरी करने के लिए पूंजी सब्सिडी फंड का आकार बढ़ाना एक उपयुक्त विकल्प लग सकता है। देश कुछ और कंपनियों के साथ अपने डिजिटल ढांचे को और ताकत देने के लिए तैयार है।

(लेखक आधारभूत ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। साथ में अचिंत्य तिवारी और वृंदा सिंह)

आपका पक्ष

घटते पेड़, बढ़ती गर्मी चिंता का विषय

मई माह में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है और लू चलने लगती है। लोगों के स्वास्थ्य पर लू बहुत ज्यादा असर डालती है जो बीमार कर देती है। दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और लू चलने लगती है। ऐसे में लोगों को बहुत आवश्यक न हो तो घरों से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए। प्रशासन को भीषण गर्मी में स्कूलों के समय में बदलाव करना चाहिए। स्कूलों में दोपहर में ही छुट्टी होती है। ऐसे में कड़क धूप में बच्चे घर लौटेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इस माह की शुरुआत में ही देश के कुछ राज्यों में लू चलने लगी है जहां स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी दे दी है। बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण हमारा प्रकृति के विरुद्ध जाना, पर्यावरण की अनदेखी करना और अंधाधुंध वृक्षों को काटना है। अगर विकास के नाम पर और अपनी सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम इसी तरह प्रकृति के विरुद्ध जाते रहे और पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सर्दी-गर्मी के मौसम बहुत ज्यादा तंग तो करेंगे ही, सांस लेने के लिए शुद्ध और साफ हवा भी भारी कीमत चुकाकर प्राप्त करनी होगी। अतः सरकार, प्रशासन, समाजसेवी संस्थाओं, बुद्धजीवियों और अन्य सभी प्रबुद्धजनों को पर्यावरण बचाने के लिए प्राथमिक और युद्ध स्तर पर जागरूक अभियान चलाने होंगे। हमें जंगल बचाने के साथ-साथ देशव्यापी अभियान चलाकर भारी मात्रा में पौधरोपण करने होंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर कड़ी धूप से बचने के लिए छाता लिए पर्यटक

कैसे सुनिश्चित हो खाद्य पदार्थों की शुद्धता

'मिलावटी उत्पाद' एक गंभीर, जरूरी और संवेदनशील मुद्दा है। सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों में मिलावट लाभ कमाने के लिए की जाती है। खाद्य अपमिश्रण से अंधापन, लकवा और ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में उपभोग करने वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध, छाछ, शहद, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, घी, खाद्य तेल, चाय-कॉफी, मसाले, खोया, आटा आदि में मिलावट की जा सकती है। भिन्न प्रकार की मिलावट के प्रभाव भी प्रतिकूल रूप से अलग ही होते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना बहुत आसान है। इसकी जांच के कई सरल और घरेलू तरीके हैं, जिससे कोई भी उपभोक्ता आसानी से खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच कर सकता है। खाद्य अपमिश्रण की जांच के कई आसान परीक्षण भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं खाद्य अभियंत्रण विभाग ने सुझाए हैं जिनका समुचित व पर्याप्त प्रचार-प्रसार बेहद जरूरी है। उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे खाद्य पदार्थों की शुद्धता के प्रति जागरूक रहें और खुली खाद्य सामग्री न खरीदें। हमेशा मानक प्रमाण चिह्न (एगमार्क, एफपीओ, हॉलमार्क) वाली सामग्री ही खरीदें और खरीदे जाने वाली सामग्री के गुणों, रंगों, शुद्धता आदि की विधिवत और समुचित जानकारी रखें।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर (बाएं) ने नई दिल्ली में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। करीब 6 महीने पहले मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद पहली उच्च स्तरीय यात्रा के तहत जमीर दिल्ली आए हैं। मुइज्जू द्वीपीय राष्ट्र से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर दे रहे हैं जिससे दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। भारत अपने अधिकतर सैन्यकर्मियों को वापस बुला चुका है। मुइज्जू ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 10 मई 2024

यात्रियों की मुसीबत

एयर इंडिया एक्सप्रेस को लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी। हालांकि सहयोगी कंपनी एयर इंडिया उसकी मदद के लिए आगे आई और खबर है कि करीब 20 रूटों पर वह उड़ानें संचालित कर रही है। फिर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस को 85 फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी। कंपनी ने बुधवार को भी 80 से ज्यादा फ्लाइट कैंसल की थी। निश्चित रूप से इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस : उड़ानें रद्द

एक महीने में दूसरी बार | करीब एक महीने के अंतर पर यह दूसरा मौका है जब टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी के यात्रियों को इस तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ा है। अप्रैल में ग्रुप की कंपनी विस्तारा को अचानक पायलटों के छुट्टी पर चले जाने से 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं।

विलय की चुनौतियां | दरअसल, टाटा ग्रुप में अलग-अलग एयरलाइन कंपनियों के विलय की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में अलग-अलग कंपनियों में सैलरी स्ट्रक्चर की रीबैलेंसिंग का चुनौतीपूर्ण काम होना है। यह बिजनेस डिसिजन ग्रुप का आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से इसका असर उड़ानों के रद्द होने के रूप में सामने आ रहा है और जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, उससे साफ है कि यह काम कुशलता से नहीं किया जा रहा।

एविएशन सेक्टर पर दबाव | देश का एविएशन सेक्टर कई तरह के दबावों से जूझ रहा है। हालांकि यह कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर को पीछे छोड़ चुका है। एयर ट्रैफिक मूवमेंट के जो आंकड़े 2022 में 18 करोड़ से कुछ ज्यादा थे, 2023 में वे 32 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। लेकिन यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या की जरूरतें पूरी करने वाले विमानों की संख्या महामारी-पूर्व के दौर से और कम हो गई है।

किराए में बढ़ोतरी | इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि हवाई किराए में अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जब भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की जाती हैं तो यात्रियों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। इन हालात में उनके लिए वैकल्पिक फ्लाइट्स का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

मार्केट पर वर्चस्व | अगर जनवरी-मार्च तिमाही की बात की जाए तो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के करीब 90% हिस्से पर इंडिगो और टाटा ग्रुप एयरलाइंस का कब्जा दिखता है। मार्केट पर दो बड़े खिलाड़ियों का वर्चस्व कॉम्पिटिशन के लिहाज से कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। इससे किराए के नीचे आने की उम्मीद भी नहीं बन रही।

यात्री न भुगतें खामियाजा | बहरहाल, ऊंचे किराए, और मुनाफे की तगड़ी संभावना के बीच यात्रियों की परेशानी की मौजूदा स्थिति स्वीकार्य नहीं हो सकती। एविएशन रेग्युलेटर DGCA को कंपनियों से यह सुनिश्चित करवाना चाहिए कि उनकी आंतरिक समस्याओं का खामियाजा यात्रियों को न भुगतना पड़े।

क्रॉस-वर्ल्ड

Tech पर तकरार

शैलेंद्र पांडेय

टिकटॉक को भूले तो नहीं होंगे आप अभी तक! बाइडन सरकार ने टिकटॉक की पैरेंट चीनी कंपनी को अल्टिमेटम दिया है कि उसे अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी बेचनी होगी, नहीं तो ऐप पर बैन लगा दिया जाएगा। भारत, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में टिकटॉक पहले ही बंद हो चुका है।

पिछले कुछ बरसों से टेक्नॉलजी को लेकर इस तरह की तकरार में तेजी आई है। विकसित और विकसित बनने के लिए दौड़ लगा रहे मुल्कों में टेक पावर बनने की होड़ है। इसे Technological Nationalism कहते हैं। जब हर मुद्दे पर Globalism की बात की जा रही है, तब तकनीकी राष्ट्रवाद बढ़ने के पीछे कि टेक मामलों में पहले अपने हितों की रक्षा की जाए। सरकारें प्रयास करती हैं कि किस तरह से तकनीकी की ताकत वैश्विक बाजार को प्रभावित किया जाए। इसी कड़ी में तकनीक के जोर से तमाम दूसरे हित भी साधने की कोशिश की जाती है। टिकटॉक एक उदाहरण है, वैसे तो चीन पर यह आरोप लगता रहा है कि वह अपनी कंपनियों के जरिये विदेशों में जासूसी कराता है। चीनी टेलिकॉम कंपनी Huawei का मामला बहुत पुराना नहीं हुआ। जब अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाई तो जवाब में चीन ने अपनी सभी पब्लिक और प्राइवेट एजेंसियों को विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करने का आदेश दिया। यानी टेक्नॉलजी सीधे तौर पर दो महाशक्तियों के बीच टकराव की वजह बन गई। टेक्नॉलजिकल नैशनलिज्म का यह भी एक रंग है, जिसमें बाजार पर नियंत्रण का खेल चलता है। हालांकि यह खेल हमेशा इतना बदरंग नहीं होता।

दूसरों के यहां ताकझांक के बजाय अपने यहां तकनीक में निवेश के जरिये टेक्नॉलजिकल नैशनलिज्म को बढ़ाने की मिसाल के रूप में दक्षिण कोरिया हमारे सामने है। Samsung और Hyundai जैसी उसकी कंपनियां कारोबारी सफलता की मिसाल हैं। इसी तरह, भारत की टेक ताकत वे लाखों देशवासी हैं, जो दुनियाभर में फैली टेक इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने टेक्नॉलजी और इनोवेशन की रफ्तार बढ़ाई है। जब AI का दखल बढ़ रहा है तब तकनीकी राष्ट्रवाद के मोर्चे पर आक्रामकता दिखने की उम्मीद अधिक है। चूंकि व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां टेक्नॉलजी के इर्द-गिर्द घूमने लगी हैं, इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि वह इसमें दूसरों पर निर्भर रहे। इसलिए संरक्षणवाद बढ़ रहा है। हालांकि इससे एक-दूसरे के प्रति अविश्वास और बढ़ेगा, स्पेस कम होगा।

एकदा

सुनहरे जूते

13वीं सदी के फारसी कवि और आध्यात्मिक गुरु शेख सादी अपने अलग तरह के धार्मिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। वह आडंबर और दिखावे के विरोधी थे और मानते थे कि हर स्थिति में खुदा की रहमत छिपी होती है। सादी नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन नमाज के लिए मस्जिद जाते समय उनके मन में ईश्वर के फैसलों पर सवाल उठने लगे। उनके पैरों में फटे जूते थे, जबकि एक धनी व्यक्ति सुनहरी मीनाकारी वाले जूते पहने नमाज पढ़ने आया। सादी ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कितनी बार नमाज पढ़ने आता है। उसने जवाब दिया- साल में एक बार। सादी ने मन ही मन ईश्वर से शिकायत की, 'मैं रोज पांच वक्त नमाज पढ़ता हूं, फिर भी मेरे पास फटे जूते हैं। जबकि यह व्यक्ति साल में एक बार आता है और उसके पास इतने महंगे जूते हैं।' उनकी यह शिकायत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दूसरा व्यक्ति मस्जिद में आया, जिसके पैर ही नहीं थे। वह घिसटते हुए मस्जिद तक पहुंचा था। यह देख सादी की आंखें खुल गईं और उन्होंने अपने स्वस्थ पैरों के लिए खुदा का शुक्रिया किया, जिससे वह चल-फिर सकते हैं। इस घटना ने सादी को संतोष का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि किसी से तुलना करने पर हमेशा अभाव का एहसास होता है, लेकिन निर्बल और असहाय लोगों को देखकर संतोष का भाव पैदा होता है। सादी ने खुदा से क्षमा मांगी और जो कुछ जीवन में मिला था, उसके लिए आभार व्यक्त किया।

Subrata Dhar

संकलन : ललित गर्ग

बिहार में दोनों गठबंधनों की लड़ाई से लगता है कि 2024 की टक्कर एकतरफा नहीं रहने वाली

लोकसभा चुनाव में हवा नहीं, हक की बात

उदय चंद्र

पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव एकतरफा होगा। लेकिन, बिहार को देखकर पता चलता है कि क्यों मुकाबला उम्मीद से अधिक करीबी हो सकता है और कैसे गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर है।

Uday Deb

मुश्किल में थी BJP | बिहार के CM और JDU प्रमुख नीतीश कुमार ने जनवरी में दोबारा पाला बदला। उससे पहले तक लग रहा था कि BJP को राज्य में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। यूपी के विपरीत बिहार में BJP के पास कोई प्रमुख क्षेत्रीय नेता नहीं था। न तो पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश पर्याप्त लग रहे थे और न ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। विपक्ष ने बिहार की तरह पूरे देश में जातिगत जनगणना का वादा कर हिंदुत्व के रथ को एक बार फिर से रोक दिया था।

OBC पर नजर | BJP के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। इसी बीच OBC मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने आखिरी प्रयास किया। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। नीतीश BJP के साथ चले गए, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत कम थे।

कमजोर कड़ी | RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सहयोगियों से पिछड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी थे। JDU के जातीय समीकरण सबसे अच्छे फिट बैठते हैं BJP के साथ। वहां उम्मीद रहती है कि BJP का परंपरागत सवर्ण वोटर पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी वोट देगा।

मंदिर का असर | NDA इस बार 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहता है, जब उसने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन, उसका समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। BJP के धुर समर्थकों को छोड़कर अयोध्या का राम मंदिर बहुत कम लोगों को उत्साहित कर रहा है। RJD के तेजस्वी यादव बिहार में जाति जनगणना का श्रेय ले रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने इसके लिए अनिच्छुक नीतीश कुमार पर दबाव डालकर इसके लिए मनाया था।

नया समाजवाद | जाति जनगणना पर आधारित नैशनल पॉलिसी का वादा कर कांग्रेस का घोषणापत्र शायद और आगे निकल गया। दिल्ली के गलियारों में इसे मंडल 2.0 के तौर पर देखा जा रहा है। हकीकत में यह डिजिटल युग के लिए नया समाजवाद है, जो 'जितनी आबादी उतना हक' के विचार पर आधारित है। तेजस्वी का नया समाजवाद उस राजनीति से ऊपर उठना चाहता है, जिसमें किसी से उसकी जाति पूछी जाती है। बिहार में अगड़ी जातियां यानी ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत आबादी के छठे हिस्से से भी कम हैं। ऐसे में जाति जनगणना का मुद्दा एक मजबूत चुनावी गठबंधन बना सकता है।

मजबूत विपक्ष | कई जिलों में, जहां मुस्लिमों की संख्या आबादी के पांचवें हिस्से के करीब है, विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। यह स्थिति खासकर मध्य और दक्षिण बिहार में है। इसके अलावा, महागठबंधन ने लाखों नई नौकरियों का वादा किया है। यह बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को जाहिर करता है।

हिंदुत्व को टक्कर | दिल्ली की सुर्खियों से दूर बिहार में हिंदुत्व को एक नया प्रतिद्वंद्वी मिला है। यह प्रतिद्वंद्वी है जाति, वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राजनीति का मिश्रण। अब BJP को जवाब देना चाहिए कि उसका झुकाव अगड़ी जातियों की ओर नहीं है। लेकिन, साथ में उसे अगड़े वोटबैंक को भी साधे रखना है।

कठिन चुनाव | दोनों विरोधी एक समान मजबूत हैं। ऐसे में swing voters को दो विरोधी धारणाओं के बीच चुनाव करना होगा। एक पक्ष मजबूत व्यक्तित्व केंद्रित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वादा करता है। साथ में, कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों तक लाभ पहुंचा रहा है। दूसरा पक्ष सामाजिक न्याय की नई राजनीति की पेशकश कर रहा। ऐसे में सात चरणों में बिहार में मतदाताओं को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की संभावना है कि निर्णय बंटा हुआ हो। ऐसे चुनाव में जहां कोई हवा न चल रही हो, वहां राजनेता वोटरों से व्यावहारिक अपील करने के लिए मजबूर होते हैं। मतदाताओं को भी उतने ही कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं।

काम पर मुहर | लोकतांत्रिक जीवन में, सभी राजनीतिक दलों में करिश्माई नेता फले-फूले। फिर हमने देखा कि उनकी अपील का चुनावों पर असर घटता गया। एक बार जब जादू टूटता है तो मतदाता अक्सर भ्रमित और निराश हो जाते हैं। नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राजनेताओं द्वारा अधिकतर अनदेखा किया जाता है, फिर चाहे वे लेफ्ट से हों या राइट से या फिर बीच से। चुनावों में जहां एक भावना प्रबल नहीं होती, मतदाता निर्णय के माध्यम से विकल्प चुनते हैं कि कौन उनके लिए क्या कर सकता है।

बिहार की चुनावी स्थिति
- BJP को राम मंदिर से ज्यादा मदद नहीं
- कास्ट सेंसस हो सकता है बड़ा दांव
- मध्य, दक्षिण बिहार में विपक्ष मजबूत

हक की बात | बिहार में ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वह बुद्ध हुए। अब यह राज्य हमें ज्ञान दे सकता है कि मतदाता यह निर्णय कैसे लेते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। जब कोई हवा कमजोर होती है या खत्म होती है, तो लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता। वास्तव में यह तब पनप सकता है। रोजमर्रा के जरूरी मुद्दों पर वोटर एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं और राजनेताओं को भी इन मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह राजनीति में हक का दायरा बढ़ता है।

(लेखक कतर की Georgetown University में राजनीति और इतिहास पढ़ाते हैं)

रायबरेली से राहुल का लड़ना है सही राजनीति

आर जगन्नाथन

अक्सर राहुल गांधी पर इल्जाम लगता है कि वह सियासत में गलत वक्त पर गलत चाल चलते हैं। 2022 में जब गुजरात में उनकी पार्टी बुरे हाल में थी, तब वह अपनी साउथ-नॉर्थ भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। लेकिन इस बार, ईस्ट-वेस्ट वाली यात्रा का समापन लोकसभा चुनाव का शेड्यूल आते ही हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यात्रा लोगों से कनेक्ट होने के लिए तो ठीक है, लेकिन चुनावी जंग में मजबूती हासिल करने के लिए उन्हें और भी बहुत कुछ करना होगा। ऐसे में उनका रायबरेली से इलेक्शन लड़ने का फैसला बिल्कुल सही कदम है।

सधी हुई चाल | मीडिया कयास लगा रही थी कि 2019 में हारने के बाद अमेठी में वह दोबारा स्मृति ईरानी के सामने उतरेंगे। लेकिन रायबरेली सीट चुनकर उन्होंने दो बातें साफ कर दी हैं- पहली, उन्हें पता है कि यूपी में जीत या हार का सियासी असर क्या होगा। दूसरी, लंबी रेस के लिए उन्हें अपनी पार्टी की जड़ें और मजबूत करनी हैं।

मुश्किल फैसला | अलबत्ता इसके चलते उन्हें वायनाड के वोटर्स को कुछ सफाई तो देनी ही पड़ेगी, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और जहां उनके जीतने की उम्मीद भी है। लेकिन यह बाद की बात है। वायनाड के लोगों को उन्होंने अपना परिवार और वायनाड को अपना घर बताया था। अब अगर वह रायबरेली भी जीत जाते हैं, जिसकी उम्मीद पहले से ही है तो उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा।

रायबरेली है सेफ | गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला कई वजहों से सही लगता है। पहली, अगर वह अमेठी से लड़ते तो स्मृति ईरानी से कड़ी टक्कर तो मिलती ही, जीत के लिए उन्हें अपना काफी वक्त देना पड़ता। वहीं, रायबरेली 2019 की मोदी लहर के बावजूद यूपी में कांग्रेस की इकलौती जीती हुई सीट है। तब पार्टी को वहां BJP के सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से 1,67,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। इस बार सियासी फायदे-नुकसान का हिसाब लगाने पर साफ दिखता है कि रायबरेली ज्यादा फायदेमंद है।

यूपी है जरूरी | जाहिर है, राहुल समझ चुके हैं कि उन्हें न सिर्फ अपनी सीट जीतनी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को दोबारा खड़ा भी करना है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में नौ सीटें थीं, जब सिर्फ सात सीटों के अंतर से वह BJP से आगे थी। 2009 के चुनाव में पार्टी ने यूपी से 21 सीटें जीती थीं। यानी 2004 हो या 2009, अविभाजित आंध्र प्रदेश के अलावा सत्ता में वापसी के लिए यूपी बहुत जरूरी था।

कॉमन रूम

जज्बे का टेंपो हाई | कांग्रेस के लिए यह मानना बेवकूफी होगी कि रायबरेली की सीट पक्की है, क्योंकि BJP इसे यूं ही तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन जीत हो या हार, राहुल ने अपनी ही पार्टी को एक मजबूत संदेश दिया है कि हम लड़ने वाले हैं। अपने सिपाहियों को यह संदेश देना हमेशा अच्छा होता है। खासकर अगर वह अमेठी में पार्टी के नए कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा के लिए जमकर प्रचार करें और स्मृति ईरानी को तगड़ी टक्कर दें।

डटे रहने का संदेश | यह कहना गलत होगा कि 4 जून को राहुल अपनी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने इतना तो दिखा दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं और भागने वाले तो बिलकुल नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले और उसके बाद भी वह लंबे वक्फे के लिए देश से गायब रहते थे, जो उनकी पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आता था।

नई तस्वीरें | भारत जोड़ो यात्रा ने उनके लिए दो काम किए। पहला, इसने उन्हें अपनी 'पप्पू' वाली इमेज से छुटकारा पाने में मदद की। और दूसरा, इसने साबित किया कि जरूरत पड़ने पर वह लंबी रेस के लिए फिट हैं। रायबरेली में वापसी का भी यही संदेश है। भले ही किसी को जातिगत जनगणना के उनके अजेंडे या वोटरों को मुफ्त की चीजें बांटने की बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन अब पार्टी को बेहतर नतीजे देने की उनकी तत्परता पर शक नहीं किया जा सकता।

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

फोन नहीं उठाते

तीन चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान कुल 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तमाम राजनीतिक दलों का दिल धक-धक करने लगा है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल एक्जिट पोल के नंबर पता लगाने में व्यस्त हो गए हैं। वे इसके लिए इतने बेताब हैं कि एक्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को फोन करके परेशान कर रखा है। ऐसी ही एक एजेंसी के मैनेजर साहब ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कई मित्र नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया है। अब वे उन्हें झूठ तो बता नहीं सकते, और कोई भी डेटा शेयर करना उनके लिए खतरनाक होगा। कहने लगे कि कई चरणों के चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती डेटा को गोपनीय बनाए रखने की होती है। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं, इन एजेंसियों के नाम पर कई फेक एक्जिट पोल भी साझा होने लगते हैं। उनकी तलाश कर उसे काउंटर करना भी बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एजेंसी वालों के लिए 4 जून तक का समय बेहद कठिन होने वाला है। हालांकि एक दूसरी एजेंसी के मैनेजर साहब कहते हैं कि ऐसी सूरत से बचने के लिए वह ग्राउंड से सारा डेटा जुटा तो लेते हैं, लेकिन उस पर फाइनल काम नहीं करते। ऐसे में उनके पास भी कोई नंबर ही नहीं होता। लिहाजा उन्हें झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

किधर जाएंगे पप्पू यादव

बिहार में चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल होने का एलान किया। लेकिन इसके बाद वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने उतर पड़े, जहां RJD के उम्मीदवार पहले से मैदान में थे। इस वजह से कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बना ली। दरअसल, इस मुद्दे पर RJD-कांग्रेस में तकरार होने लगी थी। लेकिन अब, जबकि वहां वोटिंग निपट गई, तो पप्पू यादव के फ्यूचर को लेकर फिर से बात होने लगी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की मानें तो वह चुनाव के बाद भी पार्टी में बने रहेंगे। हालांकि जब चुनाव के बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस नेताओं से आगे की रणनीति के बारे में संपर्क किया तो उनसे अभी बिहार से दूर रहने और दिल्ली आकर कन्हैया कुमार के पक्ष में हवा बनाने को कहा गया। अब अगले कुछ दिनों में पप्पू यादव दिल्ली में कन्हैया कुमार की सीट पर पूर्वांचल के लोगों के बीच कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिख सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में चुनाव के बाद पप्पू यादव के मसले पर RJD और कांग्रेस में किस तरह का समीकरण बनता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि पप्पू यादव पर RJD अभी भी समझौते के मूड में नहीं है।

दिया नहीं, लिया गया इस्तीफा

सैम पित्रोदा ने इस बार इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे लिया गया। दरअसल, उनके बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई न कोई रगड़ा हो रहा था। पार्टी के एक नेता ने कहा कि वेल्थ टैक्स को लेकर जब उनके बयान पर विवाद हुआ तब खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनसे बात की थी और उन्हें इंटरव्यू देने से बचने को कहा था। राहुल गांधी को भी इस बारे में बताया गया। इसके बाद भी उन्होंने जब इंटरव्यू दिए और फिर से विवाद हुआ, तब पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ी। नेताओं ने कहा कि अब इस मामले पर स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा। पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके रुख को लेकर कई महीने से उनसे क्षुब्ध था।

मोदी कर रहे हैं होमवर्क

भले आम चुनाव के नतीजों को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हों, मगर हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुआई में BJP बड़ी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। खुद नरेंद्र मोदी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद की गतिविधियों को लेकर भी अभी से होमवर्क कर रहे हैं। दरअसल, चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जो भी पीएम बनेगा, उसके लगातार विदेश दौरे होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अपनी जीत तय मानकर उसी हिसाब से होमवर्क कर रहे हैं। सरकार के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि पीएम मोदी तीसरे टर्म का काम बिना इंटरवल के तुरंत शुरू कर सकते हैं। परिणाम उनके पक्ष में आने के बाद तुरंत शपथ लेकर मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। साथ ही, यह भी संकेत दिया जा रहा है कि जिन लोगों को पहले दोनों टर्म में मंत्री बनने का मौका मिला, उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दें तो बाकी को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बदले नए लोगों को सरकार में जगह दी जाएगी।

अमेठी-रायबरेली पर दुविधा

कांग्रेस के अंदर अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जो दुविधा दिखी, उसे लेकर पार्टी के कई नेता अनजान थे। पार्टी को लगता है कि इस मामले पर इतनी उलझन नहीं पैदा करनी चाहिए थी। हालांकि मामला कहां फंसा, इसे लेकर बाद में अंदरखाने से कई खबरें आईं। दरअसल, पार्टी ने राहुल गांधी का नाम अमेठी और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली से दिया। खुद प्रियंका भी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक थीं। लेकिन मीटिंग में राहुल गांधी ने पूछा कि अगर दोनों अपनी-अपनी सीट जीत गए, तो क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा कि केरल की वायनाड सीट छोड़ने का गलत संदेश जाएगा। वह भी तब, जबकि एक साल बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस की अच्छी संभावना है। साथ ही, जीतकर अमेठी या रायबरेली सीट छोड़ी तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। पार्टी के दूसरे नेताओं को राहुल का यह तर्क मजबूत लगा। फिर मंथन हुआ और अंततः रायबरेली सीट पर अंतिम फैसला हुआ।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ संकट का समय

9 मई का संपादकीय 'BJP को झटका' पढ़ा। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने और JJP के कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा करने से BJP सरकार पर संकट आ गया है। हालांकि, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तत्काल संभावना नहीं होने से सरकार गिरने की स्थिति फिलहाल नहीं है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस घटनाक्रम ने BJP के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। BJP नेतृत्व को इस संकट से उबरने के लिए जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा और गहन मंत्रणा करनी होगी, ताकि आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकले।

पैंथर तोमर, किशन गंज

■ चीन पर रहे नजर

यह पत्र 9 मई के लेख 'चीनी फौज बदल रही है भारत भी ना रहे पीछे' से संबंधित है। चीन की सरकार का पूरा ध्यान अपनी सैन्य क्षमता को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाने पर है। वह अपनी सैन्य शक्ति में परिवर्तन करने के साथ-साथ AI के माध्यम से अंतरिक्ष तक अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। बेशक भारत भी अपनी तैयारियां कर रहा है। वह अपने ही देश में हथियारों को विकसित कर रहा है। यहां तक कि हथियारों का निर्यात भी कर रहा है। फिर भी उसे ध्यान रखना होगा कि चीनी तैयारियों के मुकाबले वह पीछे न रह जाए।

सुभाष बुडावन वाला, ईमेल से

■ पिछड़ों की अनदेखी

चुनावी माहौल में सभी पार्टियां दलित और पिछड़े तबकों के प्रति जागरूक हो गई हैं। हर पार्टी अपने-अपने तरीके से गरीब और पिछड़े वर्ग को राहत और न्याय दिलाने की बात कर रही है। लेकिन कोई भी पार्टी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात नहीं कर रही। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस तबके के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर बात होनी चाहिए। इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

गिरीश शर्मा, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

एस्ट्राजेनेका ने सरप्लस बता कर मार्केट से वापस ली वैक्सीन - एक खबर

- बहाना जो भी हो, काम सही किया।

प्रेरणा अग्रवाल

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

Genetic और Social memory से परे

सुरक्षित गोस्वामी

Cardiologist ने patient से उसके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, परदादा-परदादी के खानदान के विषय में पूछा कि कौन किस बीमारी से मरा था? Patient ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? Doctor बोला- हम Family genes पर study कर आपके genes में छिपी बीमारी का पता लगा रहे हैं। असलियत में genes हमें biological family से मिलते हैं। बाहर की संपत्ति की तरह वह भी हमारी पैतृक संपत्ति होती है।

इस विरासत में हमें बीमारियां भी मिली होती है, जो जन्म के समय भी हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, लेकिन ऊर्जा के कहीं गहरे तल पर छिपी होती है। यह genetic memory पीढ़ियों से genome के जरिए आने वाली पीढ़ियों में चली आती है। पिछली पीढ़ियों के प्रभाव DNA में encode हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को कुछ यूं प्रभावित करते रहते हैं कि व्यक्ति का शरीर कैसा दिखेगा, कैसे विकसित होगा और कैसे कार्य करेगा। लंबाई, वजन, बालों, आंखों व त्वचा का रंग, नाक के आकार के साथ-साथ व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की बुद्धि, शरीर व मन के रोग आदि कुछ कम या ज्यादा रूप से प्रभावित हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति जल्दी-जल्दी खाना खाता है, जबकि उसे जल्दी खाकर कोई और काम भी नहीं करना है। ऐसा genetic memory के कारण होता है, क्योंकि हजारों साल पहले जब खाना बहुत कम था तो खाने की छीना-झपटी होती थी। इससे पहले कोई जानवर या ताकतवर व्यक्ति भोजन छीन ले, भोजन को जल्द खाकर खत्म कर लिया जाता था। ऐसे ही अचानक तेज आवाज आने पर व्यक्ति डर जाता है, शेर और सांप के नाम से ही डर जाता है। ये सब genetic memory का हिस्सा है।

Genetic Memory की तरह एक दूसरी memory भी जन्म के साथ आती है। इसे Social Memory कहते हैं। यह उन यादों का ढेर होती है, जो सामाजिक अनुभवों के आधार पर बनती हैं। इसमें वे ऐतिहासिक घटनाएं, तथ्य और कहानियां शामिल होती हैं, जिन्हें सामाजिक रूप से व्यक्ति ने पूर्वजन्मों में महत्वपूर्ण माना था। social memory के कारण समाज में अनेक धारणाएं बना ली जाती हैं- जैसे लंबे और गोरे व्यक्ति अच्छे होते हैं और काले अच्छे नहीं होते!

जब तक ये memories व्यक्ति के साथ रहती हैं, वह आनंद भरा जीवन नहीं जी पाता। इन memories में विचरते रहने से ये और प्रबल होती जाती हैं। अध्यात्म में इन memories को संचित संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारी व्यक्तिगत चेतना को वैसे ही ढक देते हैं, जैसे काला बादल सूरज को। इन memories को एक-एक करके नष्ट करना नामुमकिन होता है। इसके लिए ज्ञानयोग एक अनूठा उपाय है, जिसमें टिकने पर साधक की एक साथ सभी past memories वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे प्रकाश के आने से घने से घना अंधेरा गायब हो जाता है। अध्यात्म की अन्य साधनाएं भी इन्हीं पुरानी यादों का नाश कर present में fresh तरीके से सोचना और व्यवहार करना सिखाती हैं, जिससे हम मुक्त अवस्था में जीवन का अनुभव कर सकें।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
पटना • शुक्रवार • 10 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है।
-अज्ञात

युद्ध नहीं शांति

इस्राइल ने दक्षिणी गाजा के शहर राफा में सैनिक अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने सोमवार रात को राफा में हवाई हमले किए जिनमें 23 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस सैन्य कार्रवाई के बाद इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच संभावित युद्ध-विराम के रास्ते बंद हो गए हैं। हैरानी की बात है कि इस्राइल के पैरोकार अमेरिका की अनिच्छा और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के विरोध के बावजूद इस्राइल गाजा को पूरी तरह तबाह करने पर आमादा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर. इस्राइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शांति की राह छोड़कर युद्ध के पथ पर चलने की ताकत और प्रेरणा कहां से मिल रही है। करीब आठ महीने से चल रहे इस युद्ध के बारे में कहा जा सकता है कि इस्राइल अब आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति में

बढ़त बनाने के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन इस्राइल ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया कि इससे उसकी मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं। गाजा पट्टी के शहर राफा में करीब 14 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं जो इस्राइल के ताजा सैन्य अभियान से डरे और सहमे हुए हैं। इनका जीवन संकटग्रस्त है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी है कि राफा में जमीनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी लेकिन इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने अपने कान बंद कर रखे हैं। इस्राइल के सैनिक अभियान से जाहिर होता है कि वह इसके जरिए अपने बंधकों को रिहा कराना और हमास के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है। हालांकि सैन्य कार्रवाई के जरिए बंधकों की रिहाई आसान नहीं है। हकीकत यह है कि इससे बंधकों की जान को खतरा पहुंच सकता है। वास्तव में युद्ध-विराम और शांति समझौते के रास्तों पर आगे बढ़कर ही बंधकों की सुरक्षित रिहाई संभव है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हर समस्या का हल सैनिक अभियान नहीं हो सकता। आक्रामक सैनिक अभियान से गाजा के मासूम नागरिक ही मारे जाएंगे। अब तक करीब 35 हजार नागरिक मारे गए हैं। इस्राइल को अपने गॉड फादर अमेरिका से सबक लेना चाहिए कि उसे आखिरकार, अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी क्यों करनी पड़ी। वियतनाम के साथ लड़ाई में उसे क्या हासिल हुआ। बंदूक की गोली से नहीं शांति वार्ता की मेज से ही समस्या का हल निकलेगा। यह सार्वभौमिक सत्य है, जिसे समझा जाना चाहिए।

तय जिम्मेदारी को निभाएं

भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रख्यात व सार्वजनिक हस्तियों को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि विज्ञापन जारी करने की अनुमति से पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अनुसार, विज्ञापनदाताओं से स्वघोषणापत्र हासिल किया जाए। इस कानून का नियम 7 विज्ञापन संहिता का प्रावधान करता है जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। अदालत पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है। ये विज्ञापन निषिद्ध किए जा चुके हैं। पीठ ने संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों को भी इन भ्रामक विज्ञापनों व केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा। प्रचार व विज्ञापन उपभोक्ता को प्रभावित करने में महती भूमिका निभाते हैं। उस पर जब यह किसी प्रख्यात या सार्वजनिक शख्सियत द्वारा किया जा रहा हो तो आम

जनता को खास तौर पर प्रभावित करता है। इस मामले में तो कोविड टीकाकरण व आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को सीधा निशाना बनाया गया था जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है। इसमें संदेह नहीं कि लाभ के लोभ में कंपनियां भ्रामक प्रचार द्वारा सालों-साल जनता को बरगलाती रहती हैं। संबंधित मंत्रालय व विभाग इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुंह फेर लेते हैं। निराधार दावों, अतिरंजित बातों, छद्म दावों व अनुचित सूचना वाले तथा असुरक्षित उत्पादों से उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहे तमाम विज्ञापन अभी भी बेधड़क प्रकाशित/प्रचारित हो रहे हैं जो बच्चों के कोमल मन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित व बुजुर्गों को भ्रमित कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए नामदार शख्सियत धन के लोभ में इनका बेतहाशा प्रचार करती हैं जिनके आधार पर कहना ज्यादती नहीं होगा कि वे उपभोक्ताओं के अधिकारों को तरजीह देने को राजी नहीं। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि समूची व्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही बरतती है। बात अकेले पतंजलि की नहीं है। इसे उदाहरण मान कर संबंधित मंत्रालयों व विभागों को सतर्क हो जाना चाहिए। न कि एक-एक विज्ञापन को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाने वालों के इंतजार में बैठे रहना चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

अब लो पेन ड्राइव

चुनाव आता है तो सिर्फ चुनाव आचार संहिता ही नहीं आती, घोषणापत्र ही नहीं आते। वो वाली सीडी भी आती है। इस बार भी आई। जैसे यूपी वाले एक भाजपा सांसद की आई। उनकी तो उम्मीदवारी भी घोषित हो गई थी। लेकिन इधर सीडी आई और उधर उम्मीदवारी गई। जब सीडी और सांसदी, सीडी और पद साथ-साथ रह सकते हैं तो सीडी और उम्मीदवारी भी साथ-साथ रह लेती। जहां भाजपा वालों की उम्मीदवारी सिर्फ ऐसे ही जाती है वहीं कांग्रेस वालों की उम्मीदवारी कई तरह से जाती है। एक तो पर्चा खारिज होने से जाती है, जैसे कि सूरत वाले उम्मीदवार की गई। फिर कांग्रेस में उम्मीदवारी त्यागी भी जाती है। जैसे इंदौर वाले कांग्रेसी उम्मीदवार ने त्यागी। इधर उन्होंने उम्मीदवारी त्यागी, उधर भाजपा ने उन्हें खुशी-खुशी गले लगाया। कांग्रेस की पुरी वाली उम्मीदवार ने भी उम्मीदवारी त्यागी। उन्होंने कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। चुनाव लड़ने के पैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास भी नहीं थे, ऐसा उन्होंने खुद कहा। लेकिन वे तो उम्मीदवारी के मोह में पड़ी ही नहीं। ऐसे ही फिर हरियाणा वाले एक भाजपा सांसद की उम्मीदवारी गई बताते हैं। हालांकि उनके पास तो आई ही नहीं थी तो गई कहां? लेकिन खैर, अब ऐसा लगता है कि सीडी का जमाना भी लद गया। अब पेन ड्राइव का जमाना आ गया है। बेशक, जमाना बदलता है, पर इतनी जल्दी बदलता है, यह नहीं पता था। अभी पंद्रह दिन भी नहीं हुए थे जब सीडियां इतनी ताकतवर थीं, कि चाहे इस पार्टी वाले हों या उस पार्टी वाले-सब उनसे डरे रहते थे कि पता नहीं किसकी सीडी आ जाए। वे इतनी ताकतवर थीं कि या तो सीडी वालों को उम्मीदवार बनने ही नहीं देती थीं या फिर उनकी उम्मीदवारी बदलवा देती थीं। इतनी प्रासंगिक थीं कि मीडिया में चर्चा का विषय थीं। लेकिन अचानक वे पुरानी हो गई, आउटडेटिड हो गईं, अप्रासंगिक हो गईं। अब सीडियों का कोई जिक्र ही नहीं करता। अब तो पेन ड्राइव हैं। सीडियां तो कोई एक-आध ही आती थीं, लेकिन पेन-ड्राइव थोक में आ रहे हैं। पार्कों में मिल रहे हैं। बसों में मिल रहे हैं। चौक-चौराहों पर मिल रहे हैं। थैले भर-भरकर, टोकरियां भर-भर कर मिल रहे हैं। किसी दिन अगर आपको पेन ड्राइव ले लो की हांक सुनाई दे तो चौंकना मत।

क्यों हो रहे दिवालिया

अमेरिकी बैंक
प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका में 2023 में तीन बैंक (सिलिकन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक) डूब गए थे और 2024 में भी एक बैंक (रिपब्लिक फर्स्ट बैंक) डूब गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी केंद्रीय बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व, द्वारा ब्याज दरों में की गई वृद्धि के चलते बैंकों के असफल होने की परेशानी बहुत बढ़ गई है।

सिलिकन वैली बैंक ने कई तकनीकी स्टार्टअप एवं उद्यमी पूंजी फर्म को ऋण प्रदान किया था। इस बैंक के पास 2022 के अंत में 20,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्तियां थीं और यह अमेरिका के बड़े आकार के बैंकों में गिना जाता था और हाल के समय में डूबने वाले बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक माना जा रहा है। सिग्नेचर बैंक ने न्यूयॉर्क कानूनी फर्म एवं अचल संपत्ति कंपनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रखी थीं। इस बैंक के पास 2022 के अंत में 11,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति थीं और यह अमेरिका में हाल के समय में डूबने वाले बड़े बैंकों में चौथे स्थान पर आता है। 31 जनवरी, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्तियां 600 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं जमाराशि 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर थीं। न्यू जर्सी, पेनिसल्वेनिया और न्यूयॉर्क में बैंक की 32 शाखाएं थीं जिन्हें अब फुल्टन बैंक की शाखाओं के रूप में जाना जाएगा क्योंकि फुल्टन बैंक ने इस बैंक की संपत्तियां व जमाराशि खरीद ली हैं।

पीयू रिसर्च संस्थान के अनुसार, 1980-95 के बीच अमेरिका में 2,900 बैंक असफल हुए थे। इन बैंकों के पास संयुक्त रूप से 2.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थीं। 2007-14 के बीच अमेरिका में 500 बैंक, जिनकी कुल संपत्ति 95,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर थीं, असफल हो गए थे। कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अमेरिका में सामान्यतः बैंक असफल नहीं होते हैं। परंतु, इस संबंध में अमेरिकी रिकार्ड कुछ और ही कहानी कह रहा है। 1941-79 के बीच अमेरिका में औसतन 5.3 बैंक प्रति वर्ष असफल हुए। 1996-2006 के बीच औसतन 4.3 बैंक प्रति वर्ष असफल हुए एवं 2015-22 के बीच औसतन 3.6 बैंक प्रति वर्ष असफल हुए। 2022 में अमेरिकी बैंकों को 62,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। 1921-29 के बीच अमेरिका में औसतन 635 बैंक प्रति वर्ष असफल हुए। ये अधिकतर छोटे आकार के बैंक एवं ग्रामीण बैंक थे और एक ही शाखा वाले बैंक थे। अमेरिका में आई भारी मंदी के दौरान 1930-33 के बीच 9,000 से अधिक बैंक असफल हुए थे। इनमें कई बड़े आकार के शहरों में कार्यरत बैंक भी शामिल थे और उस समय इन बैंकों में जमाकर्ताओं की भारी-भरकम राशि डूब गई थी। 1934-40 के बीच अमेरिका में औसतन 50.7 बैंक प्रति वर्ष बंद किए गए थे।

अमेरिका में इतनी भारी मात्रा में बैंकों के असफल होने के कारणों में मुख्य रूप से शामिल है कि वहां छोटे-छोटे बैंकों की संख्या बहुत अधिक होना है।

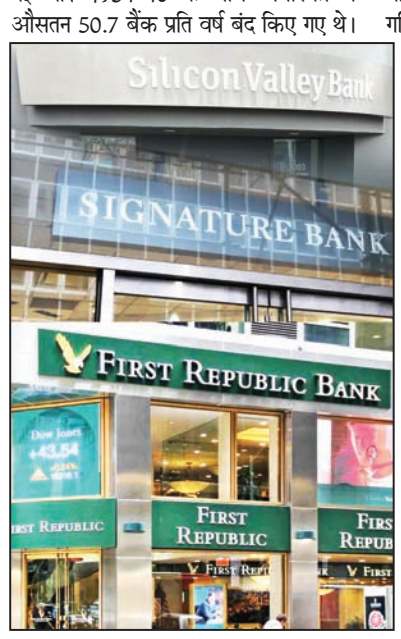

बैंकों के ग्राहक पढ़े-लिखे और समझदार हैं। बैंक में आई छोटी से छोटी परेशानी में भी वे बैंक से तुरंत अपनी जमाराशि को निकालने पहुंच जाते हैं, जबकि बैंक द्वारा इस राशि से खड़ी की गईं संपत्ति को रोकड़ में परिवर्तित करने में कुछ समय लगता है। इस बीच, बैंक यदि जमाकर्ता को जमाराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार बैंक असफल हो जाता है। कई बार बैंकों द्वारा किए गए निवेश (संपत्ति) की बाजार में कीमत भी कम हो जाती है, इससे भी बैंक जमाकर्ताओं को जमाराशि का भुगतान करने में असफल हो जाते हैं।

हाल में अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की गई जिससे इन बैंकों द्वारा अमेरिकी बॉन्ड में किए गए निवेश की बाजार में कीमत अत्यधिक कम हो गई है। अब इन बैंकों को बॉन्ड में निवेश की बाजार कीमत कम होने के स्तर तक प्रावधान करने को कहा गया है और यह राशि इन बैंकों के पास उपलब्ध ही नहीं है, जिसके चलते भी ये बैंक असफल हो रहे हैं।

एक सर्वे में बताया गया है कि आने वाले समय में अमेरिका में 190 अन्य बैंकों के असफल होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने से ऋण की मांग बहुत कम हो गई है। विभिन्न कंपनियों ने अपने विस्तार की योजनाओं को रोक दिया है, इससे निर्माण की गतिविधियों में कमी आई है। फेडरल रिजर्व का पूरा ध्यान मुद्रास्फीति कम करने पर है एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास दर को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादों की मांग कम हो और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लिया जा सके। इसके चलते कई कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं एवं युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है।

पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियां अमेरिका में बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही हैं। अब तो अमेरिकी अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में साम्यवाद के बाद पूंजीवाद भी असफल होता दिखाई दे रहा है एवं आज विश्व को नये आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट इशारा भारत की ओर है क्योंकि इस बीच भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित मॉडल भारत में आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल रहा है। अमेरिका में बैंकों के असफल होने की समस्या मुख्यतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में की गई वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है।

दरअसल, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्पादों की मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने के स्थान पर बाजार में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इन उत्पादों की कीमत कम रखी जा सके। प्राचीन भारत में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण मुद्रास्फीति की समस्या भारत में कभी रही ही नहीं है, बल्कि भारत में उत्पादों की प्रचुरता के चलते समय-समय पर उत्पादों की कीमतें कम होती रही हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मुद्रास्फीति का जिक्र ही नहीं मिलता। दूसरे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मॉडल एवं नियमों को बहुत जटिल बना दिया गया है। इससे भी कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसका हल विकसित देश नहीं निकाल पा रहे हैं।

> कहा जाता है कि अमेरिका में बैंकों के ग्राहक पढ़े-लिखे और समझदार हैं। बैंक में आई छोटी से छोटी परेशानी में भी वे तुरंत अपनी जमाराशि निकालने के लिए बैंक में जा पहुंचते हैं जबकि बैंक द्वारा इस राशि से खड़ी की गई संपत्ति को रोकड़ में परिवर्तित करने में कुछ समय लगता है। इस बीच बैंक यदि जमाकर्ता को जमाराशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यानी बैंक असफल मान लिया जाता है

आरबीआई का स्वर्ण भंडार बढ़ा

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के स्वर्ण भंडार में इस वर्ष मार्च में पांच टन की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का स्वर्ण भंडार बढ़ा है
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, अप्रैल की शुरुआत में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 822.1 टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। 2024 की शुरुआत से अब तक इसमें 18.5 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन अब हटा दिया है। भाजपा को अपने भाषणों में निशाना बना रहे आकाश को हटाकर क्या मायावती ने भाजपा के प्रति नरम रवैये की पुष्टि नहीं की है। पहले तीन चरण का मतदान बसपा के लिए ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। दलित वोट उनसे छिटक रहा है।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

कब सुधरेंगे हालात

तिहाड़ जेल **भगवती प्र. डोभाल**

आए दिन तिहाड़ जेल, जो देश ही नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी जेल है, बंदी सुधार-गृह की बजाय अपराधों का केंद्र बन गई है। होना तो यह चाहिए था कि अपराधी कैदियों, जिन्हें सजा देकर कारावास में भेजा जाता है, में सुधार नजर आते पर वह नहीं हो रहा है। हाल में विचाराधीन कैदियों के बीच तू-तू, मैं-मैं में एक कैदी को जान गंवानी पड़ी। एक अफगान नागरिक कैदी ने पैने हथियार से घोंपकर उसकी जान ले ली। दीपक सोनी शकूरपुर का रहने वाला था जिसे जेल नंबर 3 में रखा गया था, जहां वह सेवक के रूप में था। वहीं 44 वर्षीय अब्दुल बशीर अखोंडजादा अफगान नागरिक है। इस कैदी को लाजपतनगर में 2019 में हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। सोनी डकैती डालने के इल्जाम में कैद था। इस घटना ने तिहाड़ जेल के हालात सामने ला दिए हैं।

तिहाड़ सेंट्रल जेल दिल्ली के तीन जेल परिसरों में से एक है। अन्य दो जेल परिसर रोहणी और मंडोली में हैं। तिहाड़ जेल में नौ केंद्रीय जेल हैं। इस जेल परिसर की स्थापना 1957 में हुई थी। चार सौ एकड़ में फैले इस जेल कैम्पस की स्थापना सेंट्रल जेल के रूप में हुई थी। इसमें 5200 कैदी रह सकते हैं। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जेल के कर्ताधर्ता हैं, भी अब तिहाड़ जेल के कैदी बने हुए हैं। 1984 की शुरुआत में तिहाड़ जेल में अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण किया गया। आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जब जेल महानिरीक्षक थीं, ने तिहाड़ जेल में सुधार किए थे। उन्होंने इसका नाम बदल कर तिहाड़ आश्रम रखा था। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार तिहाड़ जेल की कुल क्षमता 10 हजार 26 कैदियों की है, जबकि फिलहाल इसमें 18 हजार से ज्यादा कैदी बंद हैं। क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण यहां खूंखार अपराधियों का साम्राज्य बन गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल नंबर दो में बंद हैं। यह भी दिलचस्प है, केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार होते हुए भी कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था; लेकिन अब तिहाड़ में एक साथ दो विभाग संभाल रहे हैं-मुख्यमंत्री और कैदी का। तिहाड़ के

लिए भी यह एक नया समीकरण है, क्योंकि कैदी होने के अलावा संवैधानिक तौर पर केजरीवाल दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं और बिना त्यागपत्र दिए अंदर गए हैं। अब तिहाड़ जेल में नेताओं का आना-जाना लगा रहता है; इस कारण ऐसे मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी हैं। खास यानी ऐसी जगह, जो चोर-उचक्कों, छंटे हुए बदमाशों या खूंखार गैंगस्टर या आतंकवादियों के सेल या ठिकानों से अलग है, इन खास जगहों में तिहाड़ का जेल नंबर एक, दो और चार विशेष हैं। दिल्ली सरकार के एक अन्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल नंबर सात में बंद हैं। आप के सांसद संजय सिंह को जेल नंबर पांच में रखा गया था, जिनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। केजरीवाल सुबह सवेरे उठने वालों में से हैं, इसलिए उन्हें जेल मैन्युअल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जेल में कैदियों की डेली रूटीन सुबह सूरज निकलने के साथ शुरू हो जाती है। सुबह छह बजे हर कैदी को उठना होता है। रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद सुबह साढ़े छह से सात बजे के बीच उन्हें नाश्ता दिया जाता है, जिसमें आम तौर पर ब्रेड और चाय होती है। दोपहर का खाना 11 बजे दिया जाता है। दाल, सब्जी, पांच रोटी या चावल, दोपहर तीन बजे शाम की चाय मिलती है। इसके बाद तीन से पांच बजे तक जेल में कैदियों को खेलने और टहलने का मौका मिलता है। शाम सात बजे रात का खाना। खाने में दाल, सब्जी, पांच रोटी या चावल दिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरी सलाह पर कैदियों को उनकी सेहत के अनुसार अलग से खाना मिलता है, इनमें घर का खाना भी होता है।

हाल के दौर में तिहाड़ की जो असली तस्वीर हम देख रहे हैं, वो काफी बदली-बदली सी है। अब तिहाड़ का सच कुछ और ही है। अब तमाम कायदे-कानूनों पर अकूत धन का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। वीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने जेल की दीवारें छोटी पड़ रही हैं। 1957 आजादी के ठीक दस साल बाद दिल्ली के पश्चिमी छोर पर तिहाड़ गांव में जेल की इमारत बन कर तैयार हुई। इसके बनने के बाद नौ साल तक जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब के पास रही। आगे चलकर इसकी कमान दिल्ली के हवाले कर दी गई। 1984 तक जेल का काफी विस्तार हो चुका था। जेल चाणक्यपुरी से सात किलोमीटर दूर दिल्ली के तिहाड़ गांव के करीब बनाई गई थी, इसी कारण शुरू से ही इसका नाम तिहाड़ से जुड़ा रहा। इस जेल का नाम तब पूरी दुनिया में चर्चा में आया, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के तौर पर देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने अपने सकारात्मक प्रयासों से इसका नाम तिहाड़ जेल से बदल कर आश्रम कर दिया था। हालांकि आज सकारात्मक प्रयास जेल में नहीं दिख रहे।

प्रमुख का महत्त्व **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

कुरुक्षेत्र के मैदान में भयभीत दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को आगे बताता है, 'हे आचार्य! आप सभी लोग युद्ध के मोर्चे पर अपने-अपने स्थान पर रह कर दृढ़तापूर्वक भीष्म पितामह की हर ओर से रक्षा करें।' यहां दुर्योधन की युद्ध रणनीति में गंभीर मोड़ आ जाता है। यद्यपि वह 11 क्षऔहिणी सेना का स्वामी है, किंतु आक्रामक नीति को त्याग कर रक्षात्मक नीति अपनाता है। दुर्योधन जानता है कि भीष्म न केवल कौरव पक्ष के सेनापति हैं, अपितु दोनों पक्षों के बीच सबसे वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति भी हैं। क्या भीष्म अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे? नहीं! पितामह अपनी रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम थे। ये बात दुर्योधन भी जानता था। लेकिन भीष्म ने पहले ही कहा था, 'द्रुपदपुत्र शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। इस बार वह पुरुष रूप में है। मैं अभी भी उसे स्त्री मानता हूं। वीर पुरुष स्त्रियों पर शस्त्रों से आक्रमण नहीं करते। इसलिए अगर वह आगे आएगा तो मैं उस पर हमला नहीं करूंगा।' दुर्योधन को भय था कि भीष्म स्वयं सेनापति हैं। इनके बिना विजयश्री असंभव है। लेकिन इस तरह शिखंडी के कारण भीष्म बिना युद्ध के आसानी से हार जाते हैं, तो बाजी बिगड़ जाती है। देखें तो दुर्योधन की चिंता निराधार नहीं है। उसे मुख्य व्यक्ति का महत्त्व समझ में आया है, चाहे स्वार्थ से ही क्यों न हो! किसी युद्ध की जीत-हार के लिए प्रमुख की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए थे। एक तरफ अकबर की 75,000 सेना और दूसरी तरफ मात्र 22,000 राजपूताना की सेना! शहजादे सलीम ने महाराणा प्रताप को पकड़ने की साजिश रची। लेकिन प्रताप के वफादार सरदारों में से एक मन्ना जी ने समय सूचकता से महाराणा का मुकुट और ओहदा खुद धारण करके उन्हें सकुशल अन्यत्र भेज दिया। मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया किंतु प्रताप बच गए और कुछ ही समय में उन्होंने मुगलों से अपना क्षेत्र वापस छीन लिया। इस तरह युद्ध में विजय के लिए मुख्य योद्धा की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण होती है। महंत स्वामी महाराज भी समझाते हैं कि प्रमुख संस्था की परछाई की तरह होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा संस्था की प्रतिष्ठा है। जब भी हम समूह में किसी परियोजना पर काम करते हैं, तो प्रमुख के महत्त्व को मानना मजबूरी नहीं किंतु अनुशासन है।

रीडर्स मेल

मायावती का फैसला समयानुकूल

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषित उत्तराधिकारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। आखिर, ऐसा क्या बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था कि आकाश आनंद, जो लगातार चुनावी रैलियां से बसपा का प्रचार कर रहे थे, को दायित्व मुक्त करना पड़ा। दरअसल, बेहद आक्रामक शैली से आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियों के माध्यम से भाषण दे रहे थे। उनमें कुछ शब्दावली और वक्तव्य संदेह के घेरे में थे और जिन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। सीतापुर की रैली में उनके भाषण ने लगता है कि मायावती को नाराज कर दिया था। बसपा अध्यक्ष मायावती अपना भाषण लिख कर देती हैं, और शब्दावली उचित और शुचितापूर्ण होती है एवं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करतीं। मेरा मानना है कि दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख कर और समाज के सभी वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती का फैसला समय अनुकूल एवं उचित है। यह आकाश आनंद के लिए भी ठीक है क्योंकि उनको लंबी राजनीति करनी है।

विरेंद्र कुमार, आरा

रिश्तों में संतुलन जरूरी

क्या प्रेम और आसक्ति के बीच संतुलन बनाना संभव है? बेशक! जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, और अंदर से खुशी और संतोष महसूस करते हैं, तो हम दूसरों से बेशक प्यार करने में सक्षम होते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। हम उनकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। हम अपने रिश्तों को फलने-फूलने देते हैं लेकिन किसी भी तरह के बंधन से नहीं बांधते। सच्चे प्रेम की यही मूल भावना है-स्वतंत्र चेतना की स्वीकृति और सराहना। जब हम खुद को और दूसरों को सच्चे रूप में प्यार करना सीखते हैं, तो अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। प्रेम दूसरों को आजाद करता है, और उनकी विलक्षणता को चमकने देता है। सच्चा प्यार कब्जा नहीं करता, जिंदगी बख्शता है।

चंदन कुमार नाथ, गुवाहाटी, असम

जीव-जंतुओं को गर्मी से राहत दिलाएं

भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। मानव जीवन तो भीषण गर्मी की मार झेलता ही है परंतु जीव-जंतुओं, पशु-पक्षी भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं है। तेज धूप पक्षियों के लिए खतरनाक साबित होती है। हम सभी का कर्त्तव्य होना चाहिए कि पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए द्वार, गैलरी, छत इत्यादि जगह सकोरे बांध कर रखें, उनमें लगातार पानी भरते रहें। गाय, कुत्ते और अन्य जानवरों के लिए भी पानी पीने की सुविधाएं करें। मुक प्राणी बोल नहीं सकते पर इंसान और इंसानियत का परिचय देकर मानवता के नाते हमें उनकी पीड़ा से रूबरू होना होगा। पर्यावरण में पशु-पक्षी और जीव-जंतुओं का अहम योगदान होता है। गर्मी चरम पर है, और सभी को राहत की जरूरत होती है, क्यों न हम संकल्पित होकर कर्त्तव्य निष्ठा को मूर्त रूप दें। हालांकि नगरों में सेवाभावी संस्थाएं इन कार्यों को करती ही हैं परंतु समाज के हर नागरिक को भी ऐसे सेवाभाव से जुड़ना होगा। क्या हम पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए, उनकी प्यास बुझाने में ठोस कदम उठाएंगे?

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 18, अंक 6296
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

ईवीएम बूथ पर कब्जागिरी

चुनाव लोकतंत्र की आत्मा हैं। अगर चुनाव ही ईमानदारी से नहीं होंगे तो लोकतंत्र कभी सशक्त नहीं हो सकता। चुनावी धोखाधड़ी अलग-अलग स्तर पर होती रही है। जिसमें वोटों के लिए मतदाता को प्रलोभन देना, धन बल का खुलकर इस्तेमाल करना या मतदान के स्तर पर धांधलियां किया जाना आदि शामिल है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो राजनीतिक दल बाहुबलियों का सहारा लेकर मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लेते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी, मतपत्र फाड़ दिए जाते थे, हिंसा में अनेक लोग मारे जाते थे लेकिन चुनाव प्रक्रिया में निरंतर सुधारों के चलते काफी बदलाव आ चुका है। अब चुनावों में धांधली और हिंसा की खबरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। कभी-कभी अपवाद स्वरूप हैरान कर देने वाली घटनाएं भी सामने आती हैं लेकिन निर्वाचन आयोग अब ज्यादा सख्त रवैया अपनाता है और उसकी मशीनरी तुरंत एक्शन में आ जाती है। गुजरात पुलिस ने एक भाजपा नेता के बेटे विजय भाभोर और उसके साथी मनोज मगन को फर्जी वोट डालने और फेसबुक पर इसे ऑनलाइन लाइव करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने पर तुरन्त एक्शन लिया। विजय भाभोर और उसके साथी ने बेखौफ होकर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उस पर एक्शन होना भी बहुत जरूरी था।

गुजरात में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में वोट डाले थे लेकिन दाहोद में भाजपा नेता के बेटे विजय भाभोर और उसके साथी ने बूथ में घुसकर कब्जा कर लिया। उसने ईवीएम को हाथ में लेकर इंस्ट्राग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव भी किया। फर्जी वोट डालने के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार बदनाम थे लेकिन दाहोद में जो कुछ हुआ वह अभूतपूर्व है। यह घटना महिसागर के संत रामपुर तालुका के परथमपुर गांव में हुई। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में वीडियो सबूत के साथ की। वीडियो में ईवीएम पर फर्जी मतदान के लिए बटन दबाते हुए विजय भाभोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ईवीएम मेरे बाप की है। केवल एक ही चीज काम करती है वह है बीजेपी। यहां सिर्फ विजय भाभोर की ही चलती है। उसने बूथ पर तैनात कर्मचारियों से बदतमीजी भी की और अपशब्दों का प्रयोग भी किया।

दाहोद में भाजपा नेता के बेटे विजय भाभोर और उसके साथी ने बूथ में घुसकर कब्जा कर लिया। उसने ईवीएम को हाथ में लेकर इंस्ट्राग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव भी किया। फर्जी वोट डालने के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार बदनाम थे लेकिन दाहोद में जो कुछ हुआ वह अभूतपूर्व है। यह घटना महिसागर के संत रामपुर तालुका के परथमपुर गांव में हुई। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग में वीडियो सबूत के साथ की। वीडियो में ईवीएम पर फर्जी मतदान के लिए बटन दबाते हुए विजय भाभोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ईवीएम मेरे बाप की है।

संत रामपुर के बूथ से लाइव किए गए ईवीएम के वीडियो के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि ड्यूटी स्टॉफ ने उस वक्त या उसके बाद चुनाव आयोग से कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? यह भी सामने आया है कि पुलिस ने विजय भाभोर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी ने दाहोद लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद जसवंत सिंह भाभोर को रिपीट किया था तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रभा किशेर तवियाड को मैदान में उतारा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस की लोकसभा कैंडिडेट प्रभा तवियाड की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है।

चुनाव आयोग को कांग्रेस की शिकायत का संज्ञान लेकर दादागिरि करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक स्थायी और स्वायत्त निकाय है। चुनावों के दौरान आयोग की ही सत्ता होती है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करे जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और लोकतंत्र की जीवंतता बनी रहे। यद्यपि निर्वाचन आयोग पर सत्ता के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। कई बार चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर न केवल भाजपा, कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी एक्शन लिया है। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोप तो इन चुनावों में भी उछाले गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग अब पहले से कहीं अधिक पारदर्शिता से काम कर रहा है। चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में एक विशेष समुदाय को मतदान करने से रोकने की शिकायतों का भी संज्ञान ले और निष्पक्षता से काम लेते हुए उन बूथों पर पुनर्मतदान करवाए जहां थोड़ी सी भी धांधलेबाजी की आशंका हो। आज के दौर में सभ्य लोकतंत्र में दादागिरि करने वालों को सहन नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र धांधली की खबरें दबाने से नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई से ही मजबूत होगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

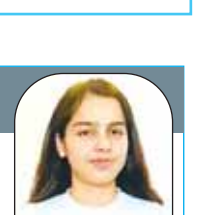

वो रात को भूख से तड़पते बच्चों...

गीता पाढा

वो कुर्सी पर बैठते ही भूल जाते हैं बेरोजगारी की मार को,
टूटी-फूटी छत से बहती बारिश की धार को,
वो रात को भूख से तड़पते बच्चों की करुण चित्कार को,
और तिल-तिल गरीबी की आग में झुलसते लाखों परिवार को..!!

महाराष्ट्र में मतदान और प्याज

नासिक, (भाषा): लोकसभा चुनाव में चौथे और पांचवें चरण के मतदान से पहले महाराष्ट्र में प्याज की पैदावार वाले क्षेत्रों में किसानों का संकट चर्चा के केंद्र में आ गया है। प्याज की खेती वाले इलाकों में राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के 24 संसदीय क्षेत्र हैं। राज्य के 13 संसदीय क्षेत्रों में प्याज उत्पादक 22 जिले हैं, जहां प्याज की खेती करने वाले किसान इस कृषि उपज पर केंद्र सरकार के कदमों से प्रभावित हुए हैं। इनमें से सोलापुर, लातूर, बारामती और उस्मानाबाद सीट पर तीसरे चरण में सात मई को मतदान हुआ।

प्याज की खेती करने वाले किसानों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी उनकी समस्याओं को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के संस्थापक-अध्यक्ष भरत दिघोले ने बृहस्पतिवार को 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''प्याज उत्पादकों के बीच जबरदस्त नाराजगी है और वे 13 एवं 20 मई को ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से अपना गुस्सा निकालेंगे।'' राज्य की 48 लोकसभा सीट पर पांच चरणों में चुनाव हो रहे हैं।

इससे पहले, केंद्र ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 14 प्रतिशत शुल्क लगाया था। किसानों के आंदोलन के बाद, केंद्र ने शुल्क हटा लिया और न्यूनतम निर्यात मूल्य 850 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तय किया। हालांकि, किसानों का दावा है कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रियंका गांधी का नुक्कड़ सभा संदेश

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक
kapurakesh@gmail.com

लोकसभा चुनाव का प्रचार युद्ध अब आर-पार की लड़ाई के चक्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार की डोर संभाले हुए हैं वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रचार की कमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रीमती प्रियंका गांधी जिस तर्ज का चुनाव प्रचार कर रही हैं वह दूसरे नेताओं से अलग माना जा रहा है। प्रियंका गांधी लोगों को समझा रही हैं कि वह नेताओं की आदत ना खराब करें। चुनाव के समय उनके द्वारा धर्म या जाति के जो उलझाव पैदा किए जाते हैं अथवा उनके नाम पर जो वोट मांगा जाता है उससे बचें और उनसे उनके पिछले 5 साल के काम का हिसाब-किताब मांगें, केवल इतना ही नहीं प्रियंका गांधी यह भी कहती हैं कि यह चुनाव आम लोगों को मजबूत बनाने के लिए होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में उन्हीं के एक वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं।

वह लोगों से जागरूक बनने की अपील करती हैं और कहती हैं कि लोकतंत्र में उनका हक सरकार या सत्ता में भागीदारी का होता है। वे जब धर्म या मजहब के नाम पर वोट डालते हैं तो अपने ही अधिकारों का हनन करते हैं। चुनाव में धार्मिक या जातिगत समूहों पर विचार करने की जगह अपने हकों के बारे में विचार किया जाना चाहिए। उनके प्रचार का यह तरीका सामान्य से अलग माना जा रहा है क्योंकि वह अपने भाषण में भारत के लोक कल्याणकारी राज होने का रहस्य भी खोलती हैं और बताती हैं कि सरकार की सभी नीतियां उन्हें ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए जिससे उनका विकास हो वे आधिकारिक मजबूत बने। उनके मजबूत बनने से ही देश मजबूत बनेगा। प्रियंका का यह अंदाज उन्हें अन्य चुनाव प्रचारकों से अलग रखता है और बताता है कि जनतंत्र में आम मतदाता का जागरूक होना कितना जरूरी होता है।

चुनाव प्रचार का यह चक्र इस हद तक आर-पार का माना जा रहा है कि इसमें अब यह फैसला होकर ही रहेगा कि भाजपा की नीति और सरकार के जो काम हैं उनकी समीक्षा किस प्रकार की जाए। प्रियंका गांधी लोगों से कहती हैं कि उन्हें जो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने मुफ्त राशन मिलता है वह कांग्रेस द्वारा बनाई गई नीतियों और कानून के तहत ही किसी भी सरकार द्वारा दिए जाने की मजबूरी है। वह बताती हैं कि कांग्रेस की डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में भोजन के अधिकार का कानून बनाया था जिसमें सरकार की जिम्मेदारी थी कि देश में कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी कानून के तहत देश के लोगों की गरीबी को देखते हुए 5 किलो मुफ्त भोजन की व्यवस्था हुई है, इससे गरीब व्यक्तियों के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। उनके स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी उठाना भी सरकार का काम है।

वह कहती हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है तो केंद्र सरकार के जो 30 लाख कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें वरीयता के आधार पर जल्दी से जल्दी भरा जाएगा तथा फौज में जवानों की भर्ती की जो अग्नि वीर योजना बनाई गई है उसको खत्म किया जाएगा तथा फौज में जवानों की स्थाई भर्ती होगी। प्रियंका गांधी को आम जनता से संवाद स्थापित करने का माहिर माना जाता है। वह जनता की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम मानी जाती हैं। इस बात का वह ध्यान रखती हैं कि जब भी वह कोई बात करें तो श्रोताओं की तरफ से उन्हें स्वीकृति का स्वर सुनाई पड़े।

फौज में भर्ती के संदर्भ में वह यह बात कहना नहीं भूलती कि पहले हिंदुस्तान की सड़कों पर ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्र में नौजवान अर्ध रात्रि के बाद सुबह सवेरे दौड़ लगाते हुए और वर्जिश करते हुए दिखाई पड़ते थे जब से आग्नि वीर योजना आई है तब से उनका उत्साह ठंडा हो गया है क्योंकि इस योजना के तहत केवल 4 साल के लिए फौज में भर्ती होती है उसके बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं। प्रियंका विवादों से बचने वाली नेता मानी जाती हैं। वह धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं और एक-एक शब्द को तोल कर बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं। जनसभा में उनके चेहरे पर जो हाव-भाव आते हैं उनसे सुनने वाले लोग प्रभावित होते हैं। वह अपने गांधी परिवार की विरासत का उल्लेख इसलिए नहीं करती कि उन्होंने इस देश पर 55 साल तक शासन किया है बल्कि इसलिए करती हैं कि गरीब गुरबों की जिंदगी सुधारने के लिए उनके दौर में जो भी काम किए गए वे कानूनी रूप से लोगों को अधिकार देने के लिए किए गए।

वह अपने भाषणों के दौरान जनता से संवाद स्थापित करने का प्रयास भी करती हैं। इसमें वह सफल भी रहती हैं, इसकी वजह यह है कि वह जो बात कहती हैं वह जन सामान्य के जीवन में गुजर रही होती है। एक राजनीतिक के खराखोटा होने की सबसे बड़ी पहचान लोकतंत्र में यही मानी जाती है कि उसकी जुबान से जो शब्द निकले वह लोगों के दिल में होना चाहिए।

चुनावी प्रचार के इस दौर में सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से भी ऐसी कोशिश की जा रही है कि जनता की अधिक से अधिक हामी इसके नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों में नजर आए। प्रियंका गांधी को कांग्रेस आलाकमान ने रायबरेली और अमेठी सीटों की निगरानी करने के लिए भेजा है। चुनाव होने तक प्रियंका गांधी इन दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक नुक्कड़ सभाएं संबोधित करेंगी। एक दिन में वह 10 से 15 नुक्कड़ सभाएं संबोधित कर सकती हैं। नुक्कड़ सभाएं करना बड़े राजनेता अपनी शान के खिलाफ मानते हैं मगर प्रियंका गांधी इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के दिल में उतरना चाहती हैं। इसी वजह से वह नुक्कड़ सभाओं का जोखिम उठाती हुई दिखाई पड़ रही हैं।

रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं जबकि अमेठी से कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा चुनाव मैदान में है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उम्मीदवार है। ऐसा माना जा रहा है की प्रियंका गांधी के चुनाव क्षेत्र में होने की वजह से मीडिया का आकर्षण इन दोनों क्षेत्रों की तरफ रहेगा परंतु जहां तक अमेठी का सवाल है तो प्रियंका गांधी की कोशिश यह है कि वह एक सामान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री के सामने खड़ा करके लोगों से यह पूछे कि वह कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों के प्रति अपना वोट डालना पसंद करेंगे या फिर पिछले चुनाव की तरह भावुकता में वोट डालेंगे। वैसे तो स्मृति ईरानी और किशोरी लाल शर्मा में कोई मुकाबला नहीं है मगर यहां व्यक्ति नहीं पार्टियां लड़ रही हैं। मैंने 1984 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया था। चौधरी साहब का चुनाव प्रचार करने का तरीका अनोखा था। वह केवल मोटर द्वारा ही चुनाव प्रचार के लिए उतरते थे। जिस भी गांव या शहर से उनकी मोटर गुजरती थी वहां लोग प्राय यह सुनकर इकट्ठे हो जाते थे कि चौधरी चरण सिंह का काफिला इस मार्ग से गुजरेगा। सड़कों पर इकट्ठा हुआ जमघट चौधरी साहब के मोटर काफिले को रोक लेता था। लोग उनसे भीड़ को संबोधित करने की प्रार्थना किया करते थे। चौधरी साहब अपनी मोटर से उतरकर भीड़ को संबोधित करने लगते थे। उनके चुनावी भाषण संवाद रूप में होते थे। वे लोगों से सीधी बात करते थे। वे समझाते थे कि भारत में गरीबी क्यों है।

वह कहते थे कि जब तक गांव का गरीब आदमी गरीब है तब तक भारत विकास कैसे कर सकता है। यही बात आज प्रियंका गांधी अपने संशोधित शब्दों में लोगों को समझने की कोशिश कर रही हैं। रायबरेली और अमेठी चुनाव क्षेत्र इस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक की नजर में है। जहां कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को लड़ाकर आश्चर्य पैदा किया वहीं दूसरी तरफ अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को खड़ा करके पूरे राजनीतिक जगत को चौंका दिया। इस आश्चर्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही लगता है प्रियंका गांधी अमेठी में डेरा डाले हुए है।

न्यायपालिका से ही अब आखिरी उम्मीद

लक्ष्मीकांता चावला
(पूर्व मंत्री पंजाब)

बहुत दिन बीत गए थे। दिन नहीं वर्षों। जब से मेरी कलम का यह संघर्ष चल रहा था कि लिव-इन रिलेशनशिप अर्थात सहजीवन अर्थात बिना विवाह के विवाहित-अविवाहिता पुरुष-स्त्री किसी भी दूसरे पुरुष-स्त्री के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। सीधा अभिप्राय यह कि पति-पत्नी की तरह रहेंगे इससे सामाजिक कद्रों कीमतों की कितनी हानि हुई कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। न सरकार, न देश के न्यायविद्, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सहजीवन को मान्यता भी मिल गई, इनके अधिकार भी तय किए गए और इन अवैध संबंधों से उत्पन्न होने वाले बच्चों को भी कानून की छतरी मिल गई। कितनी ऐसी युवतियां हैं पहले सहजीवन में रह लेती हैं उसके बाद पुरुष साथी पर बलात्कार का केस दर्ज करवा देती हैं।

कानून की कलम वाले भी यह नहीं सोचते कि ये संबंध सहमति से बनाए गए हैं, किसी ने अपहरण नहीं किया, कोई पिस्तौल के बल पर महिला को साथ नहीं ले गया फिर भी बलात्कार के केस दर्ज होते हैं। आत्महत्याएं भी इन्हीं संबंधों के कारण बहुत अधिक हुईं, परिवार भी टूटे, पर अब नए सिरे से आशा की किरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय से देश, समाज को मिली है। उच्च न्यायालय ने यह घोषणा कर दी है कि लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। यह शत-प्रतिशत सत्य है, पर न जाने इतनी देर क्यों कर दी। यह निर्णय वर्षों पहले क्यों नहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ले लिया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल की खंडपीठ ने पहले से विवाहित अब्दुल हमीद सिद्दीकी आयु 43 वर्ष और 36 वर्षीया एक हिंदू महिला के लिव- इन रिलेशनशिप से जन्मे एक बच्चे के संरक्षण का अधिकार देने के संबंध में जो याचिका आई उसका निपटारा करते हुए यह निर्णय दिया। पहले से विवाहित पुरुष पार्टनर को बच्चा सौंपने से इंकार किया।

मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ न्यायालय ने देश को एक दिशा दी है और समाज को सहजीवन से दूर रहने का मार्ग भी दिखाया है, संदेश दिया है। आज की हालत तो यह हो गई कि सहजीवन में रहने वाले सरकारों से सुरक्षा मांगते हैं और अधिकतर उन्हें मिल भी जाती है। यह स्वस्थ समाज की संरचना में सबसे बड़ी बाधा बन गई थी।

इसी प्रकार अपने देश में ऐसे अनेक मामले हैं जहां झूठे केसों में फंसाकर वर्षों तक जेलों में नारकीय यातनाएं भोगने के लिए उन्हें भी विवश किया जाता है जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं।

किसी मानव अधिकार आयोग ने इन बेचारों की हालत पर ध्यान नहीं दिया जो बिना अपराध जेलों में सड़ते हैं, जिनके परिवार उजड़ गए। बहुत पहले पढ़ा था वाराणसी के एक गांव में रानी नामक महिला ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसके पति पर हत्या का अपराध लगा। वह जेल गया। बाद में रानी सही सलामत मिल गई। एक नहीं अनेक करुण गाथाएं हैं, पर अब पुन: उत्तर प्रदेश की बरेली की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक युवक अजय उर्फ राघव निर्दोष थे, पर दुष्कर्म के झूठे केस में उन्हें 1653 दिन जेल में रहना पड़ा। उसके पश्चात यह कह सकते हैं कि सत्य की जीत हुई। युवती का झूठ सामने आया। वह विरोधाभासी बयान देती रही जिससे सेशन कोर्ट को यह विश्वास हो गया कि राघव निर्दोष है और बिना कारण उसे जेल में सड़ना पड़ा लेकिन ऐसा निर्णय भारत के इतिहास में पहली बार आया कि अदालत ने झूठे आरोप लगाने वाली युवती जो पहले पीड़ित मानी जाती थी उसे उतने दिनों के लिए ही जेल में भेज दिया जितने दिन वह निर्दोष युवक मिथ्या आरोपों के कारण जेल में रहा था। इसके साथ ही पांच लाख 88 हजार रुपये जुर्माना भी उस महिला पर लगाया गया जो उसी युवक को मिलेगा।

वैसे देश में न्यायालयों को और विधि विशेषज्ञों को बहुत गंभीर चिंतन के बाद यह निर्णय ले लेना चाहिए कि जो किसी पर भी झूठे आरोप लगाकर उसे अपमानित करता है, जेल में भेजता है उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाए। जो लोग इनके समर्थन में अदालतों में गवाह बनकर जाते हैं उन्हें भी ऐसा दंड दिया जाए कि वे भविष्य में कोई भी झूठी गवाही देने जाने से पहले सौ बार सोचें।

एक अन्य निर्णय में समाज को दिशा देने वाला फैसला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इसी सप्ताह दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। ये सभी निर्णय आज समाज को दिशा भी दिखाते हैं, सहजीवन को नकारते हैं और माननीय न्यायाधीशों के हृदय में जो मानवता की भावना है उसको भी प्रकट करते हैं। अपाहिज बहन और मां के लिए पुत्र, भाई का कर्त्तव्य है इसे मान्यता देकर माननीय न्यायाधीशों ने अत्यंत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया। मेरा तो इतना निवेदन है समाज के नेताओं से, समाजसेवियों से कि वे दुखियों का सहारा बनें, बेसहारों को संरक्षण दें तो उन सबको न्याय मिले जो आर्थिक बोझ में दबे हैं और अदालतों की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। निष्कर्ष यही कि अब आखिरी सहारा न्यायालय ही है। नेताओं से आशा व्यर्थ है।

विदेशों में सुरक्षित नहीं भारतीय युवा

आकाश चोपड़ा

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां के युवाओं में विदेश जाकर अपना भविष्य संवारने की ललक है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण भारत, लाखों भारतीय विदेशों में हैं और उन्होंने वहां के संविधान और संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। उच्च पदों पर बैठकर वे वहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

भारत में हर साल हजारों की संख्या में बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं। इन प्रोफेशनल्स की मांग देश और विदेशों में भी काफी है। कई को विदेशी कंपनियां मोटी सैलरी पर बुलाती हैं। इनमें वे युवा होते हैं जिनकी उपयोगिता उन देशों में बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के बिना उनके यहां का काम नहीं चल सकता, जैसे- इंजीनियरिंग करके जाने वाले स्टूडेंट, डॉक्टर और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आदि। विदेशी कंपनियां उन्हें लुभाने वाले पैकेज देकर बुलाती हैं। वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो खुद को तैयार ही इस हिसाब से करते हैं कि वे विदेश में काम कर सकें और पैसा कमा सकें। भारतीय छात्र भी विदेशों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर वहीं पर जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग खुद को योग्य बनाकर कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ते हैं लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो बिना किसी तैयारी के, गलत तरीके से बेहतर ज़िंदगी की चाह में विदेश पहुंच जाते हैं और कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। हजारों युवा जो शिक्षित भी नहीं हैं वे भी वहां श्रम करके पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। इन दिनों लगातार अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई में भारतीय युवाओं की मौत की खबरें दिल दहला देने वाली हैं।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय छात्र नवजीत संधू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। विक्टोरिया पुलिस के मुताबिक, 22 साल का नवजीत हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। नवजीत के चाचा ने बताया कि उसकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए उसके पिता ने आधा एकड़ जमीन बेच दी थी। वो जुलाई में अपने परिवार से मिलने आने वाला था। इसके अलावा नवजीत ऑस्ट्रेलिया में डेढ़ साल के वर्क वीजा पर था। दुबई में भी पंजाब के जालंधर छावनी के एक गांव के युवक पंकज की हत्या कर दी गई थी।

इसी वर्ष फरवरी माह में शिकागो में एक भारतीय छात्र पर हमला हुआ था। घटना का एक वीडियो सामने आया था। इसमें 3 हमलावर छात्र का पीछा करते नजर आए थे। इसके बाद तीनों ने उसे बुरी तरह पीटा था, फोन छीन लिया था और भाग गए थे। छात्र खून से लथपथ नजर आया था। जनवरी माह में अकुल धवन का शव इलिनोइस अर्बाना-शैंपेन यूनिवर्सिटी के बाहर मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या कर दी गई थी। फॉक्स न्यूज के मुताबिक 25 साल के छात्र विवेक के सिर पर एक बेघर शख्स ने हथौड़े से 50 बार वार किया था। इसके अलावा भी कई छात्रों की मौत बीमारी से भी हो चुकी है। कई छात्र दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं।

विदेश में भारतीय छात्र महफूज नहीं हैं। पिछले छह साल में विदेश में 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि 2018 से अब तक कुल 403 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। लोकसभा में उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मौत के मामले कनाडा से हैं। कनाडा में पिछले 6 साल यानी 2018 से अब तक 91 छात्रों की मौत हुई है। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की मौत के सबसे अधिक 91 मामले कनाडा से रहे। मगर विदेश में भारतीय छात्रों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा के बाद दूसरे नंबर पर ब्रिटेन का नाम आता है। यहां पिछले 6 साल में 48 छात्र मौत के शिकार हुए हैं।

वहीं, इस मामले में रूस तीसरे नंबर पर है। यहां 2018 से अब तक 40 छात्रों की मौत हुई है। अमेरिका में 36, ऑस्ट्रेलिया में 35, यूक्रेन में 21 और जर्मनी में 20 भारतीय छात्रों की इन छह साल में मौत हुई है। इसके अलावा साइप्रस में 14 छात्रों की मौत हुई है जबकि फिलीपींस और इटली में 10-10, कतर-चीन और किर्गिस्तान में 9-9 भारतीय छात्र मौत के शिकार हुए हैं। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कर्ज उठाकर भी उन्हें विदेश भेजते हैं लेकिन जब विदेशों में घर के चिराग बुझ जाते हैं तो उन पर क्या बीतती है, यह कोई दूसरा नहीं जान सकता। बेहतर होगा कि प्रतिभावान छात्रों के लिए देश में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए तो प्रतिभाओं का पलायन नहीं होगा। मां-बाप को भी अपने बच्चों को देश में ही रहकर अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करना होगा।

जुआ हारने पर पत्नी, बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी की

भुवनेश्वर, (भाषा): ओडिशा के झारसुगुड़ा में गुरुवार सुबह एक कार से एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी के शव बरामद किये गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक परमार स्मित परषोत्तमदास ने बताया कि मृतकों की पहचान सुजीत रे, उनकी पत्नी खुशबू और बेटी अर्पिता के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि जिले के लखनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में बनीपाहदा के पास खड़ी कार से उनके शव बरामद किए गए, जिन पर गोलियां लगने के घाव हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ऑनलाइन जुआ में लाखों रुपये हारने के बाद परेशान होकर सुजीत ने पहले अपनी पत्नी तथा बेटी को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवासी भारतीयों की कमाई

प्रवासियों द्वारा अपनी कमाई देश वापस भेजने के मामले में भारत फिर पहले स्थान पर आ गया है. संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में विदेशों में कार्यरत भारतीयों ने 111 अरब डॉलर से अधिक रकम देश को भेजा था. विप्रेषित धन का सौ अरब का आंकड़ा छूने और पार करने वाला भारत पहला देश बन गया है. यह उपलब्धि प्रवासी भारतीयों की दक्षता और उनकी बढ़ती कमाई को इंगित करती है. इससे पहले 2010, 2015 और 2020 में भी भारत में सबसे अधिक कमाई आयी थी. भारत के अलावा मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस इस मामले में शीर्ष के देशों में हैं. देश आने वाली कमाई विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय योगदान करती है तथा प्रवासियों के परिवार के जीवन-स्तर को बेहतर करने में बड़ी भूमिका निभाती है. साल 2020 में देश में 83.15 अरब डॉलर की राशि आयी थी, जो 2022 में 111.22 अरब डॉलर हो गयी. इसका अर्थ है कि भारत से अधिक संख्या में लोग काम करने भी जा रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है. रिपोर्ट का आकलन है कि भारत के 1.80 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, जो हमारी कुल आबादी का 1.3 प्रतिशत है. दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भी भारतीय हैं, जिनमें से अधिकतर संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में कार्यरत हैं. प्रवासन के गंतव्य देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है. हमारे देश में 44.8 लाख विदेशी प्रवासी हैं. निश्चित रूप से अधिक भारतीय कामगारों का विदेशों में काम करना संतोषजनक है. आबादी में बड़ी संख्या में युवाओं के होने के कारण इसमें आगामी वर्षों में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है. आम तौर पर प्रवासियों द्वारा भेजी गयी रकम के मामले में चीन पहले पायदान पर रहता आया है, लेकिन आबादी में युवाओं का अनुपात कम होने और जन्म दर घटने से वह पीछे होने लगा है. विदेशों में भारतवंशी भी बड़ी संख्या में बसे हैं. दूसरे देशों में भारत एवं भारतीयों को सम्मान से देखा जाता है. विभिन्न देश अपने विकास में भारतीयों के योगदान को आभार के साथ स्वीकार भी करते हैं. यह एक अनुकूल स्थिति है, जिसका पूरा लाभ भारत को उठाना चाहिए. इसके साथ-साथ कामगारों की परेशानियों पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए. बहुत से कामगारों को देश में आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिला पाता. ऐसे में उनकी पगार और सुविधाएं प्रभावित होती हैं. उन पर प्रवासन खर्च, एजेंटों के कमीशन आदि का भार भी होता है. इसके अलावा, अनेक गंतव्य देशों में उन्हें शोषण, भेदभाव, काम के अधिक बोझ, सुविधाओं की कमी आदि से जूझना पड़ता है. संबद्ध देशों से बातचीत कर इन मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए.

भारत के 1.80 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, जो हमारी कुल आबादी का 1.3 प्रतिशत है.

स्वार्थ से प्रेरित है भारत विरोधी प्रचार

अनिल त्रिगुणायत
पूर्व राजदूत
amb.trigunayat@gmail.com

पश्चिमी सरकारों, संस्थानों और मीडिया द्वारा भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान आया है, वह पूरी तरह सही है. भारत के विकास तथा उसके वैश्विक प्रभाव को बाधित करने की मंशा से कुछ देश हमारे विरुद्ध तरह-तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं. ऐसा केवल सरकारों की ओर से नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें मीडिया और संगठनों की भूमिका भी है. उदाहरण के तौर पर, जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन की ओर से खुले रूप से देश में सरकार बदलने की बातें कही गयी हैं. इस तरह के अनावश्यक हस्तक्षेप और दबाव बनाने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, पर देश में चुनावी सरगर्मी शुरू होने के साथ इसमें तेजी आयी है. पश्चिमी सरकारों और मीडिया ने निज्जर और पन्नू के मामलों में भारतीय एजेंसियों के शामिल होने की निराधार बातें की, मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाने के प्रयास हुए, आंतरिक राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था के बारे में टिप्पणियां की गयीं. भारत सरकार की ओर से कड़ा एतराज दर्ज कराया गया है. हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है. एक प्रकार से यह उनका विशेष टूल-किट है, जिसे वे अपनी मीडिया के जरिये बढ़ाना चाहते हैं.

हमें एक संचार रणनीति बनानी चाहिए. हमें भी विभिन्न पश्चिमी देशों की आंतरिक स्थिति के बारे में एक जगह जानकारी एकत्र करनी चाहिए. जब भी कोई देश हमारे आंतरिक मामलों में बेमतलब बोले, तो हमें भी उसके बारे में बोलना चाहिए. लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को भी वस्तुस्थिति तथा पश्चिम की मंशा को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि किसी दुष्प्रचार का प्रभाव कम-से-कम हो.

इसी क्रम में पश्चिम के कई देशों ने अपनी संस्थाएं स्थापित की हुई हैं, जिन्हें वे शोध संस्थान और नागरिक समाज की श्रेणी में रखते हैं. ये समूह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर तथा पूर्वाग्रह से ग्रस्त अपने विश्लेषण को बिल्कुल पेशेवर अंदाज में प्रस्तुत करते हैं. उदाहरण के लिए, हमने कई बार देखा है कि लोकतंत्र सूचकांक में पाकिस्तान जैसे देशों को भारत से ऊपर दिखा दिया जाता है, मीडिया की स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत की तुलना में अफगानिस्तान को बेहतर बता दिया जाता है. इससे स्पष्ट है कि ऐसे सूचकांकों या रिपोर्टों की विश्वसनीयता नहीं है. उनका एजेंडा एक खास तरह का नैरेटिव बनाना है, सो वे उसी दिशा में काम करते रहते हैं. ऐसा वे इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास एक मजबूत मीडिया है. अनेक देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, का मीडिया कई मामलों में पश्चिम की अंग्रेजी मीडिया पर निर्भर और उससे प्रभावित रहता है. जानकारी के अभाव में या उनके प्रभाव में भारत में भी मीडिया कई बार पश्चिम मीडिया की बातों को दोहराता रहता है. इसका लोगों पर असर होता है, जो खतरनाक है क्योंकि वे ऐसी खबरों पर भरोसा कर लेते हैं. आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है. विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर लोग बिना सोचे-विचारे खबरों को साझा कर आगे बढ़ाते रहते हैं. जब तक कोई प्रतिक्रिया आये या उसका खंडन हो, बात बहुत दूर तक फैल चुकी होती है. जबकि होना यह चाहिए कि लोग साझा करने से पहले खबरों की पड़ताल करें और उसके निहितार्थों को समझें.

ऐसी स्थिति में हमें ठोस तैयारी की आवश्यकता है. भारत के विरुद्ध पश्चिम या कुछ अन्य देशों की सरकारों और मीडिया द्वारा जो नैरेटिव रचने का उपक्रम चल रहा है, उसे 'ग्रे-जोन वॉरफेयर' कहा जाता है. अभी हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि जिन देशों में अप्रवासी नहीं आते, वहां आर्थिक विकास नहीं होता. यह कहते हुए उन्होंने भारत को चीन, जापान और रूस के साथ रख दिया. जबकि सच यह है कि हजारों वर्षों से लोग भारत आते रहे हैं और यहां बसते रहे हैं. आज भी अच्छी तादाद में दूसरे देशों के लोग भारत में हैं. इस तरह के बयानों को भारतीय मीडिया भी प्रमुखता से छापता-दिखाता है. यह जरूरी हो गया है कि हमारे देश में मीडिया अपनी भूमिका और महत्व को ठीक से समझने की कोशिश करे. भारत न केवल आर्थिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि वह स्वायत्त एवं स्वतंत्र विदेश नीति पर भी चल रहा है, जिसके केंद्र में राष्ट्रीय हित हैं. जो पहले के समृद्ध एवं शक्तिशाली देश हैं, उन्हें यह स्थिति हजम नहीं हो रही है. वे समझते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है. जहां डिजिटल और नैरेटिव दुष्प्रचार के माध्यम से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है या विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकता है. इसी सोच के अनुसार वे यह सब कर रहे हैं. ऐसे प्रयास चुनाव के दौर पर अधिक सक्रियता से किये जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में हमें एक संचार रणनीति बनानी चाहिए, ताकि इस तरह के प्रयासों के प्रभावों को रोका जा सके.

अब रूस ने भी कह दिया है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहता है. हम जानते हैं कि पश्चिम और रूस के बीच में तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है. यूक्रेन में तो दोनों पक्षों का छद्म युद्ध चल ही रहा है. अमेरिका और पश्चिम के कई चुनावों में रूस पर आरोप लगता रहा है कि वह चुनावों में असर डालने की कोशिश कर रहा है. ऐसे आरोपों को पश्चिम ठोस सबूतों से साबित नहीं कर पाया है. रूस चूंकि अपने अनुभव से यह सब समझता है, तो वह यह भी समझ रहा है कि पश्चिमी देश भारत के साथ क्या कर रहे हैं. रूस और भारत के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार भारत की स्वायत्त एवं स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा कर चुके हैं. मेरा मानना है कि रूस का बयान एक तो पश्चिम को जताने के लिए दिया गया है और दूसरी बात यह हो सकती है कि रूस भारत के प्रति अपने समर्थन को अभिव्यक्त कर रहा है.

जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें एक संचार रणनीति बनानी चाहिए. हमें भी विभिन्न पश्चिमी देशों की आंतरिक स्थिति के बारे में एक जगह जानकारी एकत्र करनी चाहिए. जब भी कोई देश हमारे आंतरिक मामलों में बेमतलब बोले, तो हमें भी उसके बारे में बोलना चाहिए. लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को भी वस्तुस्थिति तथा पश्चिम की मंशा को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि किसी दुष्प्रचार का प्रभाव कम-से-कम हो. हमारे शिक्षण संस्थाओं में यह बताया जाना चाहिए कि देश सर्वोपरि है और अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर हमें सचेत रहने की आवश्यकता है. छात्र-छात्राओं को अगर ठीक से समझ आ जाए कि पश्चिम की असली मंशा क्या है, तो आगे चलकर आधारहीन नैरेटिव के पैंतरे का प्रतिकार आसानी से किया जा सकता है. ये लोग सही तथ्य और विश्लेषण से झूठ व गलतबयानी का जवाब देने में भी सक्षम होंगे. जब हमने परमाणु परीक्षण किया, तो उन्हें परेशानी हुई कि एक गरीब देश को ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम क्यों चला रहा है. अब हमें सुविचारित ढंग से उनका जवाब देना होगा. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

प्लास्टिक संधि पर सभी देशों को एकजुट होना चाहिए

अरविंद कुमार मिश्रा
टिप्पणीकार
arvindmbj@gmail.com

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, प्रति मिनट एक ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्र में समाहित हो जाता है. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक की हिस्सेदारी 3.4 प्रतिशत से अधिक है. दुनियाभर में सृजित प्लास्टिक कचरे का मात्र 10 प्रतिशत ही रिसाइकिल किया जा सकता है. इसमें पाये जाने वाले रसायन मानवीय एवं पर्यावरणीय सेहत के लिए काफी खतरनाक बताये गये हैं. प्लास्टिक पर जरूरत से अधिक निर्भरता ने जैव विविधता पर ग्रहण लगा दिया है. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है. अप्रैल के 23 से 29 तारीख के बीच कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथे दौर की वार्ता भले ही बेनतीजा रही, पर उम्मीद की जा रही है कि वर्ष के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जायेगी.

वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है. यूएन के विशेषज्ञ समूह ने 2017 में प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि की सिफारिश की थी. पिछले आठ वर्ष से अलग-अलग वार्ताओं में इसके मसौदे पर बहस जारी है. प्लास्टिक संधि के कुछ प्रावधानों पर दुनिया दो खेमों में बंट गयी है. संधि में तकरार का सबसे बड़ा मुद्दा धरती को जहरीला बनाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती से जुड़ा है. एक तरफ हाई एंबीशन कोएलिशन (एचएसी) है, जिसने प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने में कचरे के निस्तारण के साथ इसके उत्पादन को सीमित करने की वकालत की है. दूसरी ओर ग्लोबल कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल प्लास्टिक समूह है. इस समूह में भारत समेत रूस, ईरान, सऊदी अरब, चीन, क्यूबा और बहरीन जैसे देश शामिल हैं. इन देशों का कहना है कि विकासशील देशों के लिए प्लास्टिक उत्पादन में बाध्य होकर कटौती करना व्यावहारिक नहीं है. यह समूह प्लास्टिक जनित प्रदूषण से निपटने के लिए स्वैच्छिक कदमों को प्रोत्साहित करने वाली संधि का पक्षधर है. इसमें प्लास्टिक के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए तकनीक और वित्तीय आदान-प्रदान को वरीयता देने की मांग की गयी है. एशिया-पैसिफिक देशों का समूह इस मुद्दे पर एक राय रखता है. अफ्रीकी देशों के समूह ने भी बहुपक्षीय कोष बनाने की वकालत की है.

प्लास्टिक संधि के अंतिम मसौदे को मंजूरी न मिल पाने के पीछे अमेरिकी अड़चन भी वजह बनी है. दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक खपत करने वाले अमेरिका की दलील है कि प्लास्टिक संधि पेरिस समझौते की तरह स्वैच्छिक बने. यानी देशों को प्लास्टिक जनित कार्बन प्रदूषण कम करने का लक्ष्य मिले. यहां उल्लेखनीय है कि अमेरिका पांच प्रतिशत से भी कम प्लास्टिक रिसाइकिल कर पाता है. प्लास्टिक उत्पादन का सीधा संबंध तेल और गैस उद्योग से जुड़ा है. इसमें इस्तेमाल होने वाले अहम पदार्थ कच्चे तेल एवं नेचुरल गैस से हासिल किये जाते हैं. इसी कारण पेट्रोकेमिकल लॉबी के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देश प्लास्टिक संधि के सख्त प्रावधानों के खिलाफ हैं. पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रतिनिधियों की मांग है कि प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती की जगह उसकी रिसाइक्लिंग और वस्तुओं की डिजाइनिंग को टिकाऊ बनाया जाए. प्लास्टिक जनित प्रदूषण अब जिस स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में कड़े फैसले लेने ही होंगे. प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती अहम विकल्प हो सकता है, परंतु विकासशील देशों के रोजगार परिदृश्य और उनकी सामाजिक परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा. प्लास्टिक संधि यदि अस्तित्व में आती है, तो दुनियाभर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती हो, पर बेहतर होगा कि यह स्वैच्छिक और आम सहमति से हो. विकासशील देश प्लास्टिक के विकल्पों पर निवेश बढ़ा सकें, इसके लिए उन्हें तकनीक और आर्थिक सहयोग देना टाला नहीं जा सकता. यदि विकासशील और छोटे देशों को वित्तीय मदद और रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो प्लास्टिक संधि कहीं अधिक कारगर होगी.

विकासशील देशों को भी प्लास्टिक कचरे के स्थायी समाधान के लिए विकल्पों की ओर बढ़ना होगा. भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत कदम उठाये हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी इनमें से एक है, परंतु ऐसी हर कवायद कुछ दिन चलने वाले अभियान और कागजों में कैद होकर रह जाती है. ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सबिलिटी) जैसी योजनाओं को यदि पारदर्शिता और सख्ती से लागू किया जाए तो इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे. प्लास्टिक से पैदा होने वाले किसी भी कचरे का समाधान उपभोक्ता जागरूकता पर निर्भर करता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली का अगुआ बनकर सामने आया है, ऐसे समय में प्लास्टिक जनित प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में हमारे पास एक बड़ा अवसर है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

प्लास्टिक संधि के अंतिम मसौदे को मंजूरी न मिल पाने के पीछे अमेरिकी अड़चन भी वजह बनी है. दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक खपत करने वाले अमेरिका की दलील है कि प्लास्टिक संधि पेरिस समझौते की तरह स्वैच्छिक बने.

देश दुनिया

अफीम की खेती पर रोक से नाराज अफगान किसान

उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में अफीम की खेती को साफ करने के प्रभावी अभियान के खिलाफ स्थानीय किसानों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आयी है. अफीम की फसल नष्ट होने से अपनी आय गंवा चुके किसान गुस्से में हैं. सेटेलाइट से ली गयी तस्वीरों से पता चलता है कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान अफीम उत्पादन को कम करने में सक्षम हुआ है, परंतु जो किसान खेती वाली जमीन पर अफीम की फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है. इन किसानों ने कुछ खतरनाक क्षेत्रों में एंटी नारकोटिक्स यूनिट का विरोध किया. प्रांतीय पुलिस की मानें, तो पिछले सप्ताह पहाड़ी प्रांत बदख्शां में एंटी नारकोटिक्स यूनिट और किसानों के बीच हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गयी थी. बदख्शां में वसंत के मौसम में केवल एक ही पोस्त की फसल पैदा होती है और जैसे ही एंटी नारकोटिक्स यूनिट ग्रामीण प्रांत के कुछ हिस्सों में फसलों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ी, झड़पें शुरू हो गयीं. विदित हो कि अप्रैल 2022 में तालिबान के सर्वोच्च नेता ने आदेश जारी कर पोस्त की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था. इससे पहले अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक था. संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्यों और अपराध संबंधी कार्यालय यूएनओडीसी के आंकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में पिछले वर्ष 95 प्रतिशत की गिरावट आयी है. काबुल में तालिबान अधिकारियों के इस कदम की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सराहना की. परंतु मुनाफे वाली फसल पर निर्भर रहने वाले अफगान किसानों ने अफीम के उत्पादन पर कार्रवाई के कारण पिछले वर्ष अपनी आय का 92 प्रतिशत खो दिया. किसानों को अलग-अलग फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, पर कोई भी पोस्त के वित्तीय लाभ की बराबरी नहीं कर रही है, जिससे कुछ लोग छोटी जमीनों पर चोरी-छिपे खेती करना जारी रखे हुए हैं.

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

आनंद एक साधन है

आनंद जीवन का परम लक्ष्य है, पर यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है. जीवन आनंदमय हो और सतत आगे बढ़ता जाये, इसी कामना में तो सभी जिये जा रहे हैं. जीवन की यह यात्रा चार अलग-अलग स्तरों से गुजरती है. हर स्तर पर विशिष्ट प्रेरणा, बल और कार्यशैली की आवश्यकता होती है. हम प्रयास तो कर सकते हैं, पर सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है. हमारा कर्म केवल ईश्वर को प्रसन्न करना है, हमारी सफलता का श्रेय उन्हें ही जाता है. प्रथम स्तर है, ईश्वर की पहचान. यह पहला कदम है जहां हमें ईश्वर को जानना है, उन्हें सभी प्रभुओं के प्रभु के रूप में समझना है. इस स्तर पर हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों को, इस शुभ कर्म पथ पर साथ लाने का होना चाहिए. दूसरा स्तर है, सृष्टि से एकात्मता. यहां चुनौतियां न केवल हमारी मानवीय और जैविक प्रवृत्तियों से आती हैं बल्कि अजैविक शक्तियों से भी आती हैं. हमें यह समझना होगा कि इस अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु उसी परम सत्ता का अंश है. इस स्तर पर हमें सृष्टि की हर चीज के साथ एकात्मता का अनुभव करना होगा. तीसरा स्तर है, मानसिक अनुभव और सिद्धियां. यहां विकास की गति तेज होती है और साधक कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं. परंतु यहां खतरा भी अधिक है. साधक के लिए इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रलोभन हो सकता है, जिससे पतन हो सकता है. इसलिए इस स्तर पर ईश्वर की कृपा और मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है. साधक को यह अनुभव करना होगा कि वह ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर आया है और उनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है. इस स्तर पर, परमात्मा सिर्फ प्रभु या सृष्टा नहीं, बल्कि परम गुरु बन जाते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं. चौथा स्तर है, मन का एकाग्र होना. यह अंतिम स्तर है जहां सभी लक्ष्य, सभी पदार्थ, सभी अहसास एक बिंदु में समाहित हो जाते हैं. मन एकाग्र हो जाता है. यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है. इस स्तर पर साधक को पूर्ण आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है. **-श्री श्री आनंदमूर्ति**

कुछ अलग

हमारे चिंतन को विस्तार देती हैं यात्राएं

मुकुल श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
srivastava_mukul@lkouniv.ac.in

हर मौसम से सबकी कुछ न कुछ यादें जुड़ी होती हैं. ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है. गर्मियां मुझे मेरे बचपन की याद बड़ी शिद्दत से कराती हैं, जब हम गर्मी की छुट्टियों में यात्रा पर निकल पड़ते थे. यात्राएं हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत हमारे बचपने से हो जाती है. मै बात कर रहा हूं यात्रा या सफर की. आज के बच्चे भले ही कहानी सुनने की बजाय कार्टून देख कर सोते हों, पर ज्यादातर कार्टून उन्हें यात्रा पर ले जाते हैं.

यात्राओं के बारे में सोचते हुए राहुल सांकृत्यायन याद न आयें, ऐसा हो सकता है भला. यात्रा वृतांत पढ़ते समय हमेशा ऐसा लगता है कि घुमक्कड़ी के बाद इतना शानदार कैसे लिख लेते हैं लोग. पर अब समझ में आने लगा है कि जब हम यात्राओं को जीना शुरू कर देते हैं, तो यात्रा वृतांत अपने आप जी उठते हैं. कहते हैं, किसी पल को जीभर जी लेने के बाद ही डूब कर लिखा जा सकता है. यात्राएं हमारे चिंतन को विस्तार देती हैं. आप ने वो गाना जरूर सुना होगा, 'जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने

जाना.' देखा जाये तो जिंदगी का सफर है तो सुहाना, परंतु इसके साथ जुड़ी हुई है अनिश्चितता. ऐसा ही होता है जब हम किसी सफर पर निकलते हैं. ट्रेन कब लेट हो जाए, बस कब खराब हो जाए वगैरह वगैरह मुश्किलें तो हैं, पर क्या मुश्किलों की वजह से हम सफर पर निकलना छोड़ देते हैं?

हर सफर हमें नया अनुभव देता है. जिस तरह हमारे जीवन का हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे ही दुनिया का कोई मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसका रोज का सफर एक जैसा होता है. कुछ चेहरे जाने-पहचाने हो सकते हैं, पर सभी नहीं. जिंदगी भी ऐसी ही है. मंजिल तभी तक दूर लगती है जब तक हम सफर की शुरुआत नहीं करते, परंतु एक बार चल पड़े और चलते रहे, तो मंजिल जरूर मिलेगी. जब सफर में निकले हैं, तो किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ेगी ही. जरूरी नहीं कि आप साथी के साथ ही सफर करें. सफर में भी साथी बन जाते हैं. पर साथी के चुनाव में सावधान रहें. गलत साथी आपके सफर को दर्दनाक बना सकते हैं. आगे से जब भी किसी सफर पर निकलियेगा, तो मत भूलियेगा कि यह जिंदगी का सफर है और हर सफर की शुरुआत अकेले ही होती है, पर अंत अकेले नहीं होता. साथ में कारवां होता है अपनों का. यात्राएं चाहे जीवन की हों या किसी दूर देश की, घर से दफ्तर के बीच की ही क्यों न हों, सबकी यात्राओं का अलग-अलग सुख है.

आपके पत्र

नीट यूजी में गड़बड़ी चिंताजनक

नीट यूजी की परीक्षा पिछले पांच मई को हुई, जिसके बाद पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है. हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बयान जारी किया पेपर लीक नहीं हुआ है. इसके बाद भी इस मामले की जांच पुलिस कर रही है. पेपर लीक होने की आशंका से लाखों परीक्षार्थियों में चिंता है. केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर लीक हुआ कि नहीं. यदि गड़बड़ी हुई है, तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. साथ ही इसमें भूमिका निभानेवाले अधिकारियों व अन्य लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक (पटना)

रात में चले पटना-जोगबनी ट्रेन

सीमांचल के अररिया, जोगबनी, नरपतगंज, सुपौल व समीपवर्ती जिलों के हजारों लोगो को विभिन्न कार्यो से बराबर पटना जाना-आना रहता है. लेकिन, रात में उपयुक्त ट्रेन की सुविधा नहीं होने से उन्हें बस से यात्रा करनी पड़ती है. बस की यात्रा असुविधाजनक, उबाऊ व परेशानियों से भरी होती है. अतः पूर्व मध्य रेलवे को चाहिए कि पटना से जोगबनी (नरपतगंज-सरायगढ़-दरभंगा) के लिए देर शाम पाटलिपुत्र, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, नरपतगंज होते हुए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजें.

मनीष सुमन, फुलकाहा (अररिया)

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

हरियाणा में सरकार

हरियाणा में भाजपा की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और उसके खिलाफ मुहिम चला रहे नेताओं की संख्या अचानक से बढ़ गई है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने पर विचार करने की पेशकश कर दी। विपक्षी नेताओं की मांग है कि हरियाणा में शक्ति परीक्षण कराया जाए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास शक्ति परीक्षण का आदेश देने की शक्ति है। विपक्ष ने यह भी मांग की है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी बहुमत में नहीं है, तो हरियाणा में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, पर क्या यह आसान है? नए दौर की भाजपा को अपनी सरकारों के बचाव में सबसे सक्षम माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल खट्टर के साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुमत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, उनके पास संख्या बल है और जरूरत पड़ने पर वह शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं।

दरअसल, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने अभी दो महीने ही बीते हैं और कम से कम चार विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। वैसे, उन्हें बहुमत सिद्ध किए दो महीने ही बीते हैं और कायदे से विशेष परिस्थितियों में अब राज्यपाल ही बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में, राज्यपाल को लिखे गए पत्र का महत्व बढ़ जाता है।

जब ज्यादातर नेता और राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं, तब हरियाणा में कुछ नेता सरकार बनाने और गिराने के खेल में जुटे हैं।

दो महीने पहले बनी सरकार को विपक्ष इसलिए अब अल्पमत में मान रहा है, क्योंकि सरकार को समर्थन देने वाले दो विधायकों, एक भाजपा से और दूसरे निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा तीन निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। राज्य के 90 सदस्यीय सदन में भाजपा के 40, कांग्रेस के 30, जननायक जनता पार्टी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) और आईएनएलडी के एक-एक और छह निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा के पास शुरुआत में 41 विधायक थे, पर 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली होने पर विधायकों की संख्या घटकर 40 रह गई है। इससे विपक्ष का मनोबल बढ़ा है। वास्तव में, दुष्यंत चौटाला सरकार को गिराना चाहते हैं, पर कांग्रेस के बिना सरकार को गिराना मुश्किल है। कांग्रेस का ध्यान फिलहाल लोकसभा चुनाव पर है, उसे हरियाणा में सरकार गिराने में कोई जल्दी नहीं है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान है और उसके बाद ही प्रदेश में सरकार बनाने-गिराने की राजनीति तेज होगी।

वैसे, भाजपा सत्ता बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दावा किया है कि कांग्रेस और जेजेपी के नेता भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा के पक्ष में पूरे आंकड़े नहीं दिखते हैं, पर उसे भरोसा है कि विपक्ष में सेंध लगाकर सरकार को बचाया जा सकता है। वैसे भी, चार-पांच महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके नतीजे अक्सर चौंकाते हैं। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को महज चार सीटें मिली थीं, पर अगले ही चुनाव 2014 में वह 47 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में भी भाजपा 40 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल थी और जजपा के साथ उसने सरकार बनाई। वह नहीं चाहेगी कि हरियाणा जैसा राज्य उसके हाथ से निकल जाए, तो यकीन मानिए, आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र वाले राज्य में राजनीति तेज रहने वाली है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 मई, 1949

सरदार की चेतावनी

सत्ता मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, यह कोरी कहावत नहीं, बल्कि इसमें वास्तविकता भी है। कांग्रेस बहुत दिनों तक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली संस्था रही। उस समय कांग्रेस में शामिल होने का अर्थ होता था खतरों को निमंत्रण देना। जिसमें त्याग और बलिदान की भावना होती थी, देश के लिए मर मिटने और कुछ कर गुजरने की साध होती थी, वही कांग्रेस की ओर पग धरने का साहस करता था। चतुर लोग उस समय उससे बचकर रहते थे। सत्ताधारी वर्ग की खुशामद करते रहने में ज्यादा आमद थी। किन्तु अब जमाना बदल गया है। आजादी की लड़ाई तो खत्म हो गई। अब कांग्रेस के हाथों में सत्ता आई है। कांग्रेस सत्ता और पद का पासपोर्ट दिलवाने वाली संस्था बन गई है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कांग्रेस में घुसने के लिए उतावले और बेचैन हों। कांग्रेस में नये लोग आसानी से नहीं पैठ पाते; क्योंकि जिन्होंने पहले से कांग्रेस संगठन में पदों पर कब्जा जमाया हुआ है, उन्हें अपने स्थान छिन जाने का खतरा महसूस होता है। किन्तु जो लोग सच्चे दिल से कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास रखते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे जरिया नहीं बनाना चाहते, उनके लिए कांग्रेस के द्वार सदा खुले रहने चाहिए। कांग्रेस का ध्येय जनता की निःस्वार्थ सेवा करना रहा है। उस ध्येय की पूति के लिए प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति का सहयोग वांछनीय है।

कांग्रेस सगठन में इधर एक नई मुश्किल पैदा हो गई है। जो कांग्रेसजन अब तक आत्म त्याग और बलिदान की भावना से काम करते रहे, सत्ता के स्पर्श ने उन्हें भी अपने उच्च आदर्श से विचलित कर दिया है। सत्ता के लिए कांग्रेसजनों में गुटबन्दी की भावना उग्र हो गई है। यह भावना प्रांतों और रियासती संघों, दोनों में दृष्टिगोचर हो रही है। आये दिन लोग अविश्वास के प्रस्ताव अपनी जेबों में लिये घूमते हैं। शासन स्थिर नहीं रह पाता। मंत्रियों को अपना स्थान सुरक्षित रखने की ही चिन्ता सताती रहती है। जोड़-तोड़ बिठाने में उनकी सूझ और शक्ति का व्यय होता रहता है। दूसरी ओर, विरोधी गुट इस फिक्र में रहता है कि किस प्रकार वह अपने ही पुराने साथियों को गिराकर सत्ता के स्थानों पर आसीन हो जाये। साधारण जनता हैरान और परेशान होकर देखती रह जाती है।

युवाओं की ज्यादा परवाह का समय

देश में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की आबादी लगभग 4.9 करोड़ है, पर इनमें से 38 प्रतिशत ने ही खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है, युवाओं की भागीदारी क्यों घट रही है?

यहां स्कैन करें

राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

इसी साल फरवरी के अंतिम रविवार को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के 110वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल की उम्र पूरी करने पर नए बने मतदाताओं से यह आह्वान किया था कि वे 18वीं लोकसभा चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के अभियान 'मेरा पहला वोट देश के लिए' की भी प्रशंसा की थी, पर हाल ही में 18 वर्ष के होने वाले युवाओं पर इस सबका ज्यादा असर नजर नहीं आता। 18वीं लोकसभा के लिए सात चरणों में मतदान हो रहा है। 19 अप्रैल को मतदान के पहले चरण से कुछ ही दिन पहले यह आंकड़ा आया कि देश भर में 18-19 आयु वर्ग के युवाओं के मतदाता बनने का प्रतिशत 40 से भी कम है। देश में इस आयु वर्ग के मतदाताओं की अनुमानित आबादी 4.9 करोड़ है, पर 1.8 करोड़, यानी 38 प्रतिशत ने ही खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है। यह आंकड़ा वर्ष 2014 में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने वाले इसी आयु वर्ग के नौजवानों से 1.9 प्रतिशत कम है।

राजनीतिक दल भी इससे इनकार तो नहीं करते कि युवा ही वास्तव में किसी देश का भविष्य होते हैं। तब क्या भारत के युवाओं में मतदाता बनने के प्रति ही ऐसी उदासीनता को गंभीर संकेत नहीं माना जाना चाहिए? मतदान तो अगला कदम है। मतदाता बनने के प्रति उदासीनता के राज्यवार आंकड़े भी सवाल खड़े करते हैं। मसलन, देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली में 18 से 19 आयु वर्ग के युवाओं के मतदाता बनने का प्रतिशत मात्र 21 है। राजनीतिक रूप से सजग और सक्रिय माने जाने वाले बिहार में तो यह 17 प्रतिशत पर ही अटक गया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस आयु वर्ग के 23 प्रतिशत युवाओं ने ही मतदाता बनने में दिलचस्पी दिखाई। अपेक्षाकृत नए राज्य तेलंगाना के आंकड़े अवश्य उत्साहवर्द्धक हैं, जहां इसी आयु वर्ग के 66.7 प्रतिशत युवाओं ने मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत कराया है। अरसे से आतंकवाद और अलगाववाद झेल रहा जम्मू-कश्मीर भी इस मामले में प्रशंसा का पात्र है, जहां 62 प्रतिशत नौजवानों ने मतदाता बनने में दिलचस्पी दिखाई है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में यह प्रतिशत क्रमशः 60, 49, 48 और 38 रहा। जाहिर है, कम मतदाता बनने का सीधा असर चुनाव प्रक्रिया के जरिये युवाओं की भागीदारी पर भी पड़ेगा।

चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की घटती दिलचस्पी के जो कारण जानकार बताते हैं, वे दरअसल हमारी राजनीति को ही कठघरे में खड़ा करने वाले हैं। मसलन, उम्रदराज राजनीतिक नेतृत्व में युवाओं को अपना प्रतिनिधित्व और अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नहीं दिखता। चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की घटती दिलचस्पी तब और भी चौंकाने वाली है, जब देखें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया था। एक आंकड़े के मुताबिक, 2014 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं ने शेष आबादी की तुलना में कहीं ज्यादा 70 प्रतिशत तक मतदान किया था। चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखनेवाले मानते हैं कि तब भाजपा की जीत में भी निर्णायक भूमिका युवाओं ने ही निभाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी युवा पीछे नहीं रहे। फिर अब युवाओं का चुनाव प्रक्रिया से मोहभंग क्यों नजर आ रहा है? वास्तविक कारण तो युवाओं के बीच किसी व्यापक सर्वेक्षण से ही पता चल सकता है, पर देश-काल-परिवेश के मद्देनजर उसका अनुमान लगाने की कोशिश की जा सकती है। तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार और नीतिगत जड़ता के गंभीर आरोपों के बीच हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का वायदा किया गया था, पर आज भी लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं।

युवाओं के वोट की चाह रखने वाली हर पार्टी को यह भी दिखना चाहिए कि युवाओं की चिंता क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर 83 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। आयु वर्ग की बात करें, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई, 2022 से जून, 2023 के बीच नौकरी तलाश कर रहे 17 साल के युवाओं का प्रतिशत 16.8, 18 साल के युवाओं का प्रतिशत 28.5 और 19 साल के युवाओं का प्रतिशत 31.3 था। इसी सर्वेक्षण के मुताबिक, पहली बार मतदान करने वालों की श्रम बल भागीदारी 29.7 प्रतिशत थी, यानी उनमें से 70 प्रतिशत के पास कोई रोजगार नहीं था। ऐसे में, युवाओं की चुनाव प्रक्रिया से कुछ दूरी बहुत चौंकाती तो नहीं, पर सवाल अवश्य खड़े करती है। पिछले कई सालों से भारत को युवाओं का देश कहा जा रहा है। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो जाने पर आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट बताती है कि रोजगार की दृष्टि से युवा यानी 18 से 35 वर्ष के बीच की आबादी की बात करें, तो उसका आंकड़ा 60 करोड़ के आसपास बैठता है। दिल्ली में तो 45 प्रतिशत मतदाता 40 साल से कम उम्र के हैं।

आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर की कहानी खुद आंकड़े बयान करते हैं। भारत का विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना निश्चय ही गर्व की बात है। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता कि हमारे राजनीतिक दल युवा मतदाताओं का महत्व नहीं समझते हैं। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के विभिन्न नामों से जारी चुनाव घोषणापत्रों में युवाओं के लिए लुभावनी घोषणाएं हैं। फिर भी, युवाओं में मतदान के प्रति दिलचस्पी घट रही है, तो सभी दलों को सोचना होगा। बेशक यह स्थिति राजनीतिक नेतृत्व से भी आत्म-विश्लेषण की मांग करती है, लेकिन देश सिर्फ राजनीतिक दलों-नेताओं का नहीं है। देश की सही दिशा के लिए जरूरी है कि दलों-नेताओं की दिशा भी सही रखी जाए। हालात मोहभंग से नहीं, मनोबल से ही बदले जा सकते हैं। मतदान अधिकार ही नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य भी है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए ही कहा था : उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

रेवन्ना जैसे लोगों को सभी मिलकर दें करारा जवाब

यहां स्कैन करें

शोभा नारायण | वरिष्ठ पत्रकार

यह शायद भारत का सबसे दुखद रहस्य है। मैंने इसे बहुत पहले पुरानी तमिल फिल्मों में देखा है, जिनमें अक्सर रजनीकांत हीरो रहा करते थे। दृश्य कुछ यूं होता- एक जमींदार किसी खेत के बीच से घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी या कार से जा रहा है, तभी उसकी नजर वहां काम कर रही एक महिला पर पड़ती है और उसके मन में वासना जाग उठती है। वह अपने एक नौकर के माध्यम से उस महिला को शाम में अपने फॉर्महाउस पर आने का बुलावा भेजता है, जहां वह उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जोर-जबर्दस्ती करता है। ऐसे दृश्य में आमतौर पर महिला खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रहती है। इसके लिए वह अन्ना, हुकूम, साहब, मालिक जैसे शब्द बोलती है। दरअसल, ये सभी शब्द ताकत और सामंती पदानुक्रम को व्यक्त करते हैं, जहां महिलाओं को जमींदार की जायदाद के रूप में देखा जाता है, ठीक उसकी फसल या मवेशी की तरह।

हासन में भी वीडियो में महिलाएं प्रज्वल रेवन्ना से छोड़ देने की गुहार लगा रही हैं। 'नहीं', 'भैया', 'प्लीज मुझे जाने दो' जैसे संबोधनों से विनती कर रही हैं। वे यह भी कहती हैं कि कैसे प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना कॉलेज में कहा करती थीं कि उनके बेशक दो बेटे हैं, लेकिन सभी छात्राएं उनकी बेटियां हैं। यह सोचते हुए कि इस मामले को किस तरह देखा जाए, रिश्तों के इस जटिल जाल को याद करना उचित होगा। यह हासन की उस भौगोलिक सीमा को परिभाषित करता है, जहां यह घिनौनी पटकथा लिखी जा रही थी। यहां यह मत समझिए कि मैंने वे टेप देखे हैं, जो प्रज्वल ने महिलाओं के बलात्कार के वक्त बनाए थे। मैंने सिर्फ टेप के संदेश पढ़े हैं और लोगों से बात करके यह जानने की कोशिश की है कि प्रज्वल ने किस तरह अपने सामने गिड़गिड़ाती महिलाओं के वीडियो बनाए होंगे।

उनको 'मी टू' आंदोलन की तरह एकजुट खड़े हो जाना चाहिए। एक होकर ही वे अपनी आवाजें सुना सकती हैं और हालात बदल सकती हैं।

कर्नाटक में पार्टी के दिग्गजों के बीच इस बात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं कि टेप का खुलासा किसने और कैसे किया? प्रज्वल के चाचा एचडी कुमारस्वामी ने उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर टेप जारी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें कम से कम महिलाओं के चेहरे छिपा लेने चाहिए थे। हालांकि, हासन जैसी जगहों पर यह कोई छिपा तथ्य नहीं है और सभी सबके बारे में जानते हैं। वैसे, यौन-उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में पीड़िता को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति दुनिया भर में देखी जाती है। आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि जरूर महिला ने ही बलात्कार के लिए उकसाने वाले कपड़े पहने होंगे। हालांकि, भगवान का शुक्र है कि इस मामले में सभी यही मान रहे हैं कि महिलाएं रेवन्ना परिवार के रसूख का शिकार हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या होलेनारसीपुरा की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, उसका कोई सुखद नतीजा निकल सकता है? मेरा मानना है कि रेवन्ना के दुर्व्यवहार की शिकार इन महिलाओं के लिए एकमात्र रास्ता एकजुट होना है।

दुखद सच यही है कि भारत और दुनिया भर में यौन शोषण की अनगिनत मिसालें हैं। प्रज्वल की शिकार बनी इन महिलाओं को 'मी टू' आंदोलन की तरह खड़े हो जाना चाहिए। एक होकर ही वे अपनी आवाजें सुना सकती हैं और हालात बदल सकती हैं। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भारत की हरेक महिला (मैं भी) अपने जीवनकाल में चुटकी काटने या छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक का कोई न कोई यौन उत्पीड़न झेलती ही है। इसमें शर्मिंदा महिलाएं ही होती हैं या उन पर ही उंगली उठाई जाती है। लिहाजा, हासन की इन महिलाओं को प्रज्वल, उसके पिता और उसके परिवार को अपराधियों के कठघरे में खड़ा करने के लिए संवेदनशील और मजबूत वकील मिलने चाहिए। इन महिलाओं को शर्म से सिर झुकाने के बजाय एक साथ आना चाहिए और अपने लिए खड़ा होना चाहिए।

जाहिर है, जिस तरह से एसआईटी, अदालतें, राज्य और देश इस मामले को संभालेंगे, उससे उन लाखों महिलाओं को नई दिशा मिल सकती है, जो पुरुषों का शिकार होती हैं। इससे इन महिलाओं में यह कहने का साहस भी पैदा हो सकता है- बस, बहुत हुआ! यह ताकतवर पुरुषों को महिलाओं पर हाथ उठाने से पहले संभलने का एक मौका दे सकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ईश्वर से प्रार्थना करते हुए...

ईश्वर से हमें क्या-क्या अपेक्षा करनी चाहिए? उससे हमें यही अपेक्षा करनी चाहिए कि वह हमारे संदेहों को सलामत रखे, क्योंकि संदेह प्रार्थना का एक रूप है। यह संदेह ही है, जो विकसित होने में हमारी मदद करता है। यह हमें बाध्य करता है कि हम निर्भीक होकर एक सवाल के कई-कई जवाब तलाशें, उन पर गौर करें और फिर उनमें से सही को चुन सकें।

ईश्वर हमारे फैसलों की रक्षा करे, क्योंकि निर्णय लेना भी प्रार्थना का एक तरीका है। हमें ईश्वर से यही कामना करनी चाहिए कि वह हमें एक से दूसरे रास्ते का चयन करने में सक्षम बनाए, ताकि हमारा 'हां' सदैव हां हो और 'ना' हमेशा नहीं! एक बार जब हम अपनी राह चुन लें, तो फिर कभी पीछे मुड़कर न देखें और न ही अपनी आत्मा को पश्चातापों से छलनी करें।

हमारी अपेक्षा होनी चाहिए कि भगवान हमारे कर्म की रक्षा करे, क्योंकि कर्म ही पूजा है, प्रार्थना की ही एक पद्धति है। हमारा भोजन हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ की परिणति हो। अपने कर्म और परिश्रम के जरिये हम जो भी प्यार व स्नेह कमाएं, उसमें से थोड़ा सा साझा कर सकें।

ईश्वर, हमारे सपनों को बनाए रखना, ताकि अपनी उम्र या परिस्थितियों की परवाह किए बिना हम अपने दिल में आशा और दृढ़ता की पवित्र लौ हमेशा जलाए रखने में सक्षम हो सकें। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सपने कभी मरने न पाएं!

भगवान हमारे भीतर जोश पैदा करे, क्योंकि उत्साह भी पूजा का ही एक रूप है। यह उत्साह ही है, जो हमें स्वर्ग और धरती से, बुजुर्गों और बच्चों से बांधे रखता है; यह वह शक्ति है, जो हमें बताती है कि हमारी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं और वे हमारे सर्वोत्तम प्रयासों की हकदार भी हैं। यह उत्साह ही है, जो हमारे भीतर इस बात की दृढ़ता पैदा करता है कि सब कुछ संभव है। हम जो कुछ भी कर रहे हों, यदि हम उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध और ईमानदार हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ईश्वर हमें कभी निरुत्साहित न करे!

ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु,

प्रभु, हमें ऐसे लोगों की संगति देना, जिनके भीतर संदेह हो, जो कर्मवादी हों, सपने देखते हों, जिनमें उत्साह भरा हो और जो हर दिन ऐसे जीते हों, जैसे यह आपकी महिमा को समर्पित हो!

हमारी रक्षा करना, क्योंकि आपके चमत्कार को प्रकट करने का एकमात्र तरीका यह जीवन ही है। धरती बीजों को गेहूं में बदलती रहे और हम गेहूं को रोटी में तब्दील करते रहें। यह सब तभी संभव है, जब हमारे पास प्रेम हो; इसलिए हमें एकाकी कभी मत छोड़ना। हमें हमेशा अपनी संगति में रखना और ऐसे पुरुषों व महिलाओं की संगति देना, जिनके भीतर संदेह हो, जो कार्य करते हों, सपने देखते हों, जिनमें उत्साह कूट-कूटकर भरा हो और जो प्रत्येक दिन ऐसे जीते हों, जैसे यह पूरी तरह से आपकी महिमा को समर्पित हो!

पाउलो कोएल्हो

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप अपने अरबपति मित्रों को कर कटौती का लाभ देना चाहते हैं, मैं देश के कामकाजी लोगों के लिए लड़ रहा हूं। ट्रंप चाहते हैं कि 'किफायती देखभाल कानून' को खत्म कर दिया जाए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे।

पित्रोदा का बयान एक बड़ी आबादी का अपमान

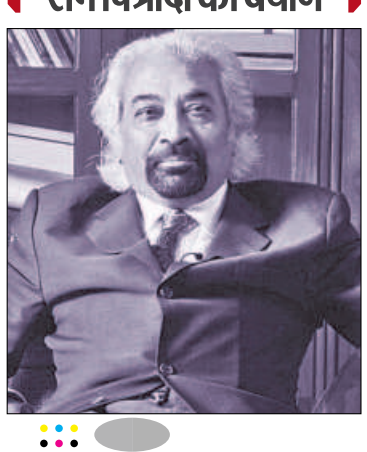

लोकसभा चुनावों में संविधान बदलने, लोकतंत्र पर खतरा, विरासत टैक्स के बाद अब रंग के आधार पर देश को बांटने जैसे आरोप-प्रत्यारोपों से सियासी तूफान मचा हुआ है। ताजा विवाद ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान से उपजा है, जिसमें उन्होंने देश के लोगों को रंग के आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास किया था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने तत्काल स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने में कोई देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान बर्दाश्त से बाहर है। उनके मुताबिक, 'शहजादे' के अमेरिका में रहने वाले अंकल की यह टिप्पणी नस्लीय है और देशवासी त्वचा के रंग को लेकर अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने स्वाभाविक ही इस बयान से किनारा कर लिया, हालांकि इससे पहले सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने संबंधी बयान दिए थे, जिस पर उनको काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

सवाल यह है कि मतदान के समय भारत के लोगों को भड़काना क्या कांग्रेस की सोची-समझी रणनीति है? अगर नहीं, तो एक बार विवादित बयान देने के बाद भी सैम पित्रोदा को क्यों नहीं रोका गया? उन्होंने फिर से विवादित बोल क्यों बोले? दिलचस्प है कि सैम पित्रोदा अपने बयान विदेश में रहकर जारी कर रहे हैं। ऐसे में, प्रधानमंत्री का यह कहना गलत नहीं जान पड़ता कि इन सबसे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आता है। प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए यह भी पूछ लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को हराने के लिए कांग्रेस ने इतनी कोशिश क्यों की? त्वचा के रंग के आधार पर देश को बांटने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि खुद भगवान श्रीकृष्ण की त्वचा का रंग हम सबकी तरह ही था। उल्लेखनीय है कि भारत में अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के रीति-रिवाज, खान-पान, धर्म-भाषा आदि भिन्न होते हैं, लेकिन वे एक-दूसरे का बखूबी सम्मान करते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस को चुनावी नुकसान होने के कयास लगा रहे हैं।

कुल मिलाकर, देश का एक अच्छा चुनावी-विमर्श बेमतलब नस्लीय दिशा में मुड़ गया। इसका दोषारोपण निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा पर किया जाएगा। देश जब अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में इस कदर गंभीर है, तब ऐसे बयान देकर पित्रोदा आम जनता की नजरों में खुद की और अपनी पार्टी की, दोनों की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। इससे उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
सैम पित्रोदा का बयान

उन्होंने भारत की विविधता को ही जाहिर किया

सैम पित्रोदा को भले कुछ लोग कठघरे में खड़ा करने का प्रयास रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, वह भारत का अपमान नहीं है। वह तो देश की विविधता को ही सामने रख रहे थे, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जिस पर हम इतराते हैं। उनका कहना था, 'हम भारत जैसे विविधता वाले देश में रहते हैं। भारत में पूरब के लोग चीनी जैसे, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे दिखते हैं। दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इसके बावजूद सब मिल-जुलकर रहते हैं। हम सब भाई-बहन हैं।' इस बयान में आखिर कौन सी ऐसी बात कह दी गई कि सैम पित्रोदा को इस तरह घेरा जा रहा है और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? वास्तव में, उनके बयान को काट-छांटकर प्रसारित किया गया और उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। हम भारतीयों के साथ दिक्कत यही है कि हम आधी-अधूरी बातें सुनकर भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण हमें छला भी जाता रहा है। इस बार भी यही हुआ है। सैम पित्रोदा के खिलाफ उस बयान के आधार पर माहौल बनाया गया, जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ ही की है। चूंकि वक्त चुनाव का है, इसलिए कांग्रेस ने भी बचाव की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अब चुनावी हवा उसके पक्ष में बनती दिख रही है और इस एक बयान से उसे चुनाव में नुकसान हो सकता था। इस लिहाज से कांग्रेस ने अच्छी तरह से इस मामले को संभाल लिया है। अब देखना यह है कि आगे उस पर किस तरह से हमला करने की कोशिश की जाती है।

दीपक चौधरी, टिप्पणीकार

यह गाली कैसे हुई

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया, जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार भी कर लिया। यह संगठन का आंतरिक मसला है, जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर सैम पित्रोदा ने भारतीय नृजातीय विविधता का जो उदाहरण दिया, वह कैसे गलत है, यह समझ से परे है। नृजातीय आधार पर दक्षिण भारत के कई नृवंशीय समूह अफ्रीकी लोगों से साम्य रखते हैं। नृजातीय विशेषता के आधार पर की गई तुलना कब से गाली हो गई? अफ्रीकी होना गाली है क्या? अगर हां, तो प्रधान जी ने जी-20 में अफ्रीकी देशों को सदस्यता क्यों दिलवाई? जब नेल्सन मंडेला को 'दक्षिण अफ्रीका का गांधी' कहा जाता है, तो यह हमारे लिए काफी गर्व की बात मानी जाती है, लेकिन अफ्रीकी लोगों से भारत के एक नृजातीय समूह की तुलना गाली हो जाती है। बड़ी अजीब थ्योरी है यह।

रनीश जैन, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

समय का मूल्य समझ लिया तो समझिए जीवन संवर गया

उड़ानों पर संकट

टाटा समूह की एअरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अचानक रद होने से विमान यात्रियों को जिस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ा और हवाई यात्रा के किराए बढ़ने की आशंका बलवती हो गई, वह नई नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है और बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो चुके हैं। यह ठीक है कि हड़ताली चालक दल के सदस्यों की बर्खास्तगी शुरू करने के बाद उन्होंने हड़ताल तो वापस ले ली, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो गया है। कर्मचारियों और प्रबंधन तंत्र में आगे जो वार्ता होनी है, उसमें यदि बात नहीं नहीं बनी तो फिर से उड़ानों पर संकट खड़ा हो सकता है। यह टाटा समूह के प्रबंधन तंत्र की खामी को ही बयान करता है कि कुछ समय पहले उसकी एक अन्य एअरलाइन विस्तारा भी इसी तरह के संकट से दो-चार हुई थी। तब विस्तारा का विलय एअर इंडिया में करने से नाराज पायलटों ने हड़ताल की राह पकड़ी थी। उस समय भी बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए थे। लगता है कि टाटा समूह ने उस संकट से कोई सबक नहीं सीखा। अब एअर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्य समूह की एक अन्य एअरलाइन एअर एशिया में विलय से क्षुब्ध हैं। वे अपनी सुविधाओं और वेतन-भत्तों में कटौती की आशंका से ग्रस्त हैं। समझना कठिन है कि टाटा समूह एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की आपत्तियों से परिचित होने के बाद भी उनका समय रहते समाधान क्यों नहीं कर पाया?

इसका कोई विशेष मतलब नहीं कि एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद होने से यात्रियों को अन्य किसी दिन की वैकल्पिक उड़ानों की पेशकश की गई और किराया वापस करने का वादा किया गया। प्रश्न यह है कि तय समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण हजारों लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? यह नुकसान केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाला ही नहीं, टाटा समूह की साख पर बट्टा लगाने वाला भी है। जब टाटा समूह ने करीब दो वर्ष पहले एअर इंडिया को सरकार से हासिल किया था, तब यह आस बंधी थी कि न केवल विमानन क्षेत्र को पंख लगेंगे, बल्कि इस विमान सेवा के साथ इस समूह की अन्य एअरलाइंस की सेवा एवं संचालन की गुणवत्ता सुधरेगी। यह विडंबना ही है कि ऐसा होने के बजाय विमान यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह सही है कि विमानन महानिदेशालय ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंधन तंत्र से जवाब-तलब किया, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि वह उसके प्रबंधन की उन खामियों का दूर कराए, जिनके कारण टाटा समूह की एअरलाइंस बार-बार विमान यात्रियों को परेशानी में डाल रही हैं। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी एअरलाइन के खराब प्रबंधन का दुष्परिणाम विमान यात्रियों को न भुगतना पड़े।

अराजकता का प्रदर्शन

पंजाब में किसान विगत लगभग तीन माह से आंदोलनरत हैं। पटियाला के शंभू बार्डर पर किसानों ने सड़क मार्ग तो बाधित कर ही रखा है, विगत लगभग 21 दिन से रेल मार्ग पर भी धरना लगाया हुआ है। इससे यात्रियों को न सिर्फ शारीरिक और मानसिक, अपितु आर्थिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, ऐसे में आम नागरिकों की पीड़ा को समझा जाना चाहिए। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर इसका रत्ती भर भी प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी प्रदेश भर में एक राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के विरुद्ध भी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें प्रचार करने से रोक रहे हैं। विगत दिनों पटियाला से भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के विरुद्ध ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। किसानों ने इसे भी मुद्दा बना लिया है। उनकी मांग पर पुलिस ने हालांकि केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब परनीत कौर के आवास के बाहर पक्का मोर्चा लगाने पर अड़े हुए थे। इसे यदि अराजकता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदर्शनकारी अपनी उचित मांगों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यह उचित मंच पर ही उठाई जानी चाहिए। मार्ग अवरुद्ध कर आम नागरिकों के लिए परेशानी खड़ी करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना कतई उचित नहीं है। प्रदेश सरकार को प्रत्याशियों की सुरक्षा के उचित प्रबंध करने के साथ ही आम नागरिकों और यात्रियों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

> मार्ग अवरुद्ध कर आम नागरिकों के लिए परेशानी खड़ी करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना कतई उचित नहीं है

संसदीय प्रणाली की समस्याएं

आर. विक्रम सिंह

संसदीय प्रणाली की सीमाओं को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करना चाहिए। वैसे भी हमारी व्यवस्था संसदीय है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति वाली है

अवधेश राजपूत

देश में निर्वाचन पर्व चल रहा है। संभावना है कि एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। पूर्ण बहुमत की सरकारें वास्तव में हमारी संसदीय प्रणाली का ऐसा उच्चतम शिखर हैं, जो अपने स्वरूप में राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन पद्धति की अनुभूति कराती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। हमारी व्यवस्था संसदीय है, किंतु व्यवहार में वह राष्ट्रपति वाली है। हम नरेन्द्र मोदी को ही प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लड़ते हुए देख रहे हैं। भाजपा नेता उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक समय नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम पर वोट मांगे जाते थे। यह व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जैसी ही है। जैसे नेहरू जी देश में कहीं से भी लड़कर चुनाव जीत सकते थे, वैसे ही आज मोदी भी कहीं से भी लड़कर जीत सकते हैं।

बीते सात दशकों में देश ने संसदीय प्रणाली अनुभव लिया है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं। उसमें कुछ अस्थिरता के लक्षण होते हैं, जबकि विकास के लिए स्थिरता आवश्यक है। सीमित आबादी एवं सीमित क्षेत्रफल के एक भाषाभाषी, एक सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रीय स्वरूप के यूरोपीय देशों में संसदीय या वेस्टमिंस्टर प्रणाली सुविधाजनक व्यवस्था हो सकती है, किंतु भारत जैसे देश में जहां बहुलताएं हैं और इन बहुलताओं को राष्ट्रीयता के एक धागे में पिरोए रखना एक मूलभूत राष्ट्रीय आवश्यकता है, वहां देश में अमेरिकी प्रणाली पर भी एक बहस की जरूरत लग रही है। संसदीय प्रणाली के प्रारंभ में हमने नेहरू और इंदिरा जैसे सशक्त प्रधानमंत्री देखे हैं तो कालांतर में वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, चरण सिंह, इंद्रकुमार गुजराल जैसे कमजोर एवं मजबूर प्रधानमंत्री भी देखे। गठबंधनों के माध्यम से किसी प्रकार अपनी सरकार को बचाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को रोकने में असहाय वीपी सिंह की प्राथमिकता अल्पसंख्यक राजनीति थी। राजीव गांधी को जैसे ही भनक लगी कि चंद्रशेखर रामजन्मभूमि मामले में समझौता कराने के निकट हैं तो उन्होंने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। देश ने मनमोहन सिंह जैसे गठबंधन धर्म को मजबूरी बताने वाले प्रधानमंत्री भी देखे हैं।

राष्ट्रपतीय प्रणाली में बंधुआ राष्ट्रपति नहीं हो सकते। इसमें वैकल्पिक या गैरजिम्मेदार सत्ता केंद्र का विकास असंभव है। संसदीय प्रणाली के साथ समस्या यह है कि उसे राष्ट्रीय नेताओं की आवश्यकता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री वही होगा, जिसके पक्ष में अधिकतम सांसद लामबंद हों। इसके लिए बहुत से दलीय हितों के घात-प्रतिघात, क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थों के समायोजन की योग्यता अपेक्षित है। राजीव गांधी, देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह आदि का संघर्ष से उपजा राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं था। गठबंधन सरकारों ने देश को अपने कद एवं क्षमता के अनुरूप खड़ा ही होने नहीं दिया। नेहरू गठबंधन राजनीति के दबाव से मुक्त थे। इसका उपयोग उन्होंने समाजवादी विकास माडल को ढालने में और पंचवर्षीय योजनाओं में लगाया। इस प्रकार देश को एक सशक्त औद्योगिक आधार देने का काम किया। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी भी गठबंधन के दबाव की मजबूरियों से मुक्त हैं। इसका परिणाम हम पिछले दस वर्षों में प्रभावशाली हो रहे भारत के रूप में देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व ऐसा रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की सीमाओं से आगे जाकर उसे गरिमा प्रदान की। गठबंधन सरकार चलाने वाले अधिकांश प्रधानमंत्रियों को तरह-तरह के समझौते करने पड़े।

हमारे यहां सक्षम राष्ट्रीय नेताओं के अभाव का मुख्य कारण यह है कि संसदीय प्रणाली राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास की अपेक्षा ही नहीं करती। इसी कारण कुछ ऐसे नेता एकाएक प्रधानमंत्री बन गए, जिनकी देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर किसने सोचा होगा कि देवेगौड़ा, गुजराल या मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन सरकारें वास्तव में राजनीतिक सौदेबाजी करने वाले क्षत्रपों के लिए ही हितकारी होती हैं, जबकि 140 करोड़ की आबादी का विशाल देश ऐसी व्यवस्था चाहता है, जो उसकी समग्र शक्ति एवं क्षमताओं को अभिव्यक्ति दे सके। इसीलिए देश को पूर्ण बहुमत की सशक्त सरकार की अपेक्षा होती है। ऐसी ही सरकार राष्ट्रीय हित से जुड़े दायित्वों को पूर्ण करने में समर्थ होती है। भारतीय लोकतंत्र अपनी समस्त शक्ति एकत्रित कर अपने आदर्श नेतृत्व को अधिक से अधिक जितना अधिकार दे सकता है, वह एक अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। संसदीय प्रणाली में गठबंधन राजनीति, राजनीतिक जोड़तोड़ की कमजोरियां बाहरी दखल की आशंकाएं बढ़ाते हैं। मित्रोखिन आर्काइव्स भारतीय राजनीति में सोवियत संघ के दखल का आंख खोलने वाला दस्तावेज है।

राष्ट्रपति प्रणाली जादू की छड़ी भी नहीं है, जो तत्काल सब कुछ सुधार देगी। इसलिए व्यवस्था के चौकीदारों को जागते रहना आवश्यक है। संसदीय प्रणाली सत्ता में भागीदारी की संभावना बढ़ाती है, लेकिन हमारे यहां जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीय समूहों, दबंगों और भ्रष्टतंत्र के हितसाधकों एवं अलगाववादियों की भागीदारी बढ़ाने लगती है। कई क्षेत्रीय दलों में तो समग्र राष्ट्रीय दृष्टि होती भी नहीं है। भारत की अखंडता उनके लिए महत्व का मुद्दा नहीं बनती। वे कई बार तो विदेश नीति को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रणाली देश के नागरिकों से सक्षम राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित करने की अपेक्षा करती है इसलिए देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाले नेतृत्व के सक्षम चरित्र राष्ट्रीय फलक पर दिखने लगेंगे। उनकी संस्कृति की, भाषा की समझ बेहतर होगी। वे कभी बंगाल में, कभी तमिलनाडु में, कभी वनवासियों तो कभी तमिल मछुआरों के बीच रहने वाले होंगे। तब देश में वह राष्ट्रीय कर्मठ एवं समर्पित नेतृत्व आकार लेगा, जिसकी दृष्टि समस्त देश को समाहित किए हुए होगी। अच्छा होगा कि राजनीतिक खानदानों और क्षत्रपों के दिन चले जाएं। देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला कोई नेता जब राष्ट्रपति शैली में चुनाव लड़ेगा तो देश के गांव-गांव में उन्हें वोट देने वाले मिलेंगे और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास की राह स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होगी।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

चुनाव का अर्थ सिर्फ प्रतिनिधि चुनना नहीं

राघवेंद्रप्रसाद तिवारी

मतदान न करने से लोकतांत्रिक प्रणाली अव्यवस्था की शिकार होती है, जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है

देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं और उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए चुनाव से संबंधित समस्त पहलुओं पर समग्रता से चिंतन-मनन करने का यह अनुकूल समय है। इस संदर्भ में दो यक्ष प्रश्न हमारे विचार-प्रक्रिया के केंद्रबिंदु में होने चाहिए। क्या उम्मीदवारों के चयन के लिए 'जीतने की क्षमता' एकमात्र मानदंड होना चाहिए? क्या मतदाताओं को प्रतिनिधियों को केवल स्वीकारने या अस्वीकारने के लिए मतदान करना चाहिए अथवा इससे परे विचार कर मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में अनुभव, सद्कार्यों के जरिये जनता में लोकप्रियता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रहित आदि गुणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास के एजेंडा के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सक्षम होना चाहिए। उनमें समावेशी एवं सतत विकास के लिए जरूरी विमर्श में जनआकांक्षाओं को रेखांकित करने की क्षमता होनी चाहिए।

चुनाव मतदाताओं के लिए कई विकल्प खोलते हैं। उनसे पता चलता है कि कौनसा राजनीतिक दल समसामयिक विषयों पर बेहतर कानून बना सकता है, लोककल्याण के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है, समावेशी एवं टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। किस राजनीतिक दल में संसद एवं संसद के बाहर जनआकांक्षाओं को सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त करने का कौशल है। कौनसा दल वैश्विक शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। यह भी देखना चाहिए कि कौनसे राजनीतिक दल राष्ट्रहित के मुद्दों को ताक पर रखकर मुफ्तखोरी की संस्कृति, जाति, संप्रदाय, धनबल, बाहुबल एवं अन्य प्रभावों के माध्यम से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। चुनाव वास्तविक अर्थों में जनता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में प्रस्तावित विभिन्न माडलों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, विदेश नीति एवं राष्ट्रहित आदि विषयों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने का अवसर होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत इन विषयों से संबंधित सर्वोत्तम माडल को ही जनप्रतिनिधियों के चयन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे जन एवं राष्ट्र-कल्याण के लिए नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनपेगी। चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों का इन बिंदुओं पर ही मूल्यांकन होना चाहिए। लोक कल्याण के लिए तत्पर, निष्पक्ष तरीके से सुशासन करने की क्षमता एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नीतियों के बारे में सोचने तथा नवाचार करने की क्षमता ही उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों के साथ मतदाताओं की भी प्रमुखता होनी चाहिए।

आवश्यक है मतदाताओं का जागरूक होना। फाइल

सार्वजनिक जीवन में जो लोग पुनः चयनित होना चाहते हैं, उन्हें जनता को लोकतंत्र और चुनावों के स्वस्थ तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। प्रचार के दौरान उन्हें विकास एवं सुशासन का वैकल्पिक माडल पेश करना चाहिए तथा अपने पूर्व-प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रबुद्ध समाज को भी सभी दलों के उम्मीदवारों के लिए साझा मंच उपलब्ध कराने चाहिए, जहां सघन विमर्श के द्वारा जनमानस राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पर उनके सोच-समझ के आधार पर समुचित निर्णय ले सकें। राजनीतिक दलों को सही उम्मीदवारों के चयन के लिए बेहतर मानदंड चुनने के लिए बाध्य करने में नोटा सहायक नहीं है। राजनीतिक दलों ने इस प्रविधान से कतई सीख नहीं ली है। पाल टैमब्या नामक विद्वान का मत है कि 'मतदान कोई विवाह नहीं है। यह एक सार्वजनिक परिवहन है। आप उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप बस में चढ़ रहे हैं और यदि कोई बस आपके गंतव्य तक नहीं जा रही है, तो आप घर पर बैठकर उदास नहीं होते। आप वह बस चुनते हैं, जो आपको आपके गंतव्य के सबसे नजदीक ले जाए।' इसका तात्पर्य है कि सर्वोत्तम विकल्प चुनाव से दूर रहना नहीं, अपितु ऐसे उम्मीदवारों का चयन है, जिसकी रीति-नीति आपके जीवन-मूल्यों के सन्निकट हो। इस संदर्भ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया सार्थक भूमिका अदा कर सकता है।

अक्सर कुछ लोग यह सोचकर मतदान करने से बचते हैं कि मेरा वोट कोई महत्व नहीं रखता। यह रवैया सही नहीं है। मतदान के अधिकार का प्रयोग न करने से अयोग्य उम्मीदवार एवं अक्षम सरकार बनने की आशंका बढ़ जाती है एवं लोकतांत्रिक प्रणाली अव्यवस्था की शिकार होती है, जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। तथ्य यह है कि मतदान अधिकार के साथ ही राष्ट्रधर्म भी है। अनेक राष्ट्र-नायकों ने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाने के लिए बलिदान दिया है। मतदान कर हम उनके जीवन मूल्यों को जीवंत करते हैं। ऐसी सद्भावनाएं ही हमें मतदान के लिए प्रेरित कर सुयोग्य सरकार के गठन में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में यह संसदीय चुनाव भारत के लिए दुनिया के समक्ष अनुकरणीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं राष्ट्रधर्म के उच्चतम आदर्श स्थापित करने का अवसर है, जिससे यह भावना दृढ़ हो जाए कि निःसंदेह भारत ही लोकतंत्र की जननी है।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

असाध्य रोग ईर्ष्या

दूसरे व्यक्ति की गुणवत्ता, कौशल, योग्यता को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले जलन के भाव को ईर्ष्या कहा जाता है। मनोविज्ञानियों ने इसे क्रोध, लाचारी और घृणा, इन सभी भावनाओं का एक संयोजन माना है। यह एक मानसिक कष्ट है। इसका संबंध मानवीय मनोवृत्ति से होता है। ईर्ष्या नकारात्मक चिंतन और मानसिक रूप से कमजोर होने का सूचक है।

ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर स्वयं की शांति आवश्यक भंग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान तथा आंतरिक उत्थान करने में सदैव असमर्थ ही रहता है। उसकी संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इसी व्यर्थ की ईर्ष्या, द्वेष में ही व्यय हो जाती है। हमारे मनीषियों ने ईर्ष्या को मानसिक पटल पर फैलने वाली महामारी के समान माना है जिसे अगर जल्दी नहीं रोका गया तो वह विनाशक सिद्ध होती है। ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त मनुष्य सदैव असंतुष्ट, तनावग्रस्त तथा दुखी ही रहता है जिससे मनुष्य के चेहरे की सुंदरता भी प्रभावित हो जाती है। जब ईर्ष्या में दूसरे का अनिष्ट करने का भाव आ जाता है तब वह हमारे मानसिक पतन का कारण बन जाती है। यह उस अग्नि की तरह होती है जिसे जंगल स्वयं उत्पन्न करता है और फिर स्वयं इसमें जलकर भस्म हो जाता है।

ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर तथा असहाय बना देती है जिससे मनुष्य अपने जीवन के आनंद से सदैव वंचित ही रहता है। ईर्ष्यालु प्रकृति के मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध कभी भी सुदृढ़ नहीं रह सकते। ईर्ष्या चित्त की एकाग्रता को भंग कर देती है जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी विकृत हो जाता है। दूसरों की समृद्धि के प्रति द्वेष का यह भाव जब मनुष्य के मन में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य अपने स्वयं की मानसिक उन्नति के मार्ग को भी बंद कर लेता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता तनाव

डा. मोनिका शर्मा

कामकाजी संसार हो या सामाजिक जीवन, संतुलन साधने के प्रयास ही लोगों को तनाव से बचा सकते हैं

सहज जीवनशैली, सार्थक संवाद और सामाजिकता के भाव-चाव को जीने वाले भारतीय समाज में तनाव एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर तीसरा व्यक्ति तनाव का शिकार है, जिसके चलते हाइपरटेंशन का जोखिम भी बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार हाइपरटेंशन यानि उच्च रक्तचाप हमारे यहां 10.8 प्रतिशत लोगों का जीवन छीनने की वजह बन रहा है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप का सीधा संबंध हृदय की सेहत से तो है ही यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों पर भी गहरा असर डालता है। हार्वर्ड हेल्थ में छपे शोध के मुताबिक दीर्घकालीन तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। यह धमनियों में रुकावट पैदा करने वाले जमाव को भी बढ़ावा देता है। समझना कठिन नहीं कि आज के प्रतियोगी और आपाधापी भरे जीवन में हर आयुवर्ग के लोगों में तनाव के कारण हृदय रोगों से जुड़े जोखिम भी बढ़े हैं।

आज दुनियाभर में महामारी बन चुके तनाव की जकड़न हर आयुवर्ग के लोगों शारीरिक-मानसिक समस्याओं का शिकार बना रही है। चिंतनीय यह भी है कि हर पांच में से चार पीड़ित व्यक्तियों का ठीक से इलाज नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर दुनिया के सभी देशों द्वारा प्रयास किए जाएं तो 2023 से 2050 तक 7.6 करोड़ लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। दरअसल कामकाजी संसार हो या सामाजिक जीवन, संतुलन साधने के प्रयास ही लोगों को तनाव से बचा सकते हैं। तनाव के फैलते स्याह साये को समय रहते समझना ही इससे बचने का का पहला कदम है। व्यायाम के प्रति जागरूक और नियमित होने से लेकर वर्चुअल दुनिया के दिखावे से अवसाद में घिरने तक, सधी, स्वस्थ और सजग जीवनशैली की आवश्यकता है। तनाव का शिकार बनाने वाले कारणों को समझना आवश्यक है। मित्रों, परिजनों, सहकर्मियों और पेशेवर लोगों के साथ अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के बारे में खुलकर संवाद करने का परिवेश बनाने की दरकार है।

मौजूदा दौर में स्मार्ट गैजेट्स की स्क्रीन में गुम रहना हो या चाहे-अनचाहे खुद तक सिमट जाने की प्रवृत्ति, अकेलापन और सामाजिक जीवन से बढ़ती दूरी तनाव के अहम कारण बन रहे हैं। समझना जरूरी है कि इंसान का जीवन भावनाओं और सामाजिक संबंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्नेह-साथ के भाव मन को सुख देते हैं। अध्ययन बताते हैं कि सामाजिक गतिविधियों का सिमटना तनाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में जमीनी जीवनशैली की ओर लौटना मन-मस्तिष्क को घेरती इन स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए बेहद जरूरी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अहम फैसले के इंतजार में देश

'सुप्रीम कोर्ट में पंथनिरपेक्षता की परीक्षा' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने का साहस किया है जिस पर प्रायः कोई भी बोलने का साहस कम ही करता है। आज एक तरफ जहां कट्टरवाद बढ़ा है वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में एक्स मुस्लिमों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ईरान, इराक में तो यह एक आंदोलन का रूप ले रहा है। ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, जो किसी मत-पंथ को नहीं मानते, वे किसी पंथक बंधन में नहीं रहना चाहते और अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जेलों में भी रहना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन देशों का कानून उन्हें पंथ छोड़ने की इजाजत नहीं देता। भारत में अतीत में संविधान में परिवर्तन कर उसमें सेक्युलरिज्म को स्थान दिया गया है। संविधान तो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसी उच्चतम न्यायालय से अपेक्षा भी है। जब न्यायालय सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने के आयोजन, गुजरात में गरबा-डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा पर राय दे सकता है तो साफिया के केस में क्यों नहीं। वैसे भी साफिया तो एक्स मुस्लिम हैं और भारत में सभी को अपना मत-पंथ चुनने की, अभिव्यक्ति की, अपने तरीके से रहन-सहन की आजादी संविधान देता ही है तो इसमें विरोधाभास कैसा! हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इस अग्निपरीक्षा में कुंदन बनकर उभरेगा और सेक्युलर भारत की छवि और मजबूत ही करेगा।

विपिन गोयल, हापुड़

मेलबाक्स

भारत पर टिप्पणी न करे अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कार्यक्रम में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए भारत समेत कुछ अन्य देशों को जेनोफोबिक की संज्ञा देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। जेनोफोबिक का अर्थ है किसी भी विदेशी के प्रति नापसंदगी, परहेज या डर का भाव। विदेशी व्यक्ति, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति इत्यादि के प्रति स्वीकार्यता का अभाव। हालांकि विवाद होता देख उनकी तरफ से एक रक्षात्मक बयान भी आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के उक्त कथन का अर्थ यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का बड़ा कारण है कि वे अप्रवासियों का स्वागत करते हैं, वहीं भारत, चीन, जापान जैसे देश अप्रवासियों के प्रति पूर्वाग्रह रखने के कारण उतनी तरक्की नहीं कर पाए। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका एक अप्रवासियों का देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं और अमेरिका की उन्नति में अप्रवासियों की बहुत अहम भूमिका है, परंतु एक ढाई-तीन सौ साल पहले जन्मे देश के राष्ट्रपति का सहस्त्रों वर्षों की हमारी समावेशी संस्कृति को जेनोफोबिक कहना हास्यास्पद ही है। अंततः ये साबित हो गया कि पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में अमेरिका का भारत के प्रति व्यवहार बदला है नजरिया नहीं। कुछ महत्व हमें देने लगा, क्योंकि हम उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार हैं, पर मूलतः वह आज भी हमें सपेरों का देश ही समझता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को अगर भारत के इतिहास का जरा भी ज्ञान होता तो उन्हें पता होता कि शक, हूण, कुषाण, मुगल से लेकर अंग्रेज तक इस धरती पर कभी आक्रांता तो कभी व्यापारी बनकर आए और इस धरती ने सबको स्वीकार कर लिया। आजादी के बाद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना आज भी जारी है। रोहिंग्यायों की समस्या से अब लगभग पूरा भारत परेशान हो रहा है, पर जब वे आ रहे थे हमने उनपर तरस खाकर उन्हें आने दिया। हालांकि गलती हमारी ही है, हमने अपनी संस्कृति को तुच्छ मानकर अपनी संस्कृति की उपेक्षा करके अमेरिकी जीवनशैली एवं उनके ब्रांडों का इतना अधिक अनुसरण कर लिया कि वे स्वयं को हमसे श्रेष्ठ मान बैठे। खैर, अगर हम मान भी लें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की कोई जानकारी नहीं, फिर भी एक राष्ट्राध्यक्ष का किसी संप्रभु राष्ट्र की संस्कृति पर टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है।

अर्जित मिश्रा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

उड़ानों पर संकट

टाटा समूह की एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अचानक रद होने से विमान यात्रियों को जिस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ा और हवाई यात्रा के किराए बढ़ने की आशंका बलवती हो गई, वह नई नहीं है। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है और बड़ी संख्या में यात्री परेशान हो चुके हैं। यह ठीक है कि हड़ताली चालक दल के सदस्यों की बर्खास्तगी शुरू करने के बाद उन्होंने हड़ताल तो वापस ले ली, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो गया है। कर्मचारियों और प्रबंधन तंत्र में आगे जो वार्ता होनी है, उसमें यदि बात नहीं बनी तो फिर से उड़ानों पर संकट खड़ा हो सकता है। यह टाटा समूह के प्रबंधन तंत्र की खामी को ही बयान करता है कि कुछ समय पहले उसकी एक अन्य एयरलाइन विस्तारा भी इसी तरह के संकट से दो-चार हुई थी। तब विस्तारा का विलय एअर इंडिया में करने से नाराज पायलटों ने हड़ताल की राह पकड़ी थी। उस समय भी बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए थे। लगता है कि टाटा समूह ने उस संकट से कोई सबक नहीं सीखा। अब एअर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्य समूह की एक अन्य एयरलाइन एअर एशिया में विलय से क्षुब्ध हैं। वे अपनी सुविधाओं और वेतन-भत्तों में कटौती की आशंका से ग्रस्त हैं। समझना कठिन है कि टाटा समूह एअर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की आपत्तियों से परिचित होने के बाद भी उनका समय रहते समाधान क्यों नहीं कर पाया? इसका कोई विशेष मतलब नहीं कि एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद होने से यात्रियों को अन्य किसी दिन की वैकल्पिक उड़ानों की पेशकश की गई और किराया वापस करने का वादा किया गया। प्रश्न यह है कि तय समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण हजारों लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? यह नुकसान केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाला ही नहीं, टाटा समूह की साख पर बट्टा लगाने वाला भी है। जब टाटा समूह ने करीब दो वर्ष पहले एअर इंडिया को सरकार से हासिल किया था, तब यह आस बंधी थी कि न केवल विमानन क्षेत्र को पंख लगेंगे, बल्कि इस विमान सेवा के साथ इस समूह की अन्य एअरलाइन की सेवा एवं संचालन की गुणवत्ता सुधरेगी। यह विडंबना ही है कि ऐसा होने के बजाय विमान यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह सही है कि विमानन महानिदेशालय ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंधन तंत्र से जवाब-तलब किया, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि वह उसके प्रबंधन की उन खामियों का दूर कराए, जिनके कारण टाटा समूह की एअरलाइन बार-बार विमान यात्रियों को परेशानी में डाल रही हैं। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी एयरलाइन के खराब प्रबंधन का दुष्परिणाम विमान यात्रियों को न भुगतना पड़े।

रहें सतर्क

नियंत्रण के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में साइबर अपराध के मामले दिनों-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड या नौकरी के नाम पर या फिर बेटे-बेटी की गिरफ्तारी का भय दिखाकर ठगी के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बीते पांच सालों में साइबर बुलिंग के मामले 88 गुना बढ़ गए हैं। चुनाव के इस मौसम में भी पार्टियों द्वारा भुगतान किए जाने संबंधी झूठे संदेश भेज कर अपराधी ठगी की कोशिश कर रहे। दरअसल, साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण अपेक्षाकृत संख्या में अपराधियों को सजा नहीं मिलना है। केवल राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 11 माह में यहां 1150 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें करीब 75 प्रतिशत मामले लंबित हैं। जाहिर है, उन वजहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिनके कारण जांच का काम अटक जाता है। इसमें एक बड़ी वजह कम्प्यूटर के जानकार अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी तो है ही, इसके अलावा आरोपितों के द्वारा सिम कहीं और से खरीदना, उनके बैंक खाते का किसी और राज्य में होना और उनका लोकेशन कहीं और होना शामिल है। अलग-अलग राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित करने में ही काफी समय बीत जाता है और साइबर अपराधियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जांच के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इसके लिए थाना स्तर पर अनुसंधान अधिकारी के साथ-साथ साइबर एक्सपर्ट की संख्या को बढ़ाने तथा पूरी व्यवस्था की मानीटरिंग के लिए नोडल एजेंसी को पुलिस व आर्थिक अपराध इकाई के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही रकम की वापसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाना आवश्यक है, ताकि पीड़ित को समय पर मदद मिल सके।

जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और आमजन की सतर्कता से ही साइबर अपराध में कमी संभव हो सकेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मायावती का यह कहना सही है कि आकाश आनंद में परिपक्वता की कमी है?

आज का सवाल

क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से कांग्रेस राजनीतिक नुकसान से बच सकेगी?

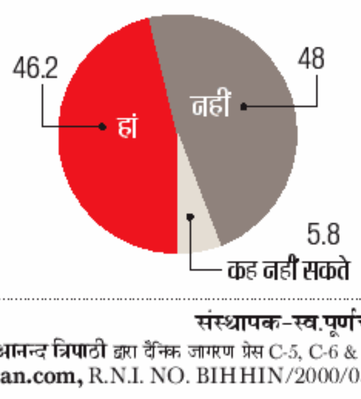

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संसदीय प्रणाली की समस्याएं

आर. विक्रम सिंह

संसदीय प्रणाली की सीमाओं को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करना चाहिए। वैसे भी हमारी व्यवस्था संसदीय है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति वाली है

देश में निर्वाचन पर्व चल रहा है। संभावना है कि एक दल की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। पूर्ण बहुमत की सरकारें वास्तव में हमारी संसदीय प्रणाली का ऐसा उच्चतम शिखर हैं, जो अपने स्वरूप में राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन पद्धति की अनुभूति कराती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। हमारी व्यवस्था संसदीय है, किंतु व्यवहार में वह राष्ट्रपति वाली है। हम नरेन्द्र मोदी को ही प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में लड़ते हुए देख रहे हैं। भाजपा नेता उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक समय नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम पर वोट मांगे जाते थे। यह व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव जैसी ही है। जैसे नेहरू जी देश में कहीं से भी लड़कर चुनाव जीत सकते थे, वैसे ही आज मोदी भी कहीं से भी लड़कर जीत सकते हैं।

बीते सात दशकों में देश ने संसदीय प्रणाली अनुभव लिया है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं। उसमें कुछ अस्थिरता के लक्षण होते हैं, जबकि विकास के लिए स्थिरता आवश्यक है। सीमित आबादी एवं सीमित क्षेत्रफल के एक भाषाभाषी, एक सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रीय स्वरूप के यूरोपीय देशों में संसदीय या वेस्टमिंस्टर प्रणाली सुविधाजनक व्यवस्था हो सकती है, किंतु भारत जैसे देश में जहां बहुलताएं हैं और इन बहुलताओं को राष्ट्रीयता के एक धागे में पिरोए रखना एक मूलभूत राष्ट्रीय आवश्यकता है, वहां देश में अमेरिकी प्रणाली पर भी एक बहस की जरूरत लग रही है। संसदीय प्रणाली के प्रारंभ में हमने नेहरू और इंदिरा जैसे सशक्त प्रधानमंत्री देखे हैं तो कालांतर में वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, चरण सिंह, इंद्रकुमार गुजराल जैसे कमजोर एवं मजबूर प्रधानमंत्री भी देखे। गठबंधनों के माध्यम से किसी प्रकार अपनी सरकार को बचाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को रोकने में असहाय वीपी सिंह की प्राथमिकता अल्पसंख्यक राजनीति थी। राजीव गांधी को जैसे ही भनक लगी कि चंद्रशेखर रामजन्मभूमि मामले में समझौता कराने के निकट हैं तो उन्होंने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। देश ने मनमोहन सिंह जैसे गठबंधन धर्म को मजबूरी बताने वाले प्रधानमंत्री भी देखे हैं।

राष्ट्रपतीय प्रणाली में बंधुआ राष्ट्रपति नहीं हो सकते। इसमें वैकल्पिक या गैरजिम्मेदार सत्ता केंद्र का विकास असंभव है। संसदीय प्रणाली के साथ समस्या यह है कि उसे राष्ट्रीय नेताओं की आवश्यकता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री वही होगा, जिसके पक्ष में अधिकतम सांसद लामबंद हों। इसके लिए बहुत से दलीय हितों के घात-प्रतिघात, क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थों के समायोजन की योग्यता अपेक्षित है। राजीव गांधी, देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह आदि का संघर्ष से उपजा राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं था। गठबंधन सरकारों ने देश को अपने कद एवं क्षमता के अनुरूप खड़ा ही होने नहीं दिया। नेहरू गठबंधन राजनीति के दबाव से मुक्त थे। इसका उपयोग उन्होंने समाजवादी विकास माडल को ढालने में और पंचवर्षीय योजनाओं में लगाया। इस प्रकार देश को एक सशक्त औद्योगिक आधार देने का काम किया। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी भी गठबंधन के दबाव की मजबूरियों से मुक्त हैं। इसका परिणाम हम पिछले दस वर्षों में प्रभावशाली हो रहे भारत के रूप में देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व ऐसा रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की सीमाओं से आगे जाकर उसे गरिमा प्रदान की। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि गठबंधन सरकार चलाने वाले अधिकांश प्रधानमंत्रियों को तरह-तरह के समझौते करने पड़े।

हमारे यहां सक्षम राष्ट्रीय नेताओं के अभाव का मुख्य कारण यह है कि संसदीय प्रणाली राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास की अपेक्षा ही नहीं करती। इसी कारण कुछ ऐसे नेता एकाएक प्रधानमंत्री बन गए, जिनकी देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर किसने सोचा होगा कि देवेगौड़ा, गुजराल या मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन सरकारें वास्तव में राजनीतिक सौदेबाजी करने वाले क्षत्रपों के लिए ही हितकारी होती हैं, जबकि 140 करोड़ की आबादी का विशाल देश ऐसी व्यवस्था चाहता है, जो उसकी समग्र शक्ति एवं क्षमताओं को अभिव्यक्ति दे सके। इसीलिए देश को पूर्ण बहुमत की सशक्त सरकार की अपेक्षा होती है। ऐसी ही सरकार राष्ट्रीय हित से जुड़े दायित्वों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने में समर्थ होती है। भारतीय लोकतंत्र अपनी समस्त शक्ति एकत्रित कर अपने आदर्श नेतृत्व को अधिक से अधिक जितना अधिकार दे सकता है, वह एक अमेरिकी राष्ट्रपति को स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। संसदीय प्रणाली में गठबंधन राजनीति, राजनीतिक जोड़तोड़ की कमजोरियां बाहरी दखल की आशंकाएं बढ़ाते हैं। हमारा देश तो स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा है।

अवधेश राजपूत

मित्रोखिन आर्काइव्स भारतीय राजनीति में सोवियत संघ के दखल का आंख खोलने वाला दस्तावेज है।

राष्ट्रपति प्रणाली जादू की छड़ी भी नहीं है, जो तत्काल सब कुछ सुधार देगी। इसलिए व्यवस्था के चौकीदारों को जागते रहना आवश्यक है। संसदीय प्रणाली सत्ता में भागीदारी की संभावना बढ़ाती है, लेकिन हमारे यहां जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीय समूहों, दबंगों और भ्रष्टतंत्र के हितसाधकों एवं अलगाववादियों की भागीदारी बढ़ाने लगती है। कई क्षेत्रीय दलों में तो समग्र राष्ट्रीय दृष्टि होती भी नहीं है। भारत की अखंडता उनके लिए महत्व का मुद्दा नहीं बनती। वे कई बार तो विदेश नीति को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रणाली देश के नागरिकों से सक्षम राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित करने की अपेक्षा करती है इसलिए देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाले नेतृत्व के सक्षम चरित्र राष्ट्रीय फलक पर दिखने लगेंगे। उनकी संस्कृति की, भाषा की समझ बेहतर होगी। वे कभी बंगाल में, कभी तमिलनाडु में, कभी वनवासियों तो कभी तमिल मछुआरों के बीच रहने वाले होंगे। तब देश में वह राष्ट्रीय कर्मठ एवं समर्पित नेतृत्व आकार लेगा, जिसकी दृष्टि समस्त देश को समाहित किए हुए होगी। अच्छा होगा कि राजनीतिक खानदानों और क्षत्रपों के दिन चले जाएं। देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला कोई नेता जब राष्ट्रपति शैली में चुनाव लड़ेगा तो देश के गांव-गांव में उन्हें वोट देने वाले मिलेंगे और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास की राह स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होगी।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

चुनाव का अर्थ सिर्फ प्रतिनिधि चुनना नहीं

देश में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं और उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए चुनाव से संबंधित समस्त पहलुओं पर समग्रता से चिंतन-मनन करने का यह अनुकूल समय है। इस संदर्भ में दो यक्ष प्रश्न हमारे विचार-प्रक्रिया के केंद्रबिंदु में होने चाहिए। क्या उम्मीदवारों के चयन के लिए 'जीतने की क्षमता' एकमात्र मानदंड होना चाहिए? क्या मतदाताओं को प्रतिनिधियों को केवल स्वीकारने या अस्वीकारने के लिए मतदान करना चाहिए अथवा इससे परे विचार कर मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में अनुभव, सद्कार्यों के जरिये जनता में लोकप्रियता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रहित आदि गुणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास के एजेंडा के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सक्षम होना चाहिए। उनमें समावेशी एवं सतत विकास के लिए जरूरी विमर्श में जनआकांक्षाओं को रेखांकित करने की क्षमता होनी चाहिए।

असल में चुनाव मतदाताओं के लिए कई विकल्प खोलते हैं। उनसे पता चलता है कि कौनसा राजनीतिक दल समसामयिक विषयों पर बेहतर कानून बना सकता है, लोककल्याण के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है, समावेशी एवं टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। किस राजनीतिक दल में संसद एवं संसद के बाहर जनआकांक्षाओं को सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त करने का कौशल है। कौनसा दल वैश्विक शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। यह भी देखना चाहिए कि कौनसे राजनीतिक दल राष्ट्रहित के मुद्दों को ताक पर रखकर मुफ्तखोरी की संस्कृति, जाति, संप्रदाय, धनबल, बाहुबल एवं अन्य प्रभावों के माध्यम से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। चुनाव वास्तविक अर्थों में जनता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में प्रस्तावित विभिन्न माडलों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, विदेश नीति एवं राष्ट्रहित आदि विषयों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने का अवसर होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत इन विषयों से संबंधित सर्वोत्तम माडल को ही जनप्रतिनिधियों के चयन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे जन एवं राष्ट्र-कल्याण के लिए नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनपेगी। चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों का इन बिंदुओं पर ही मूल्यांकन होना चाहिए। लोक कल्याण के लिए तत्पर, निष्पक्ष तरीके से सुशासन करने की क्षमता एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नीतियों के बारे में सोचने तथा नवाचार करने की क्षमता ही उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों के साथ मतदाताओं की भी प्रमुखता होनी चाहिए।

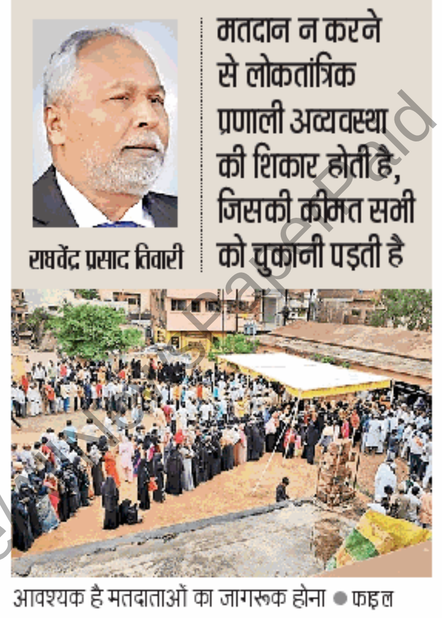

राघवेंद्र प्रसाद तिवारी

मतदान न करने से लोकतांत्रिक प्रणाली अव्यवस्था की शिकार होती है, जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है

आवश्यक है मतदाताओं का जागरूक होना ● फाइल

सार्वजनिक जीवन में जो लोग पुनः चयनित होना चाहते हैं, उन्हें जनता को लोकतंत्र और चुनावों के स्वस्थ तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। प्रचार के दौरान उन्हें विकास एवं सुशासन का वैकल्पिक माडल पेश करना चाहिए तथा अपने पूर्व-प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रबुद्ध समाज को भी सभी दलों के उम्मीदवारों के लिए साझा मंच उपलब्ध कराने चाहिए, जहां सघन विमर्श के द्वारा जनमानस राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पर उनके सोच-समझ के आधार पर समुचित निर्णय ले सकें। राजनीतिक दलों को सही उम्मीदवारों के चयन के लिए बेहतर मानदंड चुनने के लिए बाध्य करने में नोटा सहायक नहीं है। राजनीतिक दलों ने इस प्रविधान से कतई सीख नहीं ली है। पाल टैमब्या नामक विद्वान का मत है कि 'मतदान कोई विवाह नहीं है। यह एक सार्वजनिक परिवहन है। आप उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप बस में चढ़ रहे हैं और यदि कोई बस आपके गंतव्य तक नहीं जा रही है, तो आप घर पर बैठकर उदास नहीं होते। आप वह बस चुनते हैं, जो आपको आपके गंतव्य के सबसे नजदीक ले जाए।' इसका तात्पर्य है कि सर्वोत्तम विकल्प चुनाव से दूर रहना नहीं, अपितु ऐसे उम्मीदवारों का चयन है, जिसकी रीति-नीति आपके जीवन-मूल्यों के सन्निकट हो। इस संदर्भ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। वह उन मुद्दों को रेखांकित करे, जिनसे जनमानस प्रभावित होते हैं और जिनसे उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने में जनता को मदद मिले।

अक्सर कुछ लोग यह सोचकर मतदान करने से बचते हैं कि मेरा वोट कोई महत्व नहीं रखता। यह रवैया सही नहीं है। मतदान के अधिकार का प्रयोग न करने से अयोग्य उम्मीदवार एवं अक्षम सरकार बनने की आशंका बढ़ जाती है एवं लोकतांत्रिक प्रणाली अव्यवस्था की शिकार होती है, जिसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ती है। तथ्य यह है कि मतदान अधिकार के साथ ही राष्ट्रधर्म भी है। अनेक राष्ट्र-नायकों ने भारत को लोकतंत्र की जननी बनाने के लिए बलिदान दिया है। मतदान कर हम उनके जीवन मूल्यों को जीवंत करते हैं। ऐसी सद्भावनाएं ही हमें मतदान के लिए प्रेरित कर सुयोग्य सरकार के गठन में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करेंगी। वास्तव में यह संसदीय चुनाव भारत के लिए दुनिया के समक्ष अनुकरणीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं राष्ट्रधर्म के उच्चतम आदर्श स्थापित करने का अवसर है, जिससे यह भावना दृढ़ हो जाए कि निःसंदेह भारत ही लोकतंत्र की जननी है।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

असाध्य रोग ईर्ष्या

दूसरे व्यक्ति की गुणवत्ता, कौशल, योग्यता को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले जलन के भाव को ईर्ष्या कहा जाता है। मनोविज्ञानियों ने इसे क्रोध, लाचारी और घृणा, इन सभी भावनाओं का एक संयोजन माना है। यह एक मानसिक कष्ट है। इसका संबंध मानवीय मनोवृत्ति से होता है। ईर्ष्या नकारात्मक चिंतन और मानसिक रूप से कमजोर होने का सूचक है। यह निकृष्ट मनोवृत्ति है, जो हमारे मानसिक पटल पर विद्यमान असुरक्षा की भावना को दर्शाती है।

ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर स्वयं की शांति आवश्यक भंग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान तथा आंतरिक उत्थान करने में सदैव असमर्थ ही रहता है। उसकी संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इसी व्यर्थ की ईर्ष्या, द्वेष में ही व्यय हो जाती है। हमारे मनीषियों ने ईर्ष्या को मानसिक पटल पर फैलने वाली महामारी के समान माना है जिसे अगर जल्दी नहीं रोका गया तो वह विनाशक सिद्ध होती है। ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त मनुष्य सदैव असंतुष्ट, तनावग्रस्त तथा दुखी ही रहता है जिससे मनुष्य के चेहरे की सुंदरता भी प्रभावित हो जाती है। जब ईर्ष्या में दूसरे का अनिष्ट करने का भाव आ जाता है तब वह हमारे मानसिक पतन का कारण बन जाती है। यह उस अग्नि की तरह होती है जिसे जंगल स्वयं उत्पन्न करता है और फिर स्वयं इसमें जलकर भस्म हो जाता है।

ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर तथा असहाय बना देती है जिससे मनुष्य अपने जीवन के आनंद से सदैव वंचित ही रहता है। ईर्ष्यालु प्रकृति के मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध कभी भी सुदृढ़ नहीं रह सकते। ईर्ष्या चित्त की एकाग्रता को भंग कर देती है जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी विकृत हो जाता है। दूसरों की समृद्धि के प्रति द्वेष का यह भाव जब मनुष्य के मन में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य अपने स्वयं की मानसिक उन्नति के मार्ग को भी बंद कर लेता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अहम फैसले के इंतजार में देश

'सुप्रीम कोर्ट में पंथनिरपेक्षता की परीक्षा' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने का साहस किया है जिस पर प्रायः कोई भी बोलने का साहस कम ही करता है। आज एक तरफ जहां कट्टरवाद बढ़ा है वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में एक्स मुस्लिमों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ईरान, इराक में तो यह एक आंदोलन का रूप ले रहा है। ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, जो किसी मत-पंथ को नहीं मानते, वे किसी पंथक बंधन में नहीं रहना चाहते और अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जेलों में भी रहना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन देशों का कानून उन्हें पंथ छोड़ने की इजाजत नहीं देता। भारत में अतीत में संविधान में परिवर्तन कर उसमें सेक्युलरिज्म को स्थान दिया गया है। संविधान तो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसी उच्चतम न्यायालय से अपेक्षा भी है। जब न्यायालय सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने के आयोजन, गुजरात में गरबा-दांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा पर राय दे सकता है तो साफिया के केस में क्यों नहीं। वैसे भी साफिया तो एक्स मुस्लिम हैं और भारत में सभी को अपना मत-पंथ चुनने की, अभिव्यक्ति की, अपने तरीके से रहन-सहन की आजादी संविधान देता ही है तो इसमें विरोधाभास कैसा। हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट इस अग्निपरीक्षा में कुंदन बनकर उभरेगा और सेक्युलर भारत की छवि और मजबूत ही करेगा।

विपिन गोयल, हापुड़

आत्मचिंतन करे अमेरिका

बलबीर पुंज द्वारा लिखित आलेख 'बेनकाब होते पश्चिम के दोहरे मानदंड' पढ़ा। अमेरिका और पश्चिमी देश स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की गलतफहमी पाल लिए हैं, इसी भ्रम में वे भारत को उपदेश दिया करते हैं लेकिन स्वयं उन सिद्धांतों पर अमल नहीं करते हैं। कृषि कानून और सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान कनाडा एवं अमेरिका भारत को अभिव्यक्ति की आजादी की नसीहत दे रहे थे। आज अमेरिकी विश्वविद्यालय में अराजकता बढ़ चुकी है, कट्टरपंथी मुस्लिम छात्र संगठन हमास के समर्थन में खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विश्वविद्यालय परिसर में ही अस्थाई रूप से धरना स्थल पर रहने का प्रबंध कर लिया है। अब अमेरिकी सरकार को यह नागवार गुजर रहा है और छात्रों के अस्थाई ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है। आज उसे अभिव्यक्ति की आजादी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन भारत के मामले में वह उपदेश दिया करता था। हमास और इजरायल की जंग धर्म युद्ध का रूप ले रहा है। जिस तरह भारत में सीएए कानून के विरोध को धार्मिक रंग दिया जा रहा था, आज वही प्रयास अमेरिका में हो रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति को यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने वाले और इसराइल को निशाना बनाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने की अनुमति मिलेगी। अमेरिका के लिए यह समय आत्मचिंतन का है, भविष्य में उसे दोहरे मानदंड से बचना चाहिए। कनाडा को भी अमेरिका में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए। क्योंकि वह खालिस्तान समर्थकों के आचरण व वक्तव्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रश्रय दे रहा है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

चुनावी वादों पर सख्त कानून बने

फिर एक बार वादों का अंजाम देखना है। फिर एक बार चुनाव का संग्राम देखना है। 'चिंतित करने वाले चुनावी वादे' शीर्षक से लिखे आलेख में ए. सूर्यप्रकाश ने वाजिब चिंता प्रकट की है। देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल भी बढ़ चढ़ कर अविश्वसनीय वादे कर रहे हैं। क्योंकि कानून में चुनाव प्रचार के समय नेताओं को कोई भी वादा करने की पूरी आजादी है, चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हों या विपक्ष का नेता हो। इस तरह के अविश्वसनीय व भ्रमित करने वाले वादों की रोकथाम के लिए देश में कड़ा कानून बनना चाहिए, ताकि चुनाव जीत कर सरकार बनाने के बाद चुनावी वादे भुलाए नहीं जाएं। इसलिए देश में ऐसा कानून बने कि जिस पार्टी की सरकार बनती है, वह अपने चुनावी वादे व घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करे, वर्ना इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं चुनावी घोषणा पत्रों की निगरानी चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट करे, अगर कोई दल अपनी घोषणा के अनुसार कार्य नहीं करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून ऐसा बने कि नेता झूठे वादे नहीं कर सकें। चुनाव के समय नेताओं की बातों पर मतदाता विशेष ध्यान देते हैं और उस समय यह सोच कर वोट देते हैं कि ये नेता अपने वादे के अनुसार कुछ अच्छा करेगा, परंतु सरकार बनने के बाद उसकी मर्जी से कार्य होने लगता है और घोषणाएं भुला दी जाती हैं। इसलिए कानून आवश्यक है, ताकि देश की जनता को चुनाव के समय कोई बेवकूफ बनाने के बारे में सोचे भी नहीं।

रवि रंजन, नयागांव, सारण

पोस्ट

इस चुनाव में भाजपा का प्रत्येक चौथा और कांग्रेस का हर पांचवां प्रत्याशी दलबदलू है। कांग्रेस ने 1990 के बाद से सबसे अधिक दलबदलुओं को टिकट दिया है, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों की जीत का अनुपात बेहतर नहीं रहा है।

राहुल वर्मा@rahul_tverma

हर तीन में से एक मतदाता मत नहीं डाल रहा। क्या यह मतदाता की उदासीनता है या व्यवस्था के प्रति नाराजगी है या फिर यह सोचना कि मेरे एक मत से क्या होगा? गर्मी का पहलू तो है ही। ऐसे में मतदान को कानूनी तौर पर अनिवार्य करने एवं चुने हुए प्रत्याशी को वापस बुलाने की व्यवस्था लागू की जाए। शिशिर@shishirs2

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी की दलील है कि बीते पांच वर्षों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनावों के लिए जमानत दी जाती रही तो किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव तो चलते ही रहते हैं। जितेंदर शर्मा@capt_ivane

भले केएल राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं या उनका आत्मविश्वास अभी डांवाडोल है, लेकिन वह एक विश्वस्तरीय क्रिकेटर हैं। किसी टीम मालिक के पास उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। सतीश आचार्य@satishacharya

जनपथ

मुंह खोला औ कर दिए 'ब्लनडर' अंकल सैम,
सभी हितैषी कर रहे राहुल के संग गेम।
राहुल के संग गेम प्रकट कर 'गुप्त' इरादा,
सब कुर्सी की राह बन रहे आकर बाधा।
वैसे ही इस बार बंधा दिखता है झोला,
ठोंकी अंतिम कील सैम ने जब मुंह खोला!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 28

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 10 मई 2024

राजनीति इतना गंभीर मामला है कि इसे सिर्फ राजनेताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। -चार्ल्स डे गॉल

एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा कर्मचारियों की बर्खास्तगी का नोटिस वापस लेने पर राजी होने और उनकी बाकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के बाद अब बेशक कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली हो, लेकिन यह पूरा प्रकरण देश के विमानन क्षेत्र में व्यापक सुधारों की जरूरत को रेखांकित करता है।

यह कैसा विरोध

अभी पिछले ही महीने विस्तारा एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ाने रद्द होने के बाद अब ठीक उसी तर्ज पर टाटा समूह की ही दूसरी एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से अधिक केबिन क्रू सदस्यों व अधिकारियों के निर्धारित उड़ान से ऐन पहले सामूहिक रूप से 'सिक लीव' पर जाना चौंकाने वाला तो है ही, यह देश के विमानन क्षेत्र में विद्यमान अव्यवस्था व उथल-पुथल को ही दर्शाता है। इसके असर का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि सौ से अधिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और करीब 15 हजार यात्री प्रभावित हुए। दरअसल, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएक्स कनेक्ट, जिसे पहले एयर एशिया इंडिया कहा जाता था, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की सहायक इकाइयां हैं, जिनके विलय की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के स्टाफ ने इस विलय की शर्तों के विरोधस्वरूप यह कदम उठाया।

लेकिन विरोध जताने और अपनी मांगें रखने का भी एक तरीका होता है। जब यात्री एयरपोर्ट पर अपने विमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक तभी इन कर्मचारियों ने जिस तरह से ई-मेल के जरिये लीव एप्लीकेशन भेजकर तुरंत अपने फोन बंद कर लिए, यह उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये को ही ज्यादा दर्शाता है। दरअसल, जब से टाटा समूह ने एयर इंडिया को अपने अधीन किया है, तब से ही किसी न किसी वजह से विवाद उठते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि टाटा समूह अपनी एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट के विलय की योजना बना रहा है, लेकिन इन एयरलाइंस के पायलट, कर्मचारी व अन्य अधिकारी इस विलय की शर्तों को कथित तौर पर 'समानों के साथ असमान व्यवहार' करने वाली बताते हुए विरोध जता रहे हैं। दरअसल, ऐसी घटनाएं बताती हैं कि देश में विमानन उद्योग अभी परिपक्व नहीं हो सका है। बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी इत्यादि की वजहों से विमानन कंपनियां पहले ही भारी दबाव में हैं।

आंकड़े गवाह हैं कि देश की शीर्ष पांच विमानन कंपनियों में से चार हर साल करोड़ों रुपयों का घाटा सह रही हैं। देश में करीब 90 फीसदी हवाई यात्राएं इंडिगो या फिर टाटा समूह की एयरलाइंस के जरिये होने से देश का विमानन क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के घोर अभाव से जूझ रहा है, लिहाजा किराये में भी वृद्धि हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा बर्खास्तगी का नोटिस वापस लेने पर राजी होने और उनकी बाकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के बाद अब बेशक कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली हो, लेकिन यह पूरा प्रकरण देश के विमानन क्षेत्र में व्यापक सुधारों की जरूरत को रेखांकित करता है, जिसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे।

बहनजी के फैसले के पीछे

बहुजन समाज पार्टी की केंद्रीय रचना ऐसी है, जिसमें मायावती के निर्णयों के विरुद्ध जाने की गुंजाइश नहीं है। आकाश आनंद को उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जब वह अपनी सीमा रेखा लांघने लगे, तो पार्टी सुप्रीमो को उन पर अंकुश लगाना ही था।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद को धूमधाम से राजनीति में लाने के बमुश्किल पांच महीने बाद ही पद से बर्खास्त कर दिया। आकाश आनंद की बर्खास्तगी का यह कठोर कदम उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए बड़ा झटका है।

लोकसभा चुनाव के बीच में उनके इस निर्णय ने पार्टी को अजीब स्थिति में ला दिया है, जिससे पार्टी का चुनावी अभियान भी बाधित हो रहा है। माना जा रहा है कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को सत्ताधारी दल के दबाव में बर्खास्त किया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है।

अजय बोस
राजनीतिक विश्लेषक

असल में, इससे उनका व्यक्तिगत अहंकार भी उजागर होता है, जिसके चलते बहनजी एक चुने हुए उत्तराधिकारी को भी शक्तियां सौंपने के प्रति अनिच्छुक हो गईं।

उल्लेखनीय है कि सीतापुर में चुनावी रैली के दौरान दिए गए आनंद के भड़काऊ भाषण के तत्काल बाद यह विवादास्पद निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि उस रैली में उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जो बुआ मायावती को भी ठीक नहीं लगी। बसपा के इस युवा नेता के साथ चार अन्य लोगों-बसपा उम्मीदवार महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली आयोजक विकास राजवंशी पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ की गई आक्रामक टिप्पणियों को लेकर मायावती अपने भतीजे से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें निजी तौर पर चेताया गया था कि अगर बसपा ने ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में काफी तेज-तर्रार थीं और अपने विरोधियों के खिलाफ

तीखे भाषण देती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने में काफी सावधानी बरती है।

ऐसी अफवाहें भी हैं कि बहनजी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ गुप्त समझौता किया है। हालांकि भाजपा के साथ उनका कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और वह अपने भाषणों और ट्वीट में सरकार की सांकेतिक रूप से आलोचना भी करती रही हैं। अन्य विपक्षी दल उन पर आरोप लगाते हैं कि वह भाजपा विरोधी वोटों को बांटने के लिए विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। बदले में उन्हें पिछले कई दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों में राहत मिली हुई है।

फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने भतीजे को पद से हटाने के पीछे सरकारी दबाव के अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं। जब बीमार कांशीराम ने बसपा की बागडोर उन्हें सौंपी थी, उस समय भी उन्होंने किसी अन्य पार्टी नेता के साथ सत्ता साझा करने से इन्कार कर दिया था और पार्टी नेताओं से सिर्फ वफादारी ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की मांग की थी। वैसे भी आजकल ज्यादातर पार्टियों में एक सर्वोच्च नेता का वर्चस्व बढ़ रहा है और बसपा में तो बहनजी एक अनोखे पद पर आसीन हैं ही।

दिलचस्प तथ्य यह है कि पांच साल पहले जब नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, तो उसके एक हफ्ते बाद ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था। कुछ वर्षों बाद बसपा सुप्रीमो ने सार्वजनिक रूप से आनंद की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने लंबे समय से अपने कानूनी सलाहकार और विश्वासपात्र रहे सतीशचंद्र मिश्र पर वरीयता देते हुए आनंद को अपने बाद पार्टी का दूसरा स्टार प्रचारक बनाया था।

इसलिए कुछ महीने पहले जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, तो ऐसा लगा कि बसपा ने अब अपने भविष्य की रूप-रेखा तैयार कर ली है, जो एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। इससे भी बड़ी बात यह कि आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता की काट माना जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश में बसपा के गढ़ में सेंध लगाना चाह रहे हैं। लेकिन भतीजे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते वक्त भी बहनजी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश एवं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में पार्टी से जुड़े सभी मामले वह स्वयं देखेंगी, जबकि आनंद देश के अन्य राज्यों का कामकाज संभालेंगे।

लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव प्रचार की गर्मी जैसे ही बढ़ने लगी, वह उत्साही युवा यह भूल गया कि उसकी अहंकारी बुआ ने उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी है। बताया जाता है कि आनंद ने अपने उग्र चुनावी भाषणों से युवा दलितों के बीच खुद को फायरब्रांड नेता के रूप में पेश करने के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की। आनंद की चुनाव प्रचार की यह उग्र बयानबाजी उनकी डरी-सहमी बुआ से बिल्कुल अलग थी, जो उसकी बर्खास्तगी का कारण बनी।

अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि अपने उभरते हुए दलित युवा नेता और कुशल वक्ता को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए पद से हटाकर बहुजन समाज पार्टी, जो कभी दलित राजनीति की ताकत मानी जाती थी, ने अपने राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है, और अपने पुराने खोखले आवरण में सिमट गई है। मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को भाजपा सरकार पर हमले के बाद यह कहकर हटा दिया कि वह अभी परिपक्व नहीं है। इससे एक स्वतंत्र नेता के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। बसपा का जनाधार पहले ही काफी घट चुका है। ऐसे में, इससे दलित उपजाति जाटव का भी उससे मोहभंग होगा। इससे भाजपा और इंडिया गठबंधन, दोनों को लाभ हो सकता है। इसके अलावा दलित मतदाताओं की मतदान करने में भी रुचि घटेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, वह कोई अंधकारमय भाग्य नहीं, बल्कि हमारा अपना ही अतीत है। सही ढंग से समझाया गया कर्म केवल यह कहता है कि प्रत्येक कार्य पिछली स्थितियों का अपरिहार्य परिणाम ही है।

अच्छे कर्मों से ही मनुष्य अच्छा बनता है

***नैतिक** जगत में कर्म का नियम एकरूपता के भौतिक नियम का प्रतिरूप है। यह नैतिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार, नैतिक जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हम वही काटते हैं, जो बोते हैं। अच्छा बीज अच्छाई की फसल लाता है और बुरा बीज बुराई की फसल। छोटे कार्य का भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जानता है कि कार्य करने की कुछ प्रवृत्तियां जो अब उसमें विद्यमान हैं, वे उसके सचेत या बुद्धिमान विकल्प का ही परिणाम हैं। सचेतन क्रियाएं अचेतन आदतें बन जाती हैं और अस्वाभाविक रूप से हम स्वयं में जो अचेतन प्रवृत्तियां पाते हैं, उन्हें पिछले सचेतन कार्यों का परिणाम माना जाता है। नैतिक विकास की प्रक्रिया को हम तब तक नहीं रोक सकते, जब तक हम ज्वार-भाटे को नहीं रोक सकते। कर्म के नियम को लांघने का प्रयास उतना ही निरर्थक है, जितना कि किसी छाया को लांघने का प्रयास।*

यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हमारा जीवन अपने भीतर एक रिकॉर्ड रखता है, जिसे न तो मनुष्य धुंधला कर सकता है, न ही मृत्यु मिटा सकती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा बनता है। मनुष्य इच्छाशक्ति वाला प्राणी है। जैसा वह इस संसार में विश्वास करता है, वैसा ही वह इस संसार से चले जाने पर भी करेगा। इसलिए हमसे हमेशा अच्छा करने के लिए कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत अपने दायरे में मनुष्यों, देवताओं, जानवरों और पेड़-पौधों यानी समस्त जीव-जगत को शामिल करता है।

कर्म के सिद्धांत में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पर जोर दिया गया है। दरअसल, जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है वह कोई अंधकारमय भाग्य नहीं, बल्कि हमारा अपना अतीत ही है। सही ढंग से समझाया गया कर्म केवल यह कहता है कि प्रत्येक कार्य पिछली स्थितियों का अपरिहार्य परिणाम ही है। कर्म के नियम का मनुष्य की आध्यात्मिकता से कोई लेना-देना नहीं है। मनुष्य में मौजूद अनंत उसे सीमित की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। आत्मा का सार तो मुक्ति है। आध्यात्मिकता के अभ्यास से मनुष्य अपने स्वाभाविक आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि उसका जीवन यंत्रवत निर्धारित अवस्थाओं के क्रम से कहीं अधिक है। स्वतंत्र होने के लिए उसके कार्य आतंरिक आत्मा की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त करने वाले होने चाहिए। यदि मनुष्य केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का योग होता, तो वह पूरी तरह से कर्म के नियम के अधीन होता। लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है, जो मालिक है। कोई भी बाहरी चीज इसे मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया की भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों के सामने झुकना होगा। इसी तरह कर्म के नियम को आत्मा की स्वतंत्रता के अधीन किया जा सकता है। मनुष्य को सर्वोच्च स्वतंत्रता तभी मिल सकती है, जब वह ईश्वर के साथ एक हो जाए। आत्म अनुशासन द्वारा हम अच्छे आवेगों को मजबूत कर सकते हैं।

जो भी करें, अच्छा करें

सूत्र

प्रत्येक कर्म मनुष्य के मन पर प्रभाव छोड़ जाता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति का भी निर्माण करता है। यह प्रवृत्ति या संस्कार या वासना ही है, जो हमें उस कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित करती है, जो हम एक बार पहले कर चुके हैं। इसलिए सभी कर्मों के फलों का प्रभाव मन पर पड़ता है।

दूसरा पहलू

बहादुरशाह जफर के समर्पण के बाद फिरंगियों की मंशा थी कि क्रांतिकारियों का हौसला पस्त करने के लिए उनका कोर्ट मार्शल किया जाए।

मई क्रांति और जफर के खिलाफ मनमाना कोर्ट मार्शल

आज से कोई 167 साल पहले 10 मई, 1857 को मेरठ से भड़की चिंगारी की आग दिल्ली और लाल किला तक पहुंच गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए मेरठ के उन सैनिकों की ख्वाहिश थी कि मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर इस मुहिम की अगुवाई करें। विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ यह आग मेरठ से दिल्ली, तत्कालीन संयुक्त प्रांत, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों, अवध और बिहार तक फैल चुकी थी। हालांकि 82 साल का बूढ़ा बादशाह जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। एक तरफ क्रांतिकारियों की मनुहार थी और दूसरी तरफ फिरंगियों की निर्मम हुकूमत। इस द्वंद्व की स्थिति में 21 सितंबर को जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद फिरंगियों ने इस कदर दमन, उत्पीड़न किया और लूट-खसोट मचाई कि दिल्ली थर्रा उठी थी। फिरंगियों की मंशा थी कि क्रांति के दीवानों का हौसला पस्त हो जाए। आखिरकार बादशाह का कोर्ट मार्शल किए जाने का निर्णय हुआ।

विनोद पुरोहित

1857 की क्रांति के दौर की कई परतें खोलती हैं इतिहास के प्रसिद्ध लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा की किताब-*आखिरी मुगल बादशाह का कोर्ट मार्शल।*

फिरंगियों का उद्देश्य भारतीय जनमानस को यह संदेश देना था कि अब वे ही देश के शासक हैं। इस मुकदमे ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्रूर चेहरा उजागर कर दिया था।

उस दौर की ऐसी कई परतें खोलती है इतिहास के प्रसिद्ध लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा की किताब-आखिरी मुगल बादशाह का कोर्ट मार्शल। इसमें फिरंगी हुकूमत की मनमानियों का खुलासा है। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही लाल किले के दीवान-ए-खास में 21 दिनों तक चली। बादशाह को न बचाव का मौका दिया गया, न पूर्णकालिक वकील और न ही अपील का अधिकार। किताब सवाल उठाती है कि किसी कंपनी को मुल्क के बादशाह पर मुकदमा चलाने का अधिकार कहां से और कैसे मिला? बादशाह को अपदस्थ करने से तीन माह पूर्व की तारीखों में राजाज्ञाएं जारी करने का षड्यंत्र रचा गया। फिरंगियों का उद्देश्य भारतीय जनमानस को यह संदेश देना था कि अब वे ही देश के शासक हैं। इस मुकदमे ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्रूर चेहरा उजागर कर दिया था। समर्पण के वादे के मुताबिक सजा तो नहीं दी गई, लेकिन अवैध रूप से चलाए गए कोर्ट मार्शल के निर्णय में जफर को विद्रोह करने व क्रांतिकारियों को भड़काने का दोषी पाया गया। उन्हें निर्वासन में रंगून में जिस दुर्दशा में रखा गया, वह एक अलग दास्तां है। उन्हें कलम, कागज और स्याही तक नहीं दी गई। यहां तक कि 7 नवंबर, 1862 को बहादुरशाह जफर की मृत्यु के बाद लोगों को उनके अंतिम दर्शन की इजाजत भी नहीं दी गई।

आंकड़े

गेहूं आयातक देश

भारत का गेहूं निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा मूल्य के गेहूं का आयात बांग्लादेश ने किया।

स्रोत: DGCIS

माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान-पुण्य के कारण ही धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा बने।

दान का महत्व

अंतर्यात्रा
संकलित

प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक व्यक्ति थे, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे-से गांव में रहते थे। गरीब होने के कारण वह हमेशा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए चिंतित रहते थे।

धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण धर्मदास की पूजा-पाठ और दान-पुण्य में अगाध श्रद्धा थी। धर्मदास को दान करते देखकर उसके परिवार के लोग उन्हें रोकते रहते थे। फिर भी धर्मदास दान-पुण्य के कार्य से कभी विचलित नहीं हुए। अक्षय तृतीया के दिन वह खूब दान-पुण्य किया करते थे। वृद्ध होने के उपरांत भी उन्होंने उपवास करके धर्म-कर्म और दान-पुण्य किया।

वही धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान-पुण्य के कारण ही वह अपने अगले जन्म में धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतने धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में महायज्ञ में शामिल होते थे।

फिर भी अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ, वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 अगस्त, 1986

घुसपैठ रोकने के लिए भारत व बांग्लादेश सहमत

घुसपैठ रोकने हेतु भारत व बंगला देश सहमत

नई दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता)। असम में बंगलादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिये भारत और बंगलादेश उचित कदम उठाने के लिये सहमत हो गये है।

यह जानकारी विदेशमंत्री श्री पी.शिवशंकर ने आज ढाका की दो दिवसीय यात्रा से लौटने पर दी।

उन्होंने बताया कि दोनों देशों के अधिकारी इसके लिये उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा कर करेंगे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने में बंगलादेश ने पूरे सहायता देने का आश्वासन दिया है।

श्री शिवशंकर ने कहा कि बंगलादेश के विदेशमंत्री हुमायूं रशीद ने उन्हें बताया कि बंगलादेश सरकार

असम में बांग्लादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश उचित कदम उठाने के लिए सहमत हो गए हैं। यह जानकारी विदेशमंत्री पी शिवशंकर ने ढाका से लौटने पर दी।

फारूख अब्दुल्ला और चूड़ियों की बात

पाकिस्तान से वार्ता कश्मीर के राजनीतिक दलों का प्रिय एजेंडा रहा है, क्योंकि तभी उनकी भूमिका बरकरार रहेगी, अन्यथा वे असुरक्षित हो जाएंगे।

आर.विक्रम सिंह — सियासत

उन्होंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। उनके पास भी एटम बम हैं, वे हमारे ऊपर ही गिरेंगे। यह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के पीओके के स्वयं भारत में आकर मर्ज होने के बयान पर फारूख अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया है, जिससे देश का हर व्यक्ति हैरान है। पाठकों को याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने भी आगरा समिट के समय कहा था, 'हमने कौन-सी चूड़ियां पहन रखी हैं!' लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को वही डायलॉग याद था।

साफ है कि फारूख अब्दुल्ला ने फिर से वही पुराना राग छेड़ दिया है। एक दिन पहले वायुसेना की गाड़ियों के काफिले पर पुंछ में हुए आतंकी हमले में हमारा एक वायुसैनिक बलिदान हो गया और चार घायल हो गए। सेना आतंकियों को खोजने में लगी थी और फारूख अब्दुल्ला टिप्पणी कर रहे थे कि जब तक भारत और पाकिस्तान में वार्ता नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। चीन से बात हो रही है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं?

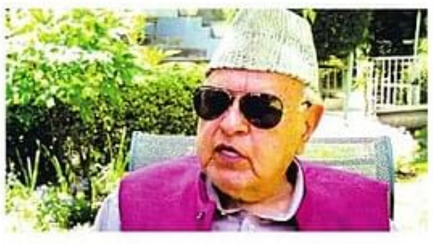

दरअसल, फारूख का भय वही है, जो कभी शेख अब्दुल्ला का था। वह भय है पीओके की भारत में वापसी का। गौरतलब है कि 1947 में कबाइली आक्रमण के बाद भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ना प्रारंभ किया, तो बड़ी संख्या में कबायली मारे गए और बहुत से भाग गए। उनका पीछा कर रही हमारी सेना को अचानक उड़ी में रोक दिया गया। यह आदेश माउंटबेटन व नेहरू के अलावा कोई दे भी नहीं सकता था। उरी से आगे के इलाके में कश्मीरी नहीं बोली जाती। वह पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी बोलने वाले गूजर बकरवालों, पंजाबियों, राजपूतों का इलाका है। वे शेख अब्दुल्ला के समर्थक नहीं थे। उनके भारत में रहने से शेख के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौतियां मिलतीं। इसलिए पीओके को जान-बूझकर पाकिस्तान के कब्जे में जाने दिया गया।

आज यदि पीओके व गिलगित-बालटिस्तान भारत में वापस आ गया, तो घाटी में फारूख के खानदानी वर्चस्व की संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। इसलिए फारूख अब्दुल्ला चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो, ताकि कोई ऐसा समझौता हो जाए कि पीओके व गिलगित-बालटिस्तान भारत में न आ सके और नियंत्रण रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया जाए। इसलिए फारूख के ऐसे बयान आते रहे हैं और आते रहेंगे।

इन दिनों कश्मीर में भी वहां की पांच संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। संभावना है कि पिछले वर्षों के 5-10 फीसदी की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी होगी। बारामूला से उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग-राजौरी से महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार हैं। ये चुनावों में पाकिस्तान एवं अलगावावाद को मुद्दा बनाते रहे हैं। इसलिए मौका मिलते ही फारूख ने अपना खानदानी पाकिस्तान कार्ड चल दिया, जो उनके पिता भी अक्सर चला करते थे। बहरहाल, तब से अब तक झेलम में बहुत पानी बह गया है। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने, कश्मीर व लद्दाख के अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बन जाने के बाद अब यह चुनाव जम्मू व कश्मीर की जनभावनाओं का लिटमस टेस्ट जैसा है। पूर्ण राज्य से कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बना देने और फिर कश्मीर के औद्योगिकीकरण के साथ आर्थिक व बुनियादी संरचना विकास और रोजगार का अभियान चलाने से एक मिला-जुला परिदृश्य उभरा है। आम मतदाता समझते हैं कि रेल नेटवर्क, हाईवे यातायात का विकास व परिणामस्वरूप पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं कश्मीर का भाग्य बदल देंगी। लेकिन देखना होगा कि इन सब सकारात्मक परिवर्तनों का असर चुनावों में आम आदमी की सोच पर किस तरह से पड़ने वाला है।

पाकिस्तान से वार्ता शुरू से ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, का प्रिय एजेंडा रहा है। उन्होंने घाटी में आतंकियों व आईएसआई की दहशत के लंबे दौर देखे भी हैं। वे पाकिस्तान की भूमिका का समापन नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि दोनों मुल्कों की राजनीतिक शतरंज में कश्मीर की खुदमुख्तारी का मुद्दा बना रहे। तभी कश्मीर की राजनीति में उनकी भूमिका बरकरार रहेगी, अन्यथा वे अप्रासंगिक व असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए उन्हें पाकिस्तान फैक्टर की जरूरत महसूस हो रही है। मगर अब घाटी की हवा बदल रही है। अब कश्मीर के लोगों को मजहबी व क्षेत्रीय सीमाओं में बांधे रखना मुश्किल होता जाएगा। अलगाववाद, ब्लैकमनी व ब्लैकमेल के जरिये राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले धीरे-धीरे हाशिये पर चले जाएंगे।

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

आर्थिक असमानता कम करने में बनें मददगार

दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पचास शहरों की सूची में भारत के मुम्बई व दिल्ली का नाम भी आया है। साथ ही बेंगलूरु को अगले दशक के सबसे तेज बढ़ते करोड़पतियों के शहर के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं एक खबर यह भी है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वर्ष 2022 में प्रवासी भारतीयों ने सबसे ज्यादा धन अपने घर भेजा। दोनों ही तथ्य देश में बढ़ती समृद्धि की ओर संकेत करते हैं। लेकिन इस उपलब्धि का धुंधला पक्ष यह भी है कि हमारे यहां आर्थिक असमानता के बीच खाई घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। सीधे तौर पर कहें तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब।

इसमें दो राय नहीं है कि हमारे महानगर कारोबारी दृष्टि से बड़े केन्द्र हैं। औद्योगिक प्रगति व निवेशकों के लिए बनने वाले अनुकूल माहौल के कारण भी महानगरों में तरक्की की रफ्तार ज्यादा होती है। मुम्बई और दिल्ली में करोड़पतियों की संख्या में अस्सी फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। ऐसी ग्रोथ जब भी होती है तो अमीर-गरीब के बीच खाई को कम करने के प्रयासों को और गति देने की जरूरत भी महसूस होती है। यह बात सही है कि कोरोना के बाद युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था भी संकट से गुजर रही है, लेकिन भारत ने इस दिशा में संतोषजनक प्रगति की है। पिछले डेढ़ दशक में ही जो प्रयास किए गए, उनसे करोड़ों लोग गरीबी से उबरने में सफल हुए हैं। दो माह पहले ही एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि अगले पांच साल में भारत में 'सुपर रिच' लोगों की तादाद बढ़ेगी।

यह भी एक तथ्य है कि आर्थिक असमानता की बड़ी वजह कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं होना भी है। एक तरफ करोड़पतियों के शहरों की सूची में हमारे देश के शहरों के नाम गौरव की अनुभूति देते हैं तो दूसरी ओर यह तथ्य भी चिंता पैदा करता है कि आबादी का बड़ा हिस्सा अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कर ही नहीं पा रहा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे कारण इसके लिए जिम्मेदार तो होते ही हैं, अमीर होते लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। ऐसा इसलिए कि जो लोग 'सुपर रिच' की श्रेणी में आ रहे हैं, वे असमानता दूर करने की दिशा में खास रुचि नहीं दिखाते। यह भी एक तथ्य है कि यह वर्ग भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद ही करोड़पतियों की श्रेणी में आया है। करोड़पतियों के शहर बढ़ने चाहिए, लेकिन इस वर्ग को गरीब लोगों के लिए आय के अधिक साधन उपलब्ध कराने में मददगार बनना होगा, तब जाकर ही आर्थिक असमानता कम हो सकेगी।

बिहार : पिछली बार त्रिकोणीय लड़ाई में बेगूसराय से आसानी से जीत गए थे गिरिराज सिंह

'मिनी मास्को' में लाल और भगवा रंग में संघर्ष बयानों के तीर से चुनावी माहौल में भी गर्मी

बेगूसराय का नाता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से भी है। सिमरिया में जन्मे दिनकर की वीर रस की कविताएं लोगों में जोश भर देती थीं।

बेगूसराय से
नवनीत मिश्र

जनसंपर्क के दौरान गिरिराज सिंह

क्षेत्र में प्रचार के दौरान अवधेश राय

देश की जिन कुछ लोकसभा सीटों पर वामपंथ का मजबूत असर है, उनमें बेगूसराय प्रमुख है। वामपंथ का गढ़ होने के कारण कोई बेगूसराय को 'पूरब का लेनिनग्राद' कहता है तो कोई 'मिनी मास्को'। चुनावी माहौल टटोलने के लिए पटना से तपती दोपहरी में 3 घंटे का सफर पूरा कर यहां हम पहुंचे तो लेफ्ट के लाल और भाजपा के भगवा रंग के बीच जमीन पर संघर्ष नजर आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीट पर भाजपा की भगवा लहर बरकरार रखने की कोशिश में जुटे हैं तो राजद और कांग्रेस समर्थित लेफ्ट उम्मीदवार अवधेश राय जातीय-सामाजिक समीकरणों के सहारे बेगूसराय पर तीन दशक बाद लाल रंग चढ़ाना चाहते हैं। बेगूसराय का नाता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से है। यहां के सिमरिया में जन्मे दिनकर जी वीर रस की ऐसी कविताएं लिखते थे कि लोगों की बाजुएं फड़फड़ा उठती थीं। इन दिनों यहां पक्ष-विपक्ष के बयान खूब सुर्खियों में हैं। विपक्ष निशाना साधता है कि गिरिराज सिंह ऐसे नेता हैं, जो बात-बात पर पाकिस्तान तक धावा बोल देते हैं। लेफ्ट उम्मीदवार अवधेश राय ने तो यहां तक कह दिया कि शिखा रखने और चंदन लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। उधर, गिरिराज सिंह चुनावी सभाओं में स्पष्ट कहते हैं- मुझे पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों के वोट नहीं चाहिए।

इस बार मामला आरपार

पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले में लेफ्ट उम्मीदवार और जेएनयू के चर्चित छात्रसंघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा मतों के भारी भरकम अंतर से हराने में सफल रहे गिरिराज सिंह के लिए इस बार बदले समीकरण कुछ चुनौती पेश कर रहे हैं। वजह कि इस बार विपक्ष ने एक ही उम्मीदवार खड़ा किया है। लेफ्ट उम्मीदवार अवधेश राय को राजद और कांग्रेस का मजबूत समर्थन मिल रहा है। कहा जाता है कि पिछली बार लेफ्ट से कन्हैया कुमार को टिकट मिलना लालू यादव को रास नहीं आया था तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए आरजेडी से तनवीर हसन को उतार दिया था, जो 2014 में भाजपा उम्मीदवार भोलासिंह से 58 हजार वोटों से हार गए थे। तब आरजेडी के तनवीर हसन 1.98 लाख वोट काटने में सफल रहे थे और कन्हैया को 2.67 लाख वोट मिले थे। महागठबंधन के वोटों के बिखराव से गिरिराज सिंह आसानी से जीतने में सफल रहे थे। इस बार मुकाबला आमने-सामने का है। ऐसे में गिरिराज सिंह मोदी मैजिक, हिंदुत्व, डबल इंजन(मोदी-नीतीश) सरकार के विकास की डोज से मैदान मारना चाहते हैं तो पिछड़ी जाति के अवधेश राय जातीय समीकरणों और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे बाजी पटलने की फिराक में हैं। गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैंती, बाया और चंद्रभागा नदियों वाले बेगूसराय में एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झीलों में से एक कावर झील भी है। सात विधानसभा वाले बेगूसराय में तीन सीट एनडीए के पास तो दो-दो राजद और सीपीएम के पास हैं।

बेगूसराय के प्रमुख मुद्दे

- दिनकर के नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
- रेल कारखाने की स्थापना
- पेट्रोकेमिकल्स फूड प्रोसेसिंग प्लांट
- हवाई अड्डे का निर्माण
- राजधानी आदि सुपर फास्ट ट्रेनों का ठहराव

2019 जैसा रोचक नहीं है चुनाव

स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि बेगूसराय में इस बार 2019 जैसा रोचक चुनाव नहीं है। कारण हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया भले ही 4 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे, लेकिन उनकी वजह से यह देश की सबसे चर्चित सीट बन गई थी। तब कन्हैया कुमार के समर्थन में फिल्मी सितारे प्रकाश राज, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर ने यहां प्रचार कर ग्लैमर का तड़का लगाया था। इस बार लेफ्ट से अवधेश राय के चुनाव लड़ने से उतना आकर्षण नहीं दिख रहा है। बेगूसराय में 2009 को छोड़ दिया जाए तो हमेशा अगड़ी जाति के भूमिहार ही यहां से सांसद बनते आए हैं।

बंद होते कल कारखाने भी मुद्दा

बेगूसराय क्षेत्र में कभी 200 से ज्यादा कल-कारखाने थे, लेकिन सरकारी उदासीनता आदि कारणों से अधिकतर बंद हो चुके हैं। ये मुद्दे चुनाव में गूंज रहे हैं। व्यवसाई प्रदीप कुमार कहते हैं कि राज्य की सरकारों ने कभी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कच्चे माल और बाजार के अभाव में यहां के कल-कारखाने बंद होते गए। फिलहाल बरौनी में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के कारखाने यहां की प्रतिष्ठा बचाए हुए हैं। यहां मोमबत्ती, कार्बन, अलकतरा आदि का उद्योग चल रहा था। शिक्षा की बात करें तो यहां उच्च शिक्षा के कई शिक्षण संस्थान हैं।

क्या कहती है जनता

यहां मतदाताओं से बात करने पर पता चलता है कि ब्रांड मोदी अब भी मजबूत है। कई मतदाता ऐसे मिले, जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन उन्हें अंतिम उम्मीद भी मोदी से ही है। पटना से बेगूसराय जाने वाली सड़क किनारे मिले राजेंद्र कुमार मुझसे ही सवाल पूछते हुए कहते हैं- मोदी के मुकाबले कौन है? महागठबंधन ने किसी को चेहरा बनाया होता तो तुलना कर वोट करते, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। सुनीता देवी कहती हैं कि जमीन का दो हजार रुपया खाते में आता है, राशन भी मिलता है, तो क्यों न मोदी को वोट करें। हालांकि, कुछ युवाओं में मोदी सरकार से गहरी नाराजगी दिखी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सुशील, राकेश आदि युवाओं का कहना है कि उन्हें मोदी सरकार ने निराश किया है। पिछली बार उन्होंने मोदी को वोट दिया था, लेकिन इस बार वो वोट नहीं करेंगे। तस्लीम और विकास यादव ने कहा कि जब डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की भर्ती कराई तो मुख्यमंत्री होने पर बहुत कुछ करेंगे। इसलिए इस चुनाव में भी तेजस्वी को मजबूत करना जरूरी है।

अक्षय तृतीया आज : सख्ती और समझाइश हो

बाल विवाह को तिलांजलि देने का अबूझ मुहूर्त

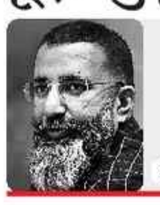

भुवन ऋभु
बाल अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत
@patrika.com

विवाह के लिए शुभ माने जाने वाले अक्षय तृतीया पर बड़े पैमाने पर बाल विवाह को एक तरह से सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। बच्चियों का जीवन बचाने के लिए बाल विवाह की कुरीति को खत्म करना आवश्यक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएचएफएस) के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में भी हर चौथी लड़की का विवाह उसके 18 साल की होने से पहले ही हो जाता है। देश के 257 जिले ऐसे हैं जहां बाल विवाह की दर 23.3 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

बाल विवाह को रोकने के लिए देश में प्रयास हो रहे हैं। पिछले साल 2023 में हमने बाल विवाह के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लामबंदी देखी। विभिन्न राज्यों के 54 सरकारी विभागों के नेतृत्व में चली इस मुहिम में 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत पांच करोड़ भारतवासियों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। बाल विवाह के खिलाफ अलख जगाने हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरीं। बाल विवाह के पूरी तरह से खात्मे की उनकी मांग को बच्चों, बिरादरी के सदस्यों, गांवों-कस्बों के बुजुर्गों, पंचायत सदस्यों, सरकारी प्रतिनिधियों और गैरसरकारी संगठनों सहित तमाम अन्य लोगों का सहयोग व समर्थन मिला। सुदूर इलाकों में जमीन पर अभियान चला रहे संगठनों के लिए यह अक्षय तृतीया परीक्षा की घड़ी है जब उन्हें पांच करोड़ लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने के नतीजे देखने को मिलेंगे। 'रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई' की परंपरा वाले इस देश में वचन की एक पवित्रता रही है और माना जा सकता है कि जिन लोगों ने यह शपथ ली है, वे उसे तोड़ेंगे नहीं।

फिर भी चौकस रहते हुए राज्य सरकारों को अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाहों के चलन को चुनौती के साथ अवसर के रूप में देखना चाहिए कि किस तरह जागरूकता के प्रसार और कानून के चाबुक से वे इसे रोक सकते हैं। जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों में कार्यशालाएं, नक्कड़ नाटक और विवाह करने जा रहे लड़के और लड़की की उम्र की जांच जैसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अगर कुछ और चाहते हैं तो लोगों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे विवाह के निमंत्रण पत्र पर लड़के व लड़की की जन्मतिथि अंकित करें।

बाल विवाह रोकने के लिए बने कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 का कड़ाई से अमल सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यह बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार बाल कल्याण समितियों जैसी एजेंसियों को बाल विवाह रोकने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान स्टे आर्डर या निषेधाज्ञा जारी करने जैसी शक्तियां देकर सुनिश्चित किया जा सकता है। बाल विवाह की रोकथाम में पंचायतों की भूमिका अहम हो सकती है। असम में वर्ष 2023 से जारी अभियान तमाम राज्य सरकारों के लिए एक उदाहरण पेश करता है कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कानूनी उपायों का इस्तेमाल कितना प्रभावी भूमिका निभा सकता है। 18 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा करके राजनीतिक दल यह दिखा सकते हैं कि वे बाल विवाह की कुरीति के खात्मे के लिए गंभीर हैं। स्वस्थ, सुशिक्षित एवं समृद्ध नागरिक किसी भी लोकतंत्र के खाद-पानी हैं। इसलिए बाल विवाह को रोकना जरूरी है।

कमल खिलावन — POLI नोक-झोंक — पंजा सिंह

स्टार प्रचारक - चचा सैम

***(तीन चरण पूरे।** चौथे चरण की तैयारी। हैदराबाद का घांसी बाजार। बिरयानी खाते बतियाते दो पुराने चावल।)*

***कमल खिलावन :** तेलंगाना भूल ही जाओ, इस बार जबरा सपोर्ट है पब्लिक का हमें।*

***पंजा सिंह:** पिछली बार 4 मिली थीं आपको यहां, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 17 की 17 जिता रहे हैं क्या ?*

***कमल खिलावन :** तुम्हारी खुद की 3 थी। हमसे कम। पर तीन चरण में कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारा। पब्लिक फुल सपोर्ट में।*

***पंजा सिंह:** पहले चरण के बाद तो हवाइयां उड़ गईं। घर-घर कैंपेनिंग बढ़ा दी।*

***कमल खिलावन:** यो ब्रो। इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं। अब तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अपडेट हो गई।*

***पंजा सिंह:** हें.. ये क्या नई बला। वो तो चुनाव से पहले ही आ गई थी।*

***कमल खिलावन:** अपडेट हुई है।*

***पंजा सिंह :** वाह, कौन-कौन से नए नाम हैं ?*

***कमल खिलावन :** पहले नंबर पर चचा सैम। तुम्हारे ओवरसीज वाले चचा सैम।*

***पंजा सिंह:** तो क्या वो भी तुम्हारे पाले में...*

***कमल खिलावन:** न .. ना। हैं तुम्हारे पाले में ही, बयान हमारे लिए दे रहे हैं।*

***पंजा सिंह:** अमां जाओ.. कुछ भी बोलते हो। स्टार प्रचारक।*

***कमल खिलावन:** और क्या! हम तो हर चुनाव में कहते ही यही हैं, तुम्हारे कुछ लोग रैली पंजे के नीचे करते हैं, वोट फूल के बढ़ाते हैं। तो हमारे ही स्टार प्रचारक हुए न!*

***पंजा सिंह:** कुछ भी...।*

***कमल खिलावन:** सच्ची।*

***पंजा सिंह:** कौन हैं तो बोलो।*

***कमल खिलावन :** एमपी वाले दिग्गी भैया। जब-जब बोले हमारी मौज। इस बार चुनाव में उलझा दिया तुमने। इसलिए हमारी मदद नहीं कर पाए।*

***पंजा सिंह:** और..*

***कमल खिलावन:** मणि काका। जब-जब बोले.. वोटों के द्वार खोले.. हमारे.. पर ये भी इस बार कुछ बोले ही नहीं। मिस किया...*

***पंजा सिंह:** तो सख्त हिदायत हैं ऊपर से.. मुंह पर उंगली।*

***कमल खिलावन:** 'ऊपर' के क्या कहने। वो भी हमारे ही स्टार प्रचारक हैं।*

***पंजा सिंह:** ओ.. भाई। हद की भी कोई हद होती है। हद में रहो।*

***कमल खिलावन:** मैं थोड़ी न कह रहा हूं। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म खोल लो। स्टैंड अप कॉमेडियंस से ज्यादा कॉमेडी वीडियो तुम्हारे वाले के नजर आते हैं।*

***पंजा सिंह:** एल्गोरिदम जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हीं ने लोग लगा रखे हैं।*

***कमल खिलावन:** सच में दोस्त, हम तो हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर तुम्हारे वाले का नाम मान कर चलते हैं।*

***पंजा सिंह:** तुम्हारी तरह प्रोपेगंडा नहीं करते। तिल को ताड़ नहीं बनाते। और जहां तक बात ओवरसीज वालों की है, दुनिया की एक बड़ी शख्सियत हैं। पद्म पुरस्कार विजेता। थिंकर.. थिंक टैंक। सुने भी हैं कभी ये शब्द।*

***कमल खिलावन:** फिलहाल तो उनके भाषण सुने। पहले अमरीका का विरासत टैक्स अब विविधता में एकता के साथ 'रंगभेद'। पहले भी सिख दंगों पर बयान से बवाल मचा चुके हैं।*

***पंजा सिंह:** बवाल होता क्या है हम बताएं।*

***कमल खिलावन:** बताओ..*

***पंजा सिंह:** ये लो।...*

(और ये कहते हुए बिरयानी कमल खिलावन के सर पर। सालन हाथ में लिए कमल खिलावन पीछे-पीछे... पंजा सिंह सरपट आगे-आगे)

अर्थव्यवस्था : चुनाव के दौरान अन्य मुद्दों के साथ आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए

कर्ज लेने की सीमा तय की जाए, ज्यादा कर्ज लेने से पहले संसद में की जाए बहस

विजय गर्ग
चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक मामलों के जानकार
@patrika.com

पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कर्ज लेने की प्रवृत्ति सरकार ही नहीं, सामान्य जनता में भी बढ़ती जा रही है। बचत और कर्ज का अनुपात हमें डरा भी रहा है।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि देश की सरकार के कर्ज की सीमा तय की जाए। कर्ज ज्यादा चाहिए तो संसद को कारण बताया जाए, कर्ज को लेकर सरकार सवालों के जवाब दे। यह बात आज इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि देश पर कर्ज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब डर यह है कि यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बराबर न हो जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्ज लेकर देश का विकास करना या जनता को उजली तस्वीर दिखाना उचित है?

सर्वप्रथम पिछले दो दशक के कर्ज के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। वर्ष 2004 में देश पर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हो गया। जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार गई तब वर्ष 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का पहला कार्यकाल खत्म होने पर वर्ष 2019 में देश पर 90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। सितंबर 2023 में यह आंकड़ा 161 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी साल जनवरी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा था कि भारत पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार इसी रफ्तार से कर्ज लेती रही तो वर्ष 2028 तक भारत पर जीडीपी का 100 प्रतिशत कर्ज हो सकता है। ऐसे में कर्ज चुकाना बेहद कठिन हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आइएमएफ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और स्पष्टीकरण दिया कि आइएमएफ का भारत पर 100 प्रतिशत कर्ज का अनुमान गलत है। मौजूदा कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। यदि सरकार के कर्ज लेने का पोस्टमार्टम किया जाए तो यह दो प्रमुख बातों पर निर्भर करता है। पहला, सरकार की आमदनी कितनी है। दूसरा, सरकार का खर्च कितना है। यदि सरकार की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है तो सरकार इसकी भरपाई कर्ज लेकर करती है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है, राजस्व घाटा बढ़ता है। साफ है कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है।

कर्ज लेने के चार विकल्प हैं। पहला, कर्ज देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे बैंकों, बीमा कंपनियां या कॉर्पोरेट कंपनियों से लिया जा रहा है। दूसरा विदेशी से कर्ज, जो आइएमएफ, वर्ल्ड बैंक व दूसरे विदेशी बैंकों से मिलता है। तीसरा, सार्वजनिक कर्ज है जैसे ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स आदि से सरकार लेती है। चौथा सरकार के पास सोना गिरवी रखकर भी पैसा उठाने का एक विकल्प होता है, जैसा वर्ष 1990 में सरकार ने किया।

दुनिया में केवल हम ही कर्ज नहीं ले रहे हैं, विकसित देश जैसे जापान, अमरीका भी कर्ज लेते हैं। जापान तो कर्ज लेने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार जापान पर जीडीपी के मुकाबले 256.9 प्रतिशत कर्ज है। अमरीका पर जीडीपी के मुकाबले 133.3 प्रतिशत कर्ज है। हालांकि, एक बात भारत में बार-बार उठती है कि अमरीका भी तो हमसे ज्यादा कर्ज लेकर बैठा है, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि अमरीका की स्थिति और हमारी स्थिति में फर्क है। अमरीका दुनिया की सेंट्रल करेंसी यानी डॉलर का मालिक है। पूरी दुनिया अमरीका से डॉलर लेकर कर्ज देती है। इसलिए अमरीकी सरकार का बॉन्ड दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश है। फिर अमरीका में कर्ज का निर्धारित स्तर होते ही सरकार रुक जाती है। वहां विपक्ष सवाल पूछता है। कुछ यही स्थिति डॉ. आंबेडकर भारत में चाहते थे। इसलिए अगस्त 1949 में संविधान सभा की बहस में उन्होंने कहा था कि संसद को कानून बनाकर सरकार के कर्ज की सीमा तय करनी चाहिए। हालांकि, यह भारत में हुआ नहीं और आज स्थिति हाथ से बाहर होती दिख रही है।

देश पर कर्ज का खतरा कितना बड़ा है, इसको कुछ यूं समझ सकते हैं कि भारत का घरेलू कर्ज गंभीर स्तर पर आ पहुंचा है। हमारी अर्थव्यवस्था सरकार और बैंकों के गठजोड़ के कारण कर्ज के जाल में फंसती जा रही है। बैंकों की कुल कर्ज होल्डिंग में सरकारी कर्ज का हिस्सा 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने 15.43 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जो कोरोनाकाल के दौरान लिए गए कर्ज से ज्यादा है। नया कर्ज महंगी ब्याज दरों पर मिला, क्योंकि सरकार की 10 साल के कर्ज की ब्याज दर सात प्रतिशत पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले साल अपनी आर्थिक समीक्षा में बताया था कि करीब 70 प्रतिशत कर्ज लंबी नहीं, छोटी अवधि यानी 10 साल तक के हैं। इसलिए लंबे समय तक ब्याज का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि वर्ष 2023 में उसने 4.1 लाख करोड़ रुपए का पुराना कर्ज चुकाया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 से 2028 के बीच चार गुना कर्ज चुकाने के लिए सिर पर खड़ा हो जाएगा।

ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार कर्ज में डूबी है। कुछ-कुछ यही स्थिति राज्यों की भी है। करीब 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राज्यों के ऊपर है। केंद्र और राज्यों के कर्ज को जोड़ लिया जाए तो यह 200 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है।

दरअसल, भारत की पहचान बचत करने वाली रही है। आम भारतीय परिवार कर्ज लेने से बचता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कर्ज लेने की प्रवृत्ति सरकार ही नहीं, सामान्य जनता में भी बढ़ती जा रही है। बचत और कर्ज का अनुपात हमें डरा रहा है। वर्ष 2023 में भारतीय परिवारों की शुद्ध बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर जीडीपी के अनुपात में 5.5 प्रतिशत पर आ गई थी, जबकि इसी वित्त वर्ष में समग्र राजकोषीय घाटा नौ प्रतिशत रहने का आकलन किया गया। साफ है, देश के परिवार जितना बचा रहे हैं, उससे अधिक तो अकेले सरकार को कर्ज लेना होगा। यह बेहद खतरनाक स्थिति है।

वर्तमान समय में देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। विडंबना यह है कि आर्थिक मुद्दों की चर्चा चुनाव में नहीं हो रही है। आर्थिक विषयों पर भी जनता अपनी राय रखे और गंभीरता से सोचे। इस तरह के मुद्दे चुनाव में उठने चाहिए। आगामी जून में बनने जा रही नई सरकार को भी चाहिए कि कर्ज को लेकर एक ठोस नीति बनाए। जैसा डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सरकार के कर्ज लेने की सीमा तय हो और संसद में बहस के बाद ही सीमा से ज्यादा कर्ज लिया जाए। यह देश के लोगों और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

आज का सवाल

किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

वेंटिलेशन का रहे ध्यान

रसोई में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। महीने में एक या दो बार नियमित रूप से गैस की नियमित जांच करें। गैस सिलेंडर को सीधे सूर्य के प्रकाश और गर्मी से दूर रखें।
-यशिका भारद्वाज, जयपुर

नियमित निरीक्षण जरूरी

घरेलू गैस पर काम करते समय सूती वस्त्र के कपड़े पहनने चाहिए। गैस इस्तेमाल के तुरंत बाद रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। गैस चूल्हे का नियमित निरीक्षण जरूरी है।
-सुषमा चौधरी, खैरथल

रेगुलेटर बंद रखें

गैस सिलेंडर, चूल्हे और पाइप के रखरखाव पर खास ध्यान देना जरूरी है। काम खत्म होने पर हमेशा सिलेंडर में लगे हुए रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। **-उमराव सिंह वर्मा,** सेमरिया बेमेतरा, छत्तीसगढ़

नहीं मिलती मदद

रसोई गैस से जुड़ी समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। गैस कंपनियों और एजेंसियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। जरूरत पड़ने पर गैस उपभोक्ताओं को मदद नहीं मिलती।
-सतीश सैन, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, ' घरेलू गैस से जुड़े हादसों को कैसे रोका जा सकता है?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें
rb.gy/bpus00

कल्पमेधा

अपूर्ण, अनिश्चित अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे से परिवर्तित करना है।

- ह्वेटले

भ्रष्टाचार का रोग

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अस्पताल जैसी जिस जगह पर लोग अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने, जान बचाने की भूख में जाते हैं, वहां अन्य कर्मचारियों से लेकर खुद कुछ चिकित्सक तक उनकी सेहत को कई बार दांव पर लगा देते हैं। सीबीआइ ने छानबीन के बाद दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे जिस भ्रष्ट तंत्र का खुलासा किया है, वह बेहद चिंताजनक है। गौरतलब है कि इस अस्पताल के दो चिकित्सकों सहित ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक ओर रिश्वत के बदले वहां कुछ खास कंपनियों के उत्पाद के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं मरीजों पर भर्ती होने के लिए पैसे भी लिए जाते थे। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खबरों के मुताबिक, किसी गर्भवती के परिजन जब तक रिश्वत की रकम नहीं चुकाते थे, तब तक उन्हें वार्ड में जगह नहीं दी जाती थी। मरीजों और उनके परिजनों को धमकाने के भी आरोप हैं।

हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी में सबसे अहम माने जाने वाले अस्पतालों में से एक में इस तरह का भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा था और उस किसी की नजर नहीं जा रही थी या फिर जानबूझ कर उसकी अनदेखी की जा रही थी। माना जाता है कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर चाकचौबंद होगी और यहां इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बन सकती। मगर इस जाने-माने अस्पताल में कुछ चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने रिश्वत के बदले कुछ खास कंपनियों के उत्पादों और उपकरणों के कारोबार को जिस तरह बढ़ावा दिया, वह हैरान करने वाला है। सवाल है कि इस भ्रष्टाचार को खुद अस्पताल के तंत्र के भीतर या फिर सरकार के संबंधित महकमों की नजर और फिर कार्रवाई के दायरे में आने में इतना वक्त कैसे लग गया? चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और उनके उपयोग पर नजर रखने के लिए क्या वहां कोई व्यवस्था नहीं है? अगर है, तो कुछ खास कंपनियों के सामानों पर लगातार मेहरबान होने पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ? अगर मरीजों से गलत तरीके से पैसे वसूले जाते थे या फिर कुछ खास ब्रांड के उत्पाद ही लेने पर मजबूर किया जाता था, तो यह इतनी देर से पकड़ में क्यों आया?

जाहिर है, भ्रष्टाचार का यह दुश्चक्र अस्पताल के कुछ डाक्टर और अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल रहा होगा। यह छिपा तथ्य नहीं है कि कई बार मरीजों को कुछ डाक्टर गैरजरूरी दवाइयां लेने की सलाह भी देते हैं। दवा या चिकित्सा उपकरणों के कारोबार को बढ़ावा देने के एवज में दवा कंपनियों की ओर से डाक्टरों को दुनिया के अलग-अलग देशों के दौरे पर ले जाने या महंगा तोहफा देने के प्रस्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जिसमें किसी खास दवा कंपनी से धन या सुविधाओं के बदले डाक्टर मरीजों को वैसी दवाएं लेने या जांच कराने की सलाह दे देते हैं, जो निहायत ही गैरजरूरी होती हैं। इसकी क्या गारंटी है कि मरीजों को इस तरह की जिन दवाओं का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, वे उनकी सेहत के लिहाज से खतरनाक या अनुपयोगी नहीं होंगे या उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा? मगर यह अफसोसनाक हकीकत है कि पैसा बनाने के खेल में शामिल चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को मरीजों के जीवन की कोई फिक्र नहीं होती।

लापरवाही की आग

उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से हर वर्ष भारी नुकसान होता है। मगर लगातार ऐसी घटना के बावजूद सरकार और संबंधित महकमों को इस बात की सुध लेने की जरूरत नहीं लगती कि इसे रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाएं। जंगल में आग लगने से बचाव की फिक्र में औपचारिक तौर पर जो कदम उठाए जाते हैं, उसकी हकीकत इसी से समझी जा सकती है कि इस वर्ष फिर नैनीताल के आसपास के जंगल में लगी आग की वजह से बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। पिछले कई दिनों से वहां आग पर काबू पाने के लिए हेलिकाप्टर के प्रयोग सहित कई अन्य उपाय आजमाए जा रहे हैं। जाहिर है, फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता जंगल क्षेत्रों में लगी आग को फैलने से रोकना और बुझाना है, ताकि नुकसान का दायरा कम किया जा सके। इसलिए यह देखने की जरूरत है कि पहाड़ी इलाकों में स्थानीय जरूरतों के अनुकूल किस तरीके से आग को बुझाया जा सकता है। मगर इतना तय है कि जिन इलाकों में जंगल धधक रहे हैं, उनमें वन संरक्षण के लिए तैनात कर्मचारियों ने शायद अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो समस्या को गंभीर शक्ल लेने से रोका जा सकता था।

सवाल है कि धधकते जंगलों के संकट की जिम्मेदारी तय करना कब संभव हो सकेगा! फिलहाल आग बुझाने के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दस वनकर्मियों के निलंबन के साथ कुल सत्रह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। माना जाता है कि जलवायु में बढ़ते तापमान और पर्यावरण असंतुलन की वजह से दुनिया भर के जंगलों में आग लग जाती है और उसमें व्यापक पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। मगर इसके समांतर वनाग्नि की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, जिनमें वन संरक्षण की ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और अधिकारियों ने सही समय पर आग से बचाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया। यह भी खबर आई कि वहां कुछ उत्पाती तत्त्वों को जंगल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे यह पता चलता है कि जंगल में आग लगने की घटनाएं केवल प्राकृतिक ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अपराधी तत्त्व भी शामिल हैं। जाहिर है, वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार को सभी चिह्नित पहलुओं के मद्देनजर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

मलेरिया से मुक्ति की मुश्किल डगर

विश्व की आधी आबादी पर मलेरिया का खतरा बना हुआ है। मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया अभी काफी पीछे है।

रामानुज पाठक

मलेरिया कोई 'वायरस' (विषाणु) या 'बैक्टीरिया' (जीवाणु) जनित रोग नहीं है। यह एक 'प्रोटोजोआ' यानी परजीवी है, जो सामान्य विषाणु से हजारों गुना बड़ा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कोविड-19 विषाणु में लगभग बारह जीन होते हैं, जबकि मलेरिया में पांच हजार जीन पाए जाते हैं। मलेरिया परजीवी चार जीवन चक्रों से गुजरता है। संक्रामक रोगाणुओं के साथ-साथ यह और विकराल रूप धारण कर लेता है। मलेरिया एक मच्छर-जनित रक्त रोग है, जो प्लास्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, फिर लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) को नष्ट करते हैं।

ऐसी पांच परजीवी प्रजातियां हैं, जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण बनती हैं। इनमें से दो प्रजातियां, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा होता है। विश्व मलेरिया रपट के अनुसार, इस बीमारी ने 2021-2022 में अनुमानित छह लाख उन्नीस हजार लोगों की जान ले ली। रपट में यह भी बताया गया है कि भारत में पिछले दस वर्षों में मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक प्रयासों के समन्वय से मलेरिया को नियंत्रित तथा खत्म करना है। इसका लक्ष्य मलेरिया मामलों और मृत्यु दर को वर्ष 2020 तक कम से कम 40 फीसद, वर्ष 2025 तक 75 फीसद और वर्ष 2015 की आधार रेखा के मुकाबले वर्ष 2030 तक कम से कम 90 फीसद कम करना है।

विश्व की आधी आबादी पर मलेरिया का खतरा बना हुआ है। मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया अभी काफी पीछे है। 'स्टैस्टिटा' की रपट के अनुसार 2022 में मलेरिया पचासी देशों में स्थानिक महामारी के रूप में सक्रिय था। मामूली सुधार के बावजूद विश्व अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस लक्ष्य से पीछे है, जिसमें 2025 तक मलेरिया से प्रभावित देशों की संख्या 75 तक लाने की बात कही गई है। अब तक कुल 43 देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। डब्लूएचओ उन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित करता है, जहां तीन साल तक मलेरिया के कोई स्थानिक मामले नहीं पाए जाते हैं।

भारत में ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा हैं। इन राज्यों में मानसून के बाद जलभराव, वेक्टर (वाहक) की मौजूदगी के कारण मच्छर पनपते हैं, जो मलेरिया के मामलों को बढ़ाते हैं। भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहां गर्मी और बरसात का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएमसीपी) 1953 में शुरू किया गया था। यह तीन प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है, डीडीटी के साथ कीटनाशक अवशिष्ट छिड़काव (आइआरएस), मामलों की जांच और निगरानी तथा रोगियों का उपचार। मलेरिया उन्मूलन के लिए डब्लूएचओ की वैश्विक तकनीकी रणनीति के आधार पर एनएफएमई (नेशनल फ्रेमवर्क आफ मलेरिया एलिमिनेशन) के लक्ष्य तय किए गए, जिसके तहत 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना है।

भारत में ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा हैं। इन राज्यों में मानसून के बाद जलभराव, वेक्टर (वाहक) की मौजूदगी के कारण मच्छर पनपते हैं, जो मलेरिया के मामलों को बढ़ाते हैं। भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहां गर्मी और बरसात का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएमसीपी) 1953 में शुरू किया गया था। यह तीन प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है, डीडीटी के साथ कीटनाशक अवशिष्ट छिड़काव (आइआरएस), मामलों की जांच और निगरानी तथा रोगियों का उपचार।

कुछ साल पहले तक किसी भी देश में कोई पैरासाइटिक (परजीवी) रोगरोधी टीका विकसित नहीं हुआ था। अब मलेरियारोधी दो टीके आ चुके हैं, जिनके नाम आरटीएस-एस तथा आर-21 हैं। इसका फार्मूला आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक एड्रियन हिल ने तैयार किया है। बच्चों में मलेरिया के गंभीर मामलों को रोकने में पहले टीके की प्रभावशीलता लगभग 30 फीसद है, लेकिन यह एकमात्र स्वीकृत टीका है। यूरोपीय संघ के औषधि नियामक ने वर्ष 2015 में यह कहते हुए इसे मंजूरी दी थी कि इसके जोखिमों की तुलना में लाभ कहीं अधिक हैं। आरटीएस का उद्देश्य मलेरिया मच्छर के काटने से मानव रक्त प्रवाह में इसके प्रवेश करने और यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करने के पहले चरण से ही बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करना है।

मगर यह परजीवी उपभेदों के खिलाफ पर्याप्त रक्षा नहीं प्रदान करता। परजीवी टीके का प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, इसलिए टीके को और विकसित करने की आवश्यकता है। टीके का प्रयोग असुविधाजनक माना गया है, क्योंकि एक बच्चे को दो साल की उम्र से पहले चार टीके लगते हैं, जो अधिकांश अन्य बीमारियों के लिए नियमित टीकों की तय अवधि से मेल नहीं खाते, वहीं टीका आंशिक रूप से ही प्रभावी है। 2009 से 2014 के बीच दस हजार से अधिक अफ्रीकी बच्चों में किए गए परीक्षण से पता चला कि चार खुराक लेने के बाद भी यह टीका लगभग 40 फीसद ही मलेरिया संक्रमणों को रोक सका। टीके का असर दीर्घकालिक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि टीका लगने के बाद प्रतिरोध कितने समय तक सक्रिय रहेगा। पिछले परीक्षणों में चार साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया था। जबकि दूसरा टीका आर-21 मलेरिया उन्मूलन में अधिक प्रभावी है।

मलेरिया के चारों जीवन चक्र बेहद अलग हैं और इनसे निपटने के लिए अलग-अलग प्रतिजन की आवश्यकता होती है। प्रतिजन वह पदार्थ है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को 'एंटीबाडी' पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। इसके अलावा 'स्पोरोजोइट्स' (कोशिकाओं के एक रूप) पर गौर किया गया, जो मच्छर त्वचा पर काटकर मानव शरीर में छोड़ते हैं। इन कोशिकाओं के यकृत में पहुंचने से पहले इनका पता लगाने की कोशिश की गई। ये कोशिकाएं तेजी से फैलती हैं और ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। हर मच्छर छोटी मात्रा में 'स्पोरोजोइट', शायद बीस 'स्पोरोजोइट', त्वचा में छोड़ते हैं। अगर इंसानी शरीर इन बीस 'स्पोरोजोइट' को झेल लेता है, तो माना जाता है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन एक भी 'स्पोरोजोइट' आगे बढ़ जाता है, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आर-21 टीकाकरण की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है।

हालांकि भारत में आर-21 टीके की लाखों खुराक भंडार करके रखी गई है। इसकी तुलना में अगर देखें तो आक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका कोरोनारोधी टीके को 2020 में नए साल की पूर्व संध्या पर मंजूरी दी गई थी और झटपट अगले ही सप्ताह कई देशों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। उस वर्ष अफ्रीका में कोविड-19 की तुलना में मलेरिया से अधिक मौतें हुई थीं। मलेरियारोधी पहला टीका आरटीएस-एस पहले ही एक बड़े सुरक्षा परीक्षण के तहत लाखों बच्चों को लगाया जा चुका है और इसका इस्तेमाल वास्तव में बहुत अधिक है, इसलिए अफ्रीका में बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। दुनिया भर में मलेरिया को जड़ से खत्म करने के बारे में अधिक गहराई से सोचने की आवश्यकता है।

खामोशी की दीवार

दीपिका शर्मा

जीवन गतिशील है। जब तक सांसें हैं, यह चलता रहता है, लेकिन परिस्थितियां हैं जो आए दिन बदलती रहती हैं। जब अच्छा समय रहता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है और जब कठिन दौर आता है तो जीवन में हताशा और मायूसी छाने लगती है। जीवन मानो अंधकार में लीन हो जाता है। ऐसा ही हमारे रिश्तों में होता है। जब रिश्ते मधुर होते हैं तो सब कुछ रंगीन होता है, मानो दुनिया में सब बेहद खूबसूरत है और हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मगर उन्हीं रिश्तों से हमें आघात पहुंचता है तो हम टूट जाते हैं। तब दुनिया बेरंग हो जाती है। हम अकेलेपन को अपना साथी मान बैठते हैं जो धीरे-धीरे हमें अंदर से खोखला करता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास खुद पर काबू पाने का हुनर होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमे निरंतर बदलाव होना स्वभाविक है। फिर रिश्तों में हताशा क्यों?

पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति पांव पसार रही है, उसका असर हमारे रिश्तों पर बहुत अधिक पड़ने लगा है। हमारे भारतीय समाज में शादी को जन्म-जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों की सोच बदल रही है। इसका सबूत है तलाक और अलगाव के बढ़ते मामले। इसमें पारिवारिक व्यवस्था का क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है? बढ़ती शिक्षा दर, आधुनिकता, सहनशीलता में कमी या कुछ और? यह समझने की जरूरत है कि पति-पत्नी का रिश्ता बेहद संवेदनशील होता है। जिसे हम विश्वास, ईमानदारी और साझेदारी के बीजों की माला बनाकर वरमाला के रूप में एक दूसरे को पहनाते हैं। मगर आज का दौर इस कदर बदल गया लगता है कि शादी के कुछ दिन या महीने बाद ही एक दूसरे से किए वादों की अनदेखी कर दी जाती है, जिससे एक दूसरे के बीच मतभेद, लड़ाई-झगड़े की नौबत आती है। हालात अगर संभाले नहीं गए तो रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है। अन्यथा पति या पत्नी में से दोनों या कोई एक मौन अलगाव का सहारा लेता हैं, जिसे मूक अलगाव या 'साइलेंट सेपरेशन' कहा जाता है। यह कोई कानूनी दांवपेच से नहीं, बल्कि खुद के फैसले से होता है।

एक मजबूत रिश्ते की नींव समानता पर आधारित है, जहां दोनों सम्मानित, सराहना और मूल्यवान महसूस करते हैं। मगर तनाव और अलगाव इन सभी पर वार करता है और रिश्ते को खामोशी की तरफ ले जाता है। वहीं यह खामोशी भावनात्मक रूप से दोनों को अलग करने का काम करती है और अंदर ही अंदर एक नासूर बन जाती है, जिसका असर शारीरिक और मानसिक रूप से देखने को मिलता है। ऐसे में मस्तिष्क में 'हैप्पी हारमोन' यानी खुशी पैदा करने वाले रसायन का बनना कई गुना कम हो जाता है। हम चाहे खुद को कितना भी व्यस्त रख लें, लेकिन एक रिश्ते की टीस खत्म नहीं होती। चाहे महिला हो या पुरुष, इसका दर्द दोनों को ही होता है। फर्क इतना है कि महिलाओं में इसका असर कुछ ज्यादा होता है, जिसका कारण है अपने जीवन साथी से उम्मीदों का भाव ज्यादा होना।

वहीं आज के समय में आमतौर पर दोनों का कामकाजी होना भी मूक अलगाव का एक कारण है, लेकिन कामकाज भी परिस्थितियों की भी मांग होती है। ऐसे में जरूरी है कि अपने काम और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। पूरे दिन में एक ऐसा समय निर्धारित किया जा सकता है, जिसमे दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातों का आदान-प्रदान कर सकें और बेहद जरूरी यह कि अपने काम की परेशानियों को दफ्तर में ही छोड़कर आया जाए, ताकि परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताया जा सके। किसी भी लड़ाई झगड़े को लंबा खींचना या मन ही मन घुटते रहना अवसाद की ओर ले जाता है, जिसके बाद व्यक्ति चाह कर भी अपने रिश्ते को सुधारने में नाकाम रहता है। इसलिए समय रहते अपने जीवनसाथी से मन में उठ रहे सवालों पर प्यार से चर्चा कर लेना ही इसका अचूक उपाय है।

मूक अलगाव एक 'खामोश हत्यारे' की तरह काम करता है। जिस तरह शरीर में उच्च रक्तचाप का बना रहना शरीर के लिए खामोश हत्यारे का कार्य करता है और शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, उसी तरह मूक अलगाव भी हमारी खुशियों पर ग्रहण की तरह रहता है। यह हमें सिर्फ इस बात की तसल्ली देता है कि हम लड़ाई झगड़ों से दूर शांतिपूर्वक अलग-थलग एक छत को साझा कर रहे हैं, जिसमें हम खुश रहने की भरपूर कोशिश करते हैं। मगर यह मन का वहम है। यह खामोशी भीतर तक खोखला करता रहता है और तनाव के साथ अकेलेपन की ओर धकेलता रहता है।

रिश्ते समय-समय पर मरम्मत की मांग करते हैं। जिस तरह एक दरार पड़ा मकान मजबूत नहीं होता और किसी भी समय उसके ढह जाने का डर हमें सताता रहता है, उसी तरह मूक अलगाव के चलते हमारे रिश्ते का खत्म हो जाने का भय हमारे मन और मस्तिष्क पर लगातार प्रहार करता जाता है। किसी भी रिश्ते को सुरक्षित रखना चौबीस घंटे की नौकरी करने के बराबर है। साथ ही समय समय पर इसे निरंतर रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता बनी रहती है। रिश्तों को संजो कर रखना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की पहचान है।

दुनिया मेरे आगे

रिश्ते समय-समय पर मरम्मत की मांग करते हैं। जिस तरह एक दरार पड़ा मकान मजबूत नहीं होता और किसी भी समय उसके ढह जाने का डर हमें सताता रहता है, उसी तरह मूक अलगाव के चलते हमारे रिश्ते का खत्म हो जाने का भय हमारे मन और मस्तिष्क पर लगातार प्रहार करता जाता है।

प्रतिक्रिया की राह

इजराइल और हमास के बीच युद्ध में कई हजार लोगों के मारे जाने के बाद अब तुर्की ने कहा है कि जब तक गाजा में स्थायी युद्धविराम और मानवीय सहायता सुनिश्चित नहीं हो जाती, वह इजराइल के साथ प्रति वर्ष सात अरब डालर का व्यापार फिर से शुरू नहीं करेगा। ऐसा कदम उठाने वाला वह इजराइल का पहला प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार है। इसराइल के तीस फीसद सीमेंट की आपूर्ति तुर्की करता है। इसके अलावा इस्पात, वाहन, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण और मशीनरी जैसे सामानों को भी तुर्की ही मुहैया कराता है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि ये उपाय तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गाजा में सहायता के 'निर्बाध और पर्याप्त प्रवाह' की अनुमति नहीं देता। तुर्की के इस कदम से इजराइल को सदमा लगा है। शायद इसीलिए इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर 'तानाशाह' की तरह काम करने का आरोप लगाया। फिलिस्तीनियों को सैन्य तरीके से सहायता तो नहीं पहुंचाया जा सकता है, मगर इजराइल का रसद मार्ग बाधित हुआ तो उसके सामने अपनी रणनीति पर विचार करने की मजबूरी पैदा हो सकती है।

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

अस्तित्व का सवाल

इतिहास साक्षी है कि नदियों के साथ ही मानवीय सभ्यता का उदय हुआ है और नदियों के साथ ही अंत। फिर भी मनुष्य खुद को प्रकृति से श्रेष्ठ साबित करने के प्रयासों में लगा हुआ है। पर्वतीय इलाकों में आपदाओं का कहर बरपना, उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगना, जैव विविधता में गिरावट, भूमिगत जल की कमी आदि से यही पता चलता है कि मनुष्य की लालची प्रवृत्ति ने कितनी निर्दयता से प्रकृति का दोहन किया है। इस बात की सत्यता स्वयंसिद्ध है कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, उसके लालच को नहीं। इसलिए मनुष्य को अपनी लालची प्रवृत्ति छोड़ कर प्रकृति की सुरक्षा करना आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में अपनी जरूरतों को भी पूरा करने में वह असमर्थ होगा और प्रकृति के अस्तित्व से पहले स्वयं के अस्तित्व को खो देगा।

- योगिता यादव, बनारस हिंदू विवि

अनदेखी का रास्ता

आज के समय में प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव सर्वाधिक महानगरों द्वारा किए जा रहे अनुचित संसाधनों के प्रयोग द्वारा हो रहा है। यों तो कहा जा सकता है कि लोग उच्चतम शिक्षा के लिए महानगरों की ओर अग्रसर होते हैं, पर ऐसी उच्च शिक्षा का क्या मतलब जो हमारे प्रकृति और उसमें विद्यमान संसाधनों की सार्थकता को न समझा जाए, जिसका अनुचित दोहन हमें भविष्य के संकट के सामने खड़ा कर दे। यह देखा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित लोग खुद भी वातानुकूलन यंत्रों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। महानगरों की संसाधनों पर इस अनुचित दोहन पर लगाम लगाना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस आने वाले संकट से उबार सके। अगर हम समय पर सचेत नहीं हो सके, तो पर्यावरण की आज की अनदेखी कल का संकट साबित हो सकती है।

- विपिन कुमार, लखनऊ।

शक का आधार

'शक की सुई' (संपादकीय, 2 मई) पढ़ा। निर्वाचन आयोग को ऐसे प्रयास करना चाहिए, जिससे संदेहों का निवारण हो सके। आज जब देश मे हरेक कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए डिजिटल प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली मे कहां कमियां रह गईं कि दो चरणों के चुनाव के बाद अंतिम आंकड़ों को समय पर देने में इतनी देरी हुई। वर्षों पूर्व बैलेट पेपर के प्रयोग के दौर में अंतिम आंकड़े चौबीस घंटे के अंदर घोषित हो जाया करते थे तो इस चुनाव मे हुई देरी शक की सुइयां तो खड़ी करती ही हैं। आजकल चुनाव के वक्त हमारे देश मे प्रयोग की जाने वाली दुनिया की श्रेष्ठ ईवीएम जब आधुनिक तकनीक से लैस हैं तो अंतिम आंकड़ों में देरी, आम मतदाता के मन में और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गड़बड़ के संदेह पैदा करती है।

- नरेश कानूनगो, देवास, मप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AINewsPaperPdf

www.readwhere.com

चिंतन

शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट स्थायी नहीं

शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जहां वित्तीय समर्थक, दलाल और संगठन सार्वजनिक निगमों के कुछ हिस्सों का व्यापार कर सकते हैं। शेयर बाजार व्यवसायों को पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है और निवेशकों को उन व्यवसायों में निवेश करने का मौका देता है और संभवतः उनके पैसे पर संभावित रिटर्न प्राप्त करता है। शेयर बाज़ार वैसे ही अर्थव्यवस्था की सामान्य भलाई का संकेत है, क्योंकि बाज़ार में उतार-चढ़ाव मौद्रिक परिस्थितियों और निवेशक भावनाओं में बदलाव को प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन बाजार हर छोटी और बड़ी घटना से प्रभावित होना जोखिम भरा भी होता है। विश्व स्तर के ऐसे अनेक कारक हैं जो बाजार को न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि उसकी चाल भी तय करते हैं। भारतीय शेयर बाजार केंद्रीय बजट, कमोडिटी की कीमतों-इनपुट लागत, सोने की कीमतों और बॉन्ड से भी प्रभावित होता है। ऐसा ही आजकल हो रहा है। बृहस्पतिवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह क्रम बीते पांच दिनों से चल रहा है। गुरुवार को सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा टूटकर 72,616 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 280 अंक गिरकर 22,022 पर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट की बड़ी वजह विदेशी निवेशकों और अन्य निवेशकों की बड़ी मुनाफावसूली मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी निवेशक इस महीने भारी बिकवाली कर रहे हैं। मई 2024 में गुरुवार तक कैश सेगमेंट से एफआईआई 15863 करोड़ रुपये बेच चुके हैं, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन (एफएंडओ) सेगमेंट में एफआईआई 5,292 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ यूएस फेड अधिकारियों की हॉकिश बातों ने भारतीय शेयरों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। इस महीने की शुरुआत में कुछ मुनाफावसूली देखने के बाद इस तरह के बयानों की वजह से अमेरिकी डॉलर में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे भारतीय शेयर बाजार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जो लगातार बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से शेयर बाजार में समय से पहले मुनाफावसूली शुरू हो गई है। ये बिकवाली केवल फ्रंटलाइन लार्ज-कैप शेयरों में ही दिखाई दे रही है। बिकवाली का एक बड़ा कारण यह भी है कि वित्त वर्ष 2024 के चौथी तिमाही के नतीजे जिस तरीके के आने चाहिए थे, वो देखने को नहीं मिले हैं। इसका असर भी शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन बाजार निवेशकों को उम्मीद थी कि चौथी तिमाही के नतीजे और बेहतर आने चाहिए थे। जो न आ पाने के कारण बाजार पस्त हो रहा है। वैसे भी अब तिमाही नतीजों का मौसम खत्म होने वाला है। उससे पहले निवेशकों की ओर मुनाफा वसूली की जा रही है। जिससे बाजार गिर रहा है, लेकिन यह तय है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है। स्थायी होने का कोई कारण भी नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाजार फिर तेजी की ओर लौटेगा।

आम चुनाव
अखिलेश आर्येंदु

राष्ट्र प्रथम हो मतदान का आधार

आज का भारतीय समाज अर्थ केंद्रित है। गुण, ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा का मूल्यांकन अच्छी नौकरी पाने या व्यापार में खूब मुनाफा कमाने तक ही सीमित हो गया है। न तो नौकरी राष्ट्र को योगदान करने की मंशा से करने की भावना है लोगों में और न तो व्यापार ही। यही वजह है आम चुनाव में विपक्ष द्वारा बार-बार सब को नौकरी देने जैसे असंभव माने जाने वाले कार्य को हवा दी जा रही है। रेवड़ियों को बांटने और किसानों की कर्ज माफी का जो वादा चुनाव में किए जा रहे हैं वे सत्ता हथियाने के हथियार ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे में संकीर्ण दायरों से बाहर आना ही होगा। उम्मीद की जानी चाहिए राजनीतिक दल राष्ट्र प्रथम की भावना से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।

चुनावी मौसम में वेद शास्त्रों व आचार्य चाणक्य के राष्ट्रपरक नीति वचन का याद आना लाजिमी है, जिसमें कहा गया है कि जनता ऐसे दूरदर्शी, त्यागी, नीतिवान व चरित्रवान व्यक्ति का चुनाव करे जिसमें दुनिया में सम्मान दिलाने की क्षमता हो। यह उपदेश तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश की नई सरकार चुनने का अवसर हो। एक नागरिक का कर्तव्य अपने देश के प्रति कैसा होना चाहिए पर चाणक्य का कहना है, कर्तव्य को विवेक से करना नीतिवान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। चाणक्य इसी संदर्भ में कहते हैं-भली प्रकार सोच-विचार कर या अवसर को पहचानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। पांच साल के बाद जनता को यह अवसर मिलता है कि वह निवर्तमान सरकार के कार्यों, नीतियों और निर्णयों का बेहतर मूल्यांकन कर नई सरकार के लिए बगैर किसी लालच के खूब सोच-समझ कर अपना मत दे। तमाम तरह के सर्वे यह समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि आम चुनाव में भी क्षेत्रीय मुद्दे और जात-पात की मानसिकता हावी है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम देशों में चुनाव देश की गम्भीर समस्याओं और विकास के मुद्दे पर लड़े व जीते जाते हैं, ऐसे में भारत के इस आम चुनाव में वे मुद्दे ज्यादा हावी हैं जो राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ साधने वाले अधिक लगते हैं। व्यक्तिगत हित साधन के मुद्दे राष्ट्र की सुरक्षा और विकास के लिए मददगार नहीं हैं। शायद हम भारतवासी बार-बार भूल करते रहे हैं कि केंद्र या राज्यों में कैसी भी सरकार हो, शासन उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होना ही चाहिए। इस भूल ने भारत को विकास की दौड़ में दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे कर दिया। हम मतदाता अपने नागरिक कर्तव्यों को बेहतर सोच व परिणाम के साथ निभाने में हमेशा पीछे रहते हैं।

ताजा सर्वेक्षण इस बात की तसदीक करते हैं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की अपेक्षा महंगाई और बेरोजगारी को अधिक तरजीह दी जा रही है यानी आतंक, धारा 370, समान नागरिक संहिता (कानून), विदेशी घुसपैठ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता के मुद्दे ज्यादातर लोगों के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। बेहतर शासन की कवायदों की जगह आरक्षण और संविधान बचाने का सब्जबाग लोगों को शायद ज्यादा भा रहा है। यदि ऐसा है तो यह भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात ही मानी जाएगी, क्योंकि न तो निवर्तमान सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है और न संविधान ही बदला जाएगा। इसका एनडीए के घोषणा पत्र में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। राजनीति के जानकारों की माने तो यह भी हो सकता है कि, लोग केंद्र और राज्य सरकार को चुनते हुए कुछ उनके निहित स्वार्थ उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों से दूर रखने का कार्य कर रहे हों। यह भारत जैसे बहुसंस्कृतियों और मजहब वाले देश के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। दरअसल, राष्ट्रवादी भावना का उद्रेक भारत में खास अवसरों पर ही देखा जाता है। आजादी के बाद पिछले 76 वर्षों में राष्ट्र प्रथम का कर्तव्यबोध का संचार सतत राष्ट्र जागरण के तौर पर हुआ ही नहीं। जैसे दुनिया के तमाम देशों में हुआ। यही वजह है हर बार आम चुनाव में यह देखा गया है कि चुनाव जीतने के लिए वे मुद्दे जो

व्यक्ति केंद्रित, तुष्टिकरण या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मद्देनजर कर्जमाफी, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ या गरीबी हटाओ जैसे मुद्दे उछाले जाते रहे।

व्यक्ति, परिवार और जाति-मजहब केंद्रित दलों की स्वार्थवादी सोच ने भारत की साख, शक्ति और अस्मिता के सवालों को कभी तवज्जो दी ही नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत हित साधन और महज आत्म-केंद्रित स्वार्थों की ही पूर्ति होती रही। राष्ट्र प्रथम के बारे में सोचा ही नहीं गया। इससे आंचलिक क्षत्रपों के पारिवारिक व सामाजिक हित साधन होते रहे, लेकिन राष्ट्र व सर्वहित हमेशा पीछे छूटता रहा। यदि आजादी के 76 साल बाद भी बेरोजगारी, महंगाई ही लोगों के लिए सबसे बड़ी देश की समस्याएं हैं तो यह उसी व्यक्तिवाद और तुष्टिकरण का परिणाम है जिससे देश में तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती रही हैं। इस चुनाव में देश संबंधी संकल्पनाओं और सर्वजन हिताय व सर्व जन सुखाय को राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कुछ दलों के घोषणा पत्रों में चर्चा तो की गई है, लेकिन यह चुनाव में प्रमुख मुद्दे के रूप में चर्चित नहीं हुआ है। हैरान करने वाली बात है कि तमाम गुलामी के प्रतीकों और संस्थाओं के विरुद्ध राष्ट्रहित में कोई बुलंद आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसकी जगह एक दूसरे पर कीचड़ उछाल प्रतियोगिता देखने को जरूर मिल रही है। इससे किसका हित साधन होगा, कहने की जरूरत नही है। नई पीढ़ी जो 21वीं सदी के शुरुआत में पैदा हुई वह जवान हो चुकी है। उसके सामने राष्ट्र निर्माण और सर्व समाजहित की बात सोचने वाले बेदाग चरित्र नायकों का अभाव दिख रहा है। यदि भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहा जाने लगा है और जनता इसके खिलाफ उठ खड़ी नहीं हो रही है तो यह भारतीय समाज व देश के लिए चिंता की बात ही कही जाएगी। व्यक्ति व समाज निर्माण में रोड़ा समझे जाने वाले नकारात्मक शब्दों और लोगों को यदि महिमामंडित करने की होड़ लगी हो तो, भला राष्ट्र निर्माण के पवित्र कार्य के लिए माहौल कैसे बनाया जा सकता है? मूल्याधारित राजनीति अब बीते जमाने की बात हो चुकी है, इसलिए राजनीतिक दलों से मूल्याधारित राजनीति और बेदाग छवि वाले नेताओं के नेतृत्व की आशा भी नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ मीडिया के अर्थ केंद्रित होने से मौजूदा राजनीति का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। दाग को बार-बार दिखाने से आंखें दाग देखने की अभ्यस्त हो जाती हैं। यही वजह है कि दागदार नेताओं की बहुत बड़ी तादाद आज भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और उनके खिलाफ कोई आक्रोश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि दागियों के प्रति जनता में कोई आक्रोश नहीं उभरता।

आज का भारतीय समाज अर्थ केंद्रित है। गुण, ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा का मूल्यांकन अच्छी नौकरी पाने या व्यापार में खूब मुनाफा कमाने तक ही सीमित हो गया है। न तो नौकरी राष्ट्र को योगदान करने की मंशा से करने की भावना है लोगों में और न तो व्यापार ही। यही वजह है आम चुनाव में विपक्ष द्वारा बार-बार सब को नौकरी देने जैसे असंभव माने जाने वाले कार्य को हवा दी जा रही है। रेवड़ियों को बांटने और किसानों की कर्ज माफी का जो वादा चुनाव में किए जा रहे हैं वे सत्ता हथियाने के हथियार ही नज़र आ रहे हैं। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है तो उन सभी मुद्दों, समस्याओं, विसंगतियों और खामियों पर ईमानदारी से गौर करना ही होगा जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में रुकावट बने हुए हैं। बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और लोगों की अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने की चुनौती केंद्र में आने वाली सरकार के सामने होगी ही। ऐसे में संकीर्ण दायरों और सोच से बाहर आना ही होगा। तभी भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए देश के सभी राजनीतिक दल राष्ट्र प्रथम की भावना से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।

(लेखक चिंतक और समाजकर्मी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और यहां भगवान शिव को 'उपचार के देवता' के रूप में पूजा जाता है। बैजनाथ या वैद्यनाथ महान भगवान शिव के अवतार हैं, और इस अवतार में, महान भगवान अपने भक्तों को सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करते हैं।

परशुराम जयंती
श्वेता गोयल

कालांतर तक अमर हैं परशुराम

हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, जो इस बार 10 मई को है। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भार्गव वंश में सप्तऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के यहां हुआ था। मान्यता है कि परशुराम के जन्म के पूर्व रेणुका तीर्थ पर जमदग्नि और रेणुका ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि स्वयं भगवान विष्णु रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के पांचवें पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। भगवान परशुराम को भगवान शिव और विष्णु का संयुक्त अवतार माना जाता है और मान्यता है कि उन्होंने भगवान विष्णु से पालनहार के गुण और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव से युद्ध कला में निपुणता हासिल की। बगैर किसी अस्त्र के ही उन्होंने बहुत सारे असुरों का नाश किया। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में है। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। उनकी दानशीलता ऐसी थी कि एक बार उन्होंने समस्त पृथ्वी ही ऋषि कश्यप को दान कर दी थी। उनके शिष्य बनने का लाभ दानवीर कर्ण ही ले पाए थे, जिसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दी थी। धर्मग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर रहने वालों में परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे खतरनाक, अद्वितीय और शक्तिशाली अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपत अस्त्र प्राप्त थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं और परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए परशुराम को भगवान विष्णु और भगवान राम दोनों के समान शक्तिशाली माना गया है। भगवान परशुराम क्रोध के पर्याय रहे हैं, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है। माता-पिता के प्रति परशुराम का समर्पण ऐसा था कि वे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक बार उनकी माता रेणुका पानी भरने नदी किनारे गई, लेकिन कुछ देवताओं के आने के कारण उन्हें आश्रम लौटने में विलंब हो गया। ऋषि जमदग्नि ने अपनी शक्ति से इसका कारण जान लिया और रेणुका के आने पर अत्यधिक क्रोधावस्था में अपने पांचों पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम को छोड़कर चारों भाईयों ने माता के प्रति प्रेमभाव व्यक्त करते हुए पितृ आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। क्रोधित जमदग्नि ने चारों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके चरणों में सिर झुकाकर अपने अस्त्र फरसे से तुरंत माता रेणुका का वध कर दिया। इस पर जमदग्नि उनसे खुश हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माता रेणुका सहित चारों भाईयों को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा और जमदग्नि ने सभी को नवजीवन प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थापित परशुराम कुंड के संबंध में मान्यता है कि परशुराम ने अपनी माता का वध करने के बाद इस कुंड में स्नान कर अपने पाप का प्रायश्चित किया था। हिंदू पुराणों के अनुसार परशुराम को कलियुग में ऋषि के रूप में पूजा जाता है और उन्हें आंठवें मानवतारा के रूप में सप्तऋषि के रूप में गिना जाता है। उनकी गिनती महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कन्डेय सहित उन आठ अमर किरदारों में होती है, जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

धैर्य के साथ करें आत्ममूल्यांकन

संकलित
दर्शन

प्रकृति हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित व उत्साहित करती रहती है। हर पेड़, पौधे, फूल, पत्ती का एक मौन संदेश हुआ करता है और वह है कि स्वयं को निरंतर गतिमान और संतुलित रखने के लिए धैर्य चाहिए। पेड़ों पर मंजरी या बौर आने के तुरंत बाद ही तो फल नहीं आ जाता। हौले-हौले ही यह प्रक्रिया सम्पन्न होती है। माटी, हवा और पानी से जिस तरह एक पौधा धीरज रखकर खुद को पुष्पित और पल्लवित करता है, हमें भी ऐसा ही जीवन दर्शन अपनाना चाहिए। महर्षि अरविंद अपने पास आने वाले जिज्ञासु को यह मंत्र देते थे कि मनुष्य अपने सारे जीवन का वास्तुकार स्वयं ही है। हम अपनी रुचि और सोच-विचार के हिसाब से दिनचर्या तय करते हैं। अपने तौर तरीके से दिन बिताते हैं। सब सामान्य रहता है, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन इस दिनचर्या में कुछ जरा-सा भी कुछ अनचाहा हुआ नहीं कि हम सिर पीटने लगते है। हमारा धैर्य डोल जाता है। हमारी पसंद से बने हुए जीवन की हलचल और हिचकोले हमें विचलित कर देते हैं। हम गलती से भी आत्म अवलोकन नहीं करते।हम अपनी भूमिका न देखकर किसी और पर दोष मढ़ देते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि इस हालत के लिए उनके अलावा सब ही जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने और खुद साफ बच जाने के इस पल में हम चतुराई से यह सच छिपा जाते हैं कि कर्म का नियम कुछ और ही है। कर्म का सिद्धांत यह साफ कहता है कि हमारे हर दुख कष्ट आदि के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं।

क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे?

संकलित
प्रेरणा

आठ साल का एक बच्चा एक रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहाः क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे?दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा! लेकिन, उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल चालीस दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछाः तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दियाः इस दुनिया में मां के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी मां दिनभर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अब अस्पताल में हैं। अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा ? डाक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदारः हां, मिलेंगे! कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चाः सिर्फ एक रुपए। बच्चे की मां का ऑप्रेशन हुआ। और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो उठीं। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहाः टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी, उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है.. मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूं।

अक्षय तृतीया

कराड में गुरुवार को अक्षय तृतीया उत्सव की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली।

आज की पाती

रेडक्रास का सर्वकालिक महत्त्व

दुनिया में मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मानवता को दर्शाते दुनिया में बहुत से दिवस मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है विश्व रेडक्रॉस दिवस। यह हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम है 'मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है'। इस थीम से ही साबित हो रहा है कि यह संस्था निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, दूसरों की मदद करके जो खुशी हासिल होती है, वो ही सच्चा इनाम होता है इतिहासकार बताते हैं कि इस दिवस के मनाने का मुख्य कारण हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर उनको याद करना है। वर्ष 1859 में सोल्फेरिनो युद्ध में हजारों सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और हजारों घायल भी हुए थे। इन घायल सैनिकों की हालत देखकर हेनरी ड्यूनेंट का हृदय विचलित हुआ तो उन्होंने इन सैनिकों की मदद की थी। *–रवि प्रकाश शर्मा, महासमुंद*

करंट अफेयर

भारत की तीस्ता परियोजना में सहयोग की पेशकश

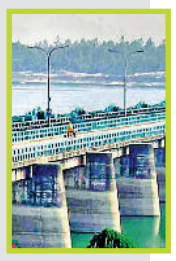

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारत ने बांग्लादेश में सीमा पार तीस्ता नदी पर एक जलाशय के निर्माण के लिए सहयोग देने की पेशकश की है। बांग्लादेश के दौरे पर आए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और हसन से मुलाकात की, जिसके बाद बांग्लादेशी मंत्री ने यह जानकारी दी। तीस्ता जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है और मुख्य रूप से इसी कारण बांग्लादेश ने जलाशय के निर्माण की पहल की और चीन ने इस परियोजना का समर्थन करने की तुरंत इच्छा जताई। क्वात्रा बुधवार शाम ढाका पहुंचे। महमूद ने क्वात्रा से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'आप जानते हैं कि हमने तीस्ता से जुड़ी एक बड़ी परियोजना शुरू की है। भारत उसका वित्त-पोषण करना चाहता है। हमने कहा कि परियोजना हमारी जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए, इसे हमारी जरूरतों को पूरा करना होगा।' बहरहाल, मंत्री ने भारत के प्रस्ताव के बारे में विस्तार से नहीं बताया। बांग्लादेश ने कुछ महीने पहले कहा था कि वह भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली तीस्ता पर जलाशय बनाने के चीनी प्रस्ताव से जुड़ी 'भू-राजनीति' पर गौर करेगा।

ऑफ बीट

जलवायु परिवर्तन बन रहा अत्यधिक बारिश का कारण

अभूतपूर्व बाढ़ के बारे में मीडिया लेखों में, आप अक्सर यह कथन सुनेंगे कि प्रत्येक 1° सेल्सियस वार्मिंग बढ़ने पर, वातावरण लगभग 7% अधिक नमी धारण कर सकता है। यह आंकड़ा फ्रांसीसी इंजीनियर साडी कार्नोट द्वारा किए गए शोध से आया है और 200 साल पहले इसी साल प्रकाशित हुआ था। अब हम जानते हैं कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। हाँ, अधिक गर्म वातावरण में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। लेकिन बारिश की बूंदें बनाने के लिए जलवाष्प के संघनन से गर्मी निकलती है। यह, बदले में, गरज के साथ मजबूत संवहन को बढ़ावा दे सकता है, जो बाद में काफी अधिक बारिश कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक वर्षा की तीव्रता प्रति डिग्री वार्मिंग से 7% से अधिक बढ़ सकती है। हम जो देख रहे हैं वह यह है कि गरज के साथ बौछारें उस दर से लगभग दोगुनी या तिगुनी हो सकती हैं – वार्मिंग की प्रत्येक डिग्री के लिए लगभग 14-21% अधिक बारिश। तूफान दुनिया भर में अत्यधिक बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, जो ब्राजील की विनाशकारी बाढ़ में योगदान देता है, जिसने सैकड़ों शहरों को जलमग्न कर दिया और दुबई के हवाई अड्डे और सड़कों पर पानी भर गया।

ट्रेंड

जलवायु संबंधी खतरे देखे

डब्लूएमओ रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में रिकॉर्ड जलवायु संबंधी खतरे देखे गए। खतरनाक मौसम और जलवायु से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्लाइमेट एक्शन की तत्काल आवश्यकता और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर एक और रिपोर्ट।
-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

आध्यात्मिक रहें

आध्यात्मिक विद्या सब प्रकार की विद्याओं में श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक बल विषम परिस्थितियों में सहायक है। अध्यात्म हमारे स्वभाव की यात्रा है, जिसका फलादेश है-अज्ञान जनित विकारों से मुक्ति। अतः जीवन की दिव्यता के उदय हेतु आध्यात्मिक रहें।
-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

नफरत नहीं, नौकरी चुनो

देश के युवाओं! 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। इंडिया की सुनो, नफरत नहीं, नौकरी चुनो।
-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी

बीजेपी का नेता आदिवासी युवक के सिर पेशाब करता है। गुजरात में गेंद छूने पर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया गया। बीजेपी दलितों पिछड़ों आदिवासियों से नफरत करती है। बीजेपी आरक्षण खत्म करेगी।
-संजय सिंह, आप नेता

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com